देशबन्धु



# { संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 17 सितम्बर 2024

*संस्थापक-सम्पादक* : स्व. मायाराम सुरजन

## देश की बुनियाद पर प्रहार

महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए अहिंसा की नीति को अपनाना, नेहरूजी की गुटनिरपेक्ष नीति और संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन तीनों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन और एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान, ये कुछ ऐसी विशिष्ट बातें हैं, जिनके कारण भारत के लोकतंत्र की दुनिया में अलग पहचान बनी। आजादी के 75 साल बाद भी भारत का लोकतंत्र मजबूत बना हुआ है और इस पर हो रहे तमाम प्रहार विफल हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत को बनाने वालों ने दूरदृष्टि के साथ जो विचार भारत की जड़ों में रोपे थे वो अब मजबूती से लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार भारत की इस खासियत को चोट पहुंचाने में लगी है। बीते दिनों ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में पहुंचे। विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका की एक सम्मानजनक दूरी होना चाहिए, लेकिन यहां वो दूरी मिटती दिखी। श्री मोदी के शासनकाल में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, पूर्व राष्ट्रपति को एक देश, एक चुनाव समिति का मुखिया बनाया गया। अब मुख्य न्यायाधीश के घर की निजी पूजा में प्रधानमंत्री के पहुंचने से कई किस्म के सवाल खड़े हुए, लेकिन भाजपा को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। भाजपा को शायद इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं है कि देश के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार अजित डोभाल रूस के राष्ट्रपति के सामने बैठकर उन्हें श्री मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी दे रहे हैं। अब तक देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटते हुए ही प्रेस को अपनी यात्रा के बारे में बताते थे, ताकि उनके जरिए देशवासियों को पता चले कि हमारे प्रधानमंत्री ने किस देश में जाकर, क्या काम किया, जो हमारे लिए लाभकारी है। इसके बाद देश लौटने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी यात्रा का ब्यौरा देते थे। लेकिन दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह जानकारी देने का अर्थ क्या यह है कि भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति और स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़ दिया है। क्या अब भारत की संप्रभुता को इस तरह दांव पर लगाया जाएगा। श्री मोदी को अब यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि यूक्रेन जाने से पहले क्या उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अनुमति भी ली थी। अगर यूक्रेन जाने का फैसला श्री मोदी ने संप्रभु राष्ट्र का मुखिया होने के नाते लिया था, तो अब कौन सी मजबूरी में उन्हें एनएसए को रूस भेजकर सफाई देनी पड़ी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह भी बताना चाहिए कि विदेश मामलों में या दूसरे देशों पर कार्रवाई का फैसला अब उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, केबिनेट इन सबकी सलाह से हो रहा है या भाजपा का कोई भी नेता इसके लिए बयान देने को अधिकृत है। क्योंकि त्रिपुरा में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि केवल 'मुरली' से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए 'सुदर्शन' भी आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना है कि विधर्मियों को अवसर नहीं देना है। बांग्लादेश जैसे स्थिति की पुनरावृत्ति यहां न होने पाए, इसके लिए ऐसी शक्तियों को हमें समाप्त करना है। हमें देश और धर्म को सुरक्षित रखना है। पाकिस्तान को मानवता का कैंसर और दुनिया का नासूर बताते हुए श्री योगी ने कहा जब तक पाकिस्तान का ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक इलाज संभव नहीं है। पाकिस्तान का उपचार शुरू हो चुका है। अब पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। क्या मोदी सरकार यह बता पाएगी कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री पीओके और बलूचिस्तान को लेकर जो दावे कर रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है और पाकिस्तान का उपचार करने का मतलब क्या है। क्या भारत ने शांति की नीति को नकार दिया है।

मुरली के साथ सुदर्शन की बात करके आदित्यनाथ योगी ने सीधे तौर पर हिंसक विचारों का समर्थन किया है और ऐसे विचार केवल पाकिस्तान के लिए ही प्रकट नहीं हो रहे हैं। देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दी जा रही धमकियां बता रही हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी की 'जीभ काटने वाले' को 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। श्री गायकवाड़ ने राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए बयान के बाद यह ऐलान किया है। उन्हें आपत्ति है कि श्री गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, हालांकि यह सरासर झूठी बात है, क्योंकि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने से साफ इंकार किया है। लेकिन उनकी चर्चा के वीडियो के एक अंश को ही गलत तरीके से फैलाया गया है। संजय गायकवाड़ साफ तौर पर फेक न्यूज का शिकार बने हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर वे हिंसक विचारों से ग्रसित दिखाई दे रहे हैं, तभी उन्होंने बर्बर सोच को प्रदर्शित किया है। राहुल गांधी के विचारों से विरोध होने पर उसका तार्किक जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से बदले का विचार जाहिर करता है कि बीते 10-11 बरसों में देश में नफरत और हिंसा लोगों में कूट-कूट कर भरी गई है। इससे पहले भाजपा के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी का हश्र उनकी दादी की तरह होने की बात कही थी और भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी को नंबर एक आतंकी ही कह दिया।

अलग-अलग वक्त और स्थानों पर हुई ये तमाम घटनाएं साबित कर रही हैं कि न्याय, शांति, अहिंसा जैसे सद्विचारों के साथ बनाए गए भारत पर राजनैतिक विरोध के नाम पर प्रहार किए जा रहे हैं, जो असल में उसकी बुनियाद को उखाड़ने की कोशिश है। जनता पर अब यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे प्रहारों का विरोध करे और संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करे।

# केजरीवाल का दांव: अग्निपरीक्षा या गुगली

सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहाई के बाद, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने पहले संबोधन में ही, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें झंझोड़कर रख देने वाला एलान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि वह दो दिन में मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद तभी स्वीकार करेंगे, जब जनता उनके ईमानदार होने पर अपने अनुमोदन की मोहर लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत देकर उनके ईमानदार होने पर कानूनी मोहर लगा दी है, लेकिन उन्हें लगता है कि इतना काफी नहीं है। अब वह जनता के सामने अग्निपरीक्षा देंगे और मुख्यमंत्री पद तभी स्वीकार करेंगे, जब जनता उनके ईमानदार होने पर अपने वोट से मोहर लगाएगी। और अपनी इस त्याग मुद्रा का दायरा बढ़ाकर, इसे आम आदमी पार्टी की ही त्याग की मुद्रा बनाते हुए, केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के फैसले के एलान में एक पेच और डाल दिया। उन्होंने एलान किया कि उन्हीं की तरह, व्यापक रूप से सरकार में नंबर-2 माने जाने वाले, उप-मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री, मनीष सिसोदिया भी इस अग्निपरीक्षा की चुनौती स्वीकार करेंगे और जनता के ईमानदार घोषित करने के बाद ही, उप-मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुन: इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए, एक और पेच जोड़ते हुए केजरीवाल ने यह मांग भी पेश कर दी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जो अगली फरवरी में होने हैं, आगे खिसका कर नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ करा दिए जाएं, ताकि केजरीवाल की अग्निपरीक्षा जल्दी हो जाए।

कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा, केजरीवाल की इस गुगली से हतप्रभ रह गयी है। भाजपा के नेता, जो अब तक जेल में रहने के आधार पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगते आ रहे थे, अचानक उनके इस्तीफे का एलान करने से समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे अपनी कामयाबी मानें या अपनी परेशानी। यह कहने के सिवा कि केजरीवाल ने पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया, वे ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हां! आखिरकार काफी कसरत के बाद उन्होंने यह नयी मांग जरूर निकाली है कि केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए! बहरहाल, मुख्य विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रियाओं से समझना मुश्किल नहीं है कि वह समझ ही नहीं पा रही है कि इस नयी स्थिति से कैसे निपटा जाए। जाहिर है कि चुनाव जल्दी कराने की आम आदमी पार्टी की मांग ने भाजपा को और भी चक्कर में डाल दिया है। उसकी चुनाव जल्दी कराने में शायद ही कोई दिलचस्पी होगी, लेकिन चुनाव जल्दी कराए जाने का विरोध वह पार्टी कैसे कर सकती है, जो इसके दावे करती नहीं थकती है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल की पार्टी से विश्वास उठ चुका है। बहरहाल, चुनाव जल्दी कराने के मुद्दे पर भाजपा, अपने हितों की रक्षा के लिए चुनाव आयोग पर भरोसा कर सकती है, जो वैसे भी केजरीवाल मनमुताबिक फैसला क्यों लेना चाहेगा? भाजपा के लिए इस मामले पर चुप लगाना ही काफी होगा। वैसे केजरीवाल ने भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं करने और मंत्रिमंडल से जल्दी चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव पारित नहीं कराने के जरिए, इसका इशारा कर दिया है कि वह भी जल्दी चुनाव की आम मांग को प्रचार के स्तर पर ही रखने जा रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ाने जा रहे हैं।

अग्निपरीक्षा के जरिए अपना "सत" साबित करने का केजरीवाल का फैसला, एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या नहीं, इसका फैसला तो सबसे बढ़कर दिल्ली के चुनाव में होगा। लेकिन, केजरीवाल की गुगली ने भाजपा के लिए उसके खिलाफ अपने प्रचार की बैटिंग में रन बनाना,



राजेंद्र शर्मा

कहने की जरूरत नहीं है कि आम तौर पर आम चुनाव के और खासतौर दिल्ली की सात सीटों पर चुनाव के नतीजों से, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से सबक लिया होगा। उसने खासतौर पर इस तथ्य से सबक तो जरूर लिया होगा कि इन सीटों पर भाजपा के मत फीसद में पिछले आम चुनाव की तुलना में कमी के बावजूद और कांग्रेस तथा आप पार्टी के बीच पूर्ण चुनावी समझौता होने और अरविंद केजरीवाल के विशेष जमानत पर प्रचार के लिए छूटकर, चुनाव प्रचार करने के बावजूद, भाजपा सभी सात सीटों पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही।

बहुत मुश्किल बना दिया है। दिल्ली शराब घोटाले के पूरे केस में कोई सचाई होने या नहीं होने से अलग, इससे इंकार करना मुश्किल है कि इस केस में एक के बाद एक, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी तथा लंबे अर्से तक उन्हें जेल में बंद रखे जाने का, आम तौर पर इस पार्टी की छवि पर और खासतौर पर उसकी भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा की छवि पर, कुछ न कुछ असर जरूर पड़ा है। याद रहे कि यही छवि, मध्यवर्ग के बीच आप पार्टी के समर्थन का मुख्य आधार है। इसके साथ, दस साल से अधिक के शासन से पैदा हुईं लोगों की निराशाएं जुड़कर, आप पार्टी के चेहरे पर बदहवासी की न सही, चिंता की रेखाएं लाती ही थीं। केजरीवाल ने इस दांव से एक ही झटके में, इसी गिरावट को थामने की कोशिश की है।

कहने की जरूरत नहीं है कि आम तौर पर आम चुनाव के और खासतौर दिल्ली की सात सीटों पर चुनाव के नतीजों से, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से सबक लिया होगा। उसने खासतौर पर इस तथ्य से सबक तो जरूर लिया होगा कि इन सीटों पर भाजपा के मत फीसद में पिछले आम चुनाव की तुलना में कमी के बावजूद और कांग्रेस तथा आप पार्टी के बीच पूर्ण चुनावी समझौता होने और अरविंद केजरीवाल के विशेष जमानत पर प्रचार के लिए छूटकर, चुनाव प्रचार करने के बावजूद, भाजपा सभी सात सीटों पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। इससे साफ था कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आप सरकार के रास्ते में बाधाएं खड़ी किए जाने से लेकर, आप नेताओं के साथ उसके अत्याचार तक की सारी शिकायतें भी, दिल्ली के मतदाताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं कर पा रही थीं। इस अपर्याप्तता ने ही केजरीवाल को इस्तीफे की गुगली फेंकने के लिए प्रेरित किया लगता है, ताकि केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा के खिलाफ अपनी आलोचनाओं को और तीखी धार दे सके।

केजरीवाल की इस्तीफे की गुगली के पीछे एक और भी कारण है। दिल्ली में, जहां उप-राज्यपाल के जरिए, केंद्र सरकार ने निर्वाचित सरकार के हाथ-पांव पहले ही बहुत ज्यादा बांध दिए हैं, केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के साथ लगायी गयीं राज्य सचिवालय नहीं जाने से लेकर किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करने तक की शर्तें, व्यवहार में उनके लिए मुख्यमंत्री के रूप में काम करना ही बहुत कठिन बना देती थीं। ऐसे में चुनाव से चंद महीने पहले, लगातार उप-राज्यपाल से खींचतान में फंसी सरकार चलाने में उलझे रहने के मुकाबले में, केजरीवाल को यही ज्यादा फायदे का सौदा लगा होगा कि मुख्यमंत्री के पद पर अपने किसी ऐसे उत्तराधिकारी को बैठा दिया जाए, जिसके काम करने पर उतने बंधन नहीं होंगे और इसलिए चुनाव से पहले, दिल्लीवासियों के लिए हित के कुछ काम हो रहे होंगे। और खुद वह स्वतंत्रता के साथ जनता के बीच जाकर, भाजपा के विरुद्ध अभियान चलाने की स्थिति में होंगे।

फिर भी, केजरीवाल के लिए यह गुगली फेकना भी कोई आसान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की चंद नेताओं पर ही केंद्रित पार्टी है, जिसके केंद्र में केजरीवाल हैं और जिसका वैचारिक आधार ज्यादा मजबूत नहीं है, संघ-भाजपा के बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक अभियान के सामने खासतौर पर वेध्य है। इस सब को देखते हुए चाहे अस्थायी रूप से ही हो, मुख्यमंत्री के पद के लिए अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी का चुनाव आसान नहीं है। भाजपा जिस तरह से साम-दाम-दंड-भेद, सभी हथियार लेकर, आप पार्टी तथा उसकी सरकार को कमजोर करने के लिए मौके की ताक में तैयार बैठी हुई है, उसके सामने तो यह और भी कठिन हो जाता है। झारखंड का उदाहरण सामने है। पहले गिरफ्तारी के जरिए, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश की गयी। जब यह कोशिश नाकाम रही और मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन वापस भी आ गए, तो उनकी जेलयात्रा के दौरान एवजीदार मुख्यमंत्री बनाए गए चंपई सोरेन को भाजपा ने तोड़ लिया। उनके सहारे एक अलग आदिवासी पार्टी खड़ी करने की कोशिश भी जब सिरे नहीं चढ़ी तो, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया। और अब खुद प्रधानमंत्री झारखंड में अपने चुनाव की घोषणा से पहले के चुनाव प्रचार में, भाजपा में नये-नये भर्ती किए गए चंपई सोरेन तथा सीता सोरेन के नाम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमले के लिए इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। अब जबकि केजरीवाल, जनमत की अग्निपरीक्षा में खरा उतरने के बाद, फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के हिसाब से चल रहे हैं, वह निश्चय ही झारखंड के घटनाक्रम की दिल्ली में पुनरावृत्ति नहीं चाहेंगे। अस्थायी उत्तराधिकारी के पद पर भी वह ऐसे उम्मीदवार को लाना चाहेंगे, जो निजी तौर पर उनके प्रति वफादार भी हो और ज्यादा स्वतंत्र होने की कोशिश भी नहीं करे।

बेशक, केजरीवाल की गुगली का जहां तक अगले महीने के शुरू में हरियाणा में होने जा रहे चुनाव पर असर पड़ेगा, भाजपा को इसका परोक्ष लाभ भी मिल सकता है। याद रहे कि भाजपा, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने की संभावनाओं को पीठ दिखाकर, अब राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल के अब खुद जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटने का रास्ता खुल जाने के बावजूद, हरियाणा के चुनाव में आप पार्टी के बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरने तो दूर, कोई खास असर डालने में समर्थ होने की भी संभावनाएं कम ही हैं। बहरहाल, दिल्ली में जरूर आम आदमी पार्टी, इस गुगली से भाजपा के खिलाफ और शेष विपक्ष के खिलाफ भी, अपने प्रचार को ज्यादा धारदार बनाने में और अपने जनाधार के छीजने को रोकने में कामयाब हो सकती है। लेकिन, यह तभी होगा जब केजरीवाल को सचमुच अपने मन मुताबिक खड़ाऊं मुख्यमंत्री मिल जाए।

**( लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं। )**

# जम्मू-कश्मीर : भाजपा की नीतियों और समझौतों पर संशय

नए जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा की 90 सीटों पर चुनावी गतिविधियां चरम पर हैं। अपनों की सरकार बनाने के लिए जम्मू के प्रवेश द्वार लखनपुर से कश्मीर के कंगन तक का अवाम उत्साहित है। नई सरकार में सुरक्षा, स्थिरता, समान विकास और समरसता ज्यादातर मतदाताओं का सपना है। सियासी दल इससे दबाव में हैं। सोच को साकार करने और सरोकार पूरा करने के लिए समीकरण साधे जा रहे हैं। सीमाएं समझते हुए संभावनाओं के हिसाब से कई खुले और गुप्त समझौते हो चुके हैं। एक ही विचारधारा के संगठनों में सहमति बन रही है। बावजूद इसके घोषित-अघोषित गठबंधन अपने-अपने हित में बहुमत की सरकार चाहते हैं। फिर भी नई सरकार के स्वरूप, केंद्र से समन्वय, संतुलन, स्थिरता और स्थानीय स्तर की स्वायत्तता को लेकर संशय हैं। संकल्पों, गारंटियों और घोषणाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन जहां सावधान करते हुए आने वाले दौर की समस्याओं का इशारा कर रहे हैं, वहीं पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने से समाप्त पूर्ण राज्य के दर्जे की वापसी के केंद्र सरकार के आश्वासन पर क्रियान्वयन के सही समय का सवाल भी सहज और स्वाभाविक है।

भाजपा ने संकल्प के रूप में 25 सरोकार बताए हैं। इनमें पांच लाख नौकरियां, विद्यार्थियों को लैपटॉप, यात्रा के लिए तीन हजार रुपये और कोचिंग के लिए 10 हजार रुपये देने के अलावा मेडिकल कॉलेजों में एक हजार सीटें बढ़ाने का मंतव्य बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान खींचता है। साथ ही मुफ्त पानी और बिजली के अलावा गरीबों को पांच मरला (125 गज) जमीन मुफ्त देने के अलावा किसानों को 10 हजार रुपये देने का वादा भी लुभावना है। वादों की आड़ में बड़े-बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) पर दावा मजबूत किया गया है। यहां भुलाने की कोशिश की गई कि 22 फरवरी, 1994 को पीवी नरसिंह राव की सरकार में संसद में पीओके को भारत का अभिन्न अंग बनाने का सर्वसम्मत संकल्प पारित किया गया था, जिसे 30 साल हो चुके हैं। इसी क्रम में जम्मू से कश्मीर का सफर 14 घंटे से चार घंटे में बताया जा रहा है। तथ्य यह कि सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में पहले आठ घंटे लगते थे। अब यह यात्रा लगभग पांच घंटे में पूरी हो रही है।



प्रदीप मिश्र

नई सरकार के स्वरूप के राजनीतिक के अलावा सांविधानिक कारण भी हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के अनुसार विधानसभा की 90 सीटों पर सीधा चुनाव होगा। पांच विधायकों का मनोनयन उपराज्यपाल करेंगे। दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों और एक सीट पीओजेके विस्थापित के लिए आरक्षित है। कश्मीरी विस्थापितों में एक सीट महिला के लिए आरक्षित रहेगी।

इंडिया गठबंधन के घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का चुनाव पूर्व गठबंधन है। दोनों के क्रमश: 51 और 32 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेकां के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 और 35 की बहाली के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने समेत 12 गारंटियां हैं। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) निरस्त करने, छह महीन में एक लाख नौकरियां देने और भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत की पहल करने की बात कही गई है। महत्वपूर्ण बात यह भी कि यदि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 हटाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी राज्य का दर्जा छीनने पर सवाल उठाए थे। शीर्ष अदालत ने ही 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कांग्रेस की गारंटियों में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना तो है ही, एक लाख खाली सरकारी पद भरने, हर नागरिक का 25 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के अलावा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की योजना को आगे बढ़ाने का वादा है। 2014 के बाद भाजपा के साथ सरकार बना चुकी पीडीपी ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पानी पर टैक्स खत्म करने, गरीबों को रसोई गैस के 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है।

जाहिर है कि नई सरकारों के लिए अपने वादों को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत होगी। केंद्र शासित प्रदेश के संसाधन सीमित हैं। जम्मू-कश्मीर में आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के सरकार के दावे के उलट यहां देनदारियां बढ़ी हैं। संसद द्वारा स्वीकृत 2024-2025 के बजट में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियां 2019-2020 में 83,573 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1,12,797 करोड़ रुपये हो गई हैं। 2020-2021 में देनदारियां 92,953 करोड़ रुपये थीं, जो 2021-2022 में 1,01,462 करोड़ रुपये और 2022-2023 में 1,12,797 करोड़ रुपये तक पहुंच गईं। हालांकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रदेश के कर्ज मुक्त होने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्ज और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के बीच उचित अनुपात बना हुआ है। दूसरी ओर जानकार मानते हैं कि नई सरकार बनने के बाद होने वाले खर्च से सरकारी खजाने पर अचानक बोझ बढ़ेगा और आमदनी के साधन इसी तरह से नहीं बढ़ाए जा सकेंगे, क्योंकि लोकप्रियता के लिए सरकारें कर्ज लेने से परहेज नहीं करतीं हैं।

नई सरकार के स्वरूप के राजनीतिक के अलावा सांविधानिक कारण भी हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के अनुसार विधानसभा की 90 सीटों पर सीधा चुनाव होगा। पांच विधायकों का मनोनयन उपराज्यपाल करेंगे। दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों और एक सीट पीओजेके विस्थापित के लिए आरक्षित है। कश्मीरी विस्थापितों में एक सीट महिला के लिए आरक्षित रहेगी। इसके अतिरिक्त सदन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर दो और सीटों पर महिलाओं को मनोनीत किया जाएगा। मुख्य संशय दिल्ली और पुडुचेरी मॉडल को लेकर है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। मनोनयन नहीं होता। पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव जबकि तीन सदस्य मनोनीत होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 239 में है। 239ए के अनुसार विधानमंडल सर्वोच्च है। सदन उपराज्यपाल से ऊपर है। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय व्यवस्था दे चुका है कि एलजी सदन में पारित विधेयकों को रोक सकते हैं। दिल्ली में 239एए के प्रावधान लागू होते हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार के लिए वित्तीय मामलों, टैक्स लगाने, छूट देने, बदलने बगैरह में उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुनर्गठन कानून की धारा 55 में संशोधित नियमों को अधिसूचित किया था। इसमें उप राज्यपाल को विस्तारित शक्तियां देने वाली नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके बाद राजनीतिक हल्कों में अटकलें लगीं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में देर लगेगी।

यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले बारामुला के निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद ने अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) और प्रतिबंधित होने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ रही जमात-ए-इस्लामी के साथ तालमेल कर लिया है। पहले चरण की 24 सीटों पर मतदान के ठीक पहले हुए इस समझौते को नए समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। राष्ट्रवादी इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। चुनाव के पहले रशीद की रिहाई केंद्र सरकार से उनके सहयोग के भरोसे का नतीजा माना जा रहा है। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी को अपने प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में मात देने की नीयत से चाल चली गई है। एआईपी कश्मीर घाटी की 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में रशीद ने 18 में से 14 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। अनजान सी पार्टी के इतनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने से आश्चर्य है। कहा जा रहा है कि 2014 में पीडीपी की तरह ही 2024 में एआईपी-जमात गठबंधन से भाजपा का चुनाव पश्चात समझौता संभव है। घाटी की 47 में से 28 सीटों को खाली छोड़कर भाजपा ने इस संभावना के सशक्त होने का संदेश दिया है। अल्पमत से बचने और बहुमत की सरकार बनाने के लिए भाजपा 62 सीटों पर लड़ कर 50 सीटें जीतने पर जोर लगा रही है।

**( लेखक जम्मू-कश्मीर में पत्रकार रह चुके हैं। )**



## ललित सुरजन की कलम से

### विदेशों में कालाधन

*'विदेशों में जमा धन को वापिस लाने की जो मुहिम चल रही है वह मुख्य तौर पर और शायद जानबूझकर, वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। ऐसा आभास दिया जा रहा है कि विदेशी बैंकों में यदि भारतीय धन है तो वह कांग्रेस नेतृत्व के चलते है। विपक्ष के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन पर आक्रमण करने का यह एक और अच्छा मौका है, लेकिन विपक्ष से जिस जिम्मेदारी और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, उसका यहां अभाव परिलक्षित होता है। एक तो ज्ञातव्य है कि जिन भारतीयों ने विदेशी बैंकों में पैसा जमा किया है वे एनआरआई अथवा पीआईओ हो सकते हैं और भारत के कानून संभवत- इस मामले में लागू उन पर न होते हों। दूसरे, राजनीतिक दलों का जो पैसा इस तरह से जमा होगा वह मुख्य रूप से सैन्य सामग्री की खरीद पर मिले कमीशन का होगा, जिसका एक अच्छा-खासा हिस्सा आम चुनावों के समय किसी न किसी तरीके से देश में आता होगा। तीसरे, अनेकानेक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आयात-निर्यात की प्रक्रिया में विदेशों में गुप्त रूप से लेनदेन करते हैं तथा स्वीट्जरलैण्ड या अन्यत्र जमाधन में बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह से बनाया गया होगा। चौथे, भारत ने मॉरीशस तथा कुछ अन्य देशों के साथ दोहरे कराधन से बचने के लिए संधियां की हैं, उसके माध्यम से जो काला धन आज आ रहा है वह पूरी तरह से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ही है। पांचवी बात यह है कि क्या देश के भीतर कालाधन नहीं है और क्या हर रोज देश के भीतर ही कालाबाजारी, जमाखोरी, गबन और घूस के नए-नए प्रकरण रोज सामने नहीं आ रहे हैं! सरकारी एजेंसियों के द्वारा छापे मारे जाते हैं, संपत्तियां जब्त की जाती हैं और फिर चुपचाप कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है।'*

**( 10 फ़रवरी 2011 को प्रकाशित )**

https://lalitsurjan.blogspot.com/2012/04/4_21.html

## पावन प्रसंग

### श्राद्ध तर्पण का प्रयोजन

श्राद्ध पितरों के नाम पर किए जाते हैं और उनमें दान-पुण्य किया जाता है। इस निमित्त उनके साथ तर्पण, पिंडदान आदि कर्मकांड भी जोड़ दिए गए हैं। वर्ष में जिस तिथि में पितरों की मृत्यु हुई हो, उस दिन भी श्राद्ध किया जाता है और आश्विन कृष्ण पक्ष में भी। चूंकि उन दिनों कन्या का सूर्य होता है इसलिए कन्यार्क का अपभ्रंश 'कनागत' भी प्रचलित हो गया है। पूर्वजों या गुरुजनों द्वारा किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उसकी वार्षिक ब्याज को चुकाना वार्षिक श्राद्ध है, चाहे वह मरण वाली तिथि को किया जाए या आश्विन कृष्ण पक्ष में।

उपकारी का प्रत्युपकार करना सामान्य मनुष्य धर्म है। धर्मकर्तव्यों के प्रति श्रद्धा बनाए रहना श्राद्ध है। अंत्येष्टि संस्कार के उपरांत जो 13 दिन बाद श्राद्ध किया जाता है, उसमें स्वावलंबी उत्तराधिकारी पूर्वजों की छोड़ी संपत्ति को उनकी धरोहर मानकर उनकी सद्गति के लिए ही परमार्थ प्रयोजनों में लगा देते हैं। मात्र असमर्थ आश्रित ही उसे निर्वाह में काम में लाते हैं। दान का परिणाम लोक और परलोक दोनों में ही होता है। इससे यश और शांति दोनों ही सह वितरण क्रम अपनाने से समाज की सुव्यवस्था भी बनती है पर वह दान सत्पात्रों को ही दिया जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की सुविधा संपन्नता भले ही न बढ़े, पर उनसे पिछड़ेपन से छुटकारा पाने और आगे बढ़ने, ऊंचा उठने में सहारा मिले। यश के लिए किसी पर भी पैसा लुटा देना दान नहीं, एक प्रकार का अहंकारी अज्ञानता है। आत्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है-'श्रद्धा।' श्रद्धा में शक्ति भी है। वह पत्थर को देवता बना देती है और मनुष्य को नर से नारायण स्तर तक उठा ले जाती है किंतु श्रद्धा मात्र चिंतन या कल्पना का नाम नहीं है। उसका प्रत्यक्ष कारण भी होना चाहिए। यह उदारता, सेवा, सहायता, करुणा आदि के रूप में ही हो सकती है। इन्हें चिंतन तक सीमित न रखकर कार्यरूप में, परमार्थपरक कार्यों में ही परिणत करना होता है। यही सच्चे अर्थों में श्राद्ध है। उपकारी के प्रति कृतज्ञता का, प्रत्युपकार का भाव रखना भावना क्षेत्र की पवित्रता एवं उत्कृष्टता का प्राणवान चिन्ह है। इसके लिए धनदान आवश्यक नहीं, समय, धन, श्रमदान, भाव दान भी - समर्थता की स्थिति में इसी प्रयोजन की पूर्ति करते हैं।

**युग निर्माण योजना**

## आपके पत्र

### महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटना आवश्यक

देश की मूलभूत आवश्यकताओं और बुनियादी ढांचों में अन्य विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य का मुद्दा भी सर्वोपरि रहा है। विशेषकर बच्चों, महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य सेवाओं तक पूरी तरह से पहुंच की बात की जाए तो आज भी यह अपेक्षाकृत कम नजर आता है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी स्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और किशोरियों में यह दूरी बहुत अधिक पाई जाती है। हालांकि सरकार की ओर से सभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की समान पहुंच बनाने के लिए कई स्तर पर योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई सामाजिक और अन्य बाधाओं के कारण महिलाओं और किशोरियों की इन क्षेत्रों तक पहुंच पूरी तरह से संभव नहीं हो पाती है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिवीव्ज़ एंड रिसर्च इन सोशल साइंस में 'महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सहायक प्राध्यापक बी. एल. सोनेकर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि आजादी के बाद से ही सरकार के समक्ष महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की, जहां उचित चिकित्सा सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 48.4 प्रतिशत जनसंख्या महिलाएं हैं, जिसमें अधिकतर की मृत्यु बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण होती है। चाहे वह प्रसव के दौरान हो या एनीमिया से ग्रसित अथवा अन्य कारणों से हो. हालांकि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीरता से ध्यान देने के कारण इसमें काफी प्रगति हुई है। यही कारण है कि जहां वर्ष 1947 में महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। वहीं अब यह बढ़कर 66 वर्ष पहुंच चुकी है।

वह लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें आर्थिक और वित्तीय संसाधनों की कमी प्रमुख है। यह कमी उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवरेज के दायरे से दूर होने के कारण होता है। जो उनके आवश्यक दस्तावेज़ पूर्ण नहीं होने के कारण बन नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देना भी महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच से दूर बना देता है। इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक कारण हैं। लगभग ऐसी ही परिस्थितियां शहरी क्षेत्रों में आबाद स्लम बस्तियों की है. जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी और अन्य कारकों के कारण महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही चुनौती उनके स्वास्थ्य और पोषण की कमी को और अधिक जोखिम बना देता है जिसे दूर करने की आवश्यकता है ताकि एक स्वस्थ और कुपोषित मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

**सुखराम, जयपुर राजस्थान**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

*प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770*

*ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in*

## दशकीय जनगणना क्यों नहीं

आम तजुर्बा है कि मौजूदा सरकार को आंकड़ों की पारदर्शिता पसंद नहीं है। वरना, यह समझना मुश्किल है कि भारत में अब तक दशकीय जनगणना क्यों नहीं हुई, जबकि कोविड-19 महामारी का साया हटे लंबा अरसा गुजर चुका है। केंद्र ने जब कुछ महीने पहले सांख्यिकी स्थायी समिति बनाई, तो उसमें शामिल 14 विशेषज्ञों में से कुछ नामों को देख कर आश्चर्य हुआ था। खास कर यह देख कर हैरत हुई कि समिति की अध्यक्षता प्रणब सेन को सौंपी गई है, जिनकी छवि आंकड़ों के प्रति ईमानदारी बरतने की रही है। बताया गया कि समिति राष्ट्रीय सैंपल सर्वे तथा अन्य सरकारी सर्वेक्षणों की सैंपलिंग एवं आंकड़ा विश्लेषण को लेकर सुझाव देगी। यह जग-जाहिर है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में तमाम सरकारी आंकड़ों की साख क्षीण होती चली गई है। अब खबर है कि सरकार ने गुपचुप प्रणब सेन समिति को भंग कर दिया है। समिति के सदस्यों का तो कहना है कि समिति क्यों भंग हुई, उन्हें इसका कारण तक नहीं बताया गया है। अधिकारियों को मीडिया से जरूर कहा है कि अब राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षणों के बारे में स्थायी संसदीय समिति बन गई है, इसलिए दोनों समितियों का दायरा टकरा रहा था। जबकि सूत्रों के आधार पर छपी अखबारी रिपोर्टों में बताया गया है कि एक बैठक के दौरान सेन समिति के सदस्यों ने जनगणना में हो रही देर पर अधिकारियों से सख्त सवाल पूछे। मुमकिन है कि सरकार इससे खफा हो गई हो। आम तजुर्बा है कि मौजूदा सरकार को सवाल और आंकड़ों की पारदर्शिता पसंद नहीं है। वरना, यह समझना किसी के लिए मुश्किल है कि भारत में अब तक दशकीय जनगणना क्यों नहीं हुई? 2021 में इसे कोविड-19 महामारी के कारण टाला गया था, हालांकि उसी वर्ष तमाम चुनाव कराए गए। बहरहाल, महामारी का साया हटे लंबा अरसा गुजर चुका है। दुनिया में कोई ऐसा प्रमुख देश नहीं है, जहां अब तक जनगणना ना हुई हो। इसलिए यह कहने का आधार बनता है कि मोदी सरकार ठोस एवं विश्वसनीय आंकड़ों के स्रोत जनगणना को जानबूझ कर टाल रही है। आंकड़े समय की सच्चाई को बताते हैं। आंकड़े ना हो, तो मनमानी कहानियां बनाई जा सकती हैं। जिस सरकार की प्राथमिकता मनपसंद आंकड़े तैयार कर विमर्श को भ्रमित करना और उसके जरिए मनगढ़ंत नैरेटिव्स को विश्वसनीय बनाना रहा हो, विशेषज्ञों से उसका गुरेज समझा जा सकता है।

## भारतीय राजनीति का असली चेहरा

चार राज्यों के आसन्न चुनावों में अभी मात्र जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा हुई है । झारखण्ड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीख अभी चुनाव आयोग ने घोषित नहीं की है । महाराष्ट्र में धर्म संकट है । भाजपा नहीं चाहेगी कि अब शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने । वे अपने भाजपा कैडर का कोई नेता को चुनेंगे । यह दूसरी बात है कि शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो जाये । पहले कई चुनावों में शिवसेना और भाजपा ने साथ- साथ चुनाव लड़ा है । फिर यदि शिंदे गुट भाजपा में शामिल हो भी जाता है तो भी भाजपा के पास अपने नेता हैं, महाराष्ट्र में । विपक्षी दलों का आरोप है कि हरियाणा में भाजपा की स्थिति कमजोर है । इसी से उनके अनुरोध पर हरियाणा का चुनाव चार दिन आगे खिसका दिया गया । अब भारत में तो स्थानीय स्तर पर रोज त्योहार होते हैं । अब तर्क कुछ गले नहीं उतरता कि चुनाव आयोग भाजपा के अनुरोध पर चुनाव की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी । ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति डांवाडोल है। वह मुख्यमंत्री के लिए कई उम्मीदवार हैं । हुड्डा एक हैं, शैलजा और सुरजावाला भी । यूं कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि ये दोनों संसद सदस्य हैं । इसी कारण विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते । राहुल गांधी चाहते थे कि विपक्षी वोट बंटे नहीं । इसी से आम आदमी पार्टी से वे समझौता चाहते थे । परन्तु स्थानीय नेतृत्व अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं । अतः दोनों के बीच वार्ता फेल हो गई । अब आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगट के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है । अब इण्डिया एलाइंस का क्या? दिल्ली में दोनों ने सात सीटों के लिए समझौता करके चार और तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था । जे.एन.यू. के छात्र नेता कन्हैया कुमार सुनीता केजरीवाल से भी मिले थे । अरविन्द केजरीवाल ने कन्हैया कुमारके लिए प्रचार भी कया था । परन्तु कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को असफलता मिली । कांग्रेस ने विनेश फोगट को लेकर जाट वोट पक्के कर लिये हैं । पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के वोट परम्परा के अनुसार शायद कांग्रेस को ही मिले । परन्तु हरियाणा में जनहित जनता पार्टी और आजाद की पार्टी भी मैदान में है । इस प्रकार विपक्ष के वोट बंटने पर भाजपा को फायदा होगा । विपक्ष का यह भी आरोप है कि वर्तमान भाजपा सरकार हरियाणा में अल्पमतमें हैं । परन्तु राज्यपाल वोटिंग नहीं कराना चाहते । चुनाव से छः महीने पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री तो बदला परन्तु जिनको टिकट नहीं मिला, ऐसे भाजपा के दिग्गज नेता अब दूसरी पार्टी से या स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं । नवीन जिंदल की मां भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं । अब नवीन जिंदल मां का साथ देंगे या पार्टी का, या अंदर खाने कुछ और पक रहा है ।

# बुढ़ापे का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनाने की सराहनीय पहल



आरती कुमारी

केंद्र सरकार ने अब सत्तर साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान भारत' योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य कदम है। अपने देश के करीब साढ़े चार करोड़ परिवार के छह करोड़ बुजुर्ग इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। दरअसल वर्ष 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना में अब तक केवल गरीब परिवार ही शामिल हो सकते थे, जिन्हें पांच लाख का कैशलेस कवर दिया जाता था। अब इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना का लाभ सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इस योजना से हम एक ऐसी दुनिया बना सकेंगे जहाँ हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी सकेंगे। इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी जनकल्याणकारी सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। पारिवारिक एवं सामाजिक घोर उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण बुढ़ापा अपने आप में एक रोग ही बनता गया है। जब आय के स्रोत सिमट जाते हैं और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं मिलती तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते हैं, फिर महंगे इलाज की चिंता और बढ़ जाती है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की नयी पहल का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो यह फैसला इस आयुवर्ग के बुजुर्गों की सेहत को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी क्योंकि आने वाले बीस वर्ष में भारत की बुजुर्ग आबादी तीन गुना होने की संभावना है। नये भारत-विकसित भारत की उन्नत एवं आदर्श संरचना बिना वृद्धों की सम्मानजनक स्थिति के संभव नहीं है। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रुग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण एवं उचित स्वास्थ्य-सेवाओं को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ एवं सुसंस्कृत परिवार परम्परा पर तो काला दाग है ही, शासन-व्यवस्थाओं के लिये भी लज्जाजनक है। हम सुविधावादी एकांगी एवं संकीर्ण सोच की तंग गलियों में भटक रहे हैं तभी वृद्धों की आंखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है, दिल में अन्तहीन दर्द है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलाने एवं उनके स्वास्थ्य विषयक खर्चो एवं चिन्ताओं को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय लाभ देने का फैसला लिया है, वह सराहनीय एवं प्रासंगिक निर्णय है। इस फैसले की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत बहुत पीछे है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ऐसे परिवारों की संख्या केवल 41 प्रतिशत है, जिनके कम से कम एक सदस्य का स्वास्थ्य बीमा हो। बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में तो यह राष्ट्रीय औसत के करीब आधे के बराबर है। स्वास्थ्य बीमा को लेकर यह उदासीन रवैया हमारी उस आदत की वजह से है, जिसमें ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। बहुत से लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन, जब बीमारी सिर पर आती है, तो पूरे घर के बजट को तहस-नहस एवं असंतुलित कर देती है। सरकार का मौजूदा कदम कई परिवारों को ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंसने से बचा सकता है। भारत में इलाज दिनों-दिन महंगा होता जा रहा है। जब आय के स्रोत सिमट जाते हैं और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं मिलती तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते हैं, फिर महंगे इलाज की चिंता और बढ़ जाती है। अकसर भारत में कर्मचारी व आम लोग सोचते हैं कि वे जीवन भर आयकर चुकाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा ना के बराबर होती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने लोकतंत्र के सामाजिक कल्याणकारी स्वरूप को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार अनेक स्वस्थ एवं आदर्श समाज-निर्माण की योजनाओं को आकार देने में जुटी है, उसने वृद्धों को लेकर भी चिन्तन करते हुए वृद्ध-कल्याण योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं को लागू करने की जरूरत इसलिये सामने आयी है कि वृद्धों को आत्म-गौरव के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा, बंधन माना जाने लगा है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। अब जब स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाया गया है तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि खर्च को लेकर परिजनों का डर कम होगा। इस योजना का पूरा खाका सामने आना बाकी है। लेकिन यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि बीमा सुरक्षा कवच होने के बावजूद बुजुर्ग मुफ्त उपचार से वंचित न रह जाएं। खास तौर से सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लेकर निजी अस्पतालों के रवैये को देखते हुए यह चिंता ज्यादा जरूरी हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत आयु 67.3 साल है। पिछले दो दशकों में ही औसत आयु में पांच बरस से अधिक का इजाफा हो चुका है। निश्चित ही यह अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ यह चिंता भी जुड़ी हुई है कि देश में दिल से जुड़े रोगों और डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अन्य रोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो आबादी वर्ष 2011 में 8.6 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 2050 तक 19.5 फीसदी हो जाएगी। यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में स्वास्थ्य देखभाल का 45 प्रतिशत खर्च बुजुर्ग मरीजों पर होगा। ऐसे में बुजुर्गों के सामने अनेक अन्य समस्याओं के साथ नई एवं असाध्य बीमारियां और उनका महंगा इलाज बड़ी समस्या है। ऐसी स्थितियों में अब इस योजना का लाभ सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। बहुत संभव है कि इस समय जब कुछ राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो इस घोषणा के राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन भाजपा ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिये जारी घोषणापत्र में किये वायदे को ही आकार दिया है। वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ निजी व राजकीय अस्पतालों में ले सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से बताया गया है कि जो सत्तर साल से अधिक के नागरिक प्राइवेट बीमा योजना या फिर राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं, वे भी नई योजना का लाभ लेने के अधिकारी होंगे। लेकिन उन्हें इस योजना के लिये आवेदन करना होगा। सरकार ने फिलहाल इस योजना के लिये करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का बजट रखा है और आवश्यकता पड़ने पर बजट बढ़ाने की बात कही है। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य के लिए कोटा बढ़ाया है। हालांकि चीन और अमेरिका की तुलना में यह अब भी कम है। मेडिकल सुविधाएं एवं साधन बढ़ाने के साथ यह इंतजाम भी करना होगा कि आम जनता उसका फायदा उठा सके। सरकार का हालिया फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना को सही ढंग से लागू किया जाए। मुफ्त उपचार से भी बड़ी जरूरत सत्तर साल की उम्र पार वरिष्ठ नागरिकों की नियमित सेहत जांच की है। अस्पतालों की भीड़ में जांच कराना इनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में बुजुर्गों के घर तक मोबाइल स्वास्थ्य जांच सेवा भी इस योजना में लागू हो तो सोने पर सुहागा हो सकता है। सरकार को भविष्य में वृद्धों के लिये अलग से अस्पताल संचालित करने के बारे में भी सोचना चाहिए।

# अंधी व्यवस्था पंगु तंत्र के बीच मौत देने वाला शैल्टर होम!

मनोज कुमार अग्रवाल

देश की राजधानी में विकलांग सिस्टम और परस्पर आरोप लगा कर पल्ला झाड़ लेने वाली राजनीति ने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के आश्रय के लिए बनाए गए शेल्टर होम को मौत का घर बना दिया। यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दिल दहलाने वाली क्रूरता का भी उदाहरण है जिसने दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला शेल्टर होम में एक महीने में 14 बच्चों की जान ले ली है। वहीं इस साल में कुल मौतों की बात करें तो ये संख्या 27 है। . चौंकाने वाली बात ये है कि अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया था इस शेल्टर होम की अंदर की स्थिति बेहद खराब है. इतना ही नहीं, बच्चों को सिर्फ आधा ही खाना दिया जाता है. आलम ये है कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब उनके लिए डेथ चैंबर बन रहा है. उपराज्यपाल वी.के सक्सेना ने इन मौतों को सबसे वंचित लोगों के खिलाफ़ अपराध करार दिया. उधर, विपक्षी दलों भाजपा और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और आश्रय गृह के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया. आतिशी ने मौतों की मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की, जिसके बाद उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को आशा किरण में हुई मौतों सहित शहर द्वारा संचालित सभी आश्रय गृहों की स्थिति की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। यहां काम करने वाली महिला का कहना है कि जो सुविधा 4 साल पहले यहां बच्चों को दी जाती थी, वो अब नहीं मिलती. पहले बच्चों को दूध, अंडा सब मिलता था, लेकिन अब सब बंद कर दिया गया है और सिर्फ दाल रोटी मिलती है. इतना ही नहीं, करीब दो दर्जन बच्चों को टीबी की बीमारी बताई गई है. इसके पीछे का कारण बच्चों को सही डाइट न मिलना और अधिक संख्या में लोगों को इसमें भर देना है. एसडीएम ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक शेल्टर होम की क्षमता लगभग 500 है, लेकिन अंदर लगभग 950 लोग हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जाना और पहचाना जाता है, वहां कहीं ना कहीं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराता नजर आ रहा है. जो जानकारी मिल रही है, उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है. बीमार हो जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता. ऐसे में एक महीने में 14 मौत हो जाना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।आशा किरण में मौत के मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. आजतक के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उनमें इसबात का साफ-साफ जिक्र है कि कैसे महीने दर महीने लोगों की मौत हुई. सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जुलाई महीने में ही एक महीने के अंदर 14 की मौत हुई है। पत्रकारों ने मंत्री आतिशी से पूछा कि क्या ये मौतें सरकार के संज्ञान में नहीं आईं, क्योंकि विभाग का कोई मुखिया नहीं है. इस पर राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा, गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों में सीरियस फिजिकल मॉर्बिडटी भी होती हैं. मृत्यु मेडिकल रूप से इससे जुड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आशा किरण शेल्टर होम में रहने वालों को न केवल गृह चिकित्सा केंद्र में बल्कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भी निरंतर चिकित्सा देखभाल दी जाती है. हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसी जांच में शामिल नहीं हैं. मजिस्ट्रेट रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने भी इसे लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है. विपक्षी दल का आरोप है कि ये शेल्टर होम्स की उपेक्षा और खराब रहने की स्थिति के कारण हुआ है. दिल्ली भाजपा की एक टीम भी स्थिति का जायजा लेने के लिए आशा किरण शेल्टर होम पहुंची थी. पार्टी के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने खाने में फंगस के साथ ये तस्वीरें शेयर की हैं. मेनू में विभिन्न आइटम हैं, कुछ भी उपलब्ध नहीं है. शेल्टर होम में रहने वाले लोगों का बीएमआई कम है. सेंटर में गर्मी से मौतों में उछाल आया है और यहां कूलर भी नहीं है. बासी खाना परोसा जा रहा है. रेखा शर्मा ने कहा कि इतने दिनों से यह संस्था चल रही है, इसके कार्यों की ऑडिट कराई जानी चाहिए और इसके लिए समीक्षा की भी जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर, इसके बाद जरूरत हो तो इस संस्था को बंद करवाना भी जरूरी है, क्यों जो लोग वहां हैं, उन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए न कि शेल्टर होम में. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मानसिक रोगियों के लिए शेल्टर होम होते हैं, बल्कि उन्हें अस्पतालों में होना चाहिए। आश्रय गृह में चिकित्सा देखभाल इकाई के प्रभारी की रिपोर्ट में फरवरी में तीन मौतें, मार्च और अप्रैल में दो-दो, मई में एक, जून में तीन और जुलाई महीने में 14 मौतें दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 जुलाई से 28 जुलाई के बीच 12 मौतें हुईं. 15 जुलाई के बाद से मौतों के रिकॉर्ड से पता चला है कि कई मृतक "गंभीर" या "गहन" बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित थे और अन्य सरकारी अस्पतालों में भी उनका इलाज चल रहा था. 20 जुलाई को दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। आश्रय गृह के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार यहां रहने वाले लोगों को गर्मियों के दौरान उचित पीने का पानी नहीं मिल रहा था और ऐसी संभावना है कि पानी दूषित हो सकता है. उन्होंने कहा, "उन्हें दस्त हो रहे थे. यहां रहने वाले लोगों को अंडे और दूध दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे विशेष आहार माना जाता है. गृह का प्रशासक एक या दो बार आता है, लेकिन उसके पास अन्य चीजें भी होती हैं. कुमार ने कहा कि 60 से 70 प्रतिशत लोग दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन कुपोषण का इलाज दवाओं से नहीं किया जा सकता है। पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 196 के तहत जांच शुरू कर दी है. अधिकारी ने आगे कहा कि केंद्र का प्रशासक ही बता सकता है कि अंदर कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. डीसीपी ने कहा, "हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार आगे की जांच और एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस शेल्टर होम की स्थापना 1989 में रोहिणी के सेक्टर 1 में की गई इसके अंदर 350 लोगों को रखने की क्षमता है.आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इस सुविधा को "हॉरर होम" बताया. उन्होंने कहा, "जिन लोगों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है! यह एक हॉरर होम है! 14 लोग मारे गए, जिनमें से 8 महिलाएं थीं. दो मृतक महिलाओं की केस फाइलों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे कुपोषित थीं. मेडिकल रिपोर्ट में निर्जलीकरण, उल्टी और बिस्तर पर घाव का भी उल्लेख किया गया है.। आशा किरण शेल्टर होम दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। आप विधायक राज कुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री थे। हालांकि, 10 अप्रैल को मंत्री पद और आप से उनके इस्तीफे के बाद से इस विभाग के हेड का पद खाली है।तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी मंत्री को विभाग का जिम्मा नहीं सौंपा है। साल 2015 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में शेल्टर होम की फंक्शनिंग पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2014 के बीच 148 मौतें हुई थीं। दिल्ली महिला आयोग की 2017 की रिपोर्ट में भी यहां की सुविधाओं पर चिंता जताई थी। सवाल है कि आखिर ये अभागे मानसिक कमजोर बच्चों को यदि पर्याप्त सुविधा नहीं दे सकते थे तो आश्रय घर खोलने की क्या जरूरत थी? यह एक अंधी व्यवस्था और कुप्रबंध का जीता जागता नजीर है राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के फेर में लगी है जबकि जरूरत सड़ गल रहे सिस्टम को बदलने की है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid




**मेष राशिः**आज आपका दिन शुभ रहने वाला है। अध्ययन और अध्यापन से जुड़े लोगों का दिन आज शानदार रहने वाला हैं। आपको जल्द ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है। सिविल सेवा करने वाले जातक आज कुछ नया करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। यदि आप कोई छोटा-मोटा व्यापार करते हैं ।

**वृष राशिः**आज आपके लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपको नौकरी में तरक्की के साथ-साथ आपकी इनकम में इन्क्रीमेंट होने के योग हैं। आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखद रहने वाला है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में सुंदर तालमेल रहेगा। आज आप आनंद पूर्वक दिन बिताएंगे। संतान की तरफ से आपको किसी प्रकार की खुशखबरी मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा।

**मिथुन राशिः**आज आपका दिन खुशहाल बीतेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखन आदि कार्यों से आपका मान-सम्मान बढेगा। कार्यस्थल पर अफसरों के साथ सद्भाव बनाकर रखेंगे। आपको तरक्की के मौके मिलेंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार के जरिए कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। पैसों के लेन-देन में थोड़ा सतर्क रहें। आपका दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा।

**कर्क राशिः**आज आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। आज आप किसी खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। बिजनेस करने वालों को किसी अच्छी कंपनी से जुड़कर बिजनेस को बढ़ाने का सुनहरा मौका मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड यात्रा करनी पड़ेगी। आज आप कुछ अनुभवी लोगों से मिलेंगे। जिससे आपको आगे चलकर लाभ मिलेगा।

**सिंह राशिः**आज आपके लिए दिन पाज़िटिव रहेगा। ऑफिस में कलीग्स के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न होंगे। आपके लिए पदोन्नति के आसार हैं। आपकी वेतन भी बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर समझदारी पूर्वक लिए गए फैसले आपको बेहतर परिणाम देंगे। आपके कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग आपको आगे बढने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस दौरान कार्यस्थल पर बाहर का खाना खाने से बचें।

**कन्या राशिः**आज आपका दिन खास रहने वाला है। किसी पुरानी जमीन जायदाद से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र में कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। आप और आपका परिवार बहुत खुश होगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। आप अपने परिवार वालों को किसी बड़े रेस्टोरेंट में ट्रीट देंगे। लवमेट के लिए बेहतरीन समय है। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आज आपको फिजूल खर्च से बचना चाहिए।

**तुला राशिः**आज आपका दिन आनंद और उत्साह से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में कुछ नए विचार लाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया ही आपको नौकरी में तरक्की दिलाएगा। आपके बॉस आपको एप्रिशिएट करेंगे। आपके सगे संबंधी आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। आप किसी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं। आज उम्मीद से अधिक लाभ की संभावना है।

**वृश्चिक राशिः**आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस जुड़े हुए हैं तो आपके के लिए लाभ के योग हैं आप अपने काम में कुछ परिवर्तन लाने का मन बना सकते हैं। दांपत्य रिश्ते को और मजबूत बनने के लिए जीवनसाथी को उपहार देंगे। इस दौरान आप नेगेटिव विचारों से बचें, तभी जीवनसाथी की बातों को समझ पाएंगे। आपके रिश्ते में परिस्थितियां बेहतर होंगी।

**धनु राशिः**आज आपका दिन खुशहाल बीतेगा। शिक्षा से रिलेटेड आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। आपको परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पाएंगे। आगे चलकर आपको नये सुनहरे अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। आप अपने खानपान पर ध्यान रखेंगे। जिससे आपकी सेहत फिट एण्ड फाइन रहेगी। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेल्स में काम करते हैं ।

**मकर राशिः**आज आपका दिन पाज़िटिव रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में बनाई गई योजनाएं कारगर साबित होगी। आपके लिए धन लाभ की संभावना बढ़ेगी?। मास इन मीडिया कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए खास अवसर मिलने की संभावना है। आपके अंदर कलात्मक चीजों के प्रति उत्साह पैदा होगा। आप किसी क्राफ्ट एग्जीबिशन में मित्रों के साथ जा सकते हैं। आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे।

**कुंभ राशिः**आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला है। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने के योग हैं। प्रापर्टी डीलर का काम करने वालों के कामकाज बेहतर रहेंगे। मास्टर डिग्री ले रहे हैं तो आपको कैंपस सलेक्शन में अच्छी नौकरी मिल सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। नौकरी कर रहे युवाओं को उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा।

**मीन राशिः**आज आपका दिन उत्साह से भरपूर रहेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर मिलेगा। जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

## शब्द सामर्थ्य -180

(भागवत साहू)

**बाएं से दाएं**

1. याद, स्मरण 3. अग्नि, आग, पवित्र करने वाला 6. गौ जाति का नर 8. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 10. मुस्कुराहट, तबस्सुम 11. खारा, नमक के स्वाद जैसा 14. मुख्यभाग, निचोड़ 16. पिंडली व एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हड्डी, गुल्फ 18. अद्भुत, विचित्र 21. सम्राट, बादशाह, नरेश 22. कृति, निर्माण करना, बनाना 23. बड़ी थाली 24. समूह, दल 26. एहसानमंद, कृतज्ञ 27. ध्वनि, सदा 28. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर।

**ऊपर से नीचे**

2. अपमान, अनादर, अवज्ञा 3. जल, नीर, अम्बु 4. वाणी, वादा, कथन 4. कर्म शब्द का अपभ्रंश, भाग्य 7. लकड़ी का घूमने वाला एक गोल खिलौना, बिजली का बल्ब 9. लोग, प्रजा 10. यात्री, राही, पथिक 12. कीड़ा 13. चोचला, अदा 15. दंड 17. अवैध, अनुचित 18. जो आधिकारिक न हो, जो अधिकार प्राप्त न हो 19. जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, सत्यपरक, वाजिब 20. ताकत, शक्ति 24. प्रश्न, समस्या 25. घटना, घटना का वर्णन 26. एक प्रसिद्ध पक्षी जो रात में विचरण करता है, लक्ष्मीजी की सवारी 27. पानी, चमक।



### शब्द सामर्थ्य क्रमांक 179 का हल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टे | ढ़ा | मे | ढ़ा | ■ | म | हा | र | त |
| क | ■ | ह | ■ | ■ | ■ | ■ | ज | न |
| ■ | जा | न | की | ■ | क | म | नी | य |
| ■ | ■ | त | म | क | ना | ■ | ■ | ■ |
| म | ■ | ■ | त | ह | त | ■ | दा | ब |
| सी | मा | ■ | ■ | ला | ■ | स | न | द |
| हा | थ | म | ल | ना | ■ | वा | ■ | च |
| ■ | ■ | द | ■ | ■ | घा | ल | मे | ल |
| ■ | ब | द | ह | वा | स | ■ | ■ | न |

### सूडोकु नवताल- 7191

मध्यम

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | 9 | | 6 | 1 | | 8 |
| 6 | 8 | | | | | | | |
| | 1 | 7 | 3 | 8 | | 4 | | |
| 3 | 4 | | 6 | | 7 | | | 9 |
| 5 | | 1 | 8 | | | 2 | | 7 |
| 2 | | | 5 | | 1 | | 8 | 4 |
| | | 3 | | 7 | 5 | 8 | 6 | |
| | | | | | | | 9 | 5 |
| 7 | | 6 | 2 | | 8 | | | 1 |

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

### सूडोकु नवताल -7190 का हल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 |
| 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |

**सुभाषित**

*अत्यधिक लंबे समयकी दूरी या ओझलपनसे प्रेम एवं स्नेहमें कमी आ जाती है।*
❐ *चाणक्य नीति*



## डिजिटल जनगणना

देशमें हर दस वर्षोंके बाद जनगणना करानेकी परम्परा है लेकिन कोविड महामारीके कारण जनगणना नहीं करायी जा सकी। केन्द्र सरकार अब जनगणना करानेकी दिशामें सक्रिय हुई है। देशमें पहली बार डिजिटल जनगणना करानेका विचार किया गया है। इसके लिए तैयारी त्वरित गतिसे शुरू हो गयी है। जनगणना प्राधिकरणने स्वजन गणना पोर्टल बनाया है। राजनीतिक दलोंने जनगणना विलम्बित होनेके कारण इसे एक मुद्दा बना लिया है। विभिन्न राजनीतिक दलोंके नेताओंकी बयानबाजीसे यह स्वत: स्पष्ट है। वैसे भी जनगणनामें काफी विलम्ब हो गया है। यह कार्य ३० सितम्बर, २०२० तक पूरा हो जाना था। २०११ की जनगणनाको आधार बनाकर जो नीतियां बनायी गयी हैं और सब्सिडी आवण्टित की जा रही हैं, उसे उचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस दौरान देशकी आबादी काफी बढ़ गयी है। डिजिटल जनगणनाके लिए जो पोर्टल तैयार किया गया है, उसे अभी लांच नहीं किया गया है। डिजिटल जनगणना पहली बार होने जा रही है, जिसमें नागरिकोंको स्वयं गणनाका अवसर प्राप्त होगा। स्वगणनामें आधार नम्बर या मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपसे एकत्र किया जायगा। डिजिटल जनगणनाको एक सीमातक उचित माना जा सकता है लेकिन यह भी ध्यानमें रखना होगा कि सभी लोग इसकी पात्रता नहीं रखते हैं। अशिक्षा अथवा मोबाइलका अभाव इसमें बड़ी बाधा है। ऐसे लोगोंके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी होगी। वैसे आधार कार्ड काफी संख्यामें लोगोंके बन गये हैं लेकिन सभी लोगोंके पास मोबाइल नहीं हैं। इस जनगणनामें एक बड़ी समस्या जातिको लेकर है। अनेक राजनीतिक दल जातीय जनगणनाके पक्षमें हैं, क्योंकि इसका वे राजनीतिक लाभ उठानेके पक्षमें हैं। यह सत्य है कि भारतीय समाजमें जातिका विशेष महत्व है। जातीय जनगणनापर अभी कोई निर्णय तो नहीं किया गया है लेकिन इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। केन्द्र सरकारको जातीय जनगणनाके बारेमें शीघ्र ही निर्णय करना चाहिए अन्यथा इसमें और देरी हो जायगी। पहलेसे ही काफी विलम्ब हो गया है, इसमें अब और विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसी जनगणनाके आधारपर ही लोकसभा और राज्य विधान सभाओंमें महिलाओंके लिए एक-तिहाई सीटें देनेकी व्यवस्था की गयी है। इसलिए केन्द्र सरकारको उन सभी पहलुओंपर अनिवार्य रूपसे विचार करना होगा, जो सवाल जनगणनाको लेकर लोगोंके मनमें है। भविष्यमें जनगणनाको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

## डाक्टरोंका पहचानपत्र

सरकारका देशके हर डाक्टरका विशिष्ट पहचान-पत्र बनानेका निर्णय मरीजोंके हितमें स्वागतयोग्य पहल है। इससे जहां एक ओर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी वहीं दूसरी ओर कुकुरमुत्तेकी तरह पैदा हो रहे झोलाछाप डाक्टरोंकी भी पहचान हो जायगी जो मरीजोंके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देशके सभी डाक्टरोंको राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) में रजिस्ट्रेशनकी अनिवार्यत सार्थक कदम है। इसके लिए डाक्टरोंको एमबीबीएस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड जमा करना होगा। इस पोर्टलको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने तैयार किया है, जिसमें भारतमें प्रैक्टिस करनेके लिए पात्र सभी एमबीबीएस डाक्टरोंके पंजीकरणकी प्रक्रिया शुरू की गयी है। इससे अब हर डाक्टरकी एक अलग पहचान होगी। इन्हें एक यूनिक आईडी नम्बर दिया जायगा जिससे किसी भी डाक्टरकी योग्यता और अनुभवकी जानकारी मिल सकेगी और लोग अच्छेसे अच्छे डाक्टरसे इलाज करा सकेंगे। साथ ही देशका डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम भी मजबूत होगा और लोग फर्जी डाक्टरोंके चंगुलमें फंसनेसे भी बच सकेंगे। एनएमआर एक डाटाबेस है जिसमें डाक्टरोंका पंजीकरण होगा और उनकी प्रामाणिकता आधार आईडी द्वारा सत्यापित की जायगी। इसके लांच होनेसे १३ लाखसे अधिक डाक्टरोंका डाटा उपलब्ध होगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाकी दिशामें सरकारका यह एक सराहनीय कदम है। इसके माध्यमसे किसी भी अच्छे डाक्टरसे आनलाइन परामर्श लेनेकी सुविधासे धन और समयकी बचत होगी और दिक्कतोंसे भी निजात मिलेगा। इसके साथ ही सरकारको दवाओंकी दिनों-दिन बढ़ती कीमतोंपर भी ध्यान अपेक्षित है। जेनेरिक दवाओंके प्रति भी लोगोंको प्रोत्साहित करनेकी जरूरत है और इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

## लोक संवाद

### फिर आओ कबीर

महोदय,-यूं तो जीवनके हर पलमें कबीरदासजीके संदेश हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, लेकिन कुछ संदेश गहरे अर्थ लिये हैं। यहु ऐसा संसार है, जैसा सेमर फूल। दिन दसके व्यवहार कौंए झूठे रंग न भूल। अर्थात् दस दिनके जीवनपर मानव नाहक ही मिथ्या अभिमान करता है। वह भूल जाता है कि जीवन तो सेमलके फूलके समान क्षणभंगुर है, जो रूईके समान सब जगह उड़ जाता है। इसलिए काल्ह करै सो आज कर, आज करै सो अब। पलमें परलय होयगी, बहुरि करैगो कब। मानवको सत्कर्म यथाशीघ्र पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि कालका कोई भरोसा नहीं, कब प्रलय आ जाय और वह कुछ अच्छा किये बिना ही कालके गालमें समा जाय। ऐसी ही जीवन और जगतकी यथार्थताका बोध कराते हुए मानव जीवनको सार्थकताकी दिशामें ले गये संत कबीर। उनका जन्म सन् १३९८ ई. के लगभग माना जाता है। कहते हैं कबीर बचपनसे ही हिन्दू भावसे भक्ति करने लगे थे। उन्हें स्वामी रामानंदके शिष्यके साथ ही प्रसिद्ध सूफी संत फकीर शेख तकीका भी शिष्य माना जाता है। देशाटन करनेके कारण उनका हठयोगियों तथा सूफी फकीरोंसे सत्संग हुआ तो उनके राम धनुर्धर साकार राम न होकर ब्रह्मके पर्याय बन गये-दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना। राम नामका मरम है आना। कबीरकी बानी निर्गुण बानी कहलाती है। वे रूढ़ियोंके विरोधी थे। अंधविश्वास, आडम्बर और पाखण्डका उन्होंने जिस निर्भीकतापूर्वक और बेबाक ढंगसे विरोध करनेका साहस दिखाया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने कर्मकाण्डको प्रधानता देनेवाले पंडितों और मुल्लों दोनोंको खरी-खरी सुनायी। आज हमारा जीवन राजनीति और समाजनीतिके दो पहलुओंके बीच कबीर आप ठगाइये और न ठगिये कोय। आप ठगे सुख ऊपजै और ठगे दुख होय। राजनीतिसे परे आज साधु-संन्यासी भी दूर-दूरतक कहीं नजर नहीं आ पाते, ऐसेमें यदि आज कबीर जीवित होते तो निश्चित वे अपनी वाणीसे सामाजिक वैषम्य, असामंजस्य, अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, अनीति और अन्यायके प्रति विरोध प्रकट कर राजनीतिके छल-कपट, वोट-नीति, फूट डालो और राज करोकी नीति, व्यक्तिवादके वर्चस्व, प्रजातंत्रकी आड़ लेकर राजतंत्रके कृत्य, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावादके प्रति जनताको सचेत कर लोकतंत्रमें जान फूंक देते जिससे स्वस्थ राष्ट्रका निर्माण हो उठता। **-कविता, वाया ईमेल।**

# कृषि सुधारोंसे बढ़ती आर्थिकी

**हालमें प्रधान मंत्रीकी अगुआईमें हुई केंद्रीय कैबिनेटकी मीटिंगमें कृषि क्षेत्रसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। इसमें सात बड़ी परियोजनाओंको मंजूरी दी गयी। इनपर कुल १४००० करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमेंसे २८१७ करोड़ रुपये डिजिटल कृषि मिशनको दिये जायेंगे। फसल विज्ञानपर ३९७९ करोड़ रुपये खर्च होंगे।**

**❐ डा. जयंतीलाल भंडारी**

कृषि शिक्षा और प्रबंधनके बेहतर करनेके लिए २२९१ करोड़ रुपयेके प्रोग्रामको मंजूरी दी गयी। पशुधनके स्थायी स्वास्थ्यके लिए १७०२ करोड़ रुपयेके प्लानको मंजूरी दी गयी है। पिछले कुछ समयसे जीडीपीमें कृषिका योगदान घट रहा था। लेकिन मोदी सरकारकी हालिया पहलसे कृषि क्षेत्र और किसानोंको बड़ा फायदा मिलनेकी उम्मीद है। इस परिप्रेक्ष्यमें केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकासमंत्री शिवराज सिंह चौहानने कहा कि ये सात योजनाएं कृषि क्षेत्रके लिए मीलका पत्थर साबित होंगी और कृषि उन्नयनके प्रयासोंसे आर्थिकी तेजीसे आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि ३ सितंबरको विश्व बैंकके द्वारा जारी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्रमें सुधार एवं ग्रामीण मांगमें तेजीके चलते भारतकी विकास दर सात फीसदीके स्तरपर पहुंचते हुए दिखाई देगी। रिपोर्टमें वृद्धि दर अनुमानको बढ़ाया गया है। मानसूनमें सुधार, निजी खपत एवं बढ़ते निर्यातसे भी भारतीय जीडीपीको मजबूती मिल रही है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि सरकारको इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासतमें मिला है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तारसे बढ़ रही है। पूरे देशके कोने-कोनेमें बेहतर मानसूनके लाभ दिखाई देने लगे हैं। बेहतर मानसूनसे ग्रामीण इलाकोंमें खपत तेजीसे बढ़ रही है। बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण भारतके विकासके लिए सरकारी योजनाओंके तहत किये गये भारी व्यय तथा स्वरोजगारकी ग्रामीण योजनाओंसे ग्रामीण परिवारोंकी आमदनीमें तेज इजाफेके साथ उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। ऐसेमें भारतके ग्रामीण क्षेत्रोंमें ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। कृषि संबंधी संसाधनोंकी अधिक बिक्री हो रही है, वरन गांवोंमें उपभोक्ताओंकी खरीददारी भी उच्च स्तरपर है। यह सब ग्रामीण भारतमें भविष्यके प्रति उत्साह और वर्तमानके बेहतर परिणामोंका प्रतीक है। नि:संदेह सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि व्यवस्थाको ट्रांसफॉर्म करना समयकी मांग है। सरकारके द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकासको सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जानेसे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको मजबूती मिल रही है। इसीके मद्देनजर इन दिनों प्रकाशित हो रही वैश्विक आर्थिक संघटनों और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियोंकी रिपोर्टोंमें भारतमें कृषि सेक्टरमें सुधार और ग्रामीण खपतमें वृद्धिके मद्देनजर भारतकी विकास दरके अनुमान बढ़ाये जा रहे हैं। ऐसेमें वैश्विक चुनौतियोंके बावजूद २०२५-२६ एवं २०२६-२७ में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गतिसे बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंकने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें तेजीके मद्देनजर चालू वित्त वर्ष २०२४-२५ के लिए भारतकी जीडीपी वृद्धि दरके अनुमानको बढ़ाकर सात फीसदी कर दिया है। इसी तरह भारतकी विकास दरके अनुमानोंको ओईसीडीने ६.२ से बढ़ाकर ६.६ प्रतिशत, स्टैंडर्ड चार्टर्डने ६.३ से बढ़ाकर सात प्रतिशत तथा फिचने सातसे बढ़ाकर ७.२ प्रतिशत किया है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि देशमें ग्रामीण अर्थव्यवस्थाकी चुनौतियोंके बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको संवारनेका रणनीतिक अभियान आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधानको बढ़ावा देनेके अभियानके तहत ११ अगस्तको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने नयी दिल्लीमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतोंमें जाकर ६१ फसलोंकी १०९ नयी एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देशमें कम जमीनमें अधिक पैदावार लेने और किसानोंकी आय बढ़ानेमें मदद मिल सकेगी। इससे महंगीसे भी बचाव होगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानके मुताबिक वर्ष २०२४-२५ के बजटके तहत किसानोंके कल्याण और कृषिको विकासका इंजन बनानेकी रणनीतिके तहत किसानोंके हितमें कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रकी क्षमताके दोहनके जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाये गये हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें नयी जान फूंकी जा सकेगी। इस बजटके माध्यमसे कृषि सेक्टरके लिए १.५२ लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किये गये हैं। बजटके तहत शीघ्र खराब होनेवाले सामानकी बाजारमें समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करनेके लिए इस बजटमें प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी हैं। बजटके तहत उपभोक्ता मामलोंके विभागको दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए दस हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं, जहां इस कोषका उपयोग दाल, प्याज और आलूके बफर स्टॉकको रखनेके लिए किया जायगा। निश्चित रूपसे सरकारके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको संवारनेकी डगरपर आगे बढ़ते हुए कई अहम बातोंपर ध्यान दिया जाना होगा। सरकारके द्वारा कृषि प्रौद्योगिकीके इस्तेमाल, कृषिमें मशीनीकरणको बढ़ाये जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपना, जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सड़कोंको मंडियोंसे जोड़ने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओंके साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखलामें सुधारसे खाद्य वस्तुओंकी महंगीको नियंत्रित रखनेके कारगर प्रयासोंकी डगरपर लगातार आगे बढ़ना होगा। चूंकि देशमें फसल कटाईके बादकी उपयुक्त व्यवस्था न होनेसे १२ से १४ फीसदीतक खाद्यान्न और करीब ३५ फीसदीतक सब्जी और फलोंकी पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसेमें बजटके तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभागके लिए जिस तरह खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंगके लिए ऋणोंकी राशि दोगुनी सुनिश्चित की गयी है, उसके कारगर उपयोगपर ध्यान देना होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संघटन (एफएओ) के अनुसार कृषि भंडारण क्षमता वर्ष २०२३ में १४.५ करोड़ टन थी। अब उसे वर्ष २०३० तक दोगुना बढ़ानेकी रणनीतिके साथ आगे बढ़ना होगा।

कृषि भंडारण क्षमताके भौगोलिक स्तरपर उचित वितरणकी डगरपर भी सरकारको आगे बढ़ना होगा। जहां उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्योंमें तो अधिक भंडारण क्षमता है, वहीं बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्योंमें इसकी भारी कमी है। सरकारको इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ज्यादातर कोल्ड स्टोरेजमें केवल एक ही फसल रखनेकी व्यवस्था होती है। अन्य फसलोंके भंडारणकी सुविधा इनमें नहीं होती। इसलिए अब देशभरमें भंडारण क्षमताको उन्नत कर इनमें सभी या एकसे अधिक कृषि उपज रखनेकी व्यवस्थाकी ओर भी ध्यान देना होगा। हम उम्मीद करें कि तीन सितंबरको सरकारने कृषि क्षेत्रके लिए मीलका पत्थर साबित होनेवाली जिन सात योजनाओं तथा ६१ फसलोंकी १०९ नयी एवं उन्नत किस्मोंसे किसानोंकी आय बढ़ानेकी जो पहल की है, उसके लाभों और प्रयोगके बारेमें किसानोंको उपयुक्त रूपसे प्रशिक्षित किया जायगा। वर्ष २०२४-२५ के नये बजटसे कृषि और ग्रामीण विकासको रफ्तार देनेके जो रणनीतिक कदम बताये गये हैं, उनके क्रियान्वयनपर शुरुआतसे ही ध्यान दिया जायगा। इन सबके साथ-साथ सरकारके द्वारा बेहतर मानसूनकी शक्तिको मुट्ठीमें लेकर कृषि सुधारोंकी डगरपर तेजीसे आगे बढ़ा जायगा। निश्चित रूपसे ऐसेमें जहां छोटे किसानों एवं ग्रामीण भारतके करोड़ों लोगोंकी खुशियां बढ़ेंगी, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजीसे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगी।



**बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण भारतके विकासके लिए सरकारी योजनाओंके तहत किये गये भारी व्ययसे ग्रामीण परिवारोंकी आमदनीमें तेज इजाफेके साथ उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। ऐसेमें भारतके ग्रामीण क्षेत्रोंमें ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। कृषि संबंधी संसाधनोंकी अधिक बिक्री हो रही है, गांवोंमें उपभोक्ताओंकी खरीददारी भी उच्च स्तरपर है। यह सब ग्रामीण भारतमें भविष्यके प्रति उत्साह और वर्तमानके बेहतर परिणामोंका प्रतीक है। नि:संदेह सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि व्यवस्थाको ट्रांसफार्म करना समयकी मांग है।**

# सामाजिक चेतनाका आधार है हिंदी

**भूमंडलीकरणके कारण लोगोंके सांस्कृतिक, भाषाई और देशज सोचमें बदलाव आये हैं। भारतीय समाजमें इस बदलावका असर कहीं अधिक देखा जा रहा है जिससे लोगोंमें मूल्योंसे अधिक सुख-सुविधाओंके प्रति कहीं ज्यादा मोह बढ़ा है।**

**❐ अखिलेश आर्येन्दु**

भूमंडलीकरणके कारण पैसा जीवनका पर्याय बन गया है। सांस्कृतिक और भाषाई चेतना धीरे-धीरे बदलती या गायब होती दिखाई पड़ रही है। ऐसेमें सांस्कृतिक और भाषाई चेतनाको लेकर संकट महसूस होना लाजिमी है। हिन्दी हमारे देशकी राज भाषाके रूपमें प्रतिष्ठित है। आजादीके पहले भी यह सम्पर्क भाषाके रूपमें प्रयोग की जाती रही है। यही कारण है कि हिन्दीके अनेक शब्द, क्रियापद और संज्ञाएं भारतकी अनेक प्रान्तीय भाषाओंमें उसी अर्थमें या दूसरे अर्थमें मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, हिन्दीकी सहजता, वैज्ञानिकता और रागात्मकता भी भारतकी प्रान्तीय भाषाओंमें मिल जाती है। यह सब सहज रूपसे हुआ है। हिन्दीके लिए जितना हिन्दी भाषा-भाषियोंके लिए महत्व है उससे कहीं अधिक गैर-हिन्दी भाषीके लिए महत्व है। वह हिन्दीको उसके शुद्धात्मक रूपमें अपनानेका कहीं अधिक प्रयास करता है। हिन्दीकी अपनी अलग बनावट और पहचान है। यह किसी प्रान्तकी भाषा रही है और न तो किसी जाति, वर्ग या क्षेत्र विशेषकी भाषा रही है। हिन्दी बहती नदीकी धाराकी तरह सबके लिए उपयोगी और कल्याणकारी रही है। यही कारण है गैर-हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रोंके हिन्दी उन्नायकोंने हिन्दीको जनभाषाके रूपमें स्वीकार करते हुए इसके उत्थानके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वह चाहे गुजराती भाषा-भाषी महर्षि दयानन्द और गांधी रहे हों, बंगालके राजाराम मोहन राय, केशवचन्द सेन और रवींद्र नाथ टैगोर तथा नेता सुभाष रहे हों या महाराष्ट्रके नामदेव, गोखले और रानाडे रहे हों। इसी तरह तमिलनाडुके सुब्रह्मण्यम भारती, पंजाबके लाला लाजपत राय, आंध्र प्रदेशके प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी जैसे अनेक अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रोंमें हिन्दीको बढ़ावा देनेके लिए अनेक महत्वपूर्ण किये। इस सचाईको हम कैसे झुठला सकते हैं कि आज भी तमिल, कर्नाटक, आंध्र, केरल, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे अनेक राज्योंमें हिन्दी समझनेवाले, बोलनेवाले ही नहीं हिन्दीमें लेखन करनेवाले सैकड़ों लेखक-पत्रकार मिल जाते हैं, जो हिन्दीको समृद्ध बनानेके लिए पूरे मनोवेगसे कार्य कर रहे हैं। इससे हिन्दीका अन्य भारतीय भाषाओंके अंतर्सम्बन्धोंमें मजबूती आ रही है, लेकिन यह आवश्यकता से बहुत कम है।

हिन्दीकी प्रगतिमें सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी रही है। अंग्रेजोंने स्वतंत्रताके पूर्व ही इसका जाल तैयार कर दिया था और भाषा जो हमारे जीवन, समाज और संस्कृतिका अभिन्न अंग है, को राजनीतिक रंग दे दिया गया। स्वतंत्रताके ७७ वर्षोंके बाद आज जब हम हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओंके संबंधोंका अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि यह संबंध सुदृढ़ होनेकी जगह निरन्तर कमजोर हुए हैं। हिन्दीवालोंको तमिल, तेलगू, कन्नड़, पंजाबी और उड़िया शब्द-संस्कृतिमें तैरनेकी जगह अंग्रेजीके जाल-जंजालमें अधिक भाता रहा है। इस विडम्बना और संकटको वर्षों पूर्व हिन्दीके महान् उन्नायक फादर डा. कामिल बुल्केने समझ लिया था। डा. बुल्के कहते हैं, भारत पहुंचकर मुझे यह देखकर दु:ख हुआ कि बहुतसे शिक्षित लोग अपनी ही संस्कृतिसे नितान्त अनभिज्ञ हैं और अंग्रेजी बोलना तथा विदेशी सभ्यतामें रंग जाना गौरवकी बात समझते हैं। भाषाविदोंके अनुसार हिन्दीका स्वभाव और भारतीय भाषाओंका स्वभाव एक जैसा है। किसी भी स्तरपर टकराव नहीं है। फिर क्यों हिन्दीका विरोध गैर-हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रोंमें यत्र-तत्र देखा जाता है। यह न अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल आजादीके पहले अंग्रेजोंने भारतीय भाषाओंका वर्गीकरण कराया था, उसके पीछे न कोई भाषाई तथ्य, व्याकरण और लिपिका आधार था और न ही सांस्कृतिक या धार्मिक ही। भारतीय भाषाओंका वर्गीकरण इस तरहसे किया गया कि जिससे यह साबित हो सके कि आर्य भाषा परिवारकी भाषाओं और द्रविड़ भाषा परिवारकी भाषाओंमें न पूरकता है और न ही कोई अंतर्सम्बंध ही है। जिससे उन्हें भाषाके नामपर भी देशको विभाजित कर राज्य करनेमें सुविधा हो सके। गौरतलब है आर्य भाषा परिवारका नामकरण मैक्समूलरके द्वारा किया गया और द्रविड़ भाषा परिवारका नामकरण पादरी राबर्ट काल्डवेलके द्वारा किया गया। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओंमें साम्यता एक स्तरपर नहीं है। सैकड़ोंकी संख्यामें ऐसे शब्द हैं जो हिन्दीमें भी इस्तेमाल किये जाते हैं और अन्य भारतीय भाषाओंमें भी। उदाहरणके लिए तेलगुमें प्रयुक्त दर्जी शब्द हिन्दीमें भी प्रयोग होता है और अन्य दूसरी भाषाओंमें भी। इसी तरह कागज, ताला, जकीर, ताजा, अम्मा आदि जैसे अनेक शब्दोंका प्रयोग हिन्दी सहित भारतकी अधिकांश भाषाओंमें प्रयोग होते हैं। इसी तरह पंजाबी भाषा जो गुरुमुखीमें लिखी जाती है, के हजारों शब्द हिन्दीमें प्रयोगमें दिखाई देते हैं। वस्तुत: ये शब्द संस्कृतसे हिन्दी और पंजाबीमें प्रयोगमें आये। आज दोनों भाषाओंमें संस्कृतके इन शब्दोंका प्रयोग धड़ल्लेके साथ किया जाता है। यदि लिपिको छोड़ दिया जाय तो कोई भी हिन्दी भाषा-भाषी व्यक्ति जो कुछ पढ़ा-लिखा हो उसे पंजाबी समझमें आ जाती है। इसी तरह पंजाबीको हिन्दी समझते देर नहीं लगती। दोनों एक ही भाषा परिवारकी मानी जाती हैं। दोनोंको प्रयोग सदियोंसे आपसी भाईचारेको बढ़ावा देनेके लिए किया जाता रहा है। पंजाबमें मध्यकालमें ब्रज भाषा और गुरुमुखी लिपिमें, इसके सुमेलसे ही हिन्दी साहित्यका सृजन हुआ। गुरु गोविन्द सिंह और इनके दरबारी कवि, पंजाबके दूसरे राज्याश्रित कवि गुरुमुखी लिपिमें ब्रज भाषाकी रचना करते थे। यह नितार हिन्दी और पंजाबी संस्कृतियोंको भी रेखांकित करती है। पंजाबी और हिन्दी भाषाके अंतर्सम्बंध भक्तिकाल, गुरुवाणी और आधुनिक युगके साहित्यमें भी सहज सुलभ है। प्रो. पूर्णसिह, अमृता प्रीतम, देवेन्द्र सत्यार्थी और अजीत कौर जैसे न जाने कितने रचनाकार जो पंजाबी पृष्ठभूमिके होते हुए भी हिन्दीमें सबको स्वीकार हुए। अब जबकि हिन्दीका संकट अन्य कई तरहसे हमारे सामने द्रष्टव्य होने लगा है, भारतीय भाषाओंका आपसी भाईचाराका मुद्दा गौढ़ होता जा रहा है। ऐसेमें डा. रामविलास शर्माका यह कथन कितना प्रासंगिक हो जाता है हिन्दी अंग्रेजीका स्थान ले, इसकी बजाय यह वातावरण बनाना चाहिए कि सभी भारतीय भाषाएं अंग्रेजीका स्थान लें। हिंदी पखवाड़ेपर हर साल हम महज औपचारिकता निभानेतक सीमित रहते हैं। हिन्दीकी चुनौतियों, समस्याओं और आनेवाले संकटोंको लेकर कभी शिद्दतसे उसपर चिंतन ही नहीं करते। हिन्दीमें हो रही मिलावट, यूरोपीय लिपिमें लिखनेका चलन, अशुद्ध उच्चारण और मातृभाषाके स्थानपर विदेशी भाषाको बहुत ज्यादा तवज्जो देनेकी मानसिकता जैसी तमाम चुनौतियों हिन्दीके उज्ज्वल भविष्यके लिए खतरनाक है। भाषाके साथ उसकी अपनी संस्कृति भी होती है। इसलिए अंग्रजीके साथ हम भारतीय जाने-अनजानेमें ईसाइयत या अंग्रेजियतके गुलाम होते जा रहे हैं, यह महज हिन्दीका पराभव नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतनाके विरासतके पराभवका भी द्योतक है। हम हिन्दीको वाकईमें प्यार करते हैं तो हिन्दीकी मौलिकता और मर्यादाको बचानेके लिए कटिबद्ध हों।

## आत्मबोध

### सच्ची श्रद्धा

**❐ सदानन्द शास्त्री**

श्राद्ध पूर्वजोंके प्रति सच्ची श्रद्धाका प्रतीक है। पितरोंके निमित्त विधिपूर्वक जो कर्म श्रद्धासे किया जाता है, उसीको श्राद्ध कहते हैं। ब्रह्म पुराणके अनुसार श्राद्धकी परिभाषा है, जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थानके अनुसार उचित (शास्त्रानुमोदित) विधि द्वारा पितरोंको लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको दिया जाता है, श्राद्ध कहलाता है। प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारंभमें माता-पिता, पूर्वजोंको नमस्कार या प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वजोंकी वंश परम्पराके कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवनका आनन्द प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्ममें, ऋषियोंने वर्षमें एक पक्षको पितृपक्षका नाम दिया, जिस पक्षमें हम अपने पितरेश्वरोंका श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। यदि किसी कारणसे उनकी आत्माको मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांतिके लिए विशिष्ट कर्म करते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं। व्यक्तिके आगेके तीन मृत पूर्वज, मानव जातिके प्रारंभ या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक लोकके अधिवासीके रूपमें कल्पित हैं। आवाहन, पूजन, नमस्कारके उपरांत तर्पण किया जाता है। जलमें दूध, जौ, चावल, चंदन डाल कर तर्पण कार्यमें प्रयुक्त करते हैं। तृप्तिके लिए तर्पण किया जाता है। स्वर्गस्थ आत्माओंकी तृप्ति किसी पदार्थसे, खाने-पहनने आदिकी वस्तुसे नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीरके लिए ही भौतिक उपकरणोंकी आवश्यकता पड़ती है। मरनेके बाद केवल सूक्ष्म शरीर ही रह जाता है। सूक्ष्म शरीरको भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदिकी आवश्यकता नहीं रहती, उसकी तृप्तिका विषय कोई खाद्य पदार्थ या हाड़-मांस वाले शरीरके लिए उपयुक्त उपकरण नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीरमें विचारणा, चेतना और भावनाकी प्रधानता रहती है, इसलिए उसमें उत्कृष्ट भावनाओंसे बना अंत:करण या वातावरण ही शांतिदायक होता है। श्राद्ध-कर्ममें पके हुए चावल, दूध और तिलको मिश्रित करके पिंड बनाते हैं, उसे सपिंडीकरण कहते हैं। पिंडका अर्थ है शरीर। यह एक पारम्परिक विश्वास है, जिसे विज्ञान भी मानता है कि हर पीढ़ीके भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनोंमें पहलेकी पीढ़ियोंके समन्वित गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। चावलके पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामहके शरीरोंका प्रतीक हैं, आपसमें मिलकर फिर अलग बांटते हैं। यह प्रतीकात्मक अनुष्ठान जिन-जिन लोगोंके गुणसूत्र (जीन्स) श्राद्ध करनेवालेकी अपनी देहमें हैं, उनकी तृप्तिके लिए होता है। दैनिक पंच यज्ञोंमें पितृ यज्ञको खास बताया गया है। इसमें तर्पण और पिंडदान भी सम्मिलित है।

# क्षमा आत्मा का स्वभाव है

**❐ विजय कुमार जैन**

अनादिकाल से जैन आगमानुसार दशलक्षण धर्म का समापन क्षमावणी पर्व के द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्यरूप से आपस में एक-दूसरे से वर्ष भर में हुई भूलों के लिए परस्पर हाथ जोड़कर मन-वचन-काय से क्षमायाचना की जाती है। एकमात्र हम जैन आगम में ही यह देखते है कि एक दूसरे से व्यक्ति आपस में हुई कलुषता के लिए क्षमावाणी पर्व मनाता है। दशलक्षण धर्म का प्रारंभ क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा पर ही समापन होता है। जैनाचार्यों के अनुसार कषाय मनुष्य को अनेक भवों तक नरक और तिर्यच गति में भ्रमण करवाता है। यदि आपस में वैर-भाव हो जाये, तो उसे 6 माह के अंदर ही हाथ जोड़कर समाप्त कर लीजिए। अन्यथा कोडाकोडी सागर वर्ष तक वह कषाय साथ-साथ चलती है। भगवान पार्श्वनाथ और कमठ का जीव दश भव तक चलता हुआ वैर इस बात का उदाहरण है। बंधुओं वैर से वैर कभी भी समाप्त नहीं होता है, जिस प्रकार से अग्नि से अग्नि नहीं समाप्त होती है। कोधरूपी अग्नि को बुझाने के लिए क्षमारूपी जल अवश्य डालना पडता है। इसी प्रकार से हम इस दुर्लभ मनुष्य भव में किसी भी प्रकार से पैर को स्थान न देकर हमेशा क्षमा को अपनाए। भारतवर्ष महात्मा और संतों का देश रहा है। हमारे राष्टपिता महात्मा गांधी ने भी अपने स्वयं के प्राणघात करने वाले को भी क्षमा प्रदान की। यह साक्षात् क्षमा का एक उदाहरण है। हम देखते है कि बच्चा कितनी भी गलती करे लेकिन अंत में मां उसे क्षमा कर देती है। यह सबसे उत्तम उदाहरण है।

**खम्मामि सव्वजीवाणं, सव्वे जीवा खमंतु मे।**
**मित्ती मे सव्वभूदेसु, वैर मज्झं ण केणवि।।3।।**

अर्थात् सब जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं। सब जीव मुझे क्षमा करें। यह हमारे जैन साधु प्रतिदिन दिन में 3 बार सामायिक करते है। उस सामायिक पाठ में यह बोलते है। जैन श्रावक प्रतिदिन मंदिर में जाकर आलोचना पाठ के माध्यम से अपने द्वारा दिनभर में की गई भूलों के लिए जिनेन्द्र प्रभु के आगे क्षमा याचना करता है। जैन शास्त्रों में कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पाण्डव मुनियों के ऊपर अग्नि जला दी, लेकिन उन्होंने उसको समता परिणामों से स्वीकार किया, न कि कोध करके अपने कोध को प्रगट किया। इसी प्रकार से अनेक मुनियों और संतों के ऊपर उपसर्ग आते हैं, लेकिन वह उस उपसर्ग को सहन करते हुए सभी को क्षमा कर देते हैं। क्षमा वीरस्य भूषण के बारे में आचार्यों ने ग्रथों में कहा कि क्षमा वीरों का आभूषण है। इसे कायर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है। क्योंकि क्षमा भी वीर पुरुष के पास होती है। कायर व्यक्ति क्षमा जैसे आभूषण को न ग्रहण कर सकता है न दे सकता है। क्षमा आत्मा का गुण है। यह आत्मा का स्वभाव होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि कोध आ जाये, तो वह कितनी भी देर कोध करे, लेकिन अंततोगत्वा उसे अपने स्वभाव में आना पड़ता है और इसी की अपेक्षा यदि हम देखें कि कोई व्यक्ति हसता है, कितना हंस सकता है। एक समय आता है कि उसे रुककर अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ता है। क्योंकि शात गुण क्षमा का है और क्षमा आत्मा का गुण है। इसलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्षमावाणी पर्व मनाकर सम्पन्न किया जाता है। जैन साध्वी आर्यिका श्री चंदनामती माताजी द्वारा रचित भजन के माध्यम से कहती हैं-



**क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में कर लो।**
**शत्रु-मित्र सबमें समता का, भाव हृदय भर लो।। क्षमा गुण को मन में धर लो।। टेक. ।। मैत्री का हो भाव सभी, प्राणी के प्रति मेरा।**
**गुणी जनों को देख हृदय, आल्हादित हो मेरा ।। वही आल्हाद प्रगट कर लो, कोध वैर भावों को तजकर, मन पावन कर लो। क्षमा गुण को मन में घर लो।।**
**सारंगी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया नंदिनी व्याघ्र पोतं । मार्जारी हंसबालं प्रणयपरवशा केकिकांता भुजगीम् ।। वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जंतवोन्ये त्यजति । श्रित्वा साम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम्।।**

हरिणी सिंह के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से स्पर्श करती है, गाय व्याघ्र के बच्चे को दूध पिलाती है, बिल्ली हसों के बच्चों को प्रीति से लालन करती है एवं मयूरी सर्पों को प्यार करने लगती है। इस प्रकार से जन्मजात भी वैर को दूर जंतुगण छोड देते हैं। कब ? जबकि वे पापों को शांत करने वाले मोहरहित और समताभाव में परिणत ऐसे योगियों का आश्रय पा लेते हैं अर्थात् ऐसे महामुनियों के प्रभाव से हिसक पशु अपनी द्वेष भावना छोड़कर आपस में प्रीति करने लगते हैं। ऐसी शात भावना का अभ्यास इस क्षमा के अवलंबन से ही होता है। वर्तमान में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी हमारे बीच में विद्यमान है, जो कि दिगम्बर जैन समाज में वर्तमान समय में लगभग 1500 साधु-साध्विया विराजमान हैं, उन सबमें सबसे प्राचीन दीक्षित है। 66 वर्ष संयम की साध् ाना के व्यतीत हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि क्षमा धर्म को धारण करके हम भव से पार होकर मुक्ति को प्राप्त हो सकते है। क्षमा धारण करने वाला व्यक्ति इस भव में भी और पर भव में भी सुख को प्राप्त करता है। कोधी व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति बैठना नहीं चाहता है, उस व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता है। उससे कोई संबंध नहीं करना चाहता है और परस्पर व्यवहार में भी आपस में उसकी निंदा करते हैं। जो व्यक्ति सौम्य स्वभावी होता है, सभी उससे जुड़ना चाहते हैं एवं उसे ही अपने पास बैठना चाहते हैं। कोधी व्यक्ति को जब कोध आता है, तब आंखे लाल हो जाती है, होंठ कपकपाने लग जाते हैं एवं वह बोलना कुछ चाहता है, शब्द मुख से कुछ और निकलता है। एक वैज्ञानिक ने कोध व्यक्ति का खून इंजेक्शन में लेकर एक चूहे के लगा दिया, तो वह चूहा कुछ समय बाद तड़पकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए कोध हर प्रकार से बुरा होता है। आज वर्तमान में सामाजिक जो भी समस्याएं है, एक देश का दूसरे देश से वैर विरोध है, वह सभी हल अहिंसा और क्षमा के द्वारा ढूंढे जा सकते हैं। यह क्षमावाणी पर्व हमे यही सदेश देता है।

# रक्षक बने भक्षक : भ्रष्टाचार ने कमजोर की नशे से लड़ाई

निश्चित रूप से नशीली दवाओं के खतरों के खिलाफ पंजाब पुलिस एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। पंजाब पुलिस को उस समय शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब एक ड्रग इंस्पेक्टर को कथित तौर पर मादक पदार्थों के तस्करों से मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हकीकत में नशे के खिलाफ जारी मुहिम ऐसी विभागीय काली भेड़ों की वजह से कमजोर ही होती है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अवैध ड्रग धंधे के संचालन में मदद करने के लिये इस ड्रग इंस्पेक्टर की गहरी भूमिका का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, नशे के काले कारोबार से हासिल सात करोड़ से अधिक की राशि का पता आरोपी के बैंक खातों से चला है। कैसी विडंबना है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति नशे पर नियंत्रण में मदद करने के लिये हुई है, वही जिम्मेदार व्यक्ति विश्वासघात करके पहले से कमजोर नशीले पदार्थ नियंत्रक तंत्र को कमजोर करने का काम करता रहा है। वैसे विगत में भी ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं कि पुलिस महकमे के लोग नशा तस्करों की राह आसान करते रहे हैं। यही वजह है कि वर्ष 2017 में अदालत में दायर एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कथित रूप से नशीली दवाओं के तस्करों से मिलीभगत के आरोपों की जांच के लिये एक विशेष जांच दल का गठन किया था। पिछले साल अप्रैल में सार्वजनिक किए गए एसआईटी के निष्कर्षों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उल्लेखनीय है कि इस जांच में खुलासा हुआ था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मोगा में तैनात एक एसएसपी के साथ मिलकर बीएसएफ कर्मियों की मदद से पाक से ड्रग्स की तस्करी की थी। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि पुलिस इंस्पेक्टर ने लोगों पर नशीले पदार्थ बेचने के झूठे आरोप लगा पैसे की उगाही भी की थी। विडंबना देखिए कि इन तमाम आरोपों के बावजूद उसकी दोहरी विभागीय प्रोन्नति की गई थी। निश्चय ही रक्षक जब भक्षक बनने लगें तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिससे समाज की रक्षा के लिये बनी संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठने लगता है। दरअसल, नौकरशाही की अक्षमता और व्यवस्थागत खामियां ऐसे विभागीय अपराधियों के निरंकुश खेल को आसान बना देती हैं। लंबे समय से ड्रग्स इंस्पेक्टर का स्वच्छंद रूप से काले धंधे में लिप्त रहना और जांच देर से होना एक मजबूत निवारक तंत्र की जरूरत को बताता है। इक्का-दुक्का लोगों की गिरफ्तारी के इतर बड़े संरचनात्मक सुधारों की जरूरत होगी। इसमें संदिग्ध अधिकारियों की समय रहते जांच, विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन, जेल की निगरानी में सतर्कता-सजगता और स्वतंत्र एजेंसियों के साथ समन्वय भी शामिल है। आंतरिक भ्रष्टाचार और जमीनी स्तर पर नशीली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिये व्हिसलब्लोअरों को संरक्षण देने व समुदाय स्तरीय पुलिसिंग को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निश्चित2 रूप से व्यवस्थागत बदलावों के बिना नशीली दवाओं के खिलाफ राज्य की लड़ाई मुश्किल होगी और इस दिशा में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाएगी।

# कौन करवाता है योजनाबद्ध धर्मांतरण

आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी धर्म को मानने या ना मानने या फिर किसी भी धर्म से जुड़ने का अधिकार संविधान देता है, पर किसी प्रलोभन या गलतफहमी में योजनाबद्ध रूप से किसी तरह के धर्मांतरण को अपराध माना गया है ।

इस आलोक में उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत द्वारा हाल ही में अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी करार दिये गये 12 लोगों को उम्रकैद और चार अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाना महत्वपूर्ण है। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, धर्मांतरण करवाने के धंधे से जुड़े शातिर लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए (राष्ट्रद्रोह) के तहत सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह के मुताबिक, उमर गौतम और मामले के अन्य अभियुक्त एक साजिश के तहत धार्मिक उन्माद, वैमनस्य और नफरत फैलाकर देशभर में अवैध धर्मांतरण का गिरोह चला रहे थे। उनके तार कई दूसरे देशों से भी जुड़े थे। इसके लिए आरोपी हवाला के जरिए विदेशों से धन भेजे जाने के मामले में भी लिप्त थे। वे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और दिव्यांगों को लालच देकर और उन पर अनुचित दबाव बनाकर बड़े पैमाने पर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे।

उमर गौतम को मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के साथ 20 जून 2021 को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया था। वह एक ऐसे अवैध संगठन का संचालन कर रहा था जो उत्तर प्रदेश में मूक- बधिर छात्रों और गरीब लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कराने में शामिल था । इस बात की पुरजोर आशंका जताई जा रही है कि इसके लिए उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से धन मिलता था। उमर गौतम पहले हिंदू था । लेकिन , उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और धर्मांतरण कराने के अवैध धंधे में सक्रिय हो गया। उसने करीब एक हजार गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया और उनकी मुस्लिमों से दूसरी या तीसरी शादी कराई है।

देखिए, भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर बहस तो होती रही है , होनी भी चाहिये। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें स्वेक्षा या स्वविवेक से धर्म बदलने का अधिकार भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म बदलने के अधिकार की बात तो कही गई है। पर उमर गौतम और उनके साथी तो गरीब-गुरुबा लोगों को लालच और जोर-जबरदस्ती से धर्मांतरण करवा रहे थे। गौतम और उनका गिरोह भूल गया था कि धर्म परिवर्तन सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है और समाज में भयंकर नफरत पैदा कर सकता है। भारत में धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा है , जिसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक सभी पहलू शामिल हैं।

कुछ साल पहले केरल के प्रतिष्ठित फिल्म निमार्ता निर्देशक अली अकबर और उनकी ईसाई पत्नी लूसीअम्मा ने आर्य समाज में हवन के जरिए हिन्दू धर्म अंगीकार कर लिया था। आर्य समाज के स्वामी जी द्वारा उनका नया नामकरण भी कर दिया गया है। अली अकबर को नया नाम मिला था राम सिम्हन। हिन्दू धर्म ही क्यों ? यह प्रश्न पूछे जाने पर अली अकबर ने कहा था, 'क्योंकि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति है। यहां नर्क में जाने का डर नहीं है। आप एक इंसान की तरह जी सकते हैं क्योंकि भगवान आपके अंदर हैं। अपने भीतर ईश्वर को देखना एक महान विचार है।' कहते हैं कि राम सिम्हन केरल में हिंदू धर्म अपनाने वाले पहले मुसलमान थे।लेकिन , यह राम सिम्हन के स्वविवेक पूर्ण निर्णय को दशार्ता है । इसपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये!

एक बात बहुत साफ है कि किसी को लालच देकर या जोर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना तो कतई सही नहीं माना जा सकता है। समझ नहीं आता कि कुछ धर्मों से जुड़े लोग क्यों इसी फिराक में रहते हैं कि उनके धर्म से अन्य धर्मों को मानने वाले जुड़े जाएं। गुस्ताखी माफ, कई इस्लामिक और ईसाई संगठन इसी कोशिश में रहते हैं कि दूसरे धर्म को मानने वाले उनके मजहब का हिस्सा बन जाएं ? यह कोई बात हुई क्या ? फिर यदि बाकी धर्मों को मानने वाले लोग भी यही करने लगें , तो समाज में भाईचारा कहाँ और कैसे बचा रहेगा ।अगर कोई अपने मन से उस धर्म को त्याग देता है ,, जिसमें उसका जन्म हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। उदाहरण के रूप में म्युजिक डायरेक्टर रहमान को ही लेते हैं। उन्होंने खुद ही हिन्दू धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर लिया। उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी इस्लाम अपना लिया। यहां तक तो सब ठीक है। पर कुछ तत्व सुदूर इलाकों में रहने वालों को अपना पाले में लाने की जुगाड़ में रहते हैं। इस सबकी तो हमारा संविधान अनुमति नहीं देता। जब गौतम जैसों पर एक्शन होता है तो कुछ कथित बुद्धिजीवी आलाप करने लगते हैं। पिछले कई सालों से पंजाब से खबरें आ रही हैं कि राज्य में दलित सिखों को लालच देकर ईसाई धर्म से जोड़ा जा रहा है।

मेरे संज्ञान में एक एक सच्ची घटना है जो मैं शेयर कर रहा हूँ।। लगभग दस वर्ष पहले मुझे अपने एक स्कूल के खेल शिक्षक के बारे में पता चला कि उसने त्यागपत्र दे दिया है और अगले महीने से हमें एक खेल शिक्षक नियुक्त करना होगा । मैंने उसे बुलाया और पूछा कि तुम्हारी तकलीफ क्या है ? उसने बताया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है । पर आप जितना वेतन मुझे दे रहे हैं, उससे दस या बीस गुना कमाने का जरिया मुझे मिल गया है । मुझे घर मरम्मत के लिये पैसों की सख्त जरूरत थी । मुझे पता चला कि मेरे इलाके में एक नया चर्च बना है उसके पादरी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मैं उनके पास गया । उन्होंने कहा कि मदद करूँगा । लेकिन , तुम्हें हर रविवार चर्च आकर प्रार्थना करनी होगी।मुझे तरीका आसान सा लगा । उन्होंने मुझे सपरिवार( पति - पत्नी , मेरी विधवा माँ और दो बच्चों को ) ईसाई बनने के लिये बीस हजार प्रति व्यक्ति की दर से एक लाख रुपये दिये ।बाद में पता चला कि मेरे जिस पड़ोसी ने मुझे ईसाई बनने का लालच दिया और पादरी से मिलवाने ले गया उसे भी इतना ही पैसा मिला । तो मुझे लगा कि इस तरह धर्म प्रचार करके तो ज्यादा कमाया जा सकता है तो मैंने इस्तीफा दे दिया ।वह आज भी धड़ल्ले से गाँव - गाँव जाकर देवभूमि उत्तराखंड को ईसाई भूमि बनाने में लगा है । पहले हाफ पैंट और टीशर्ट पहनकर साइकिल से घूमता था । अब सलीके के सूट पहनकर चमचमाती कार में घूमता है । ऐसे एक नहीं अनेक धर्म भ्रष्ट लालची लोग आपको हर इलाके में मिल जाएंगे ।

यह सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या भारत में धर्म प्रचार की अनुमति जारी रहनी चाहिए? कभी कभी लगता है इस मसले पर देश में बहस हो ही जाए कि क्या भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता जारी रहे अथवा नहीं ? देखा जाए तो केवल धर्म पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिये। धर्म के प्रचार- प्रसार की छूट की कोई आवश्यकता ही नहीं। धर्म कोई दुकान या व्यापार तो है नहीं जिसका प्रचार प्रसार करना जरूरी हो।

अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगाले तो देखते हैं कि भारत के संविधान निमार्ताओं ने सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के प्रचार की छूट दी थी। क्या इसकी कोई आवश्यकता थी? बेशक, भारत में ईसाई धर्म की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस और ईमानदारी से काम किया गया है। पर कहने वाले कहते हैं कि उस सेवा की आड़ में धर्मांतरण का ही मुख्य लक्ष्य रहा है। उधर, इस्लाम का प्रचार करने वाले बिना कुछ किए ही धर्मांतरण करवाने के मौके खोजते हैं। हालांकि मुसलमानों की शिक्षण संस्था अंजुमन इस्लाम ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। ये मुंबई में सक्रिय है। अब आप देखें कि आर्य समाज, सनातन धर्म और सिखों की तरफ से देश में सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह चल रहे हैं। पर इन्होंने किसी ईसाई या मुसलमान का धर्मांतरण का कभी प्रयास नहीं किया। आपको अपने धर्म को मानने की तो अनुमति होनी चाहिए, पर अपने धर्म का प्रचार करने या धर्मांतरण करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती।

# दिल्ली सरकार से जुड़े किंतु-परंतु



महेश खरे

कथित अरविंद केजरीवाल के ऐलान में यदि बदलाव नहीं होता है तो वे आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही दिल्ली को अधिकतम छह महीने के लिए नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जमानत पर तिहाड़ से बाहर आने के दूसरे दिन केजरीवाल ने दिल्ली समेत देश को चौंकाते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने का सियासी दांव खेला। इसके पहले केजरीवाल 177 दिन जेल से सरकार चलाने का उपक्रम करते रहे। उनका अचानक इस्तीफा देकर अपनी ईमानदारी पर जनता की अदालत में जाने का फैसला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वे कहते हैं- दिल्ली की जनता वोट देकर तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल का इमोशनल कार्ड कितना कारगर होता है। लोकसभा चुनाव में तो जेल यात्रा का लाभ वोटर ने उन्हें नहीं दिया।

## विधानसभा भंग नहीं करेंगे

यह तो तय कर लिया गया है कि केजरीवाल की कैबिनेट विधानसभा भंग की सिफारिश नहीं करेगी। विधानसभा सभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह स्पष्ट कर दिया है। सीएम से मुलाकात के बाद गोयल ने सवाल किया कि सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश क्यों करे? आतिशी का कहना था कि जब तक आप सरकार का कार्यकाल शेष है वो दिल्ली की जनता की सेवा करती रहेगी। केन्द्र सरकार जब चाहे दिल्ली में चुनाव करा सकती है। इस पर भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने सवाल किया कि क्या केजरीवाल सच में इस्तीफा देंगे? इसकी क्या गारंटी है कि वो एन समय पर यू-टर्न नहीं मारेंगे? यू-टर्न लेने का उनका पुराना इतिहास रहा है।



## कौन होगा नया सीएम

आज का सबसे संजीदा सवाल यही है कि आखिर 17 सितंबर को दिल्ली का नया सीएम कौन होगा? चार -पांच नाम तो हवा में तैर ही रहे हैं। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और गोपाल राय। आतिशी और सौरभ के नाम भी सीएम की गुड बुक के पहले पन्ने पर दर्ज हैं। आतिशी के पास तो सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण विभाग भी हैं। संगठन भी उन्हीं के हवाले है। लेकिन दोनों का नाम शराब घोटाले में आ चुका है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गेहलोत भी केजरीवाल के भरोसेमंद और वरिष्ठ नेता हैं। यदि वे सीएम बनते हैं तो जाट होने के नाते हरियाणा चुनाव में भी उनका फायदा उठाया जा सकता है। एक चेहरा जो पर्दे के पीछे से सामने आता नजर आ रहा है वह और कोई नहीं विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल हैं। अत्यंत वरिष्ठ और सबसे बड़ी बात केजरीवाल के कट्टर भरोसेमंद। याद कीजिए 21 मार्च को जब केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी उनके 'शीश महल' में पहुंचे थे तब गोयल प्रोटोकॉल तोड़कर वहां हंगामी मुद्रा में उपस्थित थे। इनके नेतृत्व में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी समेत किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता को काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

## कोई नृप होय हमें का...

कोउ नृप होय हमें का हानि...की तर्ज पर विधायक दल की बैठक में सीएम कोई भी चुन लिया जाए। दो बातें ही होनी हैं। एक)- जो भी सीएम बनेगा वो केजरीवाल की पसंद का होगा। दो)- सीएम कोई भी बने सत्ता के सूत्र केजरीवाल के हाथों में ही रहेंगे। इसके बावजूद दिल्ली सरकार के नए मुख्यमंत्री को लेकर अनेक किंतु परंतु जुड़े हुए हैं। जिनके समाधान के लिए ही संभवतः केजरीवाल ने दो दिन बाद पद त्यागने की सार्वजनिक घोषणा रविवार को की है।

## सुनीता की महत्वाकांक्षाएं

केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी दिल्ली की जनता को साफ साफ दिख रही हैं। भले ही सुनीता विधायक नहीं हैं, केजरीवाल उनको आसानी से मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। पार्टी में उनकी पूरी पकड़ है। कोई चूं भी नहीं करेगा। ऐन मौके पर पत्ते बदलने में भी केजरीवाल को समय नहीं लगेगा। इसमें केजरीवाल का फायदा भी है। उन्हें सरकारी आवास खाली नहीं करना पड़ेगा। लगभग छह महीने तक जब केजरीवाल जेल में थे तो सुनीता ही आतिशी के सहयोग से 'छाया मुख्यमंत्री' के रूप में पार्टी का नेतृत्व करती भी रही हैं। लेकिन इससे चुनाव के समय आप पर परिवारवाद का आरोप लगेगा। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा।

## भाजपा के तीखे सवाल

भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के अभियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा किया है। इसके तहत वे सीएम कार्यालय नहीं जा सकते हैं। किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे इस्तीफा नहीं देते तो क्या करते? अगर केजरीवाल इतने ही कट्टर ईमानदार हैं और उन्हें कुर्सी का मोह नहीं है तो जेल जाने के समय ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भाजपा इस संदर्भ में लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण भी दे रही है। हवाला में जब आडवाणी का नाम आया तो तुरंत उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था।

## क्या गेंद केंद्र के पाले में

आम आदमी पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के साथ नवंबर में चुनाव कराने की मांग करते हुए इस्तीफा देने का ऐलान कर गेंद भाजपा के पाले में फेंक दी है। पिछले दिनों दिल्ली के भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देकर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। वह पत्र गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। अब केजरीवाल जब स्वयं जल्दी चुनाव की मांग के साथ इस्तीफा दे रहे हैं। तब चुनाव का फैसला मोदी सरकार को ही करना है। नए मुख्यमंत्री के सियासी कदमों को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हो सकता है नया मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक कर विधान सभा भंग की सिफारिश का पत्र उपराज्यपाल (एलजी) को सौंप दे। वैसी स्थिति में यदि चुनाव कराए गए तो कामचलाऊ मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का ही बना रहेगा। प्रचंड बहुमत वाली सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजना ही होगा।

## हरियाणा के नतीजों का इंतजार

संभवतः दिल्ली के चुनाव पर निर्णय हरियाणा और जम्मू- कश्मीर के नतीजों के बाद ही लिए जाने की संभावना है। 20 दिन में यह भी साफ हो जाएगा कि केजरीवाल की 'कुबार्नी' का सहानुभूति वोट आप की झोली में कितना आता है। 2019 में आप के 48 प्रत्याशी थे और 0.48 पर्सेंट वोट शेयर के साथ सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

## कांग्रेस का टेंशन बढ़ा

केजरीवाल के नए दांव से कांग्रेस का टेंशन बढ़ा गया है। दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस और आप हरियाणा में अलग- अलग मैदान में हैं। बदली परिस्थितियों में आप को जितना भी सहानुभूति वोट मिलेगा उसका अधिकांश खामियाजा कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। संभवतः हरियाणा के चुनाव नतीजे ही यह तय करेंगे कि दिल्ली के चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ होंगे अथवा जनवरी या फरवरी 2025 में।

## राष्ट्रपति शासन का विकल्प

दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 16 फरवरी 2025 तक है। सवाल यह है कि दिल्ली के चुनाव के लिए अभी पीएम नरेंद्र मोदी क्या तैयार हैं? आम आदमी पार्टी के सूत्र तो यह बताते हैं कि जल्दी चुनाव तो केजरीवाल भी नहीं चाहते।

केन्द्र के पास दूसरा विकल्प यह है कि वह दिल्ली को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दे। ऐसी स्थिति में एलजी के हाथ में सत्ता की पूरी कमान आ जाएगी। दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते भी आज भी सत्ता एलजी के पास ही है। निर्वाचित सरकार के पास तो सीमित अधिकार हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो केजरीवाल को बैठे ठाले एक और मुद्दा मिल जाएगा। केन्द्र सरकार यह नहीं चाहेगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

# जीवन से खिलवाड़

आत्महत्या की हर घटना झकझोर जाती है, पर जब कोई प्रतिभावान युवा अपनी जान लेता है, तो यह न केवल त्रासद, बल्कि पूरे देश-समाज के लिए नुकसानदायक बात है। बड़े दुख की बात है कि दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 25 वर्षीय स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र को उसके कमरे में मृत पाया गया। प्रथम दृष्टया, ऐसा लग रहा है कि छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस को व्यापकता में जांच करनी चाहिए और हर आशंका को परखना चाहिए। जानना जरूरी है कि आखिर एक टॉपर छात्र ऐसे मुकाम पर कैसे पहुंच गया? वह रेडियोलॉजी का द्वितीय वर्ष का छात्र था और उसे बेहतरीन विशेषज्ञ डॉक्टर बनना था। लोग यह भूले नहीं थे कि पंजाब का यह छात्र साल 2017 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी या नीट) का टॉपर था। उसके पिता सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और छोटा भाई भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। जिस परिवार ने अपना होनहार खोया है, उसके साथ सबकी संवेदना होनी चाहिए।

ऐसी घटनाएं समाज को विचलित कर देती हैं। समाज विज्ञानियों और चिकित्सकों को मिलकर अध्ययन करना चाहिए। ध्यान रहे, दिल्ली में ही 27 अगस्त को ओल्ड रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल में एक 20 वर्षीय मेडिकल छात्र का शव मिला था। छात्रों के बीच भी यह सवाल बार-बार उठ रहा होगा। क्या निराशा इतनी बढ़ गई है कि अपनी जीवन में पढ़ाई के झंडे गाड़ने वाले छात्रों को भी अपना भविष्य स्याह लग रहा है? इस साल फरवरी के महीने में यह आंकड़ा सामने आया था कि पिछले पांच वर्षों में कम से कम 122 मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 64 एमबीबीएस में और 58 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों अध्ययनरत थे। यह संख्या कम नहीं है। एक भावी चिकित्सक को ऊर्जा और उत्साह से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि उसे लोगों की सेवा के लिए समर्पित होना है। उसे चिकित्सक बनने का मौका मिला है और अच्छे चिकित्सकों को लोग भगवान की तरह आदर देते हैं। सम्मानजनक जिंदगी की ओर जा रहे छात्रों के दिलोदिमाग में निराशा का एक कतरा नहीं होना चाहिए, पर हर महीने औसतन दो मेडिकल छात्र आत्महत्या कर लेते हैं?

**सम्मानजनक जिंदगी की ओर बढ़ रहे छात्रों के मन में निराशा का एक कतरा नहीं होना चाहिए, पर हर महीने औसतन दो मेडिकल छात्र आत्महत्या कर लेते हैं।**

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस साल फरवरी में यह भी बताया था कि पांच साल में 1,270 मेडिकल छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। एक और तथ्य गौरतलब है कि पढ़ाई छोड़ने वालों में से 153 विद्यार्थी एमबीबीएस कर रहे थे और 1,117 ने स्नातकोत्तर के दौरान पढ़ना छोड़ दिया। मतलब, विशेषज्ञ चिकित्सक बनने का मौका भी हाथ से निकलने दिया जा रहा है? क्या चिकित्सा शिक्षा का ध्यान रखने वाली जिम्मेदार संस्थाओं ने इन तथ्यों पर गहराई से गौर किया है? बेशक, छात्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बढ़ती जा रही है। यह होनहार सिख छात्र भी शायद आत्महत्या न करता, अगर उसके पास संस्थान के होस्टल की सुविधा होती। वह अलग कमरा लेकर रह रहा था, तो हो सकता है, अकेलेपन की वजह से अवसाद में चला गया हो। आज छात्रों के सामने समस्याओं का अंबार है। ज्यादातर शिक्षा संस्थान छात्रों की मूलभूत सुविधाओं और मनोदशा से अंजान बने रहते हैं। ऐसे में, छात्रों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अपनी मनोदशा को भी मजबूत रखना पड़ता है। आज शिक्षा संस्थानों के लिए ही नहीं, यह सरकार और समाज के लिए भी विशेष रूप से अपने घर-परिवार से दूर अकेले रहने वाले छात्रों की फिक्र का समय है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 17 सितंबर, 1949

## हवा का रुख

पाकिस्तानी प्रचारक इस बात का जोरों से प्रचार करते रहते हैं कि काश्मीर में जब कभी जनमत संग्रह होगा तो वहां के लोग निश्चय रूप से पाकिस्तान के साथ रहना पसन्द करेंगे। बाहरी दुनिया भी इस प्रचार के चक्कर में आ जाती है और मान बैठती है कि चूंकि काश्मीर में बहुमत मुसलमानों का है, इसलिए वे पाकिस्तान की छत्रछाया में रहना पसन्द करेंगे, जो एक मुस्लिम राष्ट्र है। किन्तु यह धारणा कितनी भ्रांतिकारक है, इसका पता तीन गांवों के उस निर्णय से चल जाना चाहिए, जो काश्मीर के गुरेज इलाके में युद्धबन्दी रेखा पर स्थित हैं। इस निर्णय से हवा के रुख का भली भांति अन्दाज किया जा सकता है।

काश्मीर में जो युद्धबन्दी रेखा निर्धारित होनी है, उसमें किलशाई वाला गांव पाकिस्तानी प्रदेश में पड़ेगा। इस गांव के लोगों ने, जो सब के सब मुसलमान हैं, अपने घर-बार छोड़कर भारतीय सीमा के भीतर चले आने का निर्णय किया है। इस गांव के लोगों का जनमत लिया गया, तो पाकिस्तान के अफसरों को उन्हें समझाने का पूरा मौका दिया गया था। उन्होंने उन्हें हर तरह से पाकिस्तान की सीमा में अपने घरों में ठहरे रहने को समझाया, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। दो आदमियों को छोड़कर बाकी सब, जिनकी संख्या २२१ है, भारतीय सीमा में ही बस जाने के अपने आग्रह पर कायम रहे। इस फैसले के समय पाकिस्तानी अफसरों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षक भी उपस्थित थे और इसलिए उसकी शुद्धता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। इस उदाहरण में तो पाकिस्तानी सीमा में पड़ने वाले गांव के लोग अपने घर-बार छोड़कर भारतीय सीमा में चले आये। दूसरे उदाहरण में ऐसे दो गांव हैं, जो इस समय पाकिस्तान की सीमा के अन्दर हैं, किन्तु उन्हें युद्धबन्दी रेखा निर्धारित होने के बाद भारतीय सीमा में आ जाना होगा। इन गांवों की आबादी करीब १००० है। इन लोगों की भी पाकिस्तान के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षकों की मौजूदगी में राय ली गई। पाकिस्तान के एक सैनिक अधिकारी ने उन्हें समझाया कि भारत में जो मुसलमान रह गये हैं, उन्हें सताया जाता है और वे आगे-पीछे पाकिस्तान में आकर रहेंगे, किन्तु इस कथन का गांव वालों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने भारतीय सीमा में ही रहने का फैसला किया।

# नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी के सौ दिन



यहां स्कैन करें

अनिल बलूनी | सांसद एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख, भाजपा

**विकास के जितने काम अन्य सरकारें अमूमन वर्ष भर में करती हैं, उससे कहीं अधिक कार्यों को प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में जमीन पर उतार दिया है।**



यह सुखद संयोग है कि कल ही नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हुए हैं और आज हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, जिसे पूरा देश सेवा दिवस के रूप में मना रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का पूरा जीवन जन-कल्याण और देश के विकास के लिए समर्पित रहा है, उसी तरह उनके इस कार्यकाल के बीते 100 दिन भी विकास और जन-कल्याण की दिशा में मील के पत्थर रहे हैं। एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद अपनी प्रतिभा, लगन और विजन के बल पर एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने तक के उनके जीवन संघर्ष एवं कर्तव्य बोध से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने गरीबी को जीया है, इसलिए उनकी हर योजना के केंद्र में गरीब कल्याण का भाव निहित रहता है। विकास के जितने काम कई अन्य सरकारें अमूमन पूरे वर्ष में करती हैं, उससे कहीं अधिक कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में जमीन पर उतार दिया है।

पहले ऐसा देखा गया है कि जब नई सरकार का गठन होता है, पहले 20-25 दिन तो यूं ही जश्न में निकल जाते हैं और एक-दो महीने बाद विकास योजनाओं पर काम शुरू हो पाता है, पर प्रधानमंत्री के जीवन का क्षण-क्षण इस देश के लिए समर्पित है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, उसकी बानगी उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में दिखती है। पहले 100 दिनों में विकास के जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले ही रख दी थी, जब उन्होंने अधिकारियों को मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के लिए कामकाज का टास्क दिया था, ताकि विकास की गति किंचित मात्र भी न रुके।

70 साल से अधिक उम्र के देश के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करना हो या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर हो या किसानों के कल्याण की बात, चाहे उद्योगों का विकास हो या गरीब कल्याण - प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन में कई क्रांतिकारी कदम उठाकर न केवल विकसित भारत के संकल्प को एक नया आयाम दिया है, बल्कि वैश्विक नीतियों के केंद्र में भारत को एक प्रमुख शक्ति के तौर पर भी स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का शुभारंभ किया। पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त तीन करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। हरित ऊर्जा के लिए नीतियां बनीं। पीएम ई-बस सेवा शुरू हुई और किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने के साथ-साथ कई काम किए गए।

सरकार ने बुनियादी संरचना पर फोकस रखते हुए 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें वधावन का मेगा बंदरगाह भी शामिल है, जो दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 25 हजार गांवों को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने से रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। आठ नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर, आठ नई रेलवे लाइन और 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना मंजूर की गई। बीते 100 दिनों में 15 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। कई हवाई अड्डों के विकास के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाली शिनखुन ला सुरंग जैसी कई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, आर्थिक विकास को तेज करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और जीवन को सरल बनाना है।

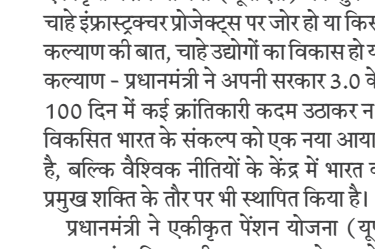

वह हमेशा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करके की। अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों के बीच 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने सत्ता संभालते ही दूसरा सबसे बड़ा फैसला एमएसपी को लेकर किया। वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना और कृषि क्षेत्र में दक्षता व उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन सहित सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। मौसम और जलवायु के अनुकूल भारत बनाने के लिए मिशन मौसम को शुरू किया गया, तो कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एग्रीश्योर नाम से नया फंड शुरू किया गया है।

मोदी सरकार 3.0 ने प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया, जिससे किसानों को फायदा होगा। जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ रुपये की कई कृषि योजनाएं और विकास परियोजनाएं शुरू की गई। सहकारी चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मल्टी-फीड सुविधा में बदला जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के बीच जैविक उत्पाद खरीदने को लेकर समझौता हुआ है, जिसके तहत मुनाफे का उचित हिस्सा सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गेमचेंजर साबित हो रही है। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति पर भी काम चल रहा है। इस साल जून में वाराणसी की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि में उनकी भूमिका के लिए स्वयं सहायता समूहों की 30,000 कृषि सखियों को भी सम्मानित किया था। मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन में 113 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। इससे देश में डॉक्टरों की कमी दूर होगी।

दुनिया को पता है, रूस-यूक्रेन युद्ध अगर कोई खत्म करा सकता है, तो वह नरेंद्र मोदी हैं। बिना भारत किसी प्रमुख बैठक की कल्पना नहीं की जा सकती, वैश्विक स्थिति में यह बदलाव बीते 10 साल में ही आया है।

कुल मिलाकर, समृद्ध, खुशहाल और विकसित होते भारत की अविरल कहानी में जहां विकास के नए मापदंड स्थापित हो रहे हैं, वहीं इसमें गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के कल्याण का विजन भी समाहित है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# मणिपुर में असम रायफल्स को लेकर जारी आंदोलन का सच



यहां स्कैन करें

प्रवेश लामा | एसोशिएट एडीटर, एचटी

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 22 असम रायफल्स के बटालियन मुख्यालय में सैनिकों ने रवानगी की तैयारी शुरू कर दी है। 20 सितंबर से उनकी जगह सीआरपीएफ के जवान ले लेंगे। जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर केंद्र ने मणिपुर से 22 और 9 असम रायफल्स बटालियनों को वहां भेजने का आदेश दिया है। इन दोनों बटालियनों में लगभग 2,500 जवान हैं, जो अभी कांगपोकपी और चुराचांदपुर में तैनात हैं। ये दोनों पहाड़ी जिले हैं, जहां कुकी समुदाय की बहुसंख्या है। इन जवानों में से कई अपने नए मिशन को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसी चुनौतियों के लिए ही उनको प्रशिक्षित किया गया है। मगर एक समस्या भी है।

22 असम रायफल्स बटालियन के मुख्यालय के बाहर करीब 80 कुकी महिलाएं केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। 20 सितंबर तक यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि हर घर ने अपनी महिला को यहां भेजने का फैसला किया है। 'कम्युनिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' के बैनर तले महिलाओं ने एलान किया है कि वे गेट को बंद कर देंगी और सैनिकों को जाने नहीं देंगी। उनका मानना है कि असम रायफल्स के जवान ही मैतेई उग्रवादियों से उनकी रक्षा कर सकते हैं। मगर वहां से करीब 45 किलोमीटर दूर मैतेई महिलाओं की मदद से सैकड़ों छात्रों ने इंफाल के काकवा बाजार में भारत-म्यांमार मार्ग को जाम कर दिया है। वे भी धरने पर बैठे हैं, हालांकि उनकी छह मांगों में एक मांग यह है कि असम रायफल्स को मणिपुर से हटाया जाए। उनका कहना है, हिंसा अब भी इसीलिए जारी है, क्योंकि सुरक्षा बल कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। इन प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, मणिपुर का इतिहास इसका गवाह है कि असम रायफल्स ने हमेशा मैतेई लोगों पर अत्याचार किया है।

**कुकी महिलाएं राज्य से असम रायफल्स की रवानगी का विरोध कर रही हैं, तो मैतेई छात्र उनकी विदाई को लेकर आंदोलनरत हैं।**

मणिपुर पिछली मई से जातीय हिंसा में जल रहा है। मैतेई को आदिवासी का दर्जा देने के अदालती फैसले (जिस पर रोक लगा दी गई) के खिलाफ आदिवासियों का विरोध-प्रदर्शन (कुकी के नेतृत्व में) जल्द ही दोनों समूहों के बीच जातीय संघर्ष में बदल गया। एन बीरेन सिंह सरकार के मैतेई समर्थक रुख से कोई मदद नहीं मिली और पुलिस बल व नौकरशाही में जातीय विभाजन के बाद माना यही गया कि असम रायफल्स की मौजूदगी ने ही यहां के हालात संभाले हैं। हालांकि, गुरुवार दोपहर असम रायफल्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाया कि एक सैनिक के लिए आदेश-पालन अनिवार्य है और सीआरपीएफ भी उतनी ही सक्षम फोर्स है। मगर महिलाओं ने रोड खाली करने से इनकार कर दिया है। इस आशंका में कि कहीं सैनिक तय समय से पहले न चले जाएं, महिलाओं ने रात भी यहीं बिताने का फैसला किया है। वहां चाय बनाने की व्यवस्था के साथ-साथ बारिश से बचने के लिए टेंट भी लगा दिए गए हैं। इस बीच, इंफाल में भी मैतेई छात्रों ने अपनी मांगें पूरी होने तक कक्षा में न जाने की कसम खाई है, जिसके कारण सरकार को कक्षाएं व परीक्षाएं निलंबित करनी पड़ी हैं। छात्रों ने इस बाबत एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा है और अपनी मांगें माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने का एलान किया है।

पिछले 16 महीनों में पहली बार असम रायफल्स को यहां से हटाया जा रहा है। कई नौकरशाह मानते हैं कि विरोध और जवाबी-विरोध की यह पटकथा महीनों पहले लिखी गई थी। उनके मुताबिक, बेशक मणिपुर में असम रायफल्स को लेकर विवाद रहे हैं, लेकिन उसको लेकर इससे पहले इतनी राजनीति कभी नहीं हुई थी। यह सच है कि जम्मू-कश्मीर में सैनिकों की जरूरत है, लेकिन अभी इसको वहां से भेजने का फैसला गलत साबित हो सकता है। हालांकि, असम रायफल्स के एक जवान ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यही एकमात्र सुरक्षा बल है, जिसके साये तले कुकी और मैतेई मिलकर शांति बहाली के लिए काम कर रहे हैं। जब पहली बार यहां हिंसा फैली थी, तब दोनों समुदायों के 20,000 से अधिक लोगों को इसी सुरक्षा बल ने बचाया था। उसके मुताबिक, हम यहां आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लिहाजा, यह अच्छा ही है कि हम में से कुछ जवान जम्मू-कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि देश की खातिर लड़ने के लिए वहां एक दुश्मन तो है।

मनसा वाचा कर्मणा

## ऊब की जड़ों को खोजिए

यदि आप ऊब गए हैं, तो उसका कारण क्या है? वह है क्या, जिसको हम ऊब कहते हैं? ऐसा क्यों है कि आपकी किसी भी चीज में रुचि नहीं है? कुछ कारण अवश्य होने चाहिए, जिन्होंने आपको मंद बना दिया है। यदि आप यह जान सकें कि आप क्यों ऊब गए हैं, तो निस्संदेह आप समस्या का हल कर लेंगे। है न? तब जागी हुई अभिरुचि कार्य करने लगेगी।

हम अंदर से, मानसिक तौर पर पता लगा सकते हैं कि हम क्यों इतनी अधिक ऊब की अवस्था में हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि हममें से अधिकांश क्यों इस हालत में हैं; हमने अपने को भावनात्मक रूप से और दिमागी तौर पर भी थकाकर निढाल कर लिया है; हमने इतनी सारी चीजों, अनुभूतियों, मनोरंजनों, प्रयोगों को आजमाया है कि हम जड़, क्लांत हो चुके हैं। यदि हम एक मनोवैज्ञानिक से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो किसी दूसरे के पास या फिर किसी धर्मगुरु के पास चले जाते हैं; यदि वहां असफल होते हैं, तो किसी तीसरे आचार्य के पास और इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। हम हमेशा दर-दर भटकते रहते हैं। लगातार खुद को तानने और फिर छोड़ देने की यह प्रक्रिया निढाल करने वाली होती है। क्या नहीं होती? दूसरी सभी उत्तेजनाओं की तरह यह शीघ्र ही मन को जड़ बना देती है।

हमने यही किया है। एक संवेदन से दूसरे संवेदन की ओर; एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना की ओर तब तक भागते जाना, जब तक कि थककर हम निढाल न हो जाएं। तो, अब इसका एहसास होने पर आप और आगे न जाएं, कुछ विश्राम करें। शांत हों और मन को स्वयं अपने से शक्ति प्राप्त करने दें, उसे बाध्य न करें। जैसे पृथ्वी पुनः अपने को नूतन कर लेती है, उसी प्रकार जब मन को शांत होने दिया जाता है, तो वह अपने को नूतन कर लेता है। परंतु मन को शांत होने देना और इस सबके बाद उसे रिक्त रहने देना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि मन हर समय कुछ-न-कुछ करते रहना चाहता है।

याद रखिए, समस्या तभी है, जब आप किसी स्थिति को जैसी वह है, वैसी आप स्वीकार नहीं करते और उसे बदलना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं संतोष करके बैठने की वकालत कर रहा हूं, बात इसके उलट है। यदि हम जो हैं, उसे स्वीकार कर लें, तो देखेंगे कि वह बात, जिससे हम भयभीत हैं; वह स्थिति, जिसे हम ऊब, निराशा या भय कहते हैं, वह पूरी तरह से बदल गई है! जिस स्थिति से हम भयभीत थे, उसका पूर्णतया परिवर्तन हो चुका है।

**कुछ कारण अवश्य होने चाहिए, जिन्होंने आपको मंद बना दिया है। यदि आप यह जान सकें कि क्यों ऊब गए हैं, तो निस्संदेह इस समस्या का समाधान कर लेंगे।**

अतः अपने सोच-विचार के तरीकों को, उनकी प्रक्रिया को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वबोध किसी अन्य से, किसी पुस्तक, किसी मनोविश्लेषक द्वारा नहीं हो सकता। यह आपको स्वयं प्राप्त करना होगा।

**जे कृष्णमूर्ति**

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक



**क्या आप एआई से डरते हैं? क्या आपको इससे डरना चाहिए? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं- बदलाव को स्वीकार करने वाले, उसका स्वागत करने वाले या आप उसके विरोधी हैं; जहां हैं, वहीं खुश हैं।**

## अब जनता की अदालत में केजरीवाल

रविवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उनके इस एलान से सियासी जगत में हलचल मच गई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आबकारी नीति से जुड़े मामले में जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, तभी से वह लगातार कह रहे थे कि पद से कतई इस्तीफा नहीं देंगे। जेल से ही उन्होंने सरकार चलाई भी। मगर सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा देने का मन बना लिया है, जिसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। हालांकि, ऐसा करके उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है।

दरअसल, इस्तीफे की उनकी घोषणा एक सोची-समझी राजनीति है। वह इस बहाने एक तरफ जनता की सहानुभूति पाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ यह दिखाने की कोशिश में हैं कि जब तक मतदाता उनको ईमानदारी का प्रमाणपत्र नहीं देंगे, वह मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे। इस घोषणा का कितना असर पड़ेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उनका ऐसा एक दांव विफल साबित हुआ था और जनता ने उनकी बात को कमोबेश नकार दिया था। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इसका जवाब हर कोई अपने हिसाब से दे रहा है, पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव चलकर साहस का परिचय जरूर दिया है। इसका असर दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, जहां उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि यहां आम आदमी पार्टी को बहुत फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन मुकाबले को वह दिलचस्प जरूर बना रही है।

बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता शराब घोटाले में भले न हो, लेकिन विरोधी पार्टियों ने उनकी छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आम जनता भी यह सब देख रही है, इसलिए केजरीवाल ने जनता के बीच ही जाने का एलान किया। वैसे भी, उनसे जब इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, तो अब पद छोड़ने का दांव खेलकर उन्होंने विपक्षी पार्टियों के हाथों से यह मुद्दा छीन लिया है। अब देखना यह है कि उनके इस कदम का दिल्ली और हरियाणा के चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है? हरियाणा विधानसभा का चुनावी नतीजा तो अगले महीने की शुरुआत में ही पता चल जाएगा, लेकिन दिल्ली के जनादेश के लिए अभी हमें कुछ वक्त इंतजार करना होगा।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

## अनुलोम-विलोम
### अरविंद केजरीवाल



## इस्तीफे का यह दांव विशुद्ध राजनीति

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तो कई शर्तें भी उन पर लगाई गई थीं। जैसे, वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे, केस को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे आदि। इसका मतलब है कि अधिकार के मामले में वह नख-दंत विहिन थे। यानी, मुख्यमंत्री के रूप में वह काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके लिए इस्तीफे का रास्ता ही बचा था। वैसे भी, अगले चंद महीनों में यहां चुनाव होना है, तो जाहिर है, पूरा गुणा-भाग करने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने यह कदम उठाया है, जो विशुद्ध राजनीतिक है। वह अपनी जेल-यात्रा को भावनात्मक मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या यह इतना आसान है, जितना उनको लग रहा होगा?

इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने के लिए शुरुआती दिनों की उनकी राजनीति पर एक नजर डालते हैं। आपको याद होगा, जब आम आदमी पार्टी का गठन होने को था, तब अरविंद केजरीवाल दावा किया करते थे कि उनके पास तमाम राजनेताओं के कच्चे-चिट्ठे हैं। वह मंच से अपने हाथ ऊपर उठाकर फाइल दिखाते, तमाम कथित भ्रष्ट नेताओं के नाम गिनाया करते और लोगों से पूछा करते, क्या इन लोगों को जेल में नहीं रहना चाहिए? विडंबना देखिए, बाद के वर्षों में वह उन्हीं तथाकथित भ्रष्ट नेताओं के हाथों खेलते रहे। नतीजतन, जब शराब घोटाले में इनका नाम उछला, तो लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की कथित वैकल्पिक राजनीति की सच्चाई लोकसभा चुनाव में भी जाहिर हुई, जब जनता ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। इन दिनों तो उनकी छवि एक ऐसे नेता की हो चली थी, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा।

वास्तव में, जेल से सरकार चलाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी रही-सही इज्जत गंवा दी है। अच्छा होता कि वह किसी अन्य नेता पर भरोसा करते, पर वह संविधान की दुहाई देते रहे, जबकि सच यही है कि अगर हमारे संविधान-निर्माताओं को यह इल्म होता कि कालांतर में कोई मुख्यमंत्री अपनी जिद के कारण पद नहीं छोड़ेगा और जेल से सरकार चलाएगा, तो वे जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के इस्तीफे संबंधी प्रावधान भी संविधान में जरूर शामिल कर देते। खैर, अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का एलान जरूर कर दिया है, लेकिन उनके इतिहास को देखते हुए यह कदम लोगों में शायद ही भरोसा पैदा कर पाएगा। चुनाव से इसकी हकीकत पता चल ही जाएगी।

हृतेश मिश्र, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 17 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

## इस्तीफे का पैंतरा

जेल से छूटने के महज दो दिन बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफे का दांव चल कर सभी को चकित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अब अपने पद पर नहीं रहेंगे। स्वाभाविक है कि दिल्ली की जनता को हो सकता है आज नया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिल जाए। बहरहाल, केजरीवाल के इस पैंतरे से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यही नहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। गौरतलब है कि केजरीवाल को अदालत ने कई सारी कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया है। लाजिमी है कि केजरीवाल के लिए ये शर्तें काफी असहज करने वाली रही और मुख्यमंत्री पद से हटने के पीछे यह भी एक प्रमुख वजह हो। हाल के वर्षों में केजरीवाल सरकार के सामने कई समस्याएं दरपेश हुईं। इनकी आम आदमी पार्टी के कई विधायक और मंत्री गिरफ्तार हुए। घोटालों के अनगिनत आरोप केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगाए गए। मगर हर बार पार्टी इन सबसे पार पाकर आगे बढ़ती रही। एक समय ऐसा भी आया जब हाल ही में संपन्न लोक सभा चुनाव में उन्हें दिल्ली में कांग्रेस का साथ मिला। हालांकि अब ये गठबंधन टूट चुका है, चुनांचे पार्टी को अकेले दम पर न केवल अपने मजबूत किले दिल्ली को बचाना है बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपना प्रसार प्रभावी तरीके से करना है। वैसे, यह काफी चुनौतीपूर्ण काज है। इसकी वजह यही दिखती है कि पार्टी लगातार अंदरूनी और बाह्य चुनौतियां का सामना कर रही है। उसके लिए इस वक्त अपनी ताकत, एकजुटता और विपक्ष की घेरेबंदी से बिना किसी झंझट के निकलना बेहद जरूरी है। अगर पार्टी ऐसा कर पाती है तो निःसंदेह वह मनोवैज्ञानिक तौर पर विपक्ष पर हावी हो सकती है। वैसे केजरीवाल का इस्तीफा देने का ऐलान करना जितना चौंकाऊ है, उतना ही दिलचस्प नये मुख्यमंत्री की घोषणा की भी है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से इस बात को लेकर फ्रिकमंद होगी कि पार्टी की कमान किसे दी जाए। चूंकि केजरीवाल ने नवम्बर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराए जाने की मांग की है, लिहाजा पार्टी को इसके लिए भी मानसिक तौर पर तैयार होने की जरूरत है। अलबत्ता, फ्री बिजली और पानी के साथ महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कराने का सरकार के निर्णय की भी आने वाले चुनाव में परीक्षा होनी है। क्योंकि अब सबकुछ जनता की अदालत में होना है।



## झूठ पर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की समय पूर्व रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वकीलों द्वारा अदालत के समक्ष तथा याचिकाओं में बार-बार झूठे बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पिछले हफ्तों के दौरान छठवें या सातवें मामले में याचिका में स्पष्ट तौर पर दिए गए झूठे बयान पर पीठ ने कहा कि हमारी प्रणाली विश्वास पर काम कर रही है। जब हम सुनवाई कर रहे होते हैं तो बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं। एक मामले के दौरान अदालत को पता चला कि सजा में छूट का अनुरोध करते हुए रिट याचिका में झूठे बयान दिए गए। साथ ही झूठी दलीलें भी दी गईं। पीठ ने जुर्माना लगाने की बात करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को वकीलों की गलतियों के लिए दंडित नहीं कर सकते। पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट वकीलों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त कर चुका है। साल की शुरुआत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वकील को लताड़ लगाते हुए कहा था कि यह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो भी ट्रेन आई उसमें चढ़ गए। मगर वकीलों के बारे में प्रसिद्ध है कि मुवक्किल सही हो या गलत उसका वकील हमेशा उसके साथ होता है। वे अदालत के समक्ष झूठी दलीलें देकर या गलत साक्ष्यों के मार्फत याचिकाकर्ता को जीत दिलाने के आश्वासन देने को अपने पेशे से जोड़ते हैं। हालांकि सच तो यह भी है कि वकीलों द्वारा मुवक्किलों से भी झूठ बोला जाता है। अदालती कार्रवाई या नियमों से अनिभिज्ञ आम व्यक्ति को वे विवेकानुसार ज्ञान देने से भी संकोच नहीं करते। मामलों को बिला-वजह लंबित रखने तथा तारीखों को बढ़ाते रहने से वाद निरंतर देखने में आते हैं। निचली अदालतों में जाते-जाते वकीलों के ये तेवर और भी बिगड़े नजर आते हैं। जो कई मामलों में जानते-बूझते अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी अदालत की इस नाराजगी को उन्हें दिशा-निर्देश की भांति देखना चाहिए। यह बार एसोसिएशन का दायित्व है कि वह वकीलों को झूठ का सहारा लेने और गलत दस्तावेज देने से रोकने के सख्त निर्देश जारी करे। क्योंकि उनके इस कदम से अदालत का विश्वास तो डगमगा ही रहा है, आम आदमी का न्याय प्रणाली पर भरोसा भी कमजोर पड़ता जा रहा है। जिसे बनाए रखने के प्रति हम सब सामूहिक तौर पर जिम्मेदार हैं।



**कहानी/ पुष्पेश कुमार पुष्प**

## सबसे सुंदर क्या है

एक बार एक कलाकार को संसार की सबसे सुंदर वस्तु का चित्र बनाने का मन हुआ। काफी सोच-विचार करने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर संसार की सबसे सुंदर वस्तु क्या है? वह धर्म गुरु के पास गया ओर बोला, 'महात्मन्! संसार की सबसे सुंदर वस्तु क्या है?'

धर्म गुरु मुस्कुराकर बोले, 'वत्स! संसार की सबसे सुंदर वस्तु है श्रद्धा। उस श्रद्धा का दर्शन तुम्हें प्रत्येक धर्मस्थल पर होगा। संसार में इससे सुंदर वस्तु और क्या हो सकती है?'

कलाकार धर्म गुरु के उत्तर से संतुष्ट न हुआ और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नवविवाहिता मिली। उसने नवविवाहिता से पूछा, 'संसार की सबसे सुंदर वस्तु क्या है?'

नवविवाहिता मुस्कुराकर बोली, 'संसार की सबसे सुंदर वस्तु प्रेम है; प्रेम निर्धनता में भी समृद्धि प्रतीत होती है। प्रेम खारे आंसुओं को भी मीठा बना देता है। प्रेम से सुंदर इस संसार में कोई और वस्तु हो नहीं सकती है।'

इस उत्तर से भी कलाकार का मन संतुष्ट न हुआ। रास्ते में एक सैनिक मिला। वह उससे भी वही प्रश्न दोहराया।

सैनिक शांत स्वर में बोला, 'संसार की सबसे सुंदर वस्तु शांति है। शांति से बढ़कर इस संसार में सुंदर और क्या हो सकती है? युद्ध तो संसार की सबसे कुरूप वस्तु है। मेरे विचार से तो शांति ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु है।

कलाकार ने तीन वस्तुएं समझ ली-'श्रद्धा, प्रेम और शांति।' वह सोचता-विचारता घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही सामने उसके बच्चे और पत्नी दौड़ पड़ी। बच्चे उससे लिपट पड़े और और पत्नी मुस्कान बिखेरने लगी।

कलाकार सोचने लगा-'मैं संसार की जिस सबसे सुंदर वस्तु की खोज में निकला था, वह तो मेरे घर में ही है। मेरे बच्चों की आंखों में श्रद्धा है। पत्नी की आंखों से प्रेम की वर्षा हो रही है और मेरा यह घर तो शांति की दिव्य भूमि है।'

कलाकार तुरंत काम में लग गया। उसने संसार की सबसे सुंदर वस्तु का चित्र तैयार कर लिया और उसका शीर्षक दिया-'घर'।

**अनमोल वचन**

*असफलता का मौसम, सफलता के बीज बोने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है*

-परमहंस योगानंद

# देशहित में तो कतई नहीं

**राहुल के वक्तव्य**

**अवधेश कुमार**



राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर मचा बवंडर बिल्कुल स्वाभाविक है। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी की यह पहली विदेश यात्रा थी। राहुल गांधी के लिए देश के हितों के प्रति सतर्क एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने वाले नेता के रूप में स्वयं की छवि निर्मित करने का महत्त्वपूर्ण अवसर था। ओवरसीज कांग्रेस ऑफ इंडिया के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कह दिया था कि राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के रूप में नहीं निजी यात्रा है। क्या लोक सभा में विपक्ष का नेता या संवैधानिक दायित्व निभाने वाला कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक वक्तव्यों के बारे में कह सकता है कि उस पद के द्वारा नहीं मेरा निजी विचार है क्योंकि मैं अपने अंदर दो चरित्र लेकर चलता हूं?

कार्यक्रमों में उनके दिए गए वक्तव्य हों या प्रश्नोत्तर या फिर मुलाकातें...कोई आयोजन ऐसा नहीं था जिसे सामान्य सहज रूप में स्वीकार किया जाए? भारत का नेता विदेश की भूमि पर जाकर यह कहे कि हमारे देश में चारों ओर भय का माहौल है, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, एक संगठन समूह को छोड़कर अन्यों को अपने मजहब, पंथ, संप्रदाय, भाषा के अनुसार और वेशभूषा के साथ निकालने या महत्त्वपूर्ण जगहों पर प्रवेश करने तक पर खतरा है अल्पसंख्यकों तथा समाज के पिछड़ों व वंचित वर्गों के विरुद्ध हिंसा हो रही है विरोधी राजनेताओं को जेल में डाला जा रहा है तथा भारत की विविधताओं को समाप्त किया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए?

जब उनका कार्यक्रम पहले से तय था तो उन्हें क्या बोलना है इनका निर्धारण भी पहले हो गया होगा। 2017 से उनकी राजनीतिक विदेश यात्राएं हो रही हैं और अभी तक के उनके वक्तव्य को देखें तो आपको हैरत नहीं होगी। हर यात्रा में उन्होंने विश्व समुदाय के समक्ष भारत की एक झूठी डरावनी तस्वीर पेश की है। वे लगातार कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद आरएसएस का सारी संस्थाओं पर कब्जा है, हम विविधता को मानते हैं वे एकरूपता के लिए सत्ता की ताकत का उपयोग कर रहे हैं। इसी में वे जोड़ते रहे हैं कि समाज में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और उनके विचार से असहमत होने वालों को हिंसा, प्रताड़ना और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संपूर्ण मीडिया पर कब्जा है और हमारे पास अपनी बात रखने के मंच नहीं हैं। लगभग ये ही बातें थोड़ी अलग या समान शब्दावलियों में उन्होंने इस बार भी बोला है। पिछले चुनाव में मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी आरक्षण समाप्त कर देगी का असर उन्हें दिखा इसलिए ये विषय भी प्रमुखता से उठाया। पिछले वर्ष की अमेरिका यात्रा में उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के बारे में कहा था कि



जब हमारे पास अपनी बात रखने या जनसंवाद करने का कोई माध्यम नहीं बचा तो हम जनता के बीच यात्रा पर निकल पड़े। इस बार भी उन्होंने इसकी चर्चा की। इस बार अंतर इतना था कि उन्होंने बताया कि लोगों ने समझा है और चुनाव परिणाम ने इसे साबित किया है। अब नरेन्द्र मोदी से लोग डर नहीं रहे, सवाल पूछ रहे हैं और उनका आत्मविश्वास विश्वास खत्म गया है। वैसे यह बात भारत में वह बोल चुके थे।

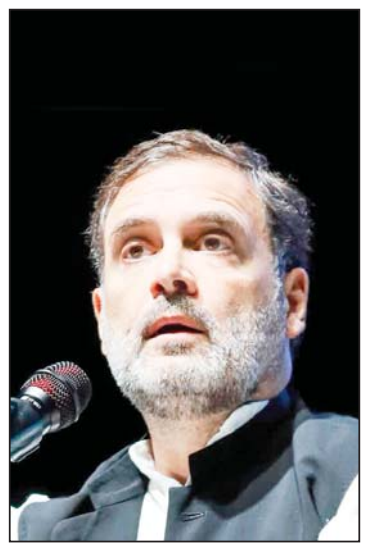

राहुल गांधी के रणनीतिकार, सलाहकार, थिंक टैंक सब प्रफुल्लित होंगे क्योंकि जैसा वे चाहते थे राहुल गांधी पूरी तरह तैयार होकर देश के साथ विदेश में भी उतर चुके हैं। किंतु यह भूल गए कि एक बार आपने देश की छवि विदेशों में खराब कर दी तो यह केवल मोदी सरकार के लिए नहीं संपूर्ण भारत के लिए समस्या और चुनौती बनेगा। कल्पना करिए, जो संस्थाएं उभरते और खड़ा होते हुए भारत को रोकने के लिए झूठी रिपोर्ट के आधार पर विश्व के निरंकुश, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का दमन करने वाले देशों की सूची में डालने की वकालत कर रहे हैं उनके लिए तो राहुल गांधी को उद्धृत कर अपनी बात की पुष्टि करना ज्यादा आसान हो जाएगा। उनकी मुलाकातों की सूची में हमने भारत विरोधी और यहां तक कि भारत के विरुद्ध अमेरिकी कांग्रेस में मतदान करने वाली इलाहान उमर की चर्चा है किंतु पूरी सूची में ऐसे ही लोग थे जो अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, मानवाधिकारों आदि के नाम पर भारत विरुद्ध अभियान चलाते रहे हैं। इनमें पाकिस्तान समर्थक हैं। जरा सोचिए, कोई विदेशी नेता पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का भाग नहीं मानता, कश्मीर में जनमत संग्रह की आवाज उठाता है तथा अमेरिका में भारतीयों के लिए वीजा नियमों को आसान करने वाले विधायक के विरुद्ध मतदान करता है उसका हमारे देश के किसी नेता के साथ खड़ा होने का अर्थ क्या है?

यह मोदी सरकार का विरोध है या भारत का? खालिस्तान की मांग सिखों की धार्मिक आजादी की मांग से जोड़ कर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जैसे देशों में सिख फॉर जस्टिस या ऐसे दूसरे समूह बीच-बीच में भारत को परेशान करने वाली गतिविधियां करते हैं। क्या राहुल गांधी को पता नहीं कि इन तत्वों ने ही भारतीय दूतावास आदि पर हमले किए और महात्मा गांधी तक की मूर्ति को अपमानित किया? सिख फॉर जस्टिस का संचालक और भारत में वांछित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयानों को हाथों-हाथ लिया और कहा कि यही तो हम कह रहे थे, आज राहुल गांधी ने इसकी पुष्टि कर दी। राहुल गांधी ने भारत का पक्ष इस कमजोर किया। इसका डरावना पहलू यह है कि इसका किंचित भी लाभ उठाकर इन तत्वों ने पंजाब में कोई गड़बड़ी पैदा कर दी तो क्या होगा?

भारत की एकता-अखंडता तथा विश्व में इसके प्रभाव बढ़ने, सम्मान मिलने के प्रति समर्पित कोई नेता विदेशी भूमि पर इस तरह की बातें नहीं कर सकता। आपको आरएसएस, बीजेपी से मतभेद है तो देश के अंदर प्रकट कर सकते हैं। उसमें भी राहुल गांधी जी अतिवाद की सीमा तक जा रहे हैं जो हमारे अंदर ही तनाव और हिंसा बढ़ाने तथा उथल-पुथल मचाने की पर्याप्त क्षमता रखता है। साफ है कि राहुल गांधी का एजेंडा देश की सामान्य राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करना या स्वयं सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। अपने देश के बारे में ऐसे दुष्प्रचार पुराने समय में उथल-पुथल और हिंसा के द्वारा सत्ता पर कब्जा करने वाले वामपंथी किया करते थे। राहुल गांधी संसदीय लोकतंत्र के अंदर क्या लक्ष्य चाहते हैं इसे समझने के लिए शोध की आवश्यकता है।

*(लेखक के निजी विचार हैं)*

राहुल गांधी जी अतिवाद की सीमा तक जा रहे हैं जो हमारे अंदर ही तनाव और हिंसा बढ़ाने तथा उथल-पुथल मचाने की पर्याप्त क्षमता रखता है। साफ है कि राहुल का एजेंडा देश की सामान्य राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करना या स्वयं सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। अपने देश के बारे में ऐसे दुष्प्रचार पुराने समय में उथल-पुथल और हिंसा के द्वारा सत्ता पर कब्जा करने वाले वामपंथी किया करते थे

https://t.me/AllNewsPaperPaid

## प्रतिबंधित चीन के लहसुन की बाजार में भरमार



- दिल्ली के बाजारों में चीनी लहसुन सस्ता होने और देखने में बड़ा-बड़ा होने के कारण उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रहा है। गृहणियों को इसका छिलका उतारने में आसानी होती है
- चीनी लहसुन भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन मुनाफोखोरों ने इसका कारोबार शुरू कर दिया है। यह नेपाल होकर भारत पहुंच रहा है
- चीन विश्व में सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक है। 2014 में भारत ने चीनी लहसुन पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि इससे देश में 'फंगस' लगे उत्पाद आने की आशंका थी
- चीनी लहसुन में कीटनाशकों की मात्रा अधिक होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

भारत सेकेंड-हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान क्यों खरीदेगा जबकि भारत का अपना तेजस (सबसे हल्का सुपरसोनिक युद्धक विमान) कहीं बेहतर है। तेजस के उत्पादन कार्यक्रम में व्यवधान इसलिए है क्योंकि अमेरिका स्पष्ट रूप से GE F404 इंजनों की अपनी आपूर्ति का लाभ उठा रहा है।

**ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक**
**@Chellaney**

# बुढ़ापे का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच



**आयुष्मान योजना | ललित गर्ग**

केंद्र सरकार ने अब सत्तर साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान भारत' योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। देश के करीब साढ़े चार करोड़ परिवार के छह करोड़ बुजुर्ग इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। दरअसल, वर्ष 2018 में शुरू हुई 'आयुष्मान भारत योजना' में अब तक केवल गरीब परिवार ही शामिल हो सकते थे, जिन्हें पांच लाख का कैशलेस कवर दिया जाता था। अब इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना का लाभ सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा।

इस योजना से हम एक ऐसी दुनिया बना सकेंगे जहां हर बुजुर्ग गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की नयी पहल का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो यह फैसला इस आयुवर्ग के बुजुर्गों की सेहत को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी क्योंकि आने वाले बीस वर्ष में भारत की बुजुर्ग आबादी तीन गुना होने की संभावना है। नये भारत-विकसित भारत की उन्नत एवं आदर्श संरचना बिना वृद्धों की सम्मानजनक स्थिति के संभव नहीं है। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ एवं सृसंस्कृत परिवार परम्परा पर तो काला दाग है ही, शासन-व्यवस्थाओं के लिए भी लज्जाजनक है। इस फैसले की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत बहुत पीछे है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ऐसे परिवारों की संख्या केवल 41 प्रतिशत है, जिनके कम से कम एक सदस्य का स्वास्थ्य बीमा हो। बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में तो यह राष्ट्रीय औसत के करीब आधे के बराबर है। स्वास्थ्य बीमा को लेकर यह उदासीन रवैया हमारी उस आदत की वजह से है, जिसमें ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। बहुत से लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन जब बीमारी सिर पर आती है, तो पूरे घर के बजट को तहस-नहस एवं असंतुलित कर देती है। सरकार का मौजूदा कदम कई परिवारों को ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंसने से बचा सकता है। भारत में इलाज दिनों-दिन महंगा होता जा रहा है। जब आय के स्रोत सिमट जाते हैं



और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं मिलती तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते है, फिर महंगे इलाज की चिंता और बढ़ जाती है। अकसर भारत में कर्मचारी व आम लोग सोचते हैं कि वे जीवन भर आयकर चुकाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा ना के बराबर होती है, लेकिन अब मोदी सरकार ने लोकतंत्र के सामाजिक कल्याणकारी स्वरूप को तरजीह दी है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। अब जब स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाया गया है तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि खर्च को लेकर परिजनों का डर कम होगा। इस योजना का पूरा खाका सामने आना बाकी है, लेकिन यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि बीमा सुरक्षा कवच होने के बावजूद बुजुर्ग मुफ्त उपचार से वंचित न रह जाएं। खास तौर से सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लेकर निजी अस्पतालों के रवैये को देखते हुए यह चिंता ज्यादा जरूरी हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत आयु 67.3 साल है। पिछले दो दशकों में ही औसत आयु में पांच बरस से अधिक का इजाफा हो चुका है। निश्चित ही यह अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ यह चिंता भी जुड़ी हुई है कि देश में दिल से जुड़े रोगों और डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अन्य रोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो आबादी वर्ष 2011 में 8.6 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 2050 तक 19.5 फीसद हो जाएगी।

यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में स्वास्थ्य देखभाल का 45 प्रतिशत खर्च बुजुर्ग मरीजों पर होगा। ऐसे में बुजुर्गों के सामने अनेक अन्य समस्याओं के साथ नई एवं असाध्य बीमारियां और उनका महंगा इलाज बड़ी समस्या है। ऐसी स्थितियों में अब इस योजना का लाभ सभी बुजुर्गो को दिया जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया है कि जो सत्तर साल से अधिक के नागरिक प्राइवेट बीमा योजना या फिर राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ ले रहे है, वे भी नई योजना का लाभ लेने के अधिकारी होंगे। लेकिन उन्हें इस योजना के लिये आवेदन करना होगा। अस्पतालों की भीड़ के कारण बुजुर्गो के घर तक मोबाइल स्वास्थ्य जांच सेवा भी इस योजना में लागू हो तो सोने पर सुहागा हो सकता है। सरकार को भविष्य में वृद्धों के लिये अलग से अस्पताल संचालित करने के बारे में भी सोचना चाहिए।

**भगवान | ओशो**

मत करो स्मरण! लेकिन जिसे तुम जानते हो, उससे पूरी तरह असंतुष्ट तो हो जाओ। जहां तुम खड़े हो, उस जमीन को तो व्यर्थ समझ लो। तो तुम्हारे पैर आतुर हो जाएंगे उस जमीन को खोजने के लिए, जहां खड़ा हुआ जा सके। जिस नाव पर तुम बैठे हो, उसे तो देख लो कि वह कागज की है। कोई फिक्र नहीं कि दूसरी नाव का हमें कोई पता नहीं है। और हमें कोई पता नहीं है कि कोई किनारा भी मिलने वाला है। हमें कोई पता ही नहीं है कि कोई और खिवैया भी हो सकता है, लेकिन यह नाव, जिस पर तुम बैठे हो, कागज की है या सपने की है, जरा नीचे इसकी तलाश कर लो। और जिस आदमी को पता चल जाए कि मैं कागज की नाव में बैठा हूं पता है वह क्या करेगा? कम-से-कम चीखकर रोका, चिल्लाएगा तो! पता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो भी मैं कहता हूं वह चिल्लाएगा और रोएगा। कोई किनारा हो या न हो, और कोई निकट हो या न हो, उस स्वात निर्जन में भी उसका रुदन तो सुनाई ही पड़ेगा, उसके प्राण तो चिल्लाने ही लगेंगे, कि मैं कागज की नाव में बैठा हूं, अब क्या होगा? इस घटना से ही, इस विह्वलता से ही अचानक हृदय का एक नया यंत्र शुरू हो जाता है। हृदय में दो यंत्र है। वैज्ञानिक से पूछने जाएंगे, तो वह कहेगा, फेफड़े के अतिरिक्त हृदय में और कुछ भी नहीं है, फुफफुस है। पंपिंग सेट के सिवाय वहा कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ श्वास को फेंकने और खून को शुद्ध करने का काम करता है। वैज्ञानिक से पूछने जाएंगे, तो हृदय जैसी कोई भी चीज नहीं है, फेफड़ा है, फुफफुस है, लेकिन शब्द हम सदा हृदय का उपयोग करते हैं, हालाकि हमारे पास भी फुफफुस है अभी, अभी हृदय नहीं है। हृदय उस फेफड़े का नाम है, जो दूसरे संसार में श्वास लेना शुरू करता है। यह फेफड़ा तो इसी संसार में श्वास लेता है, यही ऑक्सीजन और कार्बन डायआक्साइड के बीच चलता है। एक और भी ऑक्सीजन है, एक और प्राणवायु है, एक और प्राणवान जीवन है, जब वह शुरू होता है, तो इसी फुफफुस के भीतर एक और हृदय है, जिसमें नई श्वास और नई धड़कन शुरू हो जाती है। वह धड़कन अमृत की धड़कन है। तो दूसरी बात है, विह्वलता। और तीसरी बात है, समर्पण। पहली बात है, यह जो चारों तरफ है, यह व्यर्थ हो जाए, तो ही आंख उठेगी। आंख उठे, कुछ दिखाई न पड़े; बीच में आदमी अटक जाए तो विह्वलता पैदा होगी; घबड़ाहट पैदा होगी; एक बेचैनी पैदा होगी।

## रीडर्स मेल

### खत्म हो बंदूक संस्कृति

अमेरिका का रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हत्या का प्रयास हुआ है। दो महीने में दूसरी बार। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने संदिग्ध की पहचान रयान वेस्ले राउथ के रूप में की है। अब कम-से-कम दोनों प्रमुख पार्टियों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या देश से बंदूक की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए या उसे उसी तरह रहने दिया जाए। 2023 में सामूहिक गोलीबारी की रिकॉर्ड संख्या के मद्देनजर सख्त अमेरिकी बंदूक कानूनों की बढ़ती मांगों के बीच में अप्रैल 2023 में, बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली अमेरिकी संस्था नेशनल राइफल एसोसिएशन (एनआरए) ने इंडियानापोलिस में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की थी, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने भाग लिया था और सभा को संबोधित भी किया था। अब ट्रंप को ये बताना चाहिए की उन्होंने उस बैठक के दौरान राइफल एसोसिएशन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों से क्या कहा था? मुझे लगता है वर्तमान चुनावी माहौल को खूनखराबा से दूर रखना है तो तुरंत देश में बंदूकों का उत्पादन, वितरण एवं बिक्री पर शिकंजा कसने का कानून पारित किया जाय। वरना आम अमेरिकियों का मरने का सिलसिला जारी रहेगा।

**जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर**

### सबक कब लेंगे

मेरठ के जाकिर कॉलोनी में हुए हादसे में एक ही परिवार के दस सदस्यों की मौत ने कमजोर नींव पर बने मकानों की वास्तविकता उजागर कर दी। ऐसी घटनाओं के लिए केवल प्रशासन या नगर निगम को दोषी ठहरा कर नागरिक अपने दायित्वों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। देश भर में बारिश के कारण जर्जर भवनों के धराशायी होने के अनेक समाचार प्रकाश में आते रहते हैं। इस हृदय विदारक घटना में दस लोगों की मौत उन लोगों के लिए सबक है, जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके अपना जीवन दांव पर लगाए हुए हैं। लिहाजा, हमें इस घटना से सबक लेकर समाज में जागरूकता फैलानी होगी।

**डॉ. सुधाकर आशावादी, मेरठ**

### इस्तीफे का दांव

भगत सिंह को अपना आदर्श बताने वाले केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद संभाला है तब से केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच तनातनी खत्म नहीं हो रही है। अब जबकि आबकारी नीति घोटाले मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कई कठोर शर्तों पर जमानत तो दे दी है, लेकिन कठोर शर्तों के कारण केजरीवाल अब नाम मात्र के मुख्यमंत्री हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न केवल मुख्यमंत्री कार्यालय से जाने से रोका, बल्कि उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर करने से भी रोक दिया। केजरीवाल को पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब उन्हें आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री कौन होगा?

**चंदन कुमार सिंह, सीवान**

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 34

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । मुंबई । मंगलवार, 17 सितंबर 2024

# शांति का इंतज़ार

**जब भी** ऐसा लगता है कि मणिपुर में हालात शायद कुछ बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, तभी करीब डेढ़ बरस से सुलग रही आग फिर भड़क उठती है। इस महीने की शुरुआत से राज्य में जिस तरह एक के बाद एक हिंसक घटनाओं का सिलसिला चला है, उसने चिंता और बढ़ा दी है। केवल मणिपुर ही नहीं, यह पूरे देश के लिए सोचने की बात है कि आखिर मई 2023 से शुरू हुए विवाद को अभी तक क्यों सुलझाया नहीं जा सका।

**अराजक तत्व |** राज्य में चल रहा विरोध-प्रदर्शन दिन-ब-दिन और हिंसक होता जा रहा है। अब रॉकेट और बम चल रहे हैं और पुलिस अफसरों को चिंता जतानी पड़ रही है कि सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ अत्याधुनिक घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा।


मणिपुर : आग बुझ ही नहीं रही

**घातक हथियार |** अगर प्रदर्शन आम लोगों और स्टूडेंट्स का है, तो ये हथियार कहां से आ रहे? पिछले दिनों राज्य के पहले मुख्यमंत्री के आवास पर रॉकेट से हमला हुआ था। इसी शनिवार को एक मंत्री के आवास पर ग्रेनेड अटैक हुआ। इन घटनाओं से पता चलता है कि राज्य में ऐसे तत्व सक्रिय हैं, जो हालात को सामान्य नहीं होने देना चाहते।

**विवाद के कई पहलू |** मणिपुर में शांति बहाली के लिए सभी पक्षकारों का किसी आम सहमति पर आना जरूरी है। वहां तीन पक्ष हैं - मैतेई, कुकी और नगा। यह विवाद शुरू हुआ था मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने की मांग के साथ। कुकी और नगा इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन, जिस तरह से इस विवाद में जंगल और जमीन का मुद्दा, अवैध प्रवासियों की समस्या, ड्रग्स का जाल और दूसरे कानूनी पहलू उभरते चले गए, उससे स्पष्ट है कि गतिरोध कई मोर्चों पर है और इन सभी पर काम किए जाने की जरूरत है।

**अपना फायदा |** एक बड़ी समस्या यह है कि हर पक्ष मणिपुर को बस अपनी नजर से देख रहा है। कुकी समुदाय को लगता है कि राज्य का मौजूदा नेतृत्व उनके साथ न्याय नहीं कर सकता। मैतेई समुदाय चाहता है कि राज्य सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बलों की कमान भी दे दी जाए। वहीं, तीसरा धड़ा यानी नगा समुदाय अपने लिए अलग प्रशासनिक ढांचे की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत उलझी हुई है, जिसे संवेदनशीलता के साथ सुलझाने की जरूरत है।

**बाहरी संकट |** पूर्वोत्तर ने लंबे समय तक उग्रवाद की मार झेली है। मौजूदा संकट से पुरानी समस्या के फिर सिर उठाने का खतरा पैदा हो गया है। इस ओर ध्यान इसलिए भी जाता है क्योंकि पड़ोसी म्यांमार में जुंटा को सत्ता संभालने में मुश्किल आ रही है। सशस्त्र विद्रोहियों की ताकत वहां बढ़ रही है। केंद्र की नजर इस पर जरूर होगी। म्यांमार की उथल-पुथल मणिपुर में कोई हलचल न मचाए, इसके लिए अपना घर जल्द से जल्द ठीक करना होगा।

## धूप-छांव

# छुपी हुई ताक़तें

प्रणव प्रियदर्शी

**वह योग** का एक कोर्स था, लेकिन बीच-बीच में वहां ऐसी भी चीजें मिलती रहीं जिनके बारे में कल्पना तक नहीं की थी। उन्हीं में से एक था यह नुस्खा कि जिंदगी को आकार और दिशा दे रही ताकतों की पहचान कैसे की जाए। आम तौर पर हम उन्हें भगवान और किस्मत जैसे शब्दों के जरिए व्यक्त करते हैं। दिक्कत इन शब्दों में नहीं है। लेकिन इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें तब भी हम वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक ये शब्द हमें ले जाना चाहते हैं। वे ताकतें उतनी ही अनजान, हमारी नजरों से उतनी ही ओझल रह जाती हैं। ऐसे में क्या करें?

वहां बताया गया कि जिन चीजों को हम नहीं समझ रहे होते, उनमें एक अलग तरह का रहस्य, एक अलग तरह का ग्लैमर जुड़ जाता है। पहले तो खुद को उस ग्लैमर से अलग करना जरूरी होता है, वरना सच सामने आ जाए तब भी हम उसे पहचान नहीं पाते। लगता है, यह सच इतना मामूली नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि उन ताकतों को देखने-पहचानने के लिए हमें अपनी नजरों में खुद की अहमियत कम करनी होगी। नुस्खा देते हुए कहा गया कि अगर आप इस क्लास में रोज वक्त पर पहुंचते हैं तो उसमें आपको कोई खास बात नहीं लगती। इसका सारा क्रेडिट अनजाने ही आप खुद को दिए रहते हैं। कोई पूछे कि कैसे आप रोज वक्त पर पहुंच जाते हैं तो 'मैं समय पर उठता हूं, वक्त पर निकलता हूं, लेट होना मुझे पसंद ही नहीं' जैसे जवाब मिलते हैं। ये गलत भी नहीं। लेकिन एक दिन आप आधा घंटा लेट हो जाइए और फिर देखिए जवाब- रात घर पर कुछ मेहमान आ गए थे, तो वक्त पर सोना नहीं हो सका, अलार्म नहीं बजा, ट्रैफिक जाम ने पूरी कसर निकाल दी...। पता नहीं कितनी वजहें आ जाती हैं सामने।

ये सारे फैक्टर लगभग रोज होते हैं, इनकी भूमिका भी होती है, पर हमारा ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता। ये सामने तब आते हैं जब दोष हमें अपने ऊपर से हटाना होता है। वरना ये परदे के पीछे से हमारे काम को आसान या कठिन बनाते रहते हैं, हम उनकी आसानी और कठिनाई के जरिए बनती-बिगड़ती-बदलती राह पर कदम बढ़ाते रहते हैं, पर नहीं समझ पाते कि कब इनकी वजह से हमारी राह मुड़ गई, कब हमारी मंजिल बदल गई। पूरा श्रेय हमारे हिस्से ही आता है सफर तय करने और मंजिल तक पहुंचने का।

खैर, नुस्खा अपनी जगह ठीक है, मगर सवाल अब यह है ये सारे फैक्टर छुपे भी रहें तो क्या दिक्कत है, राह चाहे जैसे भी बन-बिगड़ रही हो, उस पर बढ़ रहे कदम तो हमारे ही होते हैं!

## बोल वचन

# लंगर की दाल

राहुल पाण्डेय

**कल रात** एक मित्र को फोन किया तो पता चला कि साहब लंगर की लाइन में लगे हैं। मैंने पूछा तो कहने लगे कि लंगर में जितनी जायकेदार दाल मिलती है, वैसी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। लंगर की दाल वाकई किसी अमृत से कम नहीं होती। एक तो उसमें प्रेम का नमक होता है, और दूसरे पुण्य की हल्दी। धीमे-धीमे जैसे

AI Image


पकता है कोई सपना, वैसे ही धीमे-धीमे पकती है लंगर की दाल। लंगर शब्द अब दुनिया में अनजान नहीं रह गया है। आंधी-तूफान, भूकंप-बाढ़ हो या फिर मुल्कों के बीच युद्ध करते हुए नीचता के पाताल में जाने की होड़, लंगर सब जगह चलता है और सभी का पेट भरता है। आमतौर पर इसका अर्थ होता है सामूहिक रसोई, जहां सब मिलकर बनाते और खाते हैं। लंगर आश्रमों में चलता है, साधु-संतों के डेरों, मंदिरों में और जवानों की रसोई भी लंगर कहलाती है। लंगर शब्द संस्कृत से आया है, जहां इसे अनलगृह कहते हैं यानी रसोईघर। सबसे बड़ी उपलब्धि लंगर की यह है कि इसमें रूढ़िवाद, जात-पात और ऊंच-नीच को खत्म करने की ताकत है। सिखों में खास महत्व है लंगर प्रथा का। गुरु नानक देव शिष्यों के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। वहीं, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने जिस लंगर का शुभारंभ किया, वह आज तक अनवरत चल रहा है। लंगर इंग्लैंड में भी चलता है, जहां से इंग्लिश आई। वैसे इंग्लिश में भी यह लंगर ही है। इस लंगर तो नहीं, अंग्रेजी ने पानी के जहाजों में होने वाले लंगर के लिए शब्द जरूर बनाया है, एंकर। यह वाला लंगर जहाज को स्थिर करने के काम में आता है।

## ग़ुलामी के निशानों को पीछे छोड़ PM के नेतृत्व में उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा देश

# विकसित भारत का पूरा होगा संकल्प


स्वामी चिदानन्द सरस्वती

**प्रधानमंत्री नरेंद्र** मोदी को देश का शासन संभाले 10 वर्ष पूरे चुके हैं। इस दौरान हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में हुए कार्यों ने देश की सांस्कृतिक विविधता और महान सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित तो किया ही है, साथ ही इसे पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित भी किया है।

नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। बीते 10 वर्षों में देश की राजनीतिक संस्कृति में तो बदलाव आया ही है, कार्यसंस्कृति में बदलाव का भी सबने अनुभव किया है। महान संस्कृति और विरासत के प्रति भी लोगों में भाव जागा है जो आजादी के बाद और मोदी सरकार के आने के पहले कहीं खो गया था।

आज जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। आजादी के बाद से देश में राजनीति के केंद्र रहे राम मंदिर, तीन तलाक, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और नागरिकता कानून जैसे तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री ने स्थायी समाधान तक पहुंचाया। मोदी सरकार ने बीते एक दशक में सांस्कृतिक पुनरुत्थान, गरीब कल्याण और वैश्विक सम्मान का नया कीर्तिमान बनाया है।

पहले देश की सांस्कृतिक विरासत पर कई आघात हुए। देश के विभाजन के बाद न केवल हिंदू समाज को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी बल्कि हमारी महान संस्कृति को भी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वह माहौल बदला। उन्होंने देशवासियों को सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहरों पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को आम जीवन, विदेश नीति और विकास से जोड़ा, जो देश को न केवल एकसूत्र में पिरोता है बल्कि समाज के सभी वर्गों में समानता का सेतु भी बनाता है। काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम के माध्यम से पहली बार पीएम मोदी ने बताया कि सांस्कृतिक विविधता देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में कितनी कारगर साबित हो सकती है।



बीते वर्षों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, उज्जैन में भव्य श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण, अयोध्या में लाखों दीपों से प्रभु श्रीराम की विजय यात्रा का अभिनंदन, 500 वर्ष बाद भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य, जम्मू-कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार, पावागढ़ में भव्य मंदिर का निर्माण, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण, बुद्ध सर्किट का निर्माण, जैन सर्किट का निर्माण, सूफी सर्किट का निर्माण और केदारनाथ-बदरीनाथ-सोमनाथ धाम का विकास इसका प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है।

1600 वर्ष पुरानी धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान हुआ तो योग एवं आयुर्वेद का भी परचम लहराया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने योग को संपूर्ण विश्व के सामने प्रखरता से रखते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्यता दिलवाई। देखा जाए, तो यह वैश्विक पटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की सामूहिक स्वीकार्यता का पहला महत्वपूर्ण अवसर था।

जम्मू-कश्मीर के एक बड़े कालखंड के अंतराल के बाद सैकड़ों मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है। श्रीनगर में 700 साल पुराने मंगलेश्वर भैरव मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है। अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन हो चुका है।

यह एक विडंबना ही थी कि आजादी के वर्षों बाद भी हम उपनिवेशवादी मानसिकता को ढो रहे थे। कई शहरों, सड़कों, कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और यहां तक कि देश

**मोदी का नेतृत्व खास**
- विरासत को लेकर जागरूकता बढ़ी
- विविधता में एकता का नया स्वरूप
- औपनिवेशिक प्रतीकों से छुटकारा

की शिक्षा प्रणाली पर भी उपनिवेशवाद की छाप थी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने का प्रण लेते हुए इस पर कार्य शुरू किया। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली जिस सड़क का नाम किंग्सवे रखा था, उसे बदलकर उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया। भारतीय नौसेना के ध्वज से भी औपनिवेशिक काल के सेंट जॉर्ज क्रॉस को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर से प्रेरित प्रतीक से बदला गया, इसी तरह इंडिया गेट से करीब 150 मीटर पर मौजूद कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जहां पहले किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। इस सबसे आगे बढ़ कर प्रधानमंत्री आवास रेस कोर्स रोड को बदल कर लोक कल्याण मार्ग का नाम दिया गया। ये केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि भाव का परिवर्तन था।

मोदी सरकार ने देश को भारतीयता के विचार से ओत-प्रोत नया संसद भवन दिया, जिसमें भारत की महान सभ्यता की विरासत के अंश के तौर पर सेंगोल को स्थापित किया गया। मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश करते हुए भाषाओं के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। कोई भी युवा भाषाई जटिलता के कारण तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहे इसका विशेष ध्यान रखते हुए नई शिक्षा नीति के तहत कई राज्यों मे इंजिनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा भी हिंदी भाषा में प्रारंभ की जा चुकी है।

भारत से अंग्रेजों के जाने के 70 वर्षों बाद भी उनके बनाए गए कानून न्यायालयों में बरकरार रहे। ऐसे कई कानून ब्रिटिश राज में भारतीयों के शोषण के औजार थे। गुलामी के हर प्रतीक को समाप्त करने की दिशा में इस सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के रूप में देश को स्वदेशी कानून दिए हैं, जिनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि अपराध रोकना है।

आजादी के अमृत काल में सरकार के इन प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिल रही है। आज देश का युवा अपनी भाषा, संस्कृति और महान विरासत पर गर्व कर रहा है। देश के सांस्कृतिक जागरण के इस महायज्ञ के अग्रदूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत के साथ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

*(लेखक प्रसिद्ध धर्मगुरु और ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष हैं)*

# गणपति दर्शन करेंगा, तबी कुछ मिलेंगा


दीपक पाचपोर

**अबी अपुन** अपना खास फ्रेंड बाबूराव का बोल बच्चन सुनेला। वो कहताए, 'इदर अपुन का इंडिया में रहेंगा तो तुमकूं कबी बी कंटाला नई आएंगा। बोले तो बोर नईं होने कूं सकताए। तुम कबी बी अक्खा साल का कैलेंडर देखने का। पैला जनवरी से धमाल चालू हो जाएंगा। पूरा साल चलेंगा। पैले नवा साल, फिर संक्रांत, बरस का भीतर दो-दो नवरात्रि, उसका बीच में बोले तो राखी, गणेशोत्सव, बाद में दसरा, दीवाली, हैप्पी न्यू ईयर। एक का पीछू दूसरा प्रोग्राम आएंगा तबी तुमकूं सोचने का टाइम भी नईं मिलेंगा!'

इत्ता प्रवचन सुनके अपुन समज गएला कि अबी बाबूराव कूं नईं रोकेंगा तो उसका फास्ट ट्रेन लास्ट स्टेशन पेईच जाके रुकेंगा। इस करके अपुन उसकूं बोला, 'बॉस, थोड़ा दम लेने का! पैले तुम थोड़ा अपुन कूं बताएंगा कि तुम इत्ता बोल बच्चन करताए उसका आगे कूं, पीच्छे कूं कुछ होताए कि नहीं? तुमारा पास कोई काम का बात होएंगा तबी कैने का। खाली पीली इदर अपुन का टाइम खोटी नईं करने का।'

वो अईसाए भिड़ू, कि अपुन का कंट्री का भीतर भौत सा अईसा लोग होएंगा जिसकूं कबी बी शांति नईं मिलताए। अपना भेजा खराब करेंगा अऊर दूसरा लोग का बी दिमाग का दही बनाएंगा। बाबूराव वोईच केटेगरी का होताए। उस दिन बाबूराव नवा बोल बच्चन किएला। वो कहताए, 'भिड़ू, तुम इत्ता बरस का हुएला। इदरईच बड़ा हुआ, काम-धंधा किएला, पन जबी भी गणपति का सीज़न आताए, तुम कोई ना कोई गणेश मंदिर नईं तो मंडल का भीतर दर्शन करने

AI Image


**खाली पीली**

कूं जाताए कि नईं?' अपुन बोला, 'बिलकुल जाताए, बॉस। काएंकू नईं जाएंगा? अक्खा पब्लिक कुछ न कुछ गणपति बाप्पा से मांगताए। अपुन बी मांगताए।'

बाबूराव- तुमकूं अपुन बताताए कि कोई बी भौत सारा पंडाल में काएंकू जाताए। बोले तो सबका अलग-अलग डिमांड होताए। कोई कूं नोकरी मांगताए कोई-कोई कूं घर मांगताए, कोई छोकरा कूं अच्छा नंबर से पास करने का रिक्वेस्ट करेंगा, कोई कूं उसका छोकरी का जल्दी सादी करना मांगताए। भौत सा लोग अईसा होएंगा कि उसका डिमांड का जास्ती लम्बा लिस्ट होएंगा। अबी वो एकईच पंडाल का गणपति से सब मांगेंगा तबी उसकूं कित्ता देरी लगेंगा। सब लोग जास्ती देर रुकेंगा तबी उदर गर्दी हो जाएंगा। इस करके तुमारा डिमांड का लिस्ट पाकिट में रखने का अऊर अलग-अलग पंडाल में जाके अपना डिमांड एक-एक करके रखने का। अबी तुम पूछेंगा कि कऊन सा डिमांड कौन सा पंडाल में जाकर गणपति का आगे रखने का। अईसाए बॉस, पैले समज के लेने का कि उदर गणेश भगवान बईठाएला कऊन। अबी तुमकूं कोई इंडस्ट्री में सप्लाई का काम मांगताए, तबी देखने का कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किदर कूं गणेश बईठाएला। तुमकूं कोई ठेका मांगताए तबी देखने का कि गौरमेंट का कोई सीनियर हॉफिसर किदर कूं गणेश बईठाएला। डयरेक्टर, एक्टर लोग भी गणेश बैठाताए। पिक्चर नईं तो सीरियल का भीतर कोई काम मांगताए तबी उसका गणेश दर्शन करने का। किदर हॉस्पिटल का काम पड़ताए तबी डॉक्टर का गणेश खोजने का।"

अबी तुम सोचेंगा कि अईसा जगा पे तुम काम का बात कईसा करेंगा। अपुन बताताए कि तुमकूं जास्ती बात नईं करने का। बस, आंख बंद करके आरती करने का अऊर दक्षिणा देने का। भाई लोग श्याणा होताए। सबकूं पताए कि किसका किदर लोचा होताए, कऊन इदर दर्शन करने का वास्ते आएला अऊर कऊन प्रसाद लेके आएला। बोले तो जास्ती लोग इस करके गणेश भगवान बैठाताए कि उसकूं काम का लोग मिल जाएंगा।

**शेयर करें अपने अनुभव**
आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-**'खाली पीली'**

## विशुद्ध राजनीति
### पॉलिटॉक

### यूं शांत हुआ पूजा विवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों गणेश पूजा के मौके पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो उस पर सियासत होने लगी। विपक्ष के एक धड़े और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे मुद्दा बना दिया। इसे संविधान



विरोधी बताया गया। कहा गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं, इस मामले में संविधान की धारा का भी हवाला दिया गया। हालांकि, सरकार की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। उधर, विपक्ष के अंदर ही इस मुद्दे पर दो राय रही। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों में एक वर्ग ऐसा रहा, जिन्हें लगा कि पीएम के चीफ जस्टिस के घर जाने पर ओवररिएक्ट किया गया। वे इसे मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं थे। DMK ने तो आधिकारिक रूप से बयान देकर चीफ जस्टिस को समर्थन दिया। पार्टी सांसद विल्सन ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि यह ऐसा मामला नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस की आलोचना की जाए। कई दूसरे विपक्षी दल भी इस विवाद से अलग रहे। कांग्रेस के अंदर कई नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान न दे। यही कारण है कि मुद्दा उठने के बाद एक-दो दिनों में शांत भी हो गया।

### JDU की परेशानी

बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे और उसे डिजिटल करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर राज्य में बहुत सरगर्मी है। लोग इसे लेकर शिकायत भी कर रहे हैं। सबसे पेचीदा काम है कागज जुटाना। नीतीश सरकार की योजना है कि एक साल में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए। जो जमीन सरकार के हिस्से आएगी, उसे गरीबों के बीच बांटा जाएगा। सरकार ने भूमिहीनों के लिए पिछले दिनों एक योजना भी लॉन्च की थी। लेकिन, जिस तरह इस अभियान को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है और स्थानीय स्तर पर जमीन सर्वे के नाम पर करप्शन की शिकायतें मिल रही हैं, उससे JDU नेतृत्व को चिंता होने लगी है।



अब पार्टी इस काम पर तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहती। साथ ही, इसमें अधिकारियों का हस्तक्षेप कम चाहती है। पार्टी चाहती है कि यह काम अभी या तो रोक दिया जाए या ऐसा प्रावधान हो, जिसमें लोगों को अपनी जमीन के रेकॉर्ड डिजिटल कराने के लिए बहुत अधिक कागजात की जरूरत न पड़े। दरअसल, पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि सर्वे पूरा होने के बाद गरीबों को जमीन देने की योजना तो बड़ी है, लेकिन कहीं इससे उसकी साख न प्रभावित हो जाए।

### हुड्डा ही किंग

हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को टिकट वितरण में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। राज्य में पार्टी पहले ही कई खेमों में बंटी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी हुड्डा कैंप को लेकर। इस बार भूपेंद्र हुड्डा ने साफ संकेत दे दिया कि वह समझौता नहीं करेंगे। टिकट वितरण में वह अपने लोगों को जगह दिलाने के लिए वीटो लगाते रहे। उनके पक्ष में एक बात यह भी रही कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में उनके चुने लोगों की स्थिति मजबूत दिख रही थी। इसका असर यह हुआ कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए सबसे अधिक टिकट हुड्डा कैंप के नेताओं को मिले। पार्टी के एक नेता ने बताया कि लगभग 75 उम्मीदवार हुड्डा के करीबी हैं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला सहित केंद्रीय नेतृत्व को बाकी सीटों पर ही अपने लोगों को एडजस्ट करवाना पड़ा। दरअसल, हुड्डा ने इस बार केंद्रीय नेतृत्व से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पिछली बार की तरह किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पिछली दफा पार्टी इसी वजह से बहुत करीब रहकर भी सत्ता से दूर हो गई थी। साथ ही, हुड्डा ने यह संकेत भी दिया है कि यह उनका अंतिम टर्म है और इसके बाद वह नई पीढ़ी को सत्ता सौंप सकते हैं। दिलचस्प बात है कि पार्टी ने अशोक गहलोत को वहां ऑब्जर्वर बनाया है, जो हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं।

### 'दिल्ली नहीं, श्रीनगर का हूं'

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार नैशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने पूरी ताकत लगा दी है। उन्हें पता है कि अगर इस बार सत्ता में आने में विफल रहे तो उनके लिए आगे की राह बेहद कठिन हो जाएगी। श्रीनगर में उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनने लगी है



जो दिल्ली की आबोहवा में रहना अधिक पसंद करता है। उनके बारे में यह धारणा भी बनी है कि आम लोगों से मिलना और उनके बीच आना-जाना उन्हें अधिक पसंद नहीं, और उनमें ईगो है। इस छवि को तोड़ने में उमर जी-जान से लगे हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान वह अधिक से अधिक लोगों से मिल रहे हैं और उनसे माफी भी मांग रहे हैं। उमर जनता को बता रहे हैं कि वह दिल्ली नहीं, बल्कि उनके अपने श्रीनगर के हैं। वह अपनी टोपी को सामने कर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। उनका यह बदला रूप चर्चा का विषय बना हुआ है।

### आरक्षण पर BJP की दुविधा

आरक्षण मसले पर BJP के बीच दुविधा है। वह विपक्ष के हमले का जवाब तो देना चाहती है, लेकिन यह नहीं चाहती



कि यह बहुत बड़ा मुद्दा बने। दरअसल, पार्टी को अपने कोर वोटर, मिडल क्लास और सवर्ण वर्ग की भी चिंता है। पार्टी को लगता है कि अगर वह आरक्षण के मुद्दे पर बहुत आक्रामक रूप से आगे बढ़ेगी, तो उसका प्रतिकूल असर उसके पारंपरिक कोर वोट बैंक पर पड़ सकता है। पार्टी के एक नेता के अनुसार, भले नंबर के हिसाब से इन वर्गों की संख्या कम हो, लेकिन नैरेटिव को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं।

## रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

**■ नजरिया साफ**
**16 सितंबर** का संपादकीय 'इस्तीफे का असर' पढ़ा। शराब घोटाले में अदालत का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भले ही इस्तीफे का एलान कर सबको चौंकाया है, लेकिन परदे के पीछे की राजनीति कुछ और कहती है। सवाल उठ रहा है, क्या हरियाणा चुनाव में AAP इस स्थिति को भुनाना चाहेगी? अभी के हालात में I.N.D.I.A. के साथ रिश्ते बेहतर रखना केजरीवाल की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हरियाणा चुनाव लड़ने में उनका नजरिया साफ रहेगा। राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल का कद जो भी हो, पर उनके इस इस्तीफे की पेशकश ने उन्हें ऊंचा अवश्य किया है।
**अमृतलाल मारू,** ईमेल से

**■ बोली की कीमत**
**3 सितंबर** को 'खाली-पीली' कॉलम में 'बोल बच्चन करेंगा तबी ऊंचा पोस्ट मिलेंगा' शीर्षक से प्रकाशित लेख में **खाली पीली** दिलचस्प अंदाज में किसी दफ्तर के माहौल को पेश किया गया है। जिसके पास बोलने की कला हो, वह अपना काम किसी तरह से निकाल ही लेता है। सच्ची मेहनत और ईमानदारी के बजाय अपनी बोली के दम पर उच्च पद पाने या अपनी स्थिति को मजबूत करने वाले लोगों की कमी नहीं है।
**कृतिका झा,** ईमेल से

**■ इनकी सुध लें**
**14 सितंबर** को 'दो दूनी चार' कॉलम में 'प्राइवेट में पेंशन' शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ा। प्राइवेट नौकरी करने वाला सिर्फ उन्हें ही समझा जाता है जो EPFO में रजिस्टर्ड हैं, जिनका फंड कटता है, जिन्हें ESI की सुविधा है। इनके अलावा दुकानों, फैक्ट्रियों जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों का नाम कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता और न ही इन्हें जरूरी सुविधाएं मिल पाती हैं। फर्म जानबूझकर अपने यहां 10 से कम कर्मचारी दिखाते हैं, ताकि सुविधाएं न देनी पड़ें। इन कर्मचारियों को लेबर एक्ट का साथ नहीं मिल पाता है। सरकार इनकी सुध ले।
**चंद्र प्रकाश शर्मा,** ईमेल से

**nbtedit@timesofindia.com** पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

**अंतिम पत्र**
**हरियाणा में** किसानों ने कहा, चुनाव में न मदद, न ही विरोध - एक खबर
- किसानों को नेताओं पर नहीं, अपने खेतों पर भरोसा!
**दीप्ति अग्रवाल**

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

# मशीनों की क़द्र करें, विश्वकर्मा की यही असली पूजा

हरीश बड़थ्वाल

**यात्रा हवाई** हो या समुद्री, जोखिम हमेशा बना रहता है। मशीनें कब बिगड़ जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसी तरह के जोखिम सड़क और रेल मार्ग से यात्रा में भी होते हैं। यह तब है जब वाहन का हरेक पुर्जा दक्ष हाथों से बना होता है, कई बार टेस्टिंग होती है उसकी। इन हालात में हम उस महाशक्ति की तरफ देखते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं, जो पूरी दुनिया को चला रही। हमें सदा उस शक्ति की कृपा की जरूरत महसूस होती रहती है।

इसी अंदाज में आज देशभर में मनाई जा रही विश्वकर्मा पूजा को समझना होगा। आखिर हम सभी यंत्रों पर सवार तकनीकों के महासागर की यात्रा पर जो हैं। आदि ग्रंथों में चराचर सृष्टि के सृजन का मुख्य दायित्व ब्रह्मा का माना गया है। लेकिन, सांसारिक सरोकारों के संदर्भ में विचार करें तो विश्वकर्मा की भूमिका कमतर न थी। ब्रह्मा और विश्वकर्मा, दोनों की गणना देवों में होती है। सर्वोच्च वास्तुकार या शिल्पी के रूप में विश्वकर्मा की प्रतिष्ठा को लेकर विद्वान एकमत हैं। देवताओं के समस्त रथों और शस्त्रों के निर्माण का श्रेय उन्हीं को है। इंद्रदेव का वज्र उन्होंने ही बनाया। विश्वकर्मा वास्तु, हस्तकलाओं और कौशल के पितामह थे। चारों युगों में कालजयी लंका, जगन्नाथ मंदिर पुरी, द्वारका और इंद्रप्रस्थ की वास्तुकारी विश्वकर्मा की देन है। उनके चार हाथों वाली आदिकालीन मूर्तियों के कारण उन्हें सृजनशीलता में ब्रह्मा के समकक्ष माना जाता है।

कालांतर में यंत्रों के अधिष्ठाता के रूप में पूजे जाने वाले विश्वकर्मा की छवि शिल्पियों और यंत्र कर्मियों के इष्टदेव तक सिमट गई है। लेकिन, विश्वकर्मा पूजा का एक बड़ा बेहतरीन और तर्कसंगत महत्व यह है कि इस दिन सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों और फैक्ट्रियों में, विशेषकर मशीनों पर काम करने वाले कर्मचारी यंत्रों और मशीनों की साफ-सफाई करते हैं। काम करने की जगह को संवारा, सजाया जाता है। फिर विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इस दिन यंत्रों-औजारों को विश्राम देते हैं। उनसे कोई काम नहीं लेते। यह दिन होता है उनकी आराधना का।

विश्वकर्मा पूजन निजी वाहनों और अन्य मशीनों की सुध लेने का खास दिन बन रहा है। मशीनों का रख-रखाव ऐसा अनिवार्य कार्य है, जिसके लिए रोजमर्रा के शिड्यूल में स्थान रखा जाना चाहिए अन्यथा एक दिन यकायक बड़ी मुसीबत आ सकती है। वाहन चलाने वाले रोज याद करें, पिछली बार वाहन स्टार्ट करते समय क्या उन्होंने दिशा-निर्देशों के अनुसार इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, टायर की हवा चेक की थी। मशीन चाहे आपके कार्यस्थल की हो या घर के इस्तेमाल की, उसकी कद्र करें। इसकी नियमित संवार से आप इसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। इसे सहेज कर रखेंगे तो यह धोखा नहीं देगी, साथ निभाएगी।

दैनिक जीवन में नई-नई टेक्नॉलजी आने के साथ नए-नए यंत्रों का समावेश हो रहा है। बेहतरीन शिल्पकारी में दूरदृष्टि, बुद्धि और कौशल का गठजोड़ रहता है। विभिन्न उपकरणों के सुचालन के लिए प्रशिक्षण के साथ कौशल के महागुरु विश्वकर्मा की कृपादृष्टि भी जरूरी है। इसलिए आज की पूजा उनके प्रति आस्था और आभार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति है।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

## प्रेरणा

सपने देखने का अधिकार पहला मौलिक अधिकार होना चाहिए। - **महाश्वेता देवी**, सामाजिक कार्यकर्ता

## संपादकीय

# आम जनता की तर्क शक्ति बेहतर होती जा रही है

**आरोप** में फंसे नेताओं या दलों को अक्सर कहते सुना जा सकता है, 'जनता की अदालत में फैसला होगा'। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि तो है, लेकिन उसका हर फैसला शाश्वत सत्य नहीं होता। इसीलिए तमाम संस्थाएं बनाई गई हैं। फिर जनमत धारणा से बनता है और धारणा निर्माण के टूल्स के रूप में नेता, उसकी भाषण-कला, उसकी नीतियां, यानी वादों पर जनता का भरोसा होता है। किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों का सत्य धारणा का मोहताज नहीं होता। उसके लिए कानून, उसे अमल में लाने वाली संस्थाएं और आरोप का सत्य सिद्ध करने वाली न्यायपालिका अपना काम एक जटिल और विशेष ज्ञान की व्यवस्था के तहत करती हैं, जिसे 'अपराध न्यायशास्त्र' कहा जाता है। लिहाजा शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम का यह दावा कि वह जनता की अदालत जाएंगे, एक गंभीर तार्किक दोष है। संविधान में ऐसी किसी भी अदालत का जिक्र नहीं आता। फिर सीएम को याद होना चाहिए कि हाल के लोकसभा चुनावों में तो उन्होंने जनता से अपील की थी कि उनकी पार्टी को जिताएं तो वह जेल जाने से बच जाएंगे, लेकिन जनता ने उन्हें सभी सातों सीटों पर हराया। तो क्या यह माना जाए कि तीन माह पहले वह जनता की अदालत से हार चुके हैं? इसी जनता ने उनकी पार्टी को विधानसभा चुनावों में जबरदस्त समर्थन दिया, लेकिन लोकसभा चुनावों में वही समर्थन नहीं मिला। सीएम जनता का कौन-सा फैसला उनकी अपराध-मुक्ति का फैसला मानेंगे? इमरजेंसी लगाने से लोग कांग्रेस और इंदिरा गांधी से नाराज थे, लिहाजा पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन कुछ महीनों में ही जनमत एकदम उलटा आया और कांग्रेस सत्ता में आई। तो कौन-सा सत्य जनता की अदालत का माना जाए? नेताओं को अपने को निर्दोष बताने के लिए अच्छा तर्क देना होगा क्योंकि जनता की तर्क-शक्ति बेहतर हो रही है।

**बामुलाहिजा** • पहचान की छोटी और बड़ी राजनीतियों के परस्पर संघर्ष में पिस रहा है पूर्वोत्तर का राज्य...

# कई बुरे फैसलों की जलती हुई मिसाल है मणिपुर

**नॉर्थ-ईस्ट**

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
@ShekharGupta

**सरकार** की नीतियों पर पिछले दशक में जो भी बहसें हुई हैं, उनमें 'मजबूत' विशेषण का जमकर प्रयोग किया गया है। लेकिन मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा है? अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो यही कहेंगे कि इस सरकार ने मणिपुर मसले पर 'मजबूती' से कार्रवाई की है। वहीं सरकार के आलोचक इस मसले को इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताएंगे। लेकिन हम अगर यह कहें कि इस सवाल का जवाब इन दोनों विचारों से अलग है, तब आप क्या कहेंगे? और यहां यह घिसा-पिटा तर्क भी नहीं पेश किया जा रहा है कि इन दोनों विचारों में कुछ-न-कुछ सच्चाई तो है ही।

उपरोक्त सवाल का जवाब यह है कि मणिपुर मसला इस क्षेत्र को लेकर भाजपा की जापानी मार्शल आर्ट 'जिउ-जित्सु' मार्का राजनीति का इस्तेमाल करते हुए शासन चलाने की अनूठी मिसाल है। इसमें अगर पहचान की कोई छोटी सियासत चुनौती के रूप में सामने आती है तो उसका मुकाबला पहचान को लेकर एक बड़ी सियासत से किया जाता है। 'जिउ-जित्सु' युद्धकला में आप प्रतिद्वंद्वी की ताकत और शारीरिक रचना का ही इस्तेमाल करके उसे हराते हैं। भाजपा के मुताबिक मणिपुर में अभी काम जारी है। लेकिन जो काम हो रहा है, उससे हालात सुधरे नहीं, और बिगड़े ही हैं। फिर भी पार्टी काम जारी रखने पर आमादा है। उसके विचार से कांग्रेस ने उत्तर-पूर्व और खासकर जनजातीय राज्यों में पिछले दशकों में पहचान की सियासत में भारी भूल की। इस तरह की बातें मैं उत्तर-पूर्व में काम कर चुके आरएसएस के कई नेताओं (जो अब काफी वरिष्ठ हो चुके हैं) से ही नहीं, बल्कि भाजपा के भी कुछ नेताओं या सरकार के कुछ लोगों से भी सुन चुका हूं, जो अब भी वहां की जा रही कार्रवाई से कम-से-कम दूर से भी जुड़ने को राजी हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने आग का मुकाबला आग से नहीं किया। उसने जनजातीय समूहों और ईसाई प्रभावों को मजबूत होने दिया। अलगाववाद को कुचलने के लिए केंद्रीय ताकत का इस्तेमाल तो किया मगर राजनीतिक रूप से 'स्थानीय' तत्वों को छूट दी। और यह नीति भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में कांग्रेस की 'दोषपूर्ण' समझ का नतीजा थी। वह हिंदू धर्म और व्यापक हिंदू बहुमत को इस राष्ट्रीय आकांक्षा की अभिव्यक्ति से काटकर रखने के प्रति इतनी प्रतिबद्ध थी कि उसने कई गहरे जख्मों को और गहरा होने दिया और भारत को उसकी संकटग्रस्त उत्तर-पूर्वी सीमाएं सौंप दीं।

हम इस तर्क को और सरल रूप में पेश करते हुए कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए छोटी एवं स्थानीय पहचानों की सियासत की और उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके ये समस्याएं हमारे लिए छोड़ दीं। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विविधता काफी खूबसूरत और आकर्षक है लेकिन अगर उसे हम हिंदू नजरिए से देखेंगे तो वह राष्ट्रहित के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसी गहरी समस्या को दूर करने में समय लगता है। इस बीच कुछ झटकों के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

मणिपुर के संकट को भी ऐसी ही एक समस्या में गिनिए, लेकिन यह भी देखिए कि हम वहां कर क्या रहे हैं। छोटी पहचान (कुकी-ईसाई-म्यांमारी) को बड़ी पहचान (मैतेई-हिंदू-भारतीय) से लड़ा रहे हैं। और हर

**परिणाम बुरे ही रहे हैं...**

**2014 के बाद से भाजपा ने पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले में केंद्र के रुख में एक वैचारिक बदलाव किया है। लेकिन परिणाम अब तक बुरे ही साबित हुए हैं। मणिपुर इसकी जलती हुई मिसाल है। लेकिन भाजपा के लिए यह उसकी ओर से जारी काम का एक हिस्सा है।**

किसी को पता है कि केंद्र किसके पक्ष में है। आप पहचान की सियासत करना चाहते हैं तो स्वागत है। लेकिन तब बेशक आप कुछ समस्याओं में उलझ जाते हैं। सबसे ताजा समस्या तो मणिपुर के मुख्यमंत्री स्वयं हैं, जो हिंदू हैं और भाजपाई खेमों में उनके बारे में कानाफूसियों में यही कहा जाता है कि 'मैतेई लोगों के तो अब वे ही भगवान हैं'। वे राज्यपाल को ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की कमान उन्हें सौंपी जाए, जबकि उनके दामाद इन बलों को वापस बुलाने की मांग कर चुके हैं। मुझे तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने उसी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए राज्यपाल से यह मांग की हो कि केंद्रीय बलों की कमान उसे सौंपी जाए; और दूसरी ओर, परोक्ष रूप से उन बलों को वापस बुलाने की भी मांग की हो। उनकी मंशा को समझिए। वे कह रहे हैं कि अगर आप यह चाहते हैं कि हम मैतेई हिंदुओं और कुकियों की लड़ाई लड़ें तो यह हमारे भरोसे छोड़ दीजिए; हमारे पास हथियार हैं, लोग हैं और पूरी तैयारी है, केवल केंद्रीय बलों को हमारे रास्ते से हटा लीजिए। यहां पर हमारा यह सवाल फिर उभरता है : यह एक ताकतवर सरकार है या एक कमजोर सरकार है?

यह खुद को तब जरूर ताकतवर महसूस करती होगी, जब उसके दायरे में यह मांग मजबूती से उठ रही है कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि उसके खिलाफ वहां लोग गुस्से में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही वे प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे हैं। वहां के राज्यपाल भी संविधान की शान को बहाल करने के लिए बागडोर अपने हाथों में लेने को तैयार हैं। इसके बरअक्स, पश्चिम बंगाल की आबादी के 5 प्रतिशत के बराबर आबादी वाले एक राज्य के उसके ही मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय बलों की कमान मुझे सौंपिए या उन्हें वापस बुलाइए!

मणिपुर के मामले में भाजपा का सियासी नजरिया यह है कि यह राज्य हथियारबंद विदेशी (म्यांमारी) घुसपैठी ईसाई कुकी जनजातीय समूहों के हमलों का शिकार है, और उसकी सरकार वहां के मुख्यतः कमजोर हिंदू मैतेई बहुसंख्यकों की सुरक्षा का काम कर रही है। भले ही उनकी आबादी कुकियों से तीन गुना अधिक क्यों न हो। इस लड़ाई को रोकने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

## जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

# जन्म और मरण के बीच की एक घटना है जीवन

**ये** जन्म-मरण का चक्कर अच्छे-अच्छे समझदार लोगों को भी समझ नहीं आता। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत लिखा गया। और तो और श्रीराम ने कहा, 'संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे।' रामजी भरत को कह रहे हैं, 'मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ते।' संत के गुण यानी अच्छी बातों को जीवन में उतारना और करना। असंत के गुण यानी गलत बातें करना। इनको समझेंगे, तो जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अब यह चक्कर क्या है? असल में लोग इसे समझ नहीं पाते। न तो जन्म हमारे हाथ में है, न मरण हमारे हाथ में है, पर होना दोनों ही है। जन्म और मरण के बीच में एक घटना घटती है, जिसको जीवन कहते हैं। श्रीराम उस जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं कि जीवन को समझो। जीवन के लिए निर्णय लो। कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा, 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज', 'सर्वधर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा।' ये जो मुक्त करना है, यही जीवन को समझना है। तो राम और कृष्ण कहते हैं, निर्णय लो, हमारे प्रति समर्पित हो जाओ। जो अपने से ऊपर एक परमशक्ति ईश्वर को मानता है, वो इन झंझटों से बच जाता है।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

**विश्लेषण** • दस साल की एंटी-इन्कम्बेंसी से जूझ रही भाजपा के सामने इस बार के चुनावों में कड़ी चुनौती

# हरियाणा में पहलवान, किसान और जवान मुख्य मुद्दे हैं...

**सियासत**

संजय कुमार
प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
sanjay@csds.in

**पिछले** एक दशक से हरियाणा में सत्ता पर काबिज भाजपा के सामने इस बार कड़ी चुनौती है, क्योंकि मतदाताओं में भाजपा के प्रति नाराजगी है। कांग्रेस को फायदा हो सकता है, हालांकि कई छोटे क्षेत्रीय दल अकेले या गठबंधन में मैदान में हैं। जननायक जनता पार्टी (हाल तक हरियाणा में भाजपा सरकार में सहयोगी) अब चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी के साथ गठबंधन में है और बसपा, इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लगभग सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अधिकतर सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने का अच्छा मौका इसलिए है, क्योंकि उसे सत्ता विरोधी वोटों का सबसे बड़ा फायदा होगा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस को इस समय हरियाणा के मतदाताओं के बीच अच्छा समर्थन प्राप्त है। 2024 के लोकसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन इसका प्रमाण है। क्षेत्रीय दल भले ही महत्वपूर्ण संख्या में सीटें न जीत पाएं, लेकिन अगर भाजपा विरोधी वोट बंटते हैं तो वे कांग्रेस के लिए खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं।

हरियाणा में भाजपा केवल एंटी-इनकम्बेंसी के कारण ही अपने को मुश्किल स्थिति में नहीं पाती है, उसके लिए यह भी नुकसानदायक हो सकता है कि टिकट न मिलने से पार्टी के नेताओं में बड़े पैमाने पर नाराजगी है और वे दलबदल कर रहे हैं। चुनाव से पहले अभी तक तीन दर्जन से अधिक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें से कुछ तो गैर-जाट समुदायों में भाजपा की रीढ़ रहे हैं। इस रणनीति को ही भाजपा ने पिछले एक दशक के दौरान सफलतापूर्वक अपनाया था। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले पांच सालों में हरियाणा में भाजपा के जनाधार में गिरावट आई है। लोकसभा चुनावों में भाजपा 46.1% वोटों के साथ 10 में से 5 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि कांग्रेस 43.7% वोटों के साथ शेष 5 सीटें भाजपा से छीनने में सफल रही। भाजपा के वोट-शेयर में 12% (2019 की तुलना में) की गिरावट आई, जबकि कांग्रेस ने 2019 के अपने वोट-शेयर में 15.3% वोट जोड़े। ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा में हवा किस तरफ बह रही है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के कुछ महीने बाद जब 2019 में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो भाजपा ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। उसे 36.5% वोट और 40 सीटें मिली थीं। हरियाणा के मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 10 सीटों पर जीत दिलाई थी, लेकिन राज्य में अपनी सरकार चुनने के लिए अलग तरीके से मतदान करने का फैसला किया। जबकि तब तो पहलवान, किसान और जवान के मुद्दे भी मौजूद नहीं थे। तब जनता में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रदर्शन को लेकर नाराजगी थी। अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद 2019 के विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल नहीं कर सकी, तो अब अपने प्रदर्शन में सुधार कैसे करेगी? 2019 में जब भाजपा हरियाणा में अपनी सरकार का बचाव कर रही थी, तो उसे पांच साल की एंटी-इन्कम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा था। अब तो 10 साल पुरानी एंटी-इन्कम्बेंसी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना एक तरह से भाजपा द्वारा लोगों की नाराजगी को स्वीकार करना था। चुनाव में भाजपा को कुछ हद तक सजा मिली। नतीजों के बाद भी वोटरों का मूड बदला हुआ नहीं दिख रहा है।

हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा की निर्भरता की भी परख होने वाली है। लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की अपने व्यक्तिगत करिश्मे के दम पर भाजपा के लिए वोट जुटाने की क्षमता विधानसभा चुनावों की तुलना में लोकसभा चुनावों में कहीं ज्यादा मजबूत होती है। दूसरी तरफ 2019 के मुकाबले अब हरियाणा में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसका राज्य-नेतृत्व (भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा) अलग-अलग समूहों में विभाजित होने के बावजूद मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी वाले भाजपा के राज्य नेतृत्व की तुलना में अधिक सशक्त दिखता है। इससे कांग्रेस बेहतर स्थिति में जरूर है, लेकिन कुछ सीटों पर उसके वे नाराज नेता जरूर खलल डाल सकते हैं, जो टिकट नहीं मिलने से क्षुब्ध हैं। कांग्रेस को इस पर नजर रखना होगी और पार्टी में भितरघात सहित छोटे क्षेत्रीय दलों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनानी होगी। पहलवान, किसान और जवान : ये तीन मुद्दे हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की कुंजी साबित हो सकते हैं।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

## आपकी राय

अखिलेश आर्येन्दु,
लेखक और पत्रकार

# लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव तक सीमित करके न देखें

**15** सितंबर 2008 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में लोकतंत्र की चर्चा करना मौजूं है। अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र पर प्रसिद्ध कथन है कि लोकतंत्र वह है जो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की इससे बेहतर परिभाषा शायद नहीं हो सकती, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई में दुनिया के देशों में जो लोकतंत्र हैं, वह लोकतांत्रिक मूल्यों व सिद्धांतों के अनुसार ही संचालित हो रहे हैं? यदि ऐसा है, तो लोकतांत्रिक देशों में गैर बराबरी, हिंसा, अन्याय, शोषण और तरह-तरह के वाद क्यों हैं? जन्मगत जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण जैसी कवायदें क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं? भारत में तो महज चुनाव ही लोकतंत्र की पहचान बनता जा रहा है। नौकरशाही, भ्रष्टाचार, यौन अपराध और अन्याय-शोषण भारतीय लोकतंत्र में खुलेआम क्यों चलते रहते हैं? डॉ. आम्बेडकर की लोकतंत्र के बारे में सोच आज भी अहमियत रखती है, जिसमें वे कहते हैं- राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, जीने का वह तरीका, जिसमें आजादी, बराबरी और भाईचारे को जीवन के सिद्धांत के रूप में माना जाता है।

**आप भी अपनी राय editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं।**

**पुरस्कृत तस्वीर :** खास पलों में रंग बदलने वाली फिश

**प्रशांत** महासागर क्षेत्र का यह पलाऊ द्वीप शार्क समेत कई जलीय जीवों के लिए जन्नत है। यहां समुद्र की गहराइयों में लाखों की संख्या में स्नैपर्स मछलियां जब अंडे देने के लिए जमा हुईं, तो छायाकार ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। मैटिंग के दौरान ये मछलियां अपना रंग बदलती हैं। सुबह की रोशनी में खींची इस तस्वीर के लिए छायाकार को अंडर वॉटर श्रेणी में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया था। **तस्वीर साभार : Tony Wu**

**अभियान** • कार्बन रूपी कचरे की सफाई और जरूरी

# दिखने वाला कचरा साफ, पर अदृश्य कचरे का क्या हुआ?

**क्लाइमेट**

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी
आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर
chetanss@gmail.com

**इंदौर** ने कचरे की सफाई में पूरे देश में अपना नाम स्थापित किया है और लगातार सात वर्षों तक भारत के स्वच्छतम शहर होने का खिताब जीता है। लेकिन न केवल इंदौर बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक और बड़ी चुनौती है : अदृश्य यानी न दिखाई देने वाले कचरे से निपटना। यह दिखने वाले कचरे से अधिक खतरनाक होता है। जब कोई समस्या स्पष्ट दिखती है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है, जैसे कचरा अलग करना, एकत्र करना और प्रोसेस करना। लेकिन उस दुश्मन से कैसे निपटें, जिसे न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न महसूस किया जा सकता है?

सभी लोग अपनी ऊर्जा सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से बिजली, पेट्रोल और डीजल आदि का उपयोग करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कपड़े, सीमेंट और फर्नीचर जैसे सामान का। दुर्भाग्यवश, अधिकांश ऊर्जा स्रोत कार्बन आधारित हैं और उनके उपयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। आपको पता है ये अदृश्य और गंधहीन सीओ2 वायुमंडल में 300 साल तक रहती है और वैश्विक तापमान बढ़ाने व जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है? इस खतरे से निपटना अधिक जरूरी है।

इंदौर ने कचरा प्रबंधन, उसकी री-साइकलिंग और स्वच्छता में निरंतर प्रयासों के माध्यम से भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में लगातार शीर्ष पर रहने के पीछे कचरा शून्य कॉलोनियों, खाद बनाने की पहल, निवासियों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का बड़ा योगदान है। इसके लिए इंदौर नगर निगम के प्रयास सराहनीय हैं। लेकिन इन असाधारण उपलब्धियों के बावजूद, इस शहर और दुनिया को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना है- वातावरण में उत्सर्जित कार्बन रूपी कचरे की सफाई।

दिखाई देने वाले कचरे का प्रबंधन महत्वपूर्ण है फिर भी ग्रीनहाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अनियंत्रित उत्सर्जन कहीं अधिक विनाशकारी है। ये महसूस ना होने वाली और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो दीर्घकालिक रूप से पर्यावरण के लिए खतरा है। भारत के स्वच्छतम शहर के रूप में, इंदौर को अब अगले स्तर पर जाकर एक जलवायु-सचेत शहर की भी भूमिका निभानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि 'इंदौर क्लाइमेट मिशन' या 'इंदौर क्लीन क्लाइमेट मिशन' जैसी किसी पहल की शुरुआत की जाए।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अतिरिक्त समर्पण और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है- इन्हीं की वजह से इंदौर कचरा-प्रबंधन में अग्रणी बना। इस पहल के लिए जरूरी है, ऊर्जा की सही समझ और यह समझना कि कैसे ऊर्जा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। ऊर्जा साक्षरता के महत्त्व के विषय में चर्चा जरूरी है, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि कॉर्पोरेट्स और पूरे समाज के लिए भी। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सीमित संसाधनों वाली दुनिया में बर्बादी, अत्यधिक और बिना सोचे-समझे की गई खपत न केवल वर्तमान, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगी।

**भारत के स्वच्छतम शहर के रूप में, इंदौर को अब अगले स्तर पर जाकर एक जलवायु-सचेत शहर की भी भूमिका निभानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि 'क्लाइमेट मिशन' या 'क्लीन क्लाइमेट मिशन' जैसी पहल की शुरुआत की जाए।**

हम सबको न केवल जलवायु परिवर्तन के कारण को समझना चाहिए, बल्कि ऐसे मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और जलवायु सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। इंदौर नगर निगम और नगरवासी अपने इनोवेशन को जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ ही कार्बन उत्सर्जन को करने, रिन्युएबल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने और सस्टेनेबल जीवनशैली को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। ऊर्जा खपत को कम करके, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करके और पर्यावरण के लिए उचित कदम उठाकर इंदौर अन्य शहरों के लिए एक पथ-प्रदर्शक बन सकता है। कचरा प्रबंधन और जलवायु-सुधार कार्रवाई दोनों में शहर का नेतृत्व एक स्वच्छ, हरित भविष्य की ओर एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित कर सकता है।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

**नजरिया** • आम भारतीय निवेशकों का सेबी पर भरोसा कायम रहना बहुत जरूरी है

# सेबी प्रमुख विवाद में मानक कदम क्या हो सकते हैं

**प्रासंगिक**

जी. सबरीनाथन
आईआईएम बेंगलुरु में
एसोसिएट प्रोफेसर

**सिक्योरिटी** एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) प्रमुख माधवी बुच पर लगे आरोपों के बाद ये संस्था भी खबरों में है। 1988 में सेबी की शुरुआत सीमित अधिकारों वाली संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन 1992 के सेबी अधिनियम ने इसे कई अहम शक्तियां दीं। सेबी इसका श्रेय ले सकता है कि उसने 3 लाख करोड़ रु. के छोटे व अप्रभावी बाजार, जिसमें 1% से भी कम आबादी की भागीदारी थी, उसको बदलकर अब 450 लाख करोड़ रु. के पूंजीकरण वाले बाजार में तब्दील कर दिया है, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का खाता है।

ऐसा नहीं है कि सेबी का रिकॉर्ड पूरी तरह बेदाग रहा है। कई विशेषज्ञों ने नियमों के पालन में इसकी ढिलाई, दोषियों को पकड़ने और गलत तरीके से कमाई करने वाले बेईमान मार्केट ऑपरेटर्स से पैसे वापस कराने में इसकी सक्षमता पर सवाल उठाए हैं। सेबी रिसर्च संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठा सकता था, जिससे ठोस तथ्यों पर आधारित नीतियां बनाई जा सकतीं। हालांकि, समग्र रूप से प्रतिभूति बाजार के विकास में सेबी की भूमिका को मानना होगा।

इसी संदर्भ में वर्तमान सेबी प्रमुख पर लगे आरोप चिंताजनक हैं। जब माधवी बुच ने सेबी प्रमुख का पद संभाला, तो सरकार ने एक नौकरशाह को इस पद पर नियुक्त करने की परंपरा से हटकर यह कदम उठाया था। हालांकि, तकनीकी रूप से वह पहले से ही एक पूर्णकालिक सदस्य थीं, और बाजार के विशेषज्ञों ने उन्हें निजी वित्तीय सेवाओं की इंडस्ट्री से जुड़ी काबिल व्यक्ति के रूप में देखा, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बेहतरीन थी। उन्होंने काफी हद तक उम्मीदों पर खरा उतरते हुए काम किया। उन्होंने दोषी प्रमोटर्स को न्याय के दायरे में लाने, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने, खुदरा निवेशकों को वायदा बाजार के जोखिमों के बारे में चेतावनी देने और ऊंचे वैल्यूएशन को 'बुलबुला' कहने जैसे ठोस कदम उठाए। उनकी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दी गई प्राथमिकता सराहनीय थी, खासकर जब सार्वजनिक बाजारों से रिकॉर्ड पूंजी जुटाई जा रही थी।

हालांकि सेबी प्रमुख पर अभी सिर्फ आरोप हैं और हर नागरिक की तरह, बुच को भी तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक वह दोषी साबित नहीं हो जातीं। लेकिन सेबी प्रमुख के पद पर उनका बने रहना एक अलग मुद्दा है। इस पद की जिम्मेदारी को देखते हुए, इसका प्रमुख ऐसा होना चाहिए जिस पर निवेशक पूरी तरह भरोसा कर सकें। यह पद जीवी रामकृष्ण जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने संभाला और इसकी एक मजबूत नौकरशाही परंपरा रही है। बुच को भी ऐसे कदम उठाने होंगे जो इस परंपरा को बरकरार रखें और यह सुनिश्चित करें कि आम भारतीय निवेशक सेबी पर अपने निवेश की सुरक्षा के लिए ईमानदारी से काम करने का भरोसा कर सके।

सेबी से उठती अफवाहें देखकर कोई भी सोच सकता है कि वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब समय आ गया है कि बुच और सेबी का बोर्ड वही मानक अपनाए, जो किसी कंपनी के सीईओ पर संदेह होने पर उसके बोर्ड से अपेक्षित होते हैं। उन्हें एक्सिस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक पीजे नायक से सीख लेनी चाहिए, जब 2002 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के असफल विलय से जुड़े आरोपों के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्हें इसी तरह जवाबदेही की परंपराओं का पालन करना चाहिए। यह कहना गलत है कि पद से हटना किसी अपराध को कबूल करने जैसा होगा, क्योंकि यह वही तर्क है जो अक्सर पद पर बने रहने के लिए विवादित नेताओं द्वारा दिया जाता है। देश के नागरिकों को सेबी के प्रमुख से इससे बेहतर उम्मीद होगी।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

*स्वाभिमानी लोग कभी किसी के आश्रय पर नहीं जीवित रहते हैं। वे सहारा अवश्य मांगते हैं, पर अपमानित नहीं होना चाहते, यही उनकी विशेषता है।*

*– टोरी*

## धोखादेह दलीलें

हर अधिवक्ता अदालत में इसी संकल्प और तैयारी के साथ उतरता है कि वह अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाएगा। वकालत के पेशे में नैतिक दायित्व भी यही होता है और इसी से वकील की साख बनती है। इसलिए हर वकील कानूनी बारीकियां और दलीलें पेश करते हुए अपने मुवक्किल के पक्ष को सही ठहराने का प्रयास करता है। अदालतें भी उन पर भरोसा करके चलती हैं। दरअसल, वकील अपने मुवक्किल और न्यायाधीश के बीच एक सेतु होता है। इस तरह कई बार न्यायाधीशों को भी वकीलों की जिरह से कानून की बहुत सारी बारीकियों समझने में मदद मिलती है। मगर वकील जब इस विश्वास के रिश्ते का फायदा उठा कर, जानबूझ कर अदालत की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं, तो उससे पूरी न्याय प्रक्रिया गुमराह होती और न्याय का रास्ता बाधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि वकीलों के झूठे बयानों से हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि पिछले तीन-चार हफ्तों में सात-आठ ऐसे मामले सामने आए, जिसमें वकीलों ने झूठे बयान देकर अपने मुवक्किल की सजा माफ करने या उसमें छूट देने की गुहार लगाई।

कानून में यह प्रावधान है कि किसी दोषी के अच्छे आचरण और खराब स्वास्थ्य आदि के मद्देनजर उसकी सजा कम या खत्म की जा सकती है। मगर उसके लिए न्यूनतम अवधि की सजा काटना जरूरी होता है। इसी तरह कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से कैदियों को कुछ दिन फरलो पर बाहर रहने की इजाजत दी जा सकती है। इन्हीं प्रावधानों का लाभ उठाते हुए कुछ वकील अपने मुवक्किल को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने जिन मामलों का संज्ञान लिया, उनमें देखा गया कि वकीलों ने झूठे बयान और दलील देकर सजा माफी की गुहार लगाई। एक मामले में सजायाफ्ता चार कैदियों को लेकर कहा गया कि वे चौदह वर्ष की सजा काट चुके हैं। यह भी बताया गया कि चारों को हत्या के मामले में सजा दी गई थी। मगर अदालत को पता चला कि उन्होंने न केवल चौदह वर्ष की सजा पूरी नहीं की थी, बल्कि चारों को अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था। इसी तरह एक मामले में बताया गया कि फरलो पर बाहर गए सभी कैदियों की फरलो अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे ही अन्य मामले देखे गए। निस्संदेह इस प्रवृत्ति से न्यायिक शुचिता प्रश्नांकित होती है।

हालांकि इस संदर्भ में यह भी चिंताजनक है कि जघन्य अपराध के दोषियों को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने की प्रवृत्ति पैदा कहां से हुई है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे प्रसंग सामने आए हैं, जिनमें राज्य सरकारों ने हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजायाफ्ता लोगों की सजा माफी की सिफारिश की। कुछ अपराधियों को बार-बार फरलो दी गई। समझना मुश्किल नहीं है कि इस राजनीतिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार का विस्तार हुआ है। फिर, वकालत के पेशे में भी नैतिकता का प्रकट ह्रास हुआ है। निचली अदालतों में फैसलों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति भी जड़ें जमा चुकी है। इसलिए झूठे दस्तावेजों और बयानों के बल पर अधिवक्ता अगर अदालतों को गुमराह करते देखे जा रहे हैं, तो हैरानी की बात नहीं। अच्छी बात है कि शीर्ष अदालत ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कुठाराघात किया। शायद आगे ऐसे झूठ और फरेब पर नकेल कसे।

## अंधविश्वास की परतें

जिस दौर में विज्ञान रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है, नई तकनीकी समाज के हाशिये के तबकों तक पहुंचाई जा रही है, वैसे में महज कल्पना या अंधविश्वासों की वजह से किसी को बर्बरता से पीट-पीट कर मार डालने की घटनाएं विकास के तमाम दावों पर सवालिया निशान लगाती हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक गांव में रविवार को तीन महिलाओं सहित पांच आदिवासियों की इसलिए पीट-पीट कर हत्या कर दी गई कि उन पर लोगों को यह शक था कि वे जादू-टोना करके दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के हरिसारा गांव में दो आदिवासी महिलाओं को जादू-टोना करने के संदेह में स्थानीय लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला। महज गलत धारणाओं की वजह से हुई हत्या की इन घटनाओं के बाद पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों से ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं?

इस तरह की घटनाओं के वक्त ऐसा करने वालों के भीतर कहीं भी कानून का खौफ दिखाई नहीं देता है। मगर जब ऐसा कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करती दिखती है। यह छिपा नहीं है कि आज भी बहुत सारे लोग कई तरह के अंधविश्वासों का शिकार होकर जादू-टोना जैसी झूठी आशंकाओं के प्रभाव में आकर आपराधिक वारदात को भी अंजाम देते हैं। विडंबना है कि ऐसी धारणाओं के शिकार कई बार पढ़े-लिखे कहे जाने वाले या शहरी लोग भी होते हैं। संविधान में जहां वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के प्रावधान मौजूद हैं, वहां इस दिशा में सरकार की ओर से बहुत कम ठोस प्रयास देखे जाते हैं। खासकर वैसे तबकों के बीच शिक्षा के साथ वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की जरूरत है, जो किसी भी अभाव, परेशानी, बीमारी आदि की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति पर जादू-टोना करने का शक करते और तांत्रिकों के उकसावे में आकर उन्हें मार डालने से भी नहीं हिचकते। शायद बाद में कानूनी कार्रवाई का सामना करते हुए उन्हें अपने किए पर पछतावा होता हो।

# न्याय मिलने में देरी की वजहें

**अब अदालतों का संस्थागत ढांचा बढ़ा है। उपभोक्ता, परिवार और किशोर न्यायालय अलग से अस्तित्व में आ गए हैं। फिर भी काम संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ता अदालतें अपनी कार्य संस्कृति के चलते अब बोझ साबित होने लगी हैं।**

**प्रमोद भार्गव**

जिला न्यायाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंबित मुकदमों और न्याय में देरी का उल्लेख करते हुए न्यायालयों को 'तारीख पर तारीख' देने और स्थगन की संस्कृति बदलने की नसीहत दी। इसके चलते अदालतों में लंबित मुकादमों की संख्या बढ़ती जाती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्टीकरण दिया कि अदालतों में अठाईस फीसद जजों और सत्ताईस फीसद कर्मचारियों की कमी है। त्वरित न्याय के लिए इन कमियों को दूर करना जरूरी है।

जजों की कमी कोई नई बात नहीं है, 1987 में विधि आयोग ने हर दस लाख की आबादी पर जजों की संख्या दस से बढ़ाकर पचास करने की सिफारिश की थी। फिलहाल यह संख्या सत्रह है। अब अदालतों का संस्थागत ढांचा बढ़ा है। उपभोक्ता, परिवार और किशोर न्यायालय अलग से अस्तित्व में आ गए हैं। फिर भी काम संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ता अदालतें अपनी कार्य संस्कृति के चलते अब बोझ साबित होने लगी हैं। बावजूद इसके, औद्योगिक घरानों के वादियों के लिए अलग से वाणिज्य न्यायालय बनाने की पैरवी की जा रही है।

अलबत्ता, आज भी ब्रिटिश परंपरा के अनुसार अनेक न्यायाधीश गर्मी में छुट्टियों पर चले जाते हैं। सरकारी नौकरियों में जबसे महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान हुआ है, तब से हर विभाग में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ी है। उन्हें 26 सप्ताह के प्रसूति अवकाश के साथ दो बच्चों की अठारह वर्ष की उम्र तक परवरिश के लिए दो वर्ष का 'चाइल्ड केयर अवकाश' भी दिया जाता है। अदालत से लेकर अन्य सरकारी विभागों में मामलों के लंबित होने में ये अवकाश बड़ा कारण बन रहे हैं। इधर कुछ समय से लोगों में यह धारणा बनी है कि न्यायपालिका से दबाव डलवा कर विधायिका और कार्यपालिका से छोटे से छोटा काम भी कराए जा सकते हैं। इसलिए भी न्यायालयों में जनहित याचिकाएं बढ़ रही हैं, जो न्यायालय के बुनियादी कामों को प्रभावित करती हैं। जबकि प्रदूषण, यातायात, पर्यावरण और पानी जैसे मुद्दों पर अदालत की दखल के बावजूद बेहतर स्थिति नहीं बनी है।

न्यायिक सिद्धांत का तकाजा है कि सजा मिलने से पहले किसी को अपराधी न माना जाए। दूसरे, आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति का फैसला तय समय-सीमा में हो। मगर दुर्भाग्य से हमारे यहां ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी एक वजह न्यायालय और न्यायाधीशों की कमी जरूर है, लेकिन यह आंशिक सत्य है। मुकदमों के लंबा खिंचने की एक वजह अदालतों की कार्य-संस्कृति भी है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्रमल लोढ़ा ने कहा था कि, 'न्यायाधीश भले निर्धारित दिन ही काम करें, लेकिन अगर वे कभी छुट्टी पर जाएं, तो पूर्व सूचना अवश्य दें, ताकि उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।' दरअसल, सभी अदालतों के न्यायाधीश बिना किसी पूर्व सूचना के आकस्मिक अवकाश पर चले जाते हैं। गोया, मामले की तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा था कि 'जब अस्पताल 365 दिन चल सकते हैं तो अदालतें क्यों नहीं?' हमारे यहां अस्पताल ही नहीं, राजस्व और पुलिस विभाग के लोग भी लगभग 365 दिन काम करते हैं।

किसी आपदा के समय इनका काम और बढ़ जाता है। जबकि अदालतों पर कोई परोक्ष दबाव नहीं होता है।

यही प्रवृत्ति वकीलों में भी देखी जाती है। हालांकि वकील अपने कनिष्ठ वकील से अकसर इस कमी की वैकल्पिक पूर्ति कर लेते हैं। मगर वकील

> कई बार गवाहों की अधिक संख्या भी मामले को लंबा खींचने में मदद करती है। ग्रामीण परिवेश और बलवों से जुड़े मामलों में ऐसा अक्सर देखा जाता है। इस तरह के एक ही मामले में गवाहों की संख्या पचास तक देखी गई है। जबकि घटना के सत्यापन के लिए दो-तीन गवाह पर्याप्त होते हैं। इसका लाभ फरियादी के बजाय अपराधी को मिलता है। इसी तरह चिकित्सा परीक्षण से संबंधित चिकित्सक को अदालत में साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने से छूट दी जाए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं यानी एफएसएल रपट समय से न आने के कारण भी मामला लंबा खिंचता है।

जब प्रकरण का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते या मामले को मजबूती देने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य तलाश रहे होते हैं, तो वे बिना किसी ठोस कारण के तारीख आगे खिसकाने की अर्जी लगा देते हैं। विडंबना है कि बिना किसी ठोस पड़ताल के, न्यायाधीश इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। तारीख बढ़ाने का आधार बेवजह हड़तालें और न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं के परिजनों की मौतें भी हैं। ऐसे में श्रद्धांजलि सभा कर अदालतें कामकाज को स्थगित कर देती हैं। जबकि इनसे बचने की जरूरत है। कड़ाई बरतते हुए कठोर नियम-कायदे बनाने का अधिकतम अंतराल पंद्रह दिन से ज्यादा का न हो। अगर किसी मामले का निराकरण समय-सीमा में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मामलों को विशेष प्रकरण की श्रेणी में लाकर उनका निराकरण त्वरित और लगातार सुनवाई की प्रक्रिया के अंतर्गत हो। ऐसा होता है, तो मामलों को निपटाने में तेजी आ सकती है।

ऐसी ही सोच के चलते मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा था, 'हम पूरी कोशिश करेंगे कि अदालतों में कोई भी मुकदमा पांच वर्ष से ज्यादा न खिंचे।' यह न्याय प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। मगर हाल ही में हमने देखा कि अजमेर की अदालत में बत्तीस साल बाद छह दोषियों को सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। यानी निचली अदालत में ही एक मामले के निराकरण में बत्तीस साल लग गए। इसके आगे उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

कई बार गवाहों की अधिक संख्या भी मामले को लंबा खींचने में मदद करती है। ग्रामीण परिवेश और बलवों से जुड़े मामलों में ऐसा अक्सर देखा जाता है। इस तरह के एक ही मामले में गवाहों की संख्या पचास तक देखी गई है। जबकि घटना के सत्यापन के लिए दो-तीन गवाह पर्याप्त होते हैं। इसका लाभ फरियादी के बजाय अपराधी को मिलता है। इसी तरह चिकित्सा परीक्षण से संबंधित चिकित्सक को अदालत में साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने से छूट दी जाए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं यानी एफएसएल रपट समय से न आने के कारण भी मामला लंबा खिंचता है। एफएसएल की कमी होने के कारण अब तो सामान्य रपट आने में भी एक से डेढ़ साल का समय लग जाता है। प्रयोगशालाओं में ईमानदारी न बरते जाने के कारण संदिग्ध रपटें भी आ रही हैं।

अदालतों में मुकादमों की संख्या बढ़ाने में राज्य सरकारों का रवैया भी जिम्मेवार है। वेतन विसंगतियों को लेकर एक ही प्रकृति के कई मामले ऊपर की अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें से अनेक तो ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें सरकारें आदर्श और पारदर्शी नियोक्ता की शर्तें पूरी नहीं करती हैं। नतीजतन, जो वास्तविक हकदार हैं, उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ता है। कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी बकाए के भुगतान के लिए अदालतों में जाते हैं। जबकि इन मामलों को कार्यपालिका अपने स्तर पर निपटा सकती है। इसी तरह पंचायत पदाधिकारियों और राजस्व मामलों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में न होने के कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बिजली बिलों का विभाग स्तर पर न निपटना भी अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। कई प्रांतों के भू-राजस्व कानून विसंगतिपूर्ण हैं। इनमें नाजायज कब्जे को वैध ठहराने के उपाय हैं। जबकि जिस व्यक्ति के पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं, वह भटकता रहता है। इन मामलों से निजात पाई जा सकती है, मगर नौकरशाही ऐसे कानूनों को बनाए रखना चाहती है, क्योंकि इनके जरिए ही उनका रौब-रुतबा और आर्थिक हित सुनिश्चित रहते हैं।

# परिवार का परिवेश

**राजेंद्र प्रसाद**

हमारे जीवन में परिवार का बहुत महत्त्व है। आमतौर पर हर समाज में बच्चों का जन्म और पोषण परिवार में होता है। पैदा होने से लेकर जीवन के विभिन्न पड़ावों और संघर्ष से गुजरते हुए हर सफर में कदम-कदम पर उसकी महत्ता महसूस होती है। इसके बिना जीवन सूना-सा लगता है। जो परिवार की मजबूती के लिए निरंतर तन-मन-धन रूपी निवेश करता है और जोड़े रखने में समय लगाता है, वह उसकी कीमत जानता है। अच्छे-बुरे की जिम्मेदारी ईमानदारी से लेना और उतार-चढ़ाव का दर्द झेलना परिवार रूपी चिराग को रोशन करने की कला है।

पारिवारिक रचना में मर्यादा और आदर्श परंपरागत हैं। विकास की रफ्तार से आजीविका के साधनों और उन्नति की भूख ने इस पर असर डाला है। पाश्चात्य विचारधारा की शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव समाज पर पड़ा है। ऐसे कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए चुनौती हैं। आय के असंतुलित साधन प्रतिकूलता ला रहे हैं। पारिवारिक अर्थव्यवस्था ने नई करवट ली है, जिससे उसका संयुक्त रूप समाप्ति की ओर है।

आज के दौर में संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं और नई परिभाषा भी गढ़ी जा रही है। अतीत में एक चूल्हा-चौका जीवनयापन का आधार था और तीन-चार पीढ़ी के लोग दुख-सुख में इकट्ठा जीते थे। रोटी कमाना बड़ी बात है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना ज्यादा बड़ी बात है। जिन्होंने ऐसा परिवेश जिया या देखा है, वे ऐसी व्यवस्था की स्मृति से सुखद अहसास में चले जाते हैं। बदलाव की बयार से अकेलापन बढ़ रहा है। परिवार एकमात्र जगह है, जहां सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है।

जो परिवार अतीत में सम्मान का जीवन जी रहे थे, पर समय के फेर से परिवार के अंदर कुछ ऐसे सदस्य निकल आए जो खुद समस्या हैं और परिवार के लिए भी समस्या बन जाते हैं। ऐसे में परिवार पटरी से उतर जाता है और अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जिस किसी ने परिवार बनाने में वर्षों लगाए हों, उसे टूटने का दर्द हो सकता है। इसके विपरीत जिसने स्वार्थ, तंगदिली और लोभ से जीवन चलाया हो, वह परिवार को समृद्ध क्या करेगा?

तेजी से परिवर्तित हो रहे सामाजिक और आर्थिक दौर से जीने के अंदाज बदले हैं जिनसे मनमर्जी, विरोध और स्वार्थ के स्वर फूटने से अलग संसार बन रहा है। तन-मन से एकाकी व्यक्ति गलतफहमी में शक्तिशाली होने का पाखंड करता है, जबकि अंदरखाने खोखला है। उसे टूटन का दर्द नहीं होता, क्योंकि उसने जुड़ना नहीं सीखा। जो लोग स्वार्थी और छोटे दिल के राहगीर हैं, वे अपनी संतान को भी कमोबेश वही सिखाते हैं, जो वे खुद सीखे होते हैं। लोगों को संभलने में विश्वास नहीं, बल्कि फिसलने में ज्यादा आनंद और सुविधा लगती है। गलत की सीख जल्दी रंग दिखाती है। लेकिन आघात का दर्द मरम्मत लायक भी नहीं रहता। एक व्यक्ति के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। वे अधिकारी बनकर दूसरे शहर में स्थापित हुए। गांव की संपत्ति भाइयों को इस्तेमाल के लिए दी हुई थी। जब वे गांव जाते, सब आवभगत करते। इस तरह नाम भी ऊंचा हो गया। सेवानिवृत्त हुए तो पत्नी संपति हासिल करने के लिए उकसाने लगी। पुश्तैनी मकान में पुराने कड़ी आदि लगे हुए थे। संपत्ति विभाजन मांगने पर आंखें लाल-पीली हुईं तो कुल मिलाकर इतनी रकम बंटवारे के हिस्से में आए, जो उनके लिए मायने नहीं रखते थे। भाईचारे में खटास आने पर जब भी गांव पहुंचते तो पहले जैसा सम्मान अब नहीं रहा। चायपान और भोजन तक के लिए कोई पूछने वाला नहीं था।

इसके विपरीत एक व्यक्ति दूसरे शहर में संघर्ष से कुछ स्थापित हुए। परिवार में मतभेद होने पर खबर लगती तो त्याग की रोशनी में दीपक जगमग रखने की सोचते। जब भी झगड़े सामने आते, तो पल्ले से पैसे देकर मामले शांत करवा देते। रह-रहकर परिवार को बचाने की मिसाल पेश होती। जो इस बात को समझते थे, वे एक-एक करके शांत या संसार से विदा हो रहे। कुछ कम ही बचे जो उनके त्याग को मानते, लेकिन स्वार्थ की भूख के नाम पर लालच ने अपने पैर पसार लिया। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए कोई एक सदस्य ही काफी है। घर टपकता है तो उसकी मरम्मत की जाती है, गिर जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। अक्सर एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं।

परिवार गीत है, जहां हमेशा सही गाना नहीं होता है, बस आपसी छोटी-मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर थिरकना होता है। परिवार और समाज उस समय बर्बाद होने लगते हैं, जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। पत्थर तब तक सलामत है, जब तक वह पर्वत से जुड़ा है। उसी तरह परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन जरूरतें परिवार की याद दिलाती हैं। उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से गिर जाते हैं। परिवार के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने नहीं देना चाहिए। जिस घर की छत टपकती है, उसकी दीवारें भी कमजोर होती हैं। अच्छी उम्मीदों को पोषित करने के लिए मन-कर्म-वचन से समृद्ध करते जाएंगे तो परिवार के आनंद की बगिया खिल उठेगी। जिस परिवार या समाज में लोग बातचीत से नहीं भागते, वहां कम से कम विवाद होंगे। अगर विवाद होंगे तो भी जल्दी सुलझ जाएंगे।

### दुनिया मेरे आगे

> परिवार और समाज उस समय बर्बाद होने लगते हैं, जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। पत्थर तब तक सलामत है, जब तक वह पर्वत से जुड़ा है। उसी तरह परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन जरूरतें परिवार की याद दिलाती हैं। उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से गिर जाते हैं।

## युद्ध के मोर्चे

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि यूक्रेन रूस के भीतर तक मिसाइलों से हमला कर सकता है, बशर्ते वे हथियार अमेरिका द्वारा प्रदान नहीं किए गए हों। सवाल है कि ऐसा कैसे संभव है या फिर यूक्रेन को हथियार देने का क्या मतलब हुआ। क्या यूक्रेन सिर्फ रूसी मिसाइलों, ड्रोनों और राकेटों के हमले बर्दाश्त करता रहेगा? यह मुद्दा ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की वाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा में भी सामने आने वाला है। ब्रिटेन ने पहले ही अमेरिका को संकेत दे दिया है कि वह यूक्रेन को उसकी सीमा से दूर रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अपनी 'स्टार्म शैडो' लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने देने के लिए उत्सुक है। उधर पुतिन ने धमकी देते हुए नाटो देशों को चेताया है कि वह यूक्रेन को लंबी दूरी वाले मिसाइलों से हमले करने का अनुमति देगा तो या माना जाएगा कि नाटो देश भी इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि दूसरा विश्व युद्ध तभी समाप्त हुआ था जब मित्र राष्ट्रों ने एक होकर जर्मनी पर धावा बोला था।

*– जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

## खतरे की खेती

भारत में कृषि क्षेत्र में यूरिया, कीटनाशक और रसायन का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। कीटनाशकों और रसायनों का बढ़ता प्रयोग लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कीटनाशकों और रसायनों के उपयोग से किसान को कम समय में अधिक उपज और मुनाफा हो रहा है। मगर अनाजों, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों और यूरिया के प्रयोग से लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, पेट की बीमारी और हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं। अनेक रसायन जो विदेशों में प्रतिबंधित है, उन्हें भारत में खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को नुकसानदेह रसायनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और कीटनाशक और खाद के इस्तेमाल का एक नियमावली बनानी चाहिए। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। किसानों को जैविक और परंपरागत खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

*– हिमांशु शेखर, केसपा, गया*

## इंसाफ के आयाम

विरोध बनाम दायित्व' (11 सितंबर) में जरूरी पहलू का विश्लेषण किया गया है। मगर यह भी सच है कि चिकित्सक लोगों का जीवन बचाते हैं तो उनका जीवन महत्त्वपूर्ण हो जाता है और उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही से कोई चूक होती है, तो नाराजगी जाहिर करने का हक भी वाजिब है। लेकिन अगर चिकित्सकों की नाराजगी के कारण बेगुनाह लोगों को बिना इलाज के जान गंवाना पड़े या बिना इलाज कष्ट भोगना पड़े तो उनकी जवाबदेही यह बनती है कि वे अपने कर्तव्य से विमुख न हों। चिकित्सक विरोध जारी रखते हुए भी अपने चिकित्सा धर्म का पालन कर सकते हैं। जांच और न्याय एक लंबी प्रक्रिया है, दोषियों को सजा की तत्परता के लिए जिद कर काम बंद कर बैठ जाना बेहद जरूरतमंद लोगों के साथ किया गया अन्याय होगा। हक के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इंसाफ की मांग के साथ-साथ चिकित्सकों को काम पर लौट आना चाहिए।

*– हुकुम सिंह पंवार, टोड़ी, इंदौर*

## बुजुर्गों की सेहत

वृद्धों के स्वास्थ्य लाभ के लिए लागू जन आरोग्य योजना बेशक स्वस्थ देश की पहचान कायम करेगी। इस योजना में सत्तर वर्ष से अधिक वे बुजुर्ग अपना स्वास्थ्य सही रख पाएंगे जो अभी तक इलाज के लिए परिवार पर आश्रित रहते थे। देश के छह करोड़ बुजुर्ग पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने के साथ-साथ इतनी ही राशि का स्वास्थ्य बीमा का लाभ पाने के हकदार होंगे। हालांकि स्वास्थ्य बजट की यह वृद्धि चीन और अमेरिका के मुकाबले अभी भी बहुत कम है। इलाज का खर्च दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। देखा गया है कि शिक्षा, अस्पताल और अदालत निजी व्यवसाय के रहते बेलगाम खर्च वसूलने के अड्डे बने हुए हैं। इनसे निजात सरकार की योजनाएं ही दिला सकती हैं। हृदयाघात और कैंसर जैसी बीमारियों से मरने वाले लोगों की सर्वे रपट भी डराने वाली हैं। इस ओर भी सरकार को संज्ञान लेना होगा।

*– मामचंद सागर, रजोकरी, दिल्ली*



https://t.me/AllNewsPaperPdf

www.readwhere.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 182

# सही संतुलन

केंद्र सरकार ने गत सप्ताह कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात से संबंधित कुछ निर्णय लिए। उसने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) समाप्त कर दिया। गत वर्ष बासमती चावल पर प्रति टन 1,200 डॉलर का एमईपी लगाया गया था जिसे बाद में कम करके 950 डॉलर प्रति टन कर दिया गया था। सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात शुल्क भी 40 फीसदी से कम करके 20 फीसदी कर दिया। दूसरी ओर उसने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया। अन्य घटकों को शामिल करने के बाद प्रभावी शुल्क दर 27.5 फीसदी होगी। रिफाइंड तेल पर आधारभूत कस्टम शुल्क बढ़ाकर 32.5 फीसदी कर दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि यह निर्णय घरेलू सूरजमुखी, मूंगफली और सरसों के रिफाइंड तेल की मांग बढ़ाएगा।

इन निर्णयों से उत्पादकों को लाभ होगा। चावल के मामले में चूंकि अच्छे मॉनसून के कारण अच्छी फसल होने की उम्मीद में कीमतों में गिरावट आने लगी है तो ऐसे में निर्यात प्रतिबंध जारी रखने का कोई फायदा नहीं था। बहरहाल, उम्मीद के मुताबिक ही इस निर्णय को राजनीतिक नजरिये से भी देखा जाना चाहिए। हरियाणा विधान सभा चुनावों का प्रचार पूरे जोरशोर से चल रहा है। हरियाणा बासमती चावल का एक प्रमुख उत्पादक है। वहां एमईपी की शर्त हटाने की मांग उठ रही थी। प्याज पर निर्यात शुल्क हटाने को महाराष्ट्र के विधान सभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र प्याज का प्रमुख उत्पादक प्रदेश है और हालिया लोक सभा चुनावों में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हार की एक वजह इस प्रतिबंध को भी बताया गया। खबरों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में प्याज की कमी है और यह बात भारतीय निर्यातकों को लाभ पहुंचा सकती है।

यह सही है कि ताजा कदम निर्यात अवसरों तथा खाद्य तेल के मामले में आयात प्रतिबंध के रूप में उत्पादकों को लाभ पहुंचाएगा लेकिन देश की कृषि व्यापार नीति के साथ बुनियादी प्रश्न यही है कि इसमें निरंतरता का अभाव है और यह अक्सर विरोधाभासी संकेत देती है। यह बात अच्छी तरह समझी जा चुकी है कि खाद्य कीमतों का मसला संवेदनशील मसला है और खाद्य सुरक्षा का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हस्तक्षेप सीमित होने चाहिए और पूरे विचार विमर्श के बाद किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए चावल निर्यात पर प्रतिबंध की बोआई के समय ही समीक्षा होनी चाहिए थी। इससे किसान अधिक बेहतर निर्णय ले पाते। इसके अलावा यह बात अच्छी तरह दस्तावेजी कृत है कि कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए किए जाते हैं। जैसा कि नवीनतम आर्थिक समीक्षा में भी कहा गया, 'मूल्यों को स्थिर करने के उपाय उपभोक्ताओं से जुड़े होते हैं और वे किसानों की आय समर्थन नीतियों के साथ टकराते हैं।' अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अन्य ने भी दिखाया है कि भारत के किसानों पर प्रतिबंधात्मक व्यापार और विपणन नीतियों के माध्यम से परोक्ष कर लगाया जाता है।

यह बात गत सप्ताह भी सरकार के निर्णय में नजर आई। सरकार ने कारोबारियों द्वारा भंडारित किए जाने वाले गेहूं की सीमा को 3,000 टन से कम करके 2,000 टन कर दिया। यह कदम बाजार में उपलब्धता बढ़ाने से संबंधित है ताकि कीमतें कम हो सकें। बहरहाल ऐसे कदम या भंडार सीमा का विचार आदि व्यापारियों को क्षमता निर्माण में निवेश करने से रोकते हैं। इससे बाजार का विकास प्रभावित होता है। इससे फसल के समय कीमतें कम रहेंगी और उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ऐसे में यह अहम है कि सरकार हस्तक्षेप कम करे और बाजार ताकतों को विकास का अवसर दे। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, उपलब्धता में सुधार होगा और समय के साथ कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होगा।

अजय मोहंती

# ऋण-जमा विसंगति के मूल में बचत दर

**बड़े बैंकों में बचत जमा के लिए किसी तरह की होड़ नहीं दिखती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऋण और जमा के बीच जो विसंगति है क्या उसके मूल में बचत दर है। बता रहे हैं जनक राज**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर दबाव है कि वे बड़े पैमाने पर जमा राशि जुटाएं क्योंकि ऋण और जमा का वृद्धिशील अनुपात (सी-डी रेश्यो) 98 फीसदी पर पहुंच गया है। आम तौर पर यह अनुपात 80 फीसदी से कम रहता है क्योंकि बैंकों को अपने जमा पर 4.5 फीसदी का नकद आरक्षित अनुपात और 18 फीसदी का सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना होता है। आम तौर पर बैंक अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां रखते हैं, जिससे उन्हें वृद्धिशील सी-डी अनुपात को 77.5 फीसदी से ऊपर रखने में मदद मिलती है बशर्ते अतिरिक्त प्रतिभूतियां उपलब्ध हों।

मई 2022 में मौद्रिक नीति की मौजूदा सख्ती आरंभ होने के पहले 22 अप्रैल, 2022 को एससीबी के ऋण में साल भर पहले की तुलना में 11.2 फीसदी वृद्धि हुई थी, जबकि जमा में वृद्धि 9.8 फीसदी थी। उस समय वृद्धिशील सी-डी अनुपात 80 फीसदी था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी, 2023 तक नीतिगत रीपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी। मगर इसका प्रभाव होते नहीं दिखा क्योंकि मई 2023 के अंत तक कुल ऋण में 15.4 फीसदी वृद्धि हो गई थी जबकि जमा में 11.8 फीसदी वृद्धि ही हुई। परिणामस्वरूप वृद्धिशील सी-डी अनुपात बढ़कर 94 फीसदी हो गया। नौ अगस्त, 2024 तक हालात और बिगड़ गए जब यह सी-डी अनुपात बढ़कर 98 फीसदी हो गया। इसमें 15 फीसदी ऋण वृद्धि की भूमिका थी, जबकि जमा वृद्धि 11.3 फीसदी थी।

रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती शुरू किए जाने के दो वर्ष बाद भी वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में 20 फीसदी का इजाफा सही संकेत नहीं है। दिलचस्प है कि एससीबी ने मौजूदा मौद्रिक सख्ती चक्र में सावधि जमा पर ब्याज दरों में 1 से 1.9 फीसदी तक का इजाफा किया। लेकिन बड़े बैंकों ने जमा पर बचत दर 2.7 से 3 फीसदी के बीच ही रखी।

रिजर्व बैंक ने बैंक बचत खातों पर ब्याज दर का नियमन सबसे आखिर में समाप्त किया। जब रिजर्व बैंक बचत और जमा ब्याज दर का नियमन समाप्त करने वाला था तब निजी क्षेत्र के बैंक खासकर प्रमुख निजी बैंकों ने इसका यह कहकर विरोध किया कि इससे बैंकों के बीच एक किस्म की जंग छिड़ जाएगी। इस चिंता को देखते हुए अप्रैल 2011 में एक चर्चा पत्र जारी किया गया। उस पर आई प्रतिक्रियाएं देखकर रिजर्व बैंक ने नफा-नुकसान देखा और तय किया कि वह नवंबर 2011 में बचत-जमा ब्याज दरों का नियमन बंद कर देगा। बचत खातों पर ब्याज दरों को नियमन से बाहर करने के पीछे अहम मकसद था मौद्रिक नीति में बदलाव का असर नीचे तक पहुंचाना। मगर नियमन खत्म करने के बाद भी बचत खातों पर ब्याज की दर कम ही बनी रहीं। नियमन समाप्त होते समय यह दर 3.5 फीसदी थी और खत्म होते ही पांच बड़े बैंकों में यह दर बढ़कर चार फीसदी हो गई लेकिन 2016-17 तक यानी अगले छह वर्षों तक यह जस की तस रही।

बचत-जमा ब्याज दर का अनुपात 2017 से 2020 के दौरान कम होकर 3-4 फीसदी और 2020-21 में 2.7 से 3 फीसदी पर आ गया। तब से यह अपरिवर्तित है। दो-तीन अवसरों को छोड़ दिया जाए तो बड़े निजी और सरकारी बैंकों ने बचत-जमा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने मौद्रिक नीति और अन्य ब्याज दरों को भी तवज्जो नहीं दी। इससे दो अहम प्रश्न उठते हैं। पहला, बड़े बैंकों ने अपने बचत-जमा धारकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने अपना शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़ाने के लिए ऐसा किया। उनकी कुल जमा में बचत जमा की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई रही। सरकारी बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन 2011-12 के 2.8 फीसदी से कम होकर 2017-18 में 2.1 फीसदी हो गया। मोटे तौर पर ऐसा फंसे कर्ज में इजाफे के चलते हुआ। परंतु 2022-23 तक यह बढ़कर 2.7 फीसदी हो गया। दूसरी ओर निजी बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन 2011-12 के 3.1 फीसदी से बढ़कर 2022-23 में 3.9 फीसदी हो गया। कुछ निजी बैंकों में तो यह छह फीसदी तक देखा गया। 2 से 3 फीसदी के बीच शुद्ध ब्याज मार्जिन बेहतर माना जाता है।

दूसरा, बचत-जमा ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने के कारण मौद्रिक नीति में बदलाव का असर नीचे तक नहीं गया। इससे नए जमा पर औसत घरेलू सावधि जमा ब्याज दर में 244 आधार अंकों का इजाफा हुआ जबकि बकाया जमा पर 190 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक के अनुसार मई 2022 से मई 2024 के बीच यह बढ़ोतरी हुई। बहरहाल बचत जमा पर ब्याज दर देखें तो जमा ब्याज दरों में बदलाव रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए आंकड़े से बहुत कम है।

कहा जा सकता है कि बैंक अपनी कुल जमा और उसकी लागत के लिए अधिक चिंतित हैं और विभिन्न घटकों की लागत की फिक्र उन्हें नहीं है। ऐसे में वे अपनी सावधि जमा ब्याज दरों में इस तरह बदलाव करते हैं कि बचत-जमा ब्याज दरों में किसी बदलाव की जरूरत नहीं रह जाए। यदि ऐसा है तो शायद मौद्रिक नीति का असर आगे नहीं पहुंचा हो मगर तब एक बड़ी चिंता पैदा होती है कि जमाकर्ताओं के अलग-अलग समूहों के साथ किस तरह की निष्पक्षता बरती गई।

दूसरी ओर, अगर बड़े बैंकों की सावधि जमा दर बचत-जमा दरों में बदलाव से हर प्रकार से स्वतंत्र होती तो मौद्रिक नीति का असर पहुंच सकता था। चूंकि ऋण वृद्धि ने जमा वृद्धि को काफी पीछे छोड़ दिया है इसलिए मौद्रिक सख्ती के बावजूद बैंकों ने अपने बचत बैंक जमा की दरों को कम रखा है। इसकी वजह से कुल जमा में उनकी हिस्सेदारी काफी कम हो गई है। यह मार्च 2022 के 35.1 फीसदी से घटकर मार्च 2024 में 31.1 फीसदी रह गई। अगर बड़े बैंक नीतिगत दरों में बदलाव के हिसाब से ही ब्याज दर में वाजिब बदलाव करते तो रिजर्व बैंक को शायद मौद्रिक सख्ती इस हद तक नहीं बढ़ानी पड़ती और ऋण-जमा वृद्धि दरों में इतना अंतर नहीं आता। बैंकों के बीच सावधि जमा के लिए भी होड़ होती है। यह प्रश्न तो पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर बड़े बैंक बचत खातों में जमा के लिए होड़ क्यों नहीं करते? क्या बड़े बैंकों के बीच रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीतिगत चक्रों से परे बचत-जमा ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने की मिलीभगत हो चुकी है?

*(लेखक सीएसईपी के सीनियर फेलो हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं)*

# दरों में कटौती और शेयरों के भाव

**दुनिया** भर के निवेशक शेयर बाजारों में उछाल का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में जल्द ही कटौती के संकेत दिए हैं, जिनसे उनके भीतर उत्साह भर गया है। पारंपरिक मान्यता तो यही है कि फेड दरों में कटौती करता है तो शेयरों के भाव चढ़ने लगते हैं। इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि इस सप्ताह फेड की बैठक में दरों में 50 आधार अंक तक की कटौती हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है और अब वह फेड के 2 फीसदी के लक्ष्य के आसपास है। क्या दरों में कटौती से शेयरों के भाव चढ़ेंगे? यह निराश करने वाली बात है कि आंकड़ों के मुताबिक ब्याज दरों में चाहे इजाफा हो या कटौती, शेयर बाजार का प्रदर्शन उससे बहुत अधिक नहीं जुड़ा होता। एसऐंडपी 500 जैसे व्यापक सूचकांकों को देखकर तो यही लगता है। दरों में इजाफे के ताजा उदाहरण से इसकी शुरुआत करते हैं:

वर्ष 2022 में फरवरी के मध्य में मैंने इस स्तंभ में अटकल लगाई थी कि अगर फेड मुद्रास्फीति से मुकाबला करने के लिए दरों में इजाफा करता है तो क्या वास्तव में बाजार में तेजी आएगी? यह परिकल्पना उस पारंपरिक मान्यता के विपरीत थी, जिसमें माना जाता था कि दरों में इजाफे के दौरान बाजार गिरते हैं और दरों में कटौती के दौरान उनमें इजाफा होता है। मेरा नजरिया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित था। उदाहरण के लिए 2004 के मध्य से 2006 के मध्य तक फेड ने 17 बार दरों में इजाफा किया मगर एसऐंडपी 500 में 46 फीसदी तेजी आई। इसी प्रकार दिसंबर 2015 से दिसंबर 2020 के बीच फेड ने दरों में नौ बार इजाफा किया जो 0.25 फीसदी से लेकर 2.5 फीसदी तक था। इस दौरान एसऐंडपी 1,900 से 2,800 पर पहुंच गया। दिलचस्प है कि 2018 में जब सूचकांक डगमगाया तब दरों में इजाफे का तीन साल का चक्र खत्म हो रहा था, शुरू नहीं।

वर्ष 2022 में क्या हुआ? फेड द्वारा दरों में इजाफे और यूक्रेन युद्ध के बीच बाजार में कुछ महीने के लिए गिरावट अवश्य आई। इसके बावजूद पारंपरिक समझ को धता बताते हुए बाजारों ने तेजी से वापसी की और फेड के इच्छित ब्याज दर इजाफे के एक तिहाई तक पहुंचते-पहुंचते इनमें इजाफा हो गया। एसऐंडपी 500 अक्टूबर 2022 में 3,500 तक गिर गया। उसके बाद इसने वापसी की और जुलाई 2023 तक यह 4,600 पर पहुंच गया। इस दौरान फेड ने दरों में छह बार इजाफा किया और यह नवंबर 2022 के 3.25 फीसदी से बढ़कर जुलाई 2023 में 5.5 फीसदी हो गई।

दिलचस्प है कि फेड ने जुलाई में दरें बढ़ाना रोका और अक्टूबर तक एसऐंडपी 500 में गिरावट आई। अक्टूबर के बाद से सूचकांक चढ़ता गया और पिछले सप्ताह की गिरावट के पहले वह बढ़कर 5,650 तक पहुंच गया। इस पूरी अवधि में अर्थव्यवस्था 5.5 फीसदी पर ही रुकी रही। एक पूरे चक्र में दरों में 0.25 फीसदी से 5.5 फीसदी इजाफा हुआ और एक वर्ष तक यह स्तर बरकरार रहा। इसके बावजूद बाजार में लगातार तेजी बनी रही। यह फेड के रुख से अलग था।



**अतार्किक विकल्प**

देवाशिष बसु

यह पहला मौका नहीं है जब फेड द्वारा दरों में बदलाव तथा शेयर बाजार की हलचल के बीच का संबंध अलग निकला हो। इसके विपरीत परिदृश्य पर विचार करें तो क्या फेड द्वारा दरों में कटौती के समय बाजार में तेजी आती है? यहां भी रिश्ता कमजोर नजर आता है। सबसे चकित करने वाला उदाहरण 2008 का है। जनवरी 2008 में बाजार में गिरावट के बाद फेड ने दरों में कटौती की और उन्हें 3.5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया। मार्च में बियर स्टर्न के पतन के बाद 0.75 फीसदी कटौती हुई और यह 2.25 फीसदी रह गई। अप्रैल में दरों में और कमी करके इन्हें दो फीसदी कर दिया गया और जून से सितंबर के बीच बाजार और गिरे। सितंबर में ही लीमन ब्रदर्स का भी पतन हुआ।

अक्टूबर तक दरें घटकर 1.5 फीसदी रह गईं और फिर 1 फीसदी। दिसंबर तक यह घटकर शून्य से 0.25 फीसदी रह गई। इस भारी कटौती के बावजूद 2008 के बाजार संकट को आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर संकटों में गिना जाता है। उस समय जनवरी से मार्च के बीच एसऐंडपी 500 में 50 फीसदी गिरावट आ गई थी, जबकि दरें 3.5 फीसदी से कम होकर शून्य पर आ गई थीं। बाजार को तेजी मिलना तो छोड़ दीजिए, कटौती उनमें गिरावट को भी नहीं रोक पाई। 2001 में भी यही हुआ था। फेड ने दरों में कटौती की और पांच फीसदी से घटते हुए नवंबर 2022 तक यह 1.25 फीसदी रह गई। इसके बावजूद एसऐंडपी 500 अगस्त 2000 के 1,530 से घटकर सितंबर 2002 तक 794 रह गया और मार्च 2002 के बाद इसमें उठान आया।

इसके बावजूद कई लोग यह क्यों मानते हैं कि ब्याज दरों की घट-बढ़ का बाजार के प्रदर्शन के साथ रिश्ता है? शायद इसके पीछे धारणा यह है कि नकदी महंगी होती है तो बाजार में गिरावट आती है। परंतु अन्य कारक भी काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर फेड दरों में इजाफा तब करता है जब आर्थिक वृद्धि मजबूत होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था में कारोबारी मुनाफा बढ़ता है और शेयर के भाव चढ़ते हैं। शेयरों के भाव पारंपरिक समझ के बजाय कारोबारी मुनाफे और मूल्यांकन पर ज्यादा चलते हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ फेड धीरे-धीरे दरों में इजाफा करता है। अगर वृद्धि मजबूत बनी रहती है तो कारोबारी मुनाफा बढ़ता है और शेयर कीमतों में तेजी आती है। मजबूत आर्थिक वृद्धि दर से दरों में इजाफा हो सकता है। बढ़ती दरों और बढ़ते शेयर भाव का यह चक्र भी दर्शाता है कि फेड अक्सर आर्थिक चक्र के हिसाब से चलता है, आर्थिक चक्र उसके हिसाब से नहीं चलता।

क्या ऐसा हो सकता है कि दरों में गिरावट के साथ बाजार भी गिरें? यह संभव है। सही हालात में यानी धीमी वृद्धि के बीच ऐसा हो सकता है। जब फेड दरों में इजाफा बंद कर देता हैतो यह संकेत जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि में धीमापन आ रहा है। इससे कारोबारी मुनाफा प्रभावित हो सकता है और शेयर के भावों पर भी असर हो सकता है। कई बार दरों में तेज इजाफा किया गया हो तो बाद में उनमें कटौती भी मंदी को टाल नहीं सकती। जब वृद्धि धीमी होती है तो बाजार नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। शेयर भाव को तय करने वाले कई कारकों में आर्थिक वृद्धि, कारोबारी मुनाफा और मूल्यांकन प्रमुख हैं। ब्याज दरों की तुलना में इन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

## आपका पक्ष

### सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बनाने की जरूरत

किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके मद्देनजर यह जरूरी हो जाता है कि जीवन के हर पहलू में विज्ञान-तकनीक और अनुसंधान कार्य अहम भूमिका निभाएं। विकास के पथ पर कोई देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बने और उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध तथा अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों की रफ्तार कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। सरकार के सहयोग और समर्थन के साथ, वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण, जैव-ऊर्जा, जल-तकनीक, और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश और विकास भी हुआ है। हम धीरे-धीरे परमाणु व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन



**भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों की रफ्तार कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है**

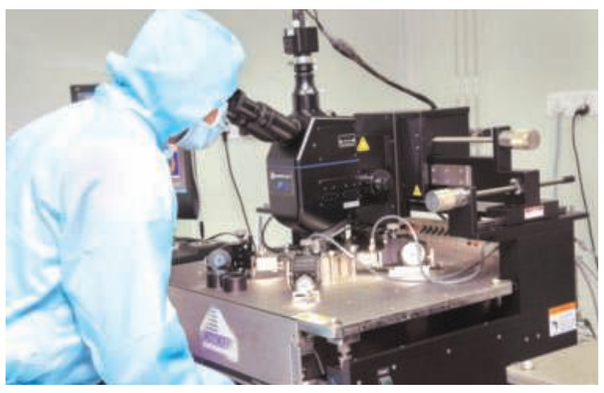

सच्चाई यह भी है कि ऐसे कई अवरोध हैं जिन्हें पार करना भारतीय अनुसंधान और विकास के लिए बहुत जरूरी है। कई बार दोषपूर्ण नीतियों के कारण अक्षम लोगों को भारत में सार्वजनिक और निजी संस्थानों में नौकरी देने की संस्कृति के साथ-साथ गैर-कार्यशील प्रणालियां विकास के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। नियुक्तियां हमेशा योग्यता पर आधारित नहीं होती हैं। हमें इसे बदलने की जरूरत है। प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्च स्तर तक एक अच्छी तरह काम करने वाली शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। मगर, उच्च शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, एक कार्यात्मक समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है, जो नियमों और विनियमों, अच्छे मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और कार्यशील बुनियादी ढांचे का आधार तैयार करे।

*सुधीर कुमार सोमानी, देवास*

### कर वसूलने और जमा की प्रक्रिया सरल हो

जीएसटी के गठन के सात साल बाद भी इसमें काफी कमियां हैं। एक देश, एक कर के नाम पर देश में लागू किए गए जीएसटी में काफी कमियां रह गई जिन्हें आज तक सरकार दूर नहीं कर सकी। देश के व्यापारियों के लिए यह एक कर ना होकर झंझट हो गया है। इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है। कर वसूलने व जमा करने की प्रक्रिया सरल होना चाहिए। जटिल प्रक्रिया गलत कामों और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रही है।

*अवधेश मंगल, मुरैना*

### प्याज फिर महंगा

देश के लगभग राज्यों में प्याज की कीमत में भारी उछाल आ गई है, इसकी कीमत बहुत से राज्यों में 50 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर हो गई है। हालांकि कुछ राज्यों में सरकारें इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रही हैं। यह किसी एक सब्जी की आसमान छूती कीमत की बात नहीं है। कभी प्याज तो कभी अन्य सब्जियों के मूल्य आसमान छू जाते हैं। कृषि प्रधान देश में प्याज की कीमत में बढ़ोतरी और किसानों की दयनीय दशा निंदनीय है। प्याज के बढ़ते दाम के लिए सरकार को नीतियों में सुधार करने की जरूरत है।

*राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

**रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेरिस में आयोजित पैरालिंपिक खेल में शामिल हुए खिलाड़ियों से नई दिल्ली में सोमवार को मुलाकात की।**

## अभूतपूर्व बरसात

### अनेक शहरों में बाढ़

**अभूतपूर्व बरसात** देश के अनेक शहरों में बाढ़ का कारण बनी है। यह शहरी नियोजन के लिए चुनौती है। अभूतपूर्व बरसात के कारण भारत के प्रमुख शहरों में आई व्यापक बाढ़ से जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ तथा दैनिक जनजीवन में भारी बाधा पड़ी। इनमें मुंबई, दिल्ली और बैंगलुरू शामिल हैं। भारी बरसात इन शहरी केन्द्रों को अब भी प्रभावित कर रही है जिसके कारण निवासियों को पानी में डूबी सड़कों से गुजरना पड़ता है, ट्रैफिक जाम होता है, बिजली चली जाती है तथा देश की शहरी ढांचागत संरचना में अनेक कमियां दिखती हैं। इस साल हुई मूसलाधार बारिश ने खासतौर से नुकसान पहुंचाया है। मुंबई में पानी निचले क्षेत्रों में सीने तक पहुंच गया, जबकि बैंगलुरू के एक समय भीड़भाड़ वाले 'टेक कारीडोर' नदियों की तरह लग रहे थे। बाढ़ के कारण देश में 100 से अधिक लोगों की जानें गईं तथा हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। घर और वाहन डूबने के कारण अनेक परिवारों की पूरी बचत कुछ ही घंटों में पानी में बह गई। इसके साथ ही उत्तर भारत के मेरठ जैसे शहर भी आंशिक रूप से डूब गए, जबकि पहले यहां जलभराव की शिकायत नहीं होती थी। बाढ़ के कारण आर्थिक नुकसान भी बहुत अधिक हैं। दूकानें, कार्यालय और उद्योगों को बंद रखने पर मजबूर होना पड़ा। सार्वजनिक ढांचागत संरचना ने बाढ़ की मार झेली है। हालांकि, भारत के शहरी केन्द्रों में ट्रैफिक जाम कोई खास बात नहीं है, पर बाढ़ के कारण पहले से ही खराब स्थिति और खराब हो गई। दिल्ली में बरसात के पानी से प्रमुख सड़कें बंद हो गई तथा यात्रा के समय में कई गुना वृद्धि हुई।

आजीविका के लिए रोज कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ी क्योंकि बाढ़ के कारण पैदा बाधा से वे काम नहीं कर सके। इन बाढ़ों की व्यापकता एवं गहनता से भारत में तत्काल शहरी नियोजन पर पुनर्विचार की आवश्यकता स्पष्ट होती है। अनेक समस्याओं की जड़ खराब जल निकासी व्यवस्था, प्राकृतिक जल स्रोतों पर कब्जे तथा शहरों का अनियंत्रित विस्तार है। मुंबई व चेन्नै जैसे शहरों में हर साल बाढ़ आती है, वहां विशेषज्ञों ने संभावित बाढ़ वाले क्षेत्रों में बेलगाम विकास के खिलाफ चेतावनी दी है। हालांकि, बरसात अभूतपूर्व रही, पर शहरी नियोजन में सुस्ती के कारण स्थिति गंभीर हुई क्योंकि वे मानसून के मौसम में भारी बरसात के लिए तैयार नहीं थे। नालियां जाम होने, आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होने अथवा बेकार होने तथा कार्रवाई में खराब नियोजन के कारण स्थिति और गंभीर होती है। देश भर में शहरों की जल-निकासी या तो पुरानी पड़ गई है अथवा वह भारी बरसात से निपटने में अक्षम है। 'स्थानीय सरकारों' को महत्वपूर्ण ढांचागत संरचना के उच्चीकरण में निवेश करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवासीय व वाणिज्यिक क्षेत्रों से पानी की सक्षम निकासी सुनिश्चित हो। 'बिल्डर-नौकरशाह गठजोड़' के कारण अनेक जल स्रोत नष्ट हुए हैं। पहले अनेक झीलें, नदियां और दलदली क्षेत्र बरसात का पानी सोख लेते थे, पर अब वे अनियोजित अवैध विकास के कारण नष्ट हो गए हैं। शहरी नियोजन में हरित क्षेत्रों को शामिल कर जमीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही टिकाऊ निर्माण व्यवहार से पानी को सतह पर एकत्र होने के बजाय भूमिगत जल में मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए 'वर्षा जल संचयन' तथा 'स्टार्मवाटर प्रबंधन' जैसे समाधानों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। शहरों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए।

# गणेश पूजा पर अकारण विवाद

भारत में प्रशासन तथा न्यायपालिका संविधान के अनुसार काम करते हैं। ऐसे में गणेश पूजा में प्रधानमंत्री व प्रधान न्यायाधीश की सहभागिता पर विवाद अनुचित है।

**गौरव वल्लभ**
(लेखक, प्रोफेसर हैं)

**भारत के** प्रधान न्यायाधीश-सीजेआई के आवास पर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति को प्रतीकात्मक सम्मान और एकता की तरह देखा जाना चाहिए। इसकी अनावश्यक आलोचना अनुचित है। भारतीय प्रशासन की जटिल संरचना में न्यायपालिका व कार्यपालिका के कार्य विशिष्ट तथा अलग होने के बावजूद परस्पर निर्भर हैं, अत: ऐसे संकेत उपयुक्त तथा देश की प्रगति में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। 'संकुचित दृष्टिकोण' से इस कृत्य की आलोचना अवसर के व्यापक महत्व को अनदेखा करना होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका भारतीय लोकतंत्र के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हालांकि, उनके काम अलग-अलग हैं, पर वे एक साझा उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यह उद्देश्य संविधान के संरक्षण के साथ जनता का कल्याण सुनिश्चित करना है। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री तथा न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधान न्यायाधीश उस नेतृत्व के प्रतीक हैं जो सरकार की दो महत्वपूर्ण शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उनकी व्यक्तिगत या धार्मिक आयोजन में सहभागिता परस्पर सम्मान तथा देश के प्रशासन में उनकी संबंधित भूमिकाओं की स्वीकारोक्ति है। गणेश पूजा भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो विवेक, समृद्धि तथा बाधाओं को हटाने का प्रतीक हैं। ऐसे आयोजन में एकसाथ आ कर दोनों नेताओं ने संदेश दिया है कि वे राष्ट्र के लक्ष्यों के प्रति एकजुट हैं तथा सबके कल्याण के लिए ईश्वर से आर्शीवाद प्राप्त कर रहे हैं। इस कृत्य को 'अनुपयुक्त' बताना इस तथ्य को अनदेखा करना होगा कि व्यक्तिगत रूप से साथ आना भारत के संवैधानिक ढांचे के प्रति साझा जिम्मेदारी का निर्वहन है। भारत के प्रधान न्यायाधीश के आवास पर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री की सहभागिता की आलोचना करने वालों को याद रखना चाहिए कि गणपति पूजा करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का अंतर्निहित अंग है। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इसे पुनर्जीवित करते हुए इसके गहन लक्ष्यों- एकता, राष्ट्रवाद तथा सामूहिक शक्ति पर जोर दिया था। गणेश पूजा के महत्व को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में गणेश पूजा केवल धार्मिक आयोजन न होकर एक शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक है जिसने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एकजुटता, एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। ऐसे आयोजन की आलोचना कर आलोचक उन मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी स्थापना लोकमान्य तिलक ने इस त्योहार के माध्यम से की थी। इस भारतीय परंपरा में 'कर्ता' का अर्थ परिवार के प्रमुख या प्रबंधक से है जो पूरे परिवार की भलाई का जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश अपने संबंधित क्षेत्रों- कार्यपालिका और न्यायपालिका के 'कर्ता' के रूप में कार्य करते हैं। भले ही उनकी भूमिकायें अलग हों, पर उनके उद्देश्य अक्सर समान होते हैं, खासकर इनका संबंध राष्ट्रीय हितों, कानून और न्याय से होता है।

इस प्रकार एक धार्मिक आयोजन में साथ आ कर उन्होंने अपने संस्थागत अलगाव के बावजूद यह प्रदर्शित किया ह कि वे किसी व्यापक व महान लक्ष्य, यानी जनता के कल्याण तथा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कार्यपालिका के कर्ता के रूप में प्रधानमंत्री सरकार चलाने, कानूनों का क्रियान्वयन करने तथा देश का विकास सुनिश्चित करने के जिम्मेदार हैं। इसी तरह न्यायपालिका के कर्ता के रूप में भारत के प्रधान न्यायाधीश सुनिश्चित करते हैं कि न्याय को लागू किया जाए तथा कानूनों की व्याख्या उचित व न्यायोचित तरीके से कर उनका क्रियान्वयन हो। ये भूमिकायें एक दूसरे की पूरक हैं और सम्मान तथा एकता की सार्वजनिक अभिव्यक्ति हैं। ऐसे में एक धार्मिक आयोजन में साथ भाग लेने से केवल यह समझदारी मजबूत होती है कि प्रशासन के इन दोनों स्तंभों के बीच समझदारी और समन्वय बना हुआ है। ऐसे में कोई संकुचित दिमाग वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री के गणेश पूजा में भाग लेने की गलतियां निकाल सकता है। अक्सर ऐसी आलोचना की जड़ें देश के व्यापक प्रशासन में कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमित समझदारी में होती हैं। सद्भावना और एकता के ऐसे संकेतों की आलोचना इन शाखाओं के बीच सहयोग के महत्व को अनदेखी करना होगा, जबकि यह लोकतंत्र के अच्छी तरह कामकाज के लिए जरूरी है। गणेश पूजा में शामिल होकर प्रधानमंत्री तथा प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्र के व्यापक कल्याण हेतु एकसाथ काम करने की प्रतिबद्धता प्रकट की है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस की अपने कार्यकाल में अनेक अवसरों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने या उसे प्रभावित करने के आरोप लगे थे। सभी प्रबुद्ध नागरिकों के मन में इसका एक उदाहरण प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.एम. सीकरी ने 25 अप्रैल, 1973 को अपनी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय का परिवर्तनकारी 'केशवानंद भारती फैसला' दिया था। इसमें कहा गया था कि संसद संविधान की 'मूल संरचना' में बदलाव नहीं कर सकती है। इस फैसले से अपने संविधान संशोधन की योजनाओं में सीमाबंधन के कारण नाराज इंदिरा गांधी ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों-जस्टिस के.एस. हेगड़े, जे.एम. शीलत व ए.एन.ग्रोवर को 26 अप्रैल को पीछे छोड़ दिया था।

इस प्रकार सरकारी दृष्टिकोण के कम आलोचक जस्टिस ए.एन. रे को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था। इस कृत्य ने सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट संदेश दिया था और इससे 'हीबियस कार्पस मामले', यानी एडीम जबलपुर में फैसला प्रभावित हुआ था। 25 जून, 1975 को घोषित आपातकाल में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार समेत मूलाधिकारों को स्थगित रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति आदेश को चुनौती देने वाली याचिकायें सुनी थीं। अटार्नी जनरल नीरेन डे ने कहा था कि आपातकाल के दौरान देश में कोई न्यायिक उपचार लागू नहीं हो सकता है। इस पर जस्टिस खन्ना ने अटार्नी जनरल से आपातकाल के दौरान गंभीर उल्लंघनों, जैसे पुलिस द्वारा की गई हत्याओं पर न्यायिक उपचार पर सवाल पूछा था। अटार्नी जनरल ने स्वीकार किया था कि इस समय कोई न्यायिक रास्ता नहीं है। इस विवादास्पद स्वीकृति के बावजूद बहुमत ने फैसला दिया था कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस खन्ना ने इसका विरोध किया, पर बाद में उनको पीछे छोड़ कर जनवरी, 1977 में एम.एच. बेग को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया। नवंबर, 1976 में कांग्रेस ने 42वां संशोधन परस किया जिसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को धक्का दे कर एक ज्यादा तानाशाही सरकार बनाना था। भारत के प्रधान न्यायाधीश के आवास पर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री की सहभागिता परस्पर सम्मान तथा एक दूसरे की भूमिकाओं एवं शक्तियों की स्वीकृति है। ऐतिहासिक रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस के उलट यह कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच स्वस्थ संबंधों का संकेत देता है। प्रधानमंत्री की धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थिति न्यायपालिका के कामकाज या उसकी निर्णय प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। सम्मानपूर्वक सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों में सहभागिता तथा राजनीतिक लाभ के लिए न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप में यह अंतर कांग्रेस युग से तुलना में साफ दिखता है।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रधान न्यायाधीश के आवास पर गणेश पूजा में सहभागिता एक ऐसा कृत्य है जो भारत के एकता, परस्पर सम्मान व समावेशन के मूल्यों को प्रकट करता है। केवल संकुचित दृष्टिकोण या विभाजनकारी राजनीतिक उद्देश्यों की सोच वाले लोग ही इसकी आलोचना कर सकते हैं। यह आयोजन न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच स्वस्थ संबंधों का द्योतक है जो संविधान को सम्मान देने तथा राष्ट्र के कल्याण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यरत हैं। अत: इसकी आलोचना करने के बजाय इसे भारत की लोकतांत्रिक व सांस्कृतिक भावना में सामंजस्य व एकता के उत्सव की तरह देखा जाना चाहिए।

# महिला अपराधों में त्वरित न्याय आवश्यक

**विकास तिवारी**
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

सुरक्षा दुनिया भर में एक बुनियादी चिंता का विषय बनी हुई है, जहां बलात्कार और दुर्व्यवहार के व्यापक मुद्दे हर दिन लाखों महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करते हैं। इन जघन्य अपराधों का गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्तिगत पीड़ितों से आगे बढ़कर परिवारों, समुदायों और समाजों को भी प्रभावित करता है। इसके परिणाम सिर्फ़ शारीरिक या भावनात्मक ही नहीं होते, बल्कि सामाजिक भी होते हैं, जो अपना स्थायी निशान छोड़ते हैं जो विश्वास और सामंजस्य को कमज़ोर करते हैं। बलात्कार और दुर्व्यवहार के मूल में सामाजिक दृष्टिकोण और गहराई से जड़ जमाए हुए सत्ता असंतुलन का एक जटिल जाल है।

अक्सर, अपराधी इन अपराधों का इस्तेमाल नियंत्रण के उपकरण के रूप में करते हैं, अपने पीड़ितों पर प्रभुत्व जताते हैं। बलात्कार के विनाशकारी परिणाम शारीरिक चोट से लेकर भावनात्मक आघात, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि मृत्यु तक हो सकते हैं। पीड़ितों द्वारा झेले गए मनोवैज्ञानिक नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, और समाज पर इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया, वह था कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर का बलात्कार और हत्या।

इस क्रूर अपराध ने कुख्यात निर्भया कांड की याद दिला दी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। एक बार फिर, इसने केंद्र और राज्य सरकारों के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया: क्या न्याय व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ अपराधों को पर्याप्त रूप से संबोधित कर रही है?

क्या पीड़ितों को वास्तव में वह न्याय मिल रहा है जिसकी वे मांग कर रही हैं? एक और कुख्यात उदाहरण 1992 का अजमेर सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेल कांड है, जिसमें 100 से अधिक लड़कियों को अश्लील तस्वीरों के साथ ब्लैकमेल किया गया था, जिनमें से कई के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस मामले में न्याय 32 साल बाद ही मिला, जिसमें छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह चौंकाने वाली देरी एक बार फिर इस बात पर चिंता जताती है कि क्या भारतीय न्याय व्यवस्था यौन हिंसा के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है। 1.5 बिलियन की आबादी वाले भारत में न्याय में तेजी लाने के लिए 750 से अधिक फास्ट-ट्रैक कोर्ट हैं। फिर भी, अजमेर सामूहिक बलात्कार, निर्भया, उन्नाव और बलरामपुर जैसे मामले दशकों तक चलते रहते हैं।

न्याय की धीमी गति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देश में सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सामूहिक विफलता को दर्शाती है। इससे यह सवाल उठता है: क्या हमें यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधार की आवश्यकता है?

वैश्विक परिदृश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण दिखाता है। उदाहरण के लिए, यू.के. ने हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए एक विधेयक पारित किया है, जो इसे इस्लामी आतंकवाद के बराबर मानता है। डेनमार्क, आइसलैंड और स्विटजरलैंड जैसे कई यूरोपीय देशों ने %जीरो टॉलरेंस% नीतियों के तहत कड़े कानून अपनाए हैं, जिनमें यौन हिंसा के दोषियों के लिए मृत्युदंड भी शामिल है। ये उदाहरण भारत के लिए संभावित मॉडल पेश करते हैं, जिस पर वह विचार कर सकता है, क्योंकि वह लिंग आधारित हिंसा के अपने संकट से जूझ रहा है। बलात्कार और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो इन अपराधों के मूल कारणों को संबोधित करता है। सहमति, स्वस्थ संबंधों और सम्मान के बारे में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक शुरुआती बिंदु हैं।

समुदायों को शामिल करना, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चर्चाओं में पुरुषों और लड़कों को शामिल करना, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और ऐसे अपराधों की व्यापकता को कम करने में मदद कर सकता है।

पीड़ितों के लिए परामर्श और कानूनी सहायता जैसी सुलभ सहायता सेवाएँ प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सेवाएँ पीड़ितों को ठीक होने और न्याय पाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों को मजबूत करने और अपराधियों के लिए त्वरित जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतिगत सुधार भी महत्वपूर्ण होते हैं।

महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना बलात्कार और दुर्व्यवहार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर किया जा सकता है, जो हिंसा के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद करता है, और सुरक्षित स्थानों को बढ़ावा देता है जहां महिलाएं बिना किसी डर के घटनाओं की रिपोर्ट कर सकती हैं। पीड़ितों को हिंसा के खिलाफ़ बोलने के लिए प्रोत्साहित करने से इन अपराधों के इर्द-गिर्द अक्सर होने वाली चुप्पी को तोड़ने में मदद मिल सकती है, कलंक को दूर किया जा सकता है और दूसरों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

आज के डिजिटल युग में, तकनीक महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सुरक्षा ऐप जैसे अभिनव उपकरण, जो महिलाओं को आपात स्थिति में परिवार या दोस्तों को सचेत करने की अनुमति देते हैं, और पीड़ितों के लिए ऑनलाइन सहायता प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा और सहायता के नए रास्ते प्रदान करते हैं। डेटा एनालिटिक्स हिंसा के पैटर्न और हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे अधिकारी रोकथाम के प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित कर सकते हैं।

अंतत:, महिलाओं की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों और सरकारों की भागीदारी की आवश्यकता है। बलात्कार और दुर्व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करके और विभिन्न स्तरों पर समाधान लागू करके, हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां महिलाएं और लड़कियां हिंसा के डर से मुक्त रहें। यह निर्णायक कार्रवाई का समय है।

महिलाओं की सुरक्षा को एक बाद की बात के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के एक बुनियादी स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। केवल एक साथ काम करके ही हम सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत दुनिया बना सकते हैं।

## आप की बात

### कांग्रेस के इरादे

**तीन परिवारों** ने मिल कर जम्मू-कश्मीर को अब तक बर्बाद किया और अपना घर भरा। इनसे कश्मीरी जनता को छुटकारा दिलाने के लिए अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने अलविदा कह दिया। तीन परिवारों-नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी व कांग्रेस ने अपने और अपनी पार्टी के भले के लिए ही इसे लागू कर रखा था। आज प्रदेश आतंकियों से मुक्त हुआ है और पूरे देश से आकर लोग वहां घूम रहे हैं। कश्मीर में व्यापार, पर्यटन व रोजगार बढ़ रहा है। वहां सिनेमा की शूटिंग हो रही है जो बरसों से आतंकवाद के कारण बंद थी। भाजपा सरकार के इन असाधारण व उल्लेखनीय कामों की प्रशंसा करने के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि 20 सीट और आ जाती तो भाजपा के लोग जेल में होते। जिस लाल चौक पर तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री जाने से डरते थे वहां आज राहुल व प्रियंका समेत आम लोग आराम से घूम रहे हैं। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर समेत सारे देश को फिर उन अंधकारमय दिनों में वापस ले जाना चाहती है, जब आतंकी कहीं भी हमला करते थे और जनता को अनजानी चीजें न छूने की सार्वजनिक घोषणायें की जाती थीं? देश की जनता को खड़गे के बयान से कांग्रेस के इरादे समझ लेने चाहिए कि उसे केवल अपने सुख और सत्ता की चिन्ता है।

**-शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

### बेलगाम वक्फ बोर्ड

**वक्फ** बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों ने तो रेलवे प्लेटफार्म तक नहीं छोड़े। वह बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से पहले कुछ इंटे रख कर सरकारी जमीन पर कब्जा शुरू करता है। थोड़े दिन बाद वहां निर्माण शुरू हो जाता है, लोबान के धुएं की खुशबू आने लगती है, वहां कोई कथित पीर बाबा अपना झोपड़ा बना कर झाड़-फूंक शुरू कर देता है। फिर एक-एक फीट कर उस जगह का दायरा बढ़ता जाता है। धार्मिक स्थल पर कुछ भी एक्शन लेने से लगभग सभी कर्मचारी-अधिकारी भयग्रस्त रहते हैं। इस प्रकार वक्फ बोर्ड की जमीन बढ़ती रहती है। पूरे देश में वक़्फ़ बोर्ड की अधिकांश जमीन इसी तरह कब्ज़ा कर हथियाई हुई है। मंदिरों की भूमि और चढ़ावे पर तो सरकार अपना अधिकार मानती है। लेकिन वक्फ बोर्ड तथा मस्जिदों पर कानून को मेहरबान बना दिया है। पिछली सरकारों ने एक खास समुदाय के वोटों के लिए वक्फ बोर्ड कानून से जमीनों पर कब्जा करने तथा चंद लोगों के मालदार होने का रास्ता खोल दिया है, जबकि इनका लाभ गरीब मुसलमानों को बिल्कुल नहीं मिलता है। मोदी सरकार जब इन भू-माफियाओं पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है तो इस्लाम खतरे में का शोर मचाया जा रहा है।

**- सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

### ट्रंप पर हमला

**अमेरिका** में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प की एक बार फिर हत्या का प्रयास हुआ है, दो महीने में दूसरी बार। हालांकि, इस घटना में ट्रंप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप के आस-पास के गोल्फकोर्स के बाहरी इलाके में एक बंदूकधारी को देखा गया। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने उस व्यक्ति पर गोली चलाई, लेकिन वह एक वाहन में भाग गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया ने संदिग्ध की पहचान रयान वेस्ले राउथ के रूप में की है। अब कम से कम दोनों प्रमुख पार्टियों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या देश से बन्दूक संस्कृति पर लगाम लगाई जाए या उसे इसी तरह रहने दिया जाय। 2023 में सामूहिक गोलीबारी की रिकॉर्ड संख्या के मद्देनजर सख्त अमेरिकी बंदूक कानूनों की मांगों हो रही है। लेकिन रिपब्लिकनों के साथ डेमोक्रेट पार्टी भी अमेरिकी हथियार लाबी के दबाव में है। हालांकि, ट्रंप को बंदूक कानून का समर्थक माना जाता है, पर हाल ही में कमला हैरिस ने भी कहा था कि उनके और उनके पति के पास बंदूक है। ऐसे में देखना होगा कि बंदूक कानून चुनाव का मजबूत मुद्दा बनता है या नहीं।

**- जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

### केजरीवाल का ढोंग

**शराब घोटाले** के षड्यंत्र में शामिल होने और 177 दिन जेल में रहकर अंतत: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अब वे इस्तीफा देने की चाल चल रहे हैं। यह उनके ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। वे दिल्ली विधानसभा का चुनाव नवम्बर में कराने की मांग करते हैं, पर विधानसभा भंग नहीं करना चाहते हैं। वे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की सोच सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हो सकता है। इससे आम आदमी पार्टी-आप में कुर्सी की लड़ाई छिड़ सकती है। उन्होंने बड़ी चालाकी से यह भी कहा कि उनके अलावा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी जनता का विश्वास मिलने तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल बार-बार जनता को भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहे हैं। देखना होगा कि इस बार वे कितना सफल होंगे। यह भी देखना होगा कि वे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे या अपने कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सलाह पर कांग्रेस को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

**-युगल किशोर शर्मा,** फरीदाबाद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
**responsemail.hindipioneer@gmail.com**
पर भी भेज सकते हैं।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

# अंधविश्वास का खूनी खेल

**अंधविश्वास** समाज में फैला ऐसा रोग है जिसने समाज की नींव खोखली कर दी है। अंधविश्वास किसी जाति, समुदाय या वर्ग से संबंधित नहीं है, बल्कि हर किसी के अंदर विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास केवल भारत में ही है। यह लगभग सभी देशों में है। अंधकार और मौत से सबको डर लगता है। सभी को सुख चाहिए दुख से सब डरते हैं। सबको धन-दौलत चाहिए। किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए तो किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जादू-टोना, भूत-प्रेत, आत्मा अवतरण आदि से संवाद और निदान के आडम्बर-प्रपंच की रचना की जाती है। जब भी समाज में गरीबी, बीमारी, बदहाली, बेरोजगारी इत्यादि को पूर्व जन्म के कर्मों और भाग्य से तोला जा रहा है तो लोगों की मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास कैसे मजबूत हो सकता है। झूठी आस्था के नाम पर अंधविश्वास व्यापार बन चुका है। हैरानी की बात है कि जिस भारत में वैदिक विज्ञान की पढ़ाई होती रही और हम ज्ञान और सम्पदा में विश्व गुरु कहलाएं वह देश अंधविश्वास की गिरफ्त में कैसे फंस गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले सुकमा के एक गांव में जादू-टोना करने के संदेह में दो दंपतियों और एक महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों को शक था कि पीड़ित परिवार के जादू-टोना करने से उन पर आपदाएं आ रही हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के ही बालौदाबाजार के कसडोल में एक ही परिवार के चार लोगों की पड़ोसी परिवार ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या दी। ऐसी वारदातों की खबरें अन्य राज्यों से भी आती रहती हैं। कभी कोई संतान प्राप्ति के लिए छोटे बच्चों की बलि दे देता है तो कभी डायन होने के संदेह में महिलाओं को मार दिया जाता है। अंधविश्वास के प्रभाव से पढ़े-लिखे लोग भी अछूते नहीं हैं।

**तर्कवादी कहते हैं कि यह दुख की बात है कि एक ऐसा देश जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है और अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक भेजे जा रहे हैं, वहां इंसानों की बलि दी जाती है और बेमतलब के रीति-रिवाज माने जाते हैं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच के अंतर के बारे में तर्कवादी कहते हैं, "अगर कोई रिवाज उसके पीछे के तर्क को लेकर सवाल उठाए बिना माना जाता है तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिवाज के पीछे के तर्क को परख नहीं पाता तो यह खतरनाक हो सकता है।" उन्हें लगता है कि हल्दी, मुर्गी, पत्थरों, संख्याओं और रंग जैसी चीजों को शक्तिशाली समझना अवैज्ञानिक है और इन्हें वैज्ञानिक कहे जाने के कारण कई जानें जाती हैं।**

तर्कवादी कहते हैं कि यह दुख की बात है कि एक ऐसा देश जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है और अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक भेजे जा रहे हैं, वहां इंसानों की बलि दी जाती है और बेमतलब के रीति-रिवाज माने जाते हैं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच के अंतर के बारे में तर्कवादी कहते हैं, "अगर कोई रिवाज उसके पीछे के तर्क को लेकर सवाल उठाए बिना माना जाता है तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिवाज के पीछे के तर्क को परख नहीं पाता तो यह खतरनाक हो सकता है।" उन्हें लगता है कि हल्दी, मुर्गी, पत्थरों, संख्याओं और रंग जैसी चीजों को शक्तिशाली समझना अवैज्ञानिक है और इन्हें वैज्ञानिक कहे जाने के कारण कई जानें जाती हैं।

आज सड़कों, चौराहों और बस स्टैंडों पर बंगाली बाबा के पोस्टर और पर्चे आप को आसानी से मिल जाएंगे। तथाकथित तांत्रिकों ने अब तो अपनी वेबसाइट भी शुरू कर रखी है। वशीकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती कई वेबसाइटें आप को मिल जाएंगी जिनमें प्यार व जिंदगी से जुड़ी किसी समस्या को हल करने के दावे किए गए हैं। सवाल भी ईमेल के जरिए लिए जाते हैं और अपॉइंटमेंट लेनी हो तो भी ईमेल के जरिए। आप को उपाय तब बताया जाएगा जब आप उनके खाते में पैसे डालते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जादू-टोने और काले जादू के शक में लोगों को मार देने के आंकड़े काफी हैरान कर देने वाले हैं। दार्शनिक और वैज्ञानिक कहते हैं कि जब राज्य धर्म को राज्य मंदिर मिलन परिसर के विचार के साथ मिला रहे हो तो यह समाज के लिए नुक्सानदेह हो सकता है। कौन नहीं जानता कि डाक्टर दभोलकर, गोविंद पानसरे, एन.एम. कलबुर्गी की हत्याएं इसलिए की गई क्योंकि वे अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र का विरोध कर रहे थे। समस्या यह भी है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों में भी तंत्र-मंत्र बसा हुआ है।

भारत में कई तथाकथित तांत्रिक भी हुए हैं जो सत्ता के काफी करीब रहे। राजनीतिक दलों के सर्वोच्च नेता भी उनकी शरण में जाते थे। चुनाव जीतने के लिए गोपनीय ढंग से बड़े-बड़े अनुष्ठान भी कराए जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में तांत्रिक बाबा सत्ता के समानांतर केन्द्र चलाने की हैसियत में भी पहुंचते रहे हैं। आज के बाबा बहुत आधुनिक हो चुके हैं। जो लोग अंधविश्वासी होते हैं उन्हें फंसाना इनके बाएं हाथ का काम है। आज के राजनीतिज्ञ भी ऐसे तथाकथित बाबाओं का गोपनीय ढंग से सहारा लेते हैं। कौन नहीं जानता कि वर्तमान में तंत्र-मंत्र का जाल फैलाने वाले बाबाओं ने पॉवर, सैक्स, हथियार, मनी और पॉवर ब्रोकिंग का कॉकटेल बनाया हुआ है और बड़ी-बड़ी डील की जाती है। अब सवाल यह है कि अंधविश्वास के खूनी खेल पर कैसे रोक लगाई जाए। लगातार हो रही घटनाएं बार-बार इस बहस को हवा दे रही हैं कि भारत में एक राष्ट्रीय अंधविश्वास विरोधी कानून होना चाहिए। अंधविश्वासी प्रयासों पर रोक लगाने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों ने कानून बना रखे हैं लेकिन यह कानून इतने प्रभावशाली नहीं हैं। राज्यों के कानून एक आधार प्रदान करते हैं जबकि एक राष्ट्रीय अंधविश्वास विरोधी कानून खतरनाक मान्यताओं को खत्म करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। यह भी सच है कि कोई भी कानून अपराधों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता लेकिन अंधविश्वास के नाम पर शोषण करने वालों को दंड दिलाने में सक्षम हो सकता है। समाज को खुद और अपने बच्चों को वैज्ञानिक नजरिए से सोचना, सीखना चाहिए और जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए ताकि भविष्य में विश्वास अंधविश्वास में न बदल जाए।

**आदित्य नारायण चोपड़ा**
Adityachopra@punjabkesari.com

## सख्त कानून की दरकार लगा रहे...

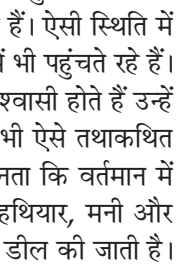

एक के बाद एक इस्तीफों का दौर जारी है,
शायद चुनावी पैंतरेबाजी में अब इस्तीफों की बारी है,
भले ही इसे कोई अग्नि परीक्षा तो कोई जनता की मर्जी का नाम बता रहे हैं,
पर वास्तव में आम जनमानस भ्रष्टाचार और औरतों की-
सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून की दरकार लगा रहे हैं...!!!

**गीता पाढा**

# प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 'सेवा पर्व' मनाने का अवसर

**प्रधानमंत्री** नरेंद्र मोदी मंगलवार को 74 साल के हो जाएंगे जिससे उनकी दशकों की सार्वजनिक सेवा में एक और शानदार साल जुड़ जाएगा। पीएम मोदी का जन्मदिन किसी भी अन्य कार्य दिवस की तरह ही है लेकिन यह 'सेवा पर्व' मनाने का अवसर भी है जो एक पखवाड़ा उत्सव है, जिसे भारतीय जनता पार्टी हर साल नागरिक कल्याण और मानवता को ध्यान में रखकर निस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित करती है।

17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार तीन कार्यकाल (2001-14) तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और अब वह रिकॉर्ड तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। हर साल की तरह इस बार भी भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को 'सेवा पखवाड़ा' या 'सेवा पर्व' शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत देशभर में रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।

इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान, मोदी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने बढ़ावा दिया था, जिसमें दावा किया गया कि इस अभियान ने 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राजस्थान की प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह पर 4000 किलो शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। गुजरात के सूरत में कई व्यापारियों ने 17 सितंबर को अपने उत्पादों पर 10 से 100% तक की छूट की घोषणा की है। यह छूट होटल, बाजार, परिवहन सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में अपना जन्मदिन कुछ इस अंदाज में मनाया... साल 2023- पिछले साल पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन देश के किसानों, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक गेम चेंजर योजना की घोषणा करके मनाया था। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को 'पीएम विश्वकर्मा योजना' शुरू की, इसका लक्ष्य कारीगरों को कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। पीएम मोदी ने दो प्रमुख परियोजनाओं - इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (आईआईसीसी) और दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार भी शुरू किया था। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके शुभचिंतकों ने जमकर जश्न मनाया और उनकी उम्र के प्रतीक के रूप में पारंपरिक केक की जगह 73 किलो का लड्डू केक काटा। हनुमान मंदिर में हर्षोल्लास के साथ 'अखंड रामायण पाठ' का भी आयोजन किया गया।

साल 2022, 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी का जन्मदिन बेहद ही खास रहा। उन्होंने देश से विलुप्त हो चुके चीतों को बसाने के लिए 'प्रोजेक्ट चीता' शुरू किया। जिसके तहत नामीबिया से आठ चीतों को विशेष विमान से मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। पीएम मोदी ने खुद अपने जन्मदिन पर उन चीतों को बाड़े में छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने अपने कैमरे से तस्वीरें भी खींची थी। साल 2021 - उन्होंने इस साल का जन्मदिन समारोह एक विशेष क्षण को समर्पित किया था, क्योंकि देश ने एक ही दिन में 2.26 करोड़ कोविड टीकाकरण का अद्भुत देने वाला रिकॉर्ड बनाया था। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को गति देने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया।

साल 2020 - साल 2020 में पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं मनाया गया। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने 'सेवा सप्ताह' के तहत शिविर और हेल्प डेस्क का आयोजन किया था। जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया, जबकि कई जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। साल 2019 - इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में 'नमामि नर्मदा' उत्सव में भाग लिया। यह साल बांध के 138.88 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर तक भरने के उपलक्ष्य में मनाया गया। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। साल 2018 - प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों के साथ मनाया था। इसके साथ पीएम मोदी ने छात्रों को कई उपहार भी भेंट किए थे।

**(आईएएनएस)**

# सर्द ब्रिटेन में कश्मीर को लेकर गर्मी क्यों?

**डा. विजय दर्डा**
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

**'कश्मीर फाइल्स'** फिल्म को लेकर दुनिया भर में मशहूर हुए फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने पिछले सप्ताह जब ऑक्सफोर्ड डिबेट में जाने से मना कर दिया तो यह खबर सुर्खियों में आ गई लेकिन क्या आपको पता है कि विवेक जब 2022 में ऑक्सफोर्ड के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे तो ऐन मौके पर कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। कारण यह था कि मुट्ठी भर पाकिस्तानियों ने विरोध जता दिया था।

यह पुरानी घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि विवेक अग्निहोत्री को ऑक्सफोर्ड ने फिर से एक डिबेट के लिए आमंत्रित किया था जिसका विषय था 'सदन स्वतंत्र कश्मीर राज्य में विश्वास करता है' जरा सोचिए कि ऐसे एकतरफा विषय पर क्या कोई हिंदुस्तानी बहस में भाग लेना पसंद करेगा? पूरे विश्व को पता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां तक पाकिस्तान के कब्जे वाला और पाकिस्तान द्वारा चीन को गलत तरीके से उपहार में दिया गया कश्मीर का हिस्सा भी भारत का अभिन्न अंग है। जब वह हमारा अंग है तो ऐसे किसी विषय का सवाल ही पैदा नहीं होता। विवेक ने ऑक्सफोर्ड को सही जवाब दिया कि बहस का विषय भारत की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती है, और यह मुझे अस्वीकार्य है, मैं इसे न केवल अप्रिय बल्कि अपमानजनक मानता हूं, कश्मीर बहस का नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी का विषय है। ऑक्सफोर्ड बौद्धिक खेल के लिए घावों को फिर से न कुरेदे।

मैं विवेक से बिल्कुल सहमत हूं। ऑक्सफोर्ड तो क्या, दुनिया के किसी देश का सदन भी यदि जम्मू-कश्मीर को हमसे जुदा करने की बात भी जुबां पर लाए तो हमें वह कदापि मंजूर नहीं। जहां तक ऑक्सफोर्ड का सवाल है तो मेरे मन में बार-बार यह सवाल उठता है कि ब्रिटेन की हालत तो खुद खराब है, वह देश भीषण समस्याओं से जूझ रहा है। बेरोजगारी, आर्थिक संकट और आरोग्य सेवा में कमी से पूरा देश जूझ रहा है। कहने का मतलब है कि खुद का घर तो संभल नहीं रहा है, दूसरे के घर में झांक रहे हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्द ब्रिटेन में कश्मीर को लेकर गर्मी क्यों बढ़ी हुई है? ऑक्सफोर्ड क्या किसी का तोता बना हुआ है जो अपने अदृश्य मालिक या संचालनकर्ता की भाषा बोल रहा है? ब्रिटेन को समझना चाहिए कि फूट डालो और राज करो का जमाना चला गया। उसे ऐसी हरकतों से दूर रहना चाहिए, मुझे याद आ रहा है कि जब अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ था तब भी ऑक्सफोर्ड ने बहस का आयोजन किया था जिसका विषय था 'क्या कश्मीर का विशेष अधिकार हटाना चाहिए था?' उसमें भाजपा नेता बैजयंत पांडा और वामपंथी नेता मरहूम सीताराम येचुरी ने भाग लिया था। मैं तब भी सोच रहा था कि ऐसी किसी बहस में भाग ही क्यों लेना?

मैं स्पष्ट कर दूं कि एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक और स्वतंत्र विचारों का घनघोर पक्षधर होने के नाते मैं मानता हूं कि हर विषय पर बहस होनी चाहिए लेकिन सवाल है कि जब किसी षड्यंत्र के तहत बहस किए जाने का अंदेशा हो तो हम क्यों जाएं? विवेक को जिस बहस के लिए बुलाया गया था उसमें पाकिस्तान के भी किसी वक्ता को आमंत्रित किया गया था। निश्चित रूप से इस बहस के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को वैश्विक स्तर पर तूल देने की कोशिश की जाती।

बहस से गुरेज नहीं है, बहस के विषय से गुरेज है, भारत सरकार को भी इस तरह के विषय पर आयोजन की मुखालफत करनी चाहिए। बहस करना है तो इस विषय पर कीजिए कि कश्मीर में आतंकवाद ने अब तक 40 हजार से ज्यादा जानें ले ली हैं। एक पूरी पीढ़ी जन्म से लेकर जवानी पार तक पहुंच गई लेकिन उसने दुनिया नहीं देखी, न स्कूल देखे, न खेल के मैदान देखे, न फिल्में देखीं। उसने देखा तो बस लादा गया आतंकवाद जिसने बचपन छीन लिया, जवानी छीन ली, महिलाओं को बेवा बना दिया, मां की कोख सूनी कर दी।

चीन में दस लाख से ज्यादा वीगर मुसलमानों की दर्दनाक जिंदगी की बात ऑक्सफोर्ड क्यों नहीं करता? उसे केवल कश्मीर ही नजर आता है? चीन की बात वह इसलिए नहीं करता क्योंकि चीन के साथ वह गलबहियां डाले हुए है। वहां ऑक्सफोर्ड चाइना फोरम नाम की संस्था चलती है, कौन सा देश क्या कर रहा है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता लेकिन यह जरूर जानता हूं कि भारत के खिलाफ हर तरफ से साजिशें चल रही हैं।

मैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर की इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि उपनिवेशवादियों का नजरिया भारत के प्रति नहीं बदला है। उन्हें यह बात पच नहीं रही है कि जो देश सैकड़ों साल गुलाम रहा, वह खुद को गुलाम बनाने वाले देश को भी आर्थिक तरक्की में बहुत पीछे छोड़ चुका है और जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है। हमारे पड़ोसियों को भी यह बात नहीं पच रही है, वे हर हाल में भारत को पीछे खींचना चाहते हैं, इसलिए आतंकवाद से लेकर दूसरे तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं लेकिन ऐसी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम लाख मुश्किलें खड़ी कर लो लेकिन अब भारत की रफ्तार रुकने वाली नहीं है।

इतिहास के पन्नों पर
दफन हो गईं त्रासदियां
ये नए दौर का भारत है
हम न रुकेंगे, न हम झुकेंगे
मेरे प्यारे दुश्मनों...
हम तो अब
आंख में आंख डालकर देखेंगे।

# कौन करवाता है योजनाबद्ध धर्मांतरण

**आर. के. सिन्हा**
पूर्व राज्यसभा सांसद

**भारत** के प्रत्येक नागरिक को किसी धर्म को मानने या ना मानने या फिर किसी भी धर्म से जुड़ने का अधिकार संविधान देता है, पर किसी प्रलोभन या गलतफ़हमी में योजनाबद्ध रूप से किसी तरह के धर्मांतरण को अपराध माना गया है। इस आलोक में उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत द्वारा हाल ही में अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी करार दिये गये 12 लोगों को उम्रकैद और चार अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाना महत्वपूर्ण है। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, धर्मांतरण करवाने के धंधे से जुड़े शातिर लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए (राष्ट्रद्रोह) के तहत सजा सुनायी गई। विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह के मुताबिक, उमर गौतम और मामले के अन्य अभियुक्त एक साजिश के तहत धार्मिक उन्माद, वैमनस्य और नफरत फैलाकर देशभर में अवैध धर्मांतरण का गिरोह चला रहे थे। उनके तार कई दूसरे देशों से भी जुड़े थे। इसके लिए आरोपी हवाला के जरिए विदेशों से धन भेजे जाने के मामले में भी लिप्त थे। वे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और दिव्यांगों को लालच देकर और उन पर अनुचित दबाव बनाकर बड़े पैमाने पर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे।

उमर गौतम को मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के साथ 20 जून 2021 को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया था। वह एक ऐसे अवैध संगठन का संचालन कर रहा था जो उत्तर प्रदेश में मूक- बधिर छात्रों और गरीब लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कराने में शामिल था। इस बात की पुरज़ोर आशंका जताई जा रही है कि इसके लिए उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से धन मिलता था। उमर गौतम पहले हिंदू था लेकिन उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और धर्मांतरण कराने के अवैध धंधे में सक्रिय हो गया। उसने करीब एक हजार गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया और उनकी मुस्लिमों से दूसरी या तीसरी शादी कराई है।

देखिए, भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर बहस तो होती रही है, होनी भी चाहिये। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें स्वेक्षा या स्वविवेक से धर्म बदलने का अधिकार भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म बदलने के अधिकार की बात तो कही गई है। पर उमर गौतम और उनके साथी तो गरीब-गुरुबा लोगों को लालच और जोर-जबरदस्ती से धर्मांतरण करवा रहे थे। गौतम और उनका गिरोह भूल गया था कि धर्म परिवर्तन सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है और समाज में भयंकर नफरत पैदा कर सकता है। भारत में धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक सभी पहलू शामिल हैं।

कुछ साल पहले केरल के प्रतिष्ठित फ़िल्म निर्माता निर्देशक अली अकबर और उनकी ईसाई पत्नी लूसीअम्मा ने आर्य समाज में हवन के जरिए हिन्दू धर्म अंगीकार कर लिया था। आर्य समाज के स्वामी जी द्वारा उनका नया नामकरण भी कर दिया गया है। अली अकबर को नया नाम मिला था राम सिम्हन। हिन्दू धर्म ही क्यों? यह प्रश्न पूछे जाने पर अली अकबर ने कहा था, 'क्योंकि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति है। यहां नर्क में जाने का डर नहीं है। आप एक इंसान की तरह जी सकते हैं क्योंकि भगवान आपके अंदर हैं। अपने भीतर ईश्वर को देखना एक महान विचार है।' कहते हैं कि राम सिम्हन केरल में हिंदू धर्म अपनाने वाले पहले मुसलमान थे लेकिन, यह राम सिम्हन के स्वविवेकपूर्ण निर्णय को दर्शाता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक बात बहुत साफ है कि किसी को लालच देकर या जोर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना तो कतई सही नहीं माना जा सकता है। समझ नहीं आता कि कुछ धर्मों से जुड़े लोग क्यों इसी फिराक में रहते हैं कि उनके धर्म से अन्य धर्मों को मानने वाले जुड़ जाएं। गुस्ताखी माफ, कई इस्लामिक और ईसाई संगठन इसी कोशिश में रहते हैं कि दूसरे धर्म को मानने वाले उनके मजहब का हिस्सा बन जाएं? यह कोई बात हुई क्या? फिर यदि बाकी धर्मों को मानने वाले लोग भी यही करने लगें, तो समाज में भाईचारा कहां और कैसे बचा रहेगा। अगर कोई अपने मन से उस धर्म को त्याग देता है, जिसमें उसका जन्म हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। उदाहरण के रूप में म्युजिक डायरेक्टर रहमान को ही लेते हैं। उन्होंने खुद ही हिन्दू धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार कर लिया। उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी इस्लाम अपना लिया। यहां तक तो सब ठीक है। पर कुछ तत्व सुदूर इलाकों में रहने वालों को अपना पाले में लाने की जुगाड़ में रहते हैं। इस सबकी तो हमारा संविधान अनुमति नहीं देता। जब गौतम जैसों पर एक्शन होता है तो कुछ कथित बुद्धजीवी अलाप करने लगते हैं। पिछले कई सालों से पंजाब से खबरें आ रही हैं कि राज्य में दलित सिखों को लालच देकर ईसाई धर्म से जोड़ा जा रहा है।

धर्म परिवर्तन को लेकर ईसाई धर्म के ठेकेदार भी कम नहीं हैं। बल्कि चर्चों से जुड़े प्रमुख लोग ईसाई धर्म के प्रचार में लगे हैं और मजदूर और गरीब तबके के लोगों को टारगेट बना कर उन्हें लाख या सवा लाख रुपया देकर पादरियों से मिला कर पक्का कागजी काम भी करवा लेते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी अभिव्यक्तियां लोग खूब शेयर करते रहते हैं। ऐसे ही एक पादरी के बारे में उत्तराखंड में शिफ्ट होने की बातें भी पिछले दिनों खूब वायरल हुई थी।

यह सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या भारत में धर्म प्रचार की अनुमति जारी रहनी चाहिए? कभी-कभी लगता है इस मसले पर देश में बहस हो ही जाए कि क्या भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता जारी रहे अथवा नहीं ? देखा जाए तो केवल धर्म पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिये। धर्म के प्रचार-प्रसार की छूट की कोई आवश्यकता ही नहीं। धर्म कोई दुकान या व्यापार तो है नहीं जिसका प्रचार-प्रसार करना जरूरी हो।

अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगाले तो देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के प्रचार की छूट दी थी। क्या इसकी कोई आवश्यकता थी? बेशक, भारत में ईसाई धर्म की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस और ईमानदारी से काम किया गया है। पर कहने वाले कहते हैं कि उस सेवा की आड़ में धर्मांतरण का ही मुख्य लक्ष्य रहा है।

उधर इस्लाम का प्रचार करने वाले बिना कुछ किए ही धर्मांतरण करवाने के मौके खोजते हैं। हालांकि मुसलमानों की शिक्षण संस्था अंजुमन इस्लाम ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। ये मुंबई में सक्रिय है। अब आप देखें कि आर्य समाज, सनातन धर्म और सिखों की तरफ से देश में सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह चल रहे हैं। पर इन्होंने किसी ईसाई या मुसलमान का धर्मांतरण का कभी प्रयास नहीं किया। आपको अपने धर्म को मानने की तो अनुमति होनी चाहिए, पर अपने धर्म का प्रचार करने या धर्मांतरण करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस : 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग : 011-30712224
विज्ञापन विभाग : 011-30712229
सम्पादकीय विभाग : 011-30712292-93
मैगजीन विभाग : 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

दैनिक जागरण

जीवन का उद्देश्य मिल जाने में ही उसकी सार्थकता है

# जनगणना में देरी

2021 में होने वाली जनगणना को लेकर ऐसे संकेत सामने आना ठीक नहीं कि उसमें न केवल देरी होगी, बल्कि वह 2027 से पहले संभव नहीं होगी। ऐसे संकेत इसलिए उभर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कि वह वस्तुतः कब शुरू होगी। जनगणना में देर होने की आशंका उभरने का एक कारण यह भी है कि इस बार बजट में उसके लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया। अब यदि अगले बजट में उसके लिए प्रविधान किया जाता है तो 2025-26 में ही जनगणना का काम शुरू हो सकता है। जनगणना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है और उसके पूरा होते-होते यदि 2027 बीत जाए तो हैरानी नहीं। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित की गई थी। यह ठीक ही था। इस भयावह महामारी से जूझते हुए जनगणना संभव नहीं थी, लेकिन उसके समाप्त होने के बाद तो वह सरकार की प्राथमिकता में शामिल होनी ही चाहिए थी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महामारी के दौर में भी अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाते रहे और कई अन्य बड़े आयोजन भी किए जाते रहे। यह सही है कि लोकसभा चुनाव के आसपास जनगणना कराना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें भी आम तौर पर उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, जो जनगणना करते हैं। समझना कठिन है कि यह क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा सका कि 2025 में जनगणना का काम हर हाल में शुरू हो सकता।

जनगणना में देरी होने का मतलब है सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और योजनाओं के निर्माण में 2011 के आंकड़ों से ही काम चलाने की मजबूरी। ध्यान रहे कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। इसके अतिरिक्त संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े सामने आने में देरी होती है तो फिर महिला आरक्षण लागू करने में भी विलंब हो सकता है। संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना तब संभव होगा, जब निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा और परिसीमन के लिए जनगणना के अद्यतन आंकड़े चाहिए होंगे। जनगणना में देरी से उसका चक्र प्रभावित होने की भी आशंका है, क्योंकि अभी यह कहना कठिन है कि 2031 में जनगणना कराने की आवश्यकता समझी जाएगी या नहीं? निःसंदेह मौजूदा सरकार के समक्ष यह दुविधा भी होगी कि जनगणना के साथ जाति गणना कराई जाए या नहीं? जाति गणना की मांग बढ़ती चली जा रही है और पिछले दिनों तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उसकी आवश्यकता जता दी। सरकार का जाति गणना पर जो भी फैसला हो, यह मानकर चला जाना चाहिए कि वह ऐसे जतन अवश्य कर रही होगी, जिससे जनगणना में अधिक विलंब न होने पाए।

# सकारात्मक पहल

विद्यार्थी जीवन सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी शिक्षकों का दायित्व है। अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन स्वयं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिक्षा क्षेत्र में गहन सुधार और प्रणालीगत बदलाव का आह्वान किया गया था। इसमें जीवन कौशल को पाठ्यक्रम के अंग के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की गई। इसी दिशा में पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी समग्र शिक्षा अभियान ने छठी से 12वीं कक्षा तक जीवन कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। छात्रों को जीवन कौशल की शिक्षा देना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बच्चों के विकास से जुड़ा मामला है। जीवन में होने वाले बदलावों के लिए व्यावहारिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आत्मप्रबंधन कौशल लाने में मदद करेगा। आज के समाज में इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। छात्रों के विकास के लिए जीवन कौशल की शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे चुनौतियों से लड़ना सीख सकें। इससे विद्यार्थी जीवन में तनाव और चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करने में मदद मिलेगी। समग्र मानसिक स्वास्थ्य के साथ सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। सभी जानते हैं कि बच्चे काफी समय स्कूल में बिताते हैं। अभिभावकों के साथ शिक्षकों का भी दायित्व है कि वे बच्चों की कमियों को समझें और उन्हें जीवन कौशल से अवगत करवाएं, ताकि वे विषम परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

**बच्चों को जीवन कौशल की शिक्षा देने के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे**

# नवनिर्माण के शिल्पकार

**योगी आदित्यनाथ**

**प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर ही कई बड़े निर्णय ले लिए हैं**

अवधेश राजपूत

नई विश्व व्यवस्था में आज भारत केंद्रीय भूमिका में है। बहुध्रुवीय हो चुकी विश्व राजनीति में भारत के बिना हर वैश्विक समूह अधूरा है। आपदाकाल में सहायता की आवश्यकता हो अथवा नीतिगत विषयों पर आम राय बनाने की जरूरत, दुनिया की दृष्टि भारत की ओर होती है। बीते एक दशक में विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। युद्धग्रस्त राष्ट्र भी समाधानकारी हस्तक्षेप पर जिन पर भरोसा करते हैं, वह मोदी ही हैं। रूस और यूक्रेन के मध्य तनावपूर्ण हालात हों या पश्चिम एशिया का संकट, हर वैश्विक तनाव के समाधान हेतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत केंद्र में है। 'मोदी हैं तो मुमकिन हैं', के भाव को आज न केवल देश मानता है, बल्कि महाशक्ति देशों को भी 'मोदी की गारंटी' पर विश्वास है।

अपने संकल्पों की सिद्धि, समस्याओं के समाधान और चिरआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह देश मोदी को 'भगीरथ' के रूप में देखता है। सुदूर किसी खेत में काम कर रही महिला किसान हो या किसी साफ्टवेयर कंपनी में कुछ नया प्रयोग कर रहा युवा, सीमा पर मुस्तैद जवान हो या विदेश में प्रवासरत भारतीय, सभी को मोदी की नीति, नीयत और निर्णयों पर भरोसा है। यही जनविश्वास मोदी को 'बड़े और कड़े' निर्णय लेने का सामर्थ्य देता है। अनुच्छेद 370 और 35 ए का हटना असंभव माना जाता था। कश्मीर में राष्ट्रध्वज जलाए जाते थे, संविधान का मखौल उड़ाया जाता था, लेकिन आज यह सब अतीत की बात है। नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति ने कश्मीर से एक देश में 'दो निशान-दो विधान' का कलंक मिटा दिया। आज घाटी में स्थापित होते नए उद्योग, चिनाब पर बनते एफिल टावर से ऊंचे रेलवे ब्रिज के चित्र देखने को मिलते हैं। नए भारत के नए कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव के लिए तत्पर है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ है। भारत 'स्व से साक्षात्कार' कर रहा है। पांच सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्रीअयोध्याधाम में भगवान श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पुनरुद्धार जैसे चिरप्रतीक्षित कार्यों से भारत की आस्था गौरवान्वित हुई है। आजादी के बाद से जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को पोसने वाले दलों के दलदल में फंसे देश को 2014 के बाद मुक्ति मिली। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, स्वनिधि, सौभाग्य, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, मातृ वंदना जैसी योजनाओं के भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन ने सामान्य भारतीय परिवारों के जीवन को सरल बनाया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' इसी नवीन कार्यसंस्कृति का प्राण है। 'अंत्योदय से सर्वोदय' का मंत्र आत्मसात करने वाली इस व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। पहली बार कृषि और किसान राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। आज किसानों को फसल बीमा, एमएसपी, सब्सिडी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर ही कई बड़े निर्णय ले लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कवर प्रदान किया और लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' लागू करने का निर्णय लिया।

विगत 10 वर्षों में जनधन, आधार और मोबाइल के रूप जैम-त्रिशक्ति का उपयोग करते हुए तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करके आम आदमी को सरकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैम का आशय है, खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल, गरीबों का अधिकतम सशक्तीकरण और जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार। प्रधानमंत्री की यह पहल एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी। यूपीआइ, रूपे कार्ड, डिजीलाकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग-अलग तरह के डिजिटल प्लेटफार्म्स, आम आदमी की दिनचर्या का अंग बन गए हैं।

पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक समुदाय भी समझ रहा है कि जो विकास स्थायी नहीं, वह वास्तविक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया है और हमारा देश इस आंदोलन के अग्रणी मार्गदर्शक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री की 'पंचामृत और लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फार एनवायरनमेंट' की पहल ने भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल माडल के रूप में प्रस्तुत किया है। दस वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2300 प्रतिशत बढ़ी है। 2014 के बाद से सौर ऊर्जा दरों में लगभग 70-80 प्रतिशत की कमी आई है। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली जैसी योजना के माध्यम से पूरा भारत अक्षय ऊर्जा से लाभान्वित हो रहा है।

कोविड महामारी के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध से उबरने का प्रयास कर रहे अनेक बड़े देश आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मोदी की कूटनीति और वित्तीय कुशलता के चलते इसी दौरान भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। आज वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की मेजबानी में संपन्न 'सेमिकान इंडिया' सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग के ग्लोबल हब बनने के अभियान का औपचारिक शुभारंभ था। प्रधानमंत्री ने कहा भी था, 'मेरा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो।' सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वह सब करने वाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान कोष की जो स्थापना की, वह हमारे नवाचारी युवाओं के लिए बड़ा संबल बनेगी।

यह सुखद दैवीय योग है कि देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और प्रधानमंत्री की जन्मतिथि एक ही दिन है। आज भारत विश्वनेता की भूमिका में भविष्य की आकांक्षाओं की आधारशिला पर गौरवशाली निर्माण कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस 'अमृत नव निर्माण' के शिल्पकार बन रहे हैं।

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

response@jagran.com

# विदेशी धरती पर बेलगाम राहुल गांधी

उमेश चतुर्वेदी

**विदेश यात्रा पर राहुल की बयानबाजी को प्रचार जरूर मिलता है, पर इससे भारत की छवि भी बिगड़ती है**




वाशिंगटन में एक सभा को संबोधित करते राहुल। प्रेट्र

महाभारत का एक प्रसंग है। वनवास के आखिरी दिनों में एक बार भीम ने देखा कि दुर्योधन को यक्ष बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। दुश्मन दुर्योधन को बंदी बनाया जाते देख भीम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। कुटिया पर लौटते ही इसकी जानकारी उन्होंने धर्मराज को दी, लेकिन युधिष्ठिर ने भीम की खुशी पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि आपस में भले ही हमारा बैर हो, लेकिन किसी बाहरी के लिए हम एक सौ पांच हैं। विदेशी धरती पर भारतीय राजनीति भी अपने घरेलू मुद्दों को लेकर इसी परंपरा को ही निभाती रही है, जिसे दुनिया ने 27 फरवरी, 1994 को जेनेवा में देखा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा था। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो भारत को सुरक्षा परिषद के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इसकी अनूठी काट खोजी। भारत का पक्ष रखने के लिए उस समय विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल जेनेवा भेजा, जिसमें तब के विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद सदस्य की भूमिका में थे। भारतीय राजनीति ने उस संकट का मिलकर सामना किया और पाकिस्तान का प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया।

राहुल गांधी अब नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस परंपरा में उनका कोई विश्वास नहीं है। वह जब भी विदेश जाते हैं तो ऐसे बयान देते हैं, जिनसे देशविरोधी मुद्दों को हवा मिलती दिखती है। गत दिनों अमेरिका दौरे पर गए राहुल ने कहा, 'आज भारत में लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें पगड़ी या कड़ा धारण करने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जाने में सक्षम होंगे। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।' इस बयान के जरिये राहुल गांधी विदेशी धरती पर यह जताने की कोशिश करते नजर आए कि भारत में सिख असुरक्षित हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने या गुरुद्वारा जाने से रोका जा रहा है? निश्चित तौर पर इसका जवाब न में है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान को अगर उनके विरोधी खालिस्तानी आंदोलन से जोड़कर देखें तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा द्वारा राहुल को 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाना भी स्वाभाविक है।

विदेशी धरती पर राहुल गांधी की बयानबाजी को वैश्विक प्रचार जरूर मिलता है, लेकिन इससे भारत की छवि लोकतंत्रहीन और तानाशाही वाले देश की बनती है। इस तरह राहुल दुनिया को यह बताने की कोशिश करते नजर आते हैं कि भारत में हर कोई खतरे में है और वहां नागरिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। पिछले साल अमेरिका में ही राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसके पहले 2022 में लंदन में कहा था कि भारत के आत्मा पर हमले हो रहे हैं और बिना आत्मा के देश कुछ भी नहीं होता। 2018 में जर्मनी दौरे पर गए राहुल ने कहा था कि मोदी के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। तब उन्होंने मोदी की तुलना ट्रंप से की थी। 2017 में अमेरिका में राहुल ने कहा था कि मोदी को देश की संघीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है और वह देश को बांटना चाहते हैं। दिलचस्प यह है कि बीते आम चुनाव में राहुल लगातार लोगों को डराते रहे कि भाजपा और मोदी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना के मूल में उनके आरक्षण संबंधी विचार ही हैं, लेकिन अमेरिका के हालिया दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर उन्होंने कह दिया कि जब भारत में बेहतर हालात होंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में आरक्षण बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। आरक्षण और जातिगत जनगणना वहां के बड़े मुद्दे हैं। विवाद बढ़ता देखकर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वह आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक करना चाहते हैं। राहुल ने अमेरिका में यह भी कह दिया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषियों से कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, संस्कृति और खानपान कमतर हैं।

बेलगाम बयानबाजी के जरिये राहुल गांधी का एक मकसद देश में जारी चुनावों में अपने पक्ष में माहौल बनाना भी रहता है, क्योंकि विदेशी धरती पर घट रही भारत से संबंधित घटनाएं पूरे देश का ध्यान खींचती हैं। इसके जरिये राहुल अपने वोटरों को लुभाने और अपना समर्थक आधार वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त भूल जाते हैं कि वह मामूली नेता नहीं हैं। पहले उनके बयानों को तवज्जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के बयानों के नाते मिलती थी, अब वह नेता विपक्ष की भूमिका में हैं। इसलिए उनके बयानों को और महत्व मिलना स्वाभाविक है। अब वह भी संविधान और राष्ट्र के प्रति उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना सत्ता पक्ष है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह जो भी बोलेंगे, नपा-तुला और जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे, लेकिन राहुल यहीं चूक रहे हैं। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों से भारत और भारत के बाहर स्थित देशविरोधी ताकतों का उत्साह बढ़ता है। राहुल के बयानों को लेकर कांग्रेस जिस तरह उनका बचाव करती दिख रही है, उससे लगता नहीं कि भविष्य में वह अपनी बयानबाजी को लेकर सचेत होंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## आध्यात्मिक प्रगति

बौद्धिक स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, जो समाज में नवाचार की कमी का कारण बनता है। यह स्वतंत्रता न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो उसका मन हमेशा भोजन के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार बौद्धिक स्वतंत्रता की कमी प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से शारीरिक और मानसिक प्रगति की योजना बनाने में रुकावट डालती है।

आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति के जीवन में गहरी मानसिक और आत्मिक उन्नति को संदर्भित करती है। यह प्रगति उस स्थिति की ओर इशारा करती है, जहां व्यक्ति आत्म-ज्ञान, जागरूकता और परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साधना, ध्यान और स्वयं की गहन खोज से होकर गुजरता है। यह प्रक्रिया आत्मा के भीतर की सच्चाई को पहचानने की यात्रा है।

आध्यात्मिक प्रगति के लिए नियमित साधना, मानसिक शांति और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करता है, तो उसकी आध्यात्मिक समझ और अनुभव में वृद्धि होती है। ध्यान, योग और आत्मा की खोज के माध्यम से व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को खोजता है और जीवन के उच्चतर उद्देश्यों को समझने में सक्षम होता है। आध्यात्मिक प्रगति और बौद्धिक स्वतंत्रता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बौद्धिक स्वतंत्रता आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा को सुगम और प्रभावी बनाती है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

# आत्मरक्षा के उपाय भी सीखें महिलाएं

सोनम लवंशी

बदलते समय के साथ महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के लचर होने की वजह से महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि महिलाएं स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और आत्मरक्षा के उपाय अपनाएं, क्योंकि सिर्फ रहनुमाई प्रयास इस दिशा में नाकाफी साबित हो रहे हैं। नारी कभी भी अबला नहीं रही है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हों या मां-दुर्गा और चंडी, ये ऐसी संदेश वाहक हैं, जिनके मुताबिक मातृशक्ति हर समय सशक्त और समर्थवान रहीं है। ऐसे में जब नवरात्रि का पर्व नजदीक है, तो हमारी बहन-बेटियों को यह प्रण लेना चाहिए कि अत्याचार किसी भी प्रकार का क्यों न हो! उससे निपटने के लिए उनको मोर्चा स्वयं संभालना होगा।

जिस समाज में प्रतिदिन औसतन 87 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हों और राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2022 में महिलाओं में खिलाफ दर्ज अपराधों की कुल संख्या 4,28,278 हो, उस समाज से महिलाएं आस करें कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा तो यह स्वयं को धोखा देने जैसा है। इसी वजह से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। महिलाएं जब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगी, तब तक समाज में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकेंगी। इसीलिए जरूरी है कि महिलाएं सुरक्षा के उपायों को अपनाएं।

**महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक समाज की मानसिकता और जागरूकता के स्तर का आईना होते हैं**

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक समाज की मानसिकता और जागरूकता के स्तर का आईना होते हैं। ऐसे में समाज की मानसिकता में बदलाव के साथ महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो-कराटे का प्रशिक्षण लेना चाहिए। यह न केवल शारीरिक हमलों से बचाव के लिए कारगर साबित होगा, अपितु यह उन्हें आत्मविश्वास से भी भरेगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, यौन उत्पीड़न के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में हमलावरों का लक्ष्य महिलाओं को कमजोर या असुरक्षित बनाना होता है। इस स्थिति में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण उन्हें इन खतरों का सामना करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा महिलाएं अपने साथ पेपर स्प्रे, इलेक्ट्रिक शाक गन और अलार्म डिवाइस जैसे सुरक्षा उपकरण रख सकती हैं। ये उपकरण किसी आपात स्थिति में निपटने में उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानूनी प्रविधान भी किए हैं, जैसे कि यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मतांतरण का खतरा

आरके सिन्हा ने अपने आलेख 'मत प्रचार की स्वतंत्रता पर हो पुनर्विचार' में उचित प्रश्न उठाया है कि संविधान निर्माताओं ने मत प्रचार की जो छूट दी थी क्या उसकी कोई आवश्यकता थी? वह भी भारत जैसे देश में जहां बिना 'सेक्युलरिज्म' रूपी किसी सिद्धांत के सदियों से सभी धर्म के लोग भयरहित होकर साथ-साथ रहते आए हैं। शायद यही कारण था कि संविधान निर्माताओं द्वारा मूल संविधान में सेक्युलर जैसा कोई शब्द भी नहीं रखा गया था। हालांकि कालांतर में कुछ स्वार्थी नेताओं ने इस शब्द को जोड़ दिया। ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक युग में प्रचार के द्वारा हर बढ़िया और हर खराब चीज बेच दी जाती है, लेकिन धर्म कोई चीज नहीं है, खासकर सनातन धर्म। यह अन्य मजहबों की तरह संगठित गिरोह जैसा नहीं है जिसे अपने जीवन के लिए निरंतर नए सदस्यों की आवश्यकता हो। यही कारण है कन्वर्जन जैसा कोई सिद्धांत किसी भारतीय धर्म में नहीं है। जैसा अरबी या वेटिकन मजहबों में दिखता है। इसलिए मत प्रचार के अधिकार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। नीति नियंताओं को इस पर विचार करना चाहिए।

युवराज पल्लव, धामपुर, बिजनौर

## आत्ममंथन करे आम आदमी पार्टी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की परवाह होती तो वह तभी त्यागपत्र दे दिए होते, जब आबकारी नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर किया गया था। 177 दिन जेल में रहकर अंततः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बाहर आकर अचानक इस्तीफा देने की विवशता समझ आ गई है। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री सुझाने की तकनीकी एवं कानूनी गलती कर बैठे तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। अभी विधानसभा की अवधि छह माह से कम बची है। मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों में मंत्री आतिशी, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, संदीप पाठक आदि के नाम बेशक चर्चा में हैं, किंतु आप दलित कार्ड खेलने की फिराक में है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पंद्रह दिन के अंतराल पर सरकारी बंगला खाली करना कानूनी आवश्यकता है। बेहतर होगा कि स्वाध्याय एवं सिंहावलोकन करते हुए आम आदमी पार्टी को अपने पाप धोने की कोशिश करनी चाहिए।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

## मेलबाक्स

## राहुल गांधी का नया एजेंडा

राहुल गांधी कांग्रेस को सुधारने के बजाय उसे जटिल समस्याओं में धकेल रहे हैं। उनकी राजनीति अब केवल भाषणों और अंतरराष्ट्रीय छवि तक सिमट गई है। वे जमीनी मुद्दों से लगातार दूर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी का नया एजेंडा सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे कांग्रेस को सुपरहिट बनाने का कोई मास्टरप्लान लेकर आए हैं, पर असल में ये प्लान किसके लिए है, यह सवाल कांग्रेस के ही लोग नहीं समझ पा रहे। राहुल का कहना है कि कांग्रेस को पुरानी धारणाओं से बाहर आकर कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आखिर पुरानी धारणाओं से चिपककर तो पार्टी दशकों से वहीं एक ही जगह खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि ये नया है क्या? अमेरिका जाकर भाषण देने से लेकर विदेशी मीडिया के सामने भारत की राजनीति की निंदा करने तक राहुल ने कांग्रेस को ग्लोबल बना दिया है, पर भारतीय मतदाता अभी तक इसको समझने के मूड में नहीं दिख रहे। राहुल की राजनीति अब सिर्फ भाषणों और आरोपों तक सीमित रह गई है। जब वे खुद को 'पप्पू' कहते हैं तो जनता यह सोचने लगती है कि यह आत्मविश्लेषण है या फिर कोई स्टैंड-अप कामेडी? शायद राहुल को यह अहसास नहीं है कि देश की राजनीति में स्टैंड-अप कामेडी ज्यादा समय तक नहीं चलती, यहां सीरियस मुद्दे चलाने पड़ते हैं। तो अब राहुल गांधी का 'नया एजेंडा' कांग्रेस को ऊपर ले जाएगा या फिर नीचे धकेलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये नई उड़ान ज्यादा ऊंचाई पर जाती नहीं दिख रही। अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

********

संपादकीय जागरण

(12) मंगलवार, 17 सितंबर, 2024: भाद्रपद शुक्ल - 14 वि. 2081

जीवन का उद्देश्य मिल जाने में ही उसकी सार्थकता है

# जनगणना में देरी

2021 में होने वाली जनगणना को लेकर ऐसे संकेत सामने आना ठीक नहीं कि उसमें न केवल देरी होगी, बल्कि वह 2027 से पहले संभव नहीं होगी। ऐसे संकेत इसलिए उभर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कि वह वस्तुतः कब शुरू होगी। जनगणना में देर होने की आशंका उभरने का एक कारण यह भी है कि इस बार बजट में उसके लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया। अब यदि अगले बजट में उसके लिए प्रविधान किया जाता है तो 2025-26 में ही जनगणना का काम शुरू हो सकता है। जनगणना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है और उसके पूरा होते-होते यदि 2027 बीत जाए तो हैरानी नहीं। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित की गई थी। यह ठीक ही था। इस भयावह महामारी से जूझते हुए जनगणना संभव नहीं थी, लेकिन उसके समाप्त होने के बाद तो वह सरकार की प्राथमिकता में शामिल होनी ही चाहिए थी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महामारी के दौर में भी अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाते रहे और कई अन्य बड़े आयोजन भी किए जाते रहे। यह सही है कि लोकसभा चुनाव के आसपास जनगणना कराना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें भी आम तौर पर उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, जो जनगणना करते हैं। समझना कठिन है कि यह क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा सका कि 2025 में जनगणना का काम हर हाल में शुरू हो सकता। जनगणना में देरी होने का मतलब है सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और योजनाओं के निर्माण में 2011 के आंकड़ों से ही काम चलाने की मजबूरी। ध्यान रहे कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। इसके अतिरिक्त संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े सामने आने में देरी होती है तो फिर महिला आरक्षण लागू करने में भी विलंब हो सकता है। संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना तब संभव होगा, जब निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा और परिसीमन के लिए जनगणना के अद्यतन आंकड़े चाहिए होंगे। जनगणना में देरी से उसका चक्र प्रभावित होने की भी आशंका है, क्योंकि अभी यह कहना कठिन है कि 2031 में जनगणना कराने की आवश्यकता समझी जाएगी या नहीं? निःसंदेह मौजूदा सरकार के समक्ष यह दुविधा भी होगी कि जनगणना के साथ जाति गणना कराई जाए या नहीं? जाति गणना की मांग बढ़ती चली जा रही है और पिछले दिनों तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उसकी आवश्यकता जता दी। सरकार का जाति गणना पर जो भी फैसला हो, यह मानकर चला जाना चाहिए कि वह ऐसे जतन अवश्य कर रही होगी, जिससे जनगणना में अधिक विलंब न होने पाए।

# निरंतरता जरूरी

सरकार के स्तर पर जनकल्याण की कई योजनाएं संचालित हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर किसानों-युवाओं से जुड़ी योजनाएं, यदि इनकी मानीटरिंग सही तरीके से हो और निरंतरता बनी रहे तो आमजन की बहुत सारी समस्या यूं ही हल हो जाएंगी। समस्या यह है कि योजना शुरू होती है, लेकिन कुछ समय के बाद कई कारणों से इसका फलाफल मिलता नहीं दिखता। सरकारी स्तर पर जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक कई योजनाएं संचालित हैं, जो एक आम आदमी के जीवन को सरल बनाने में मददगार हैं। यदि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा तंत्र अपनी इच्छाशक्ति का परिचय नहीं देता तो पूंजी के नुकसान के साथ-साथ आमजन की अपेक्षाओं पर भी कुठाराघात होता है। उदाहरण के तौर पर अरवल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक मामला है। यहां वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने नौ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की स्वीकृति दी थी। इनमें से सात अस्पतालों का अब तक अता-पता नहीं। रोचक यह कि इन अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की बहाली भी कर दी गई। जब चिकित्सकों ने अपने पदस्थापन का अस्पताल ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वे अस्तित्व में ही नहीं हैं। जाहिर है, सरकार ने स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की, लेकिन इस योजना की न तो ढंग से मानीटरिंग हुई और न ही विभाग के अधिकारियों ने इसकी चिंता की। राज्य सरकार की ओर से रविवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में प्रत्येक प्रखंड में दो-दो टीकाकरण कार्नर खोले गए हैं। फिलहाल राज्य में इनकी संख्या एक हजार है। आगे भी एक हजार ऐसे टीकाकरण कार्नर की स्थापना की घोषणा की गई है।

योजनाओं की मानीटरिंग और निरंतरता से ही आम आदमी को लाभ मिल सकता है।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा?

आज का सवाल

क्या ट्रंप पर एक और हमला उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा?

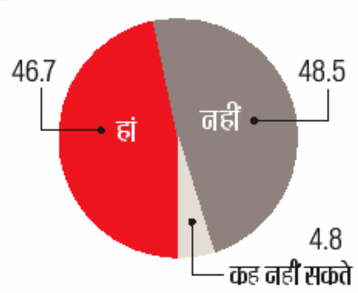


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# नवनिर्माण के शिल्पकार

योगी आदित्यनाथ

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर ही कई बड़े निर्णय ले लिए हैं

नई विश्व व्यवस्था में आज भारत केंद्रीय भूमिका में है। बहुध्रुवीय हो चुकी विश्व राजनीति में भारत के बिना हर वैश्विक समूह अधूरा है। आपदाकाल में सहायता की आवश्यकता हो अथवा नीतिगत विषयों पर आम राय बनाने की जरूरत, दुनिया की दृष्टि भारत की ओर होती है। बीते एक दशक में विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। युद्धग्रस्त राष्ट्र भी समाधानकारी हस्तक्षेप पर जिन पर भरोसा करते हैं, वह मोदी ही हैं। रूस और यूक्रेन के मध्य तनावपूर्ण हालात हों या पश्चिम एशिया का संकट, हर वैश्विक तनाव के समाधान हेतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत केंद्र में है। 'मोदी हैं तो मुमकिन हैं', के भाव को आज न केवल देश मानता है, बल्कि महाशक्ति देशों को भी 'मोदी की गारंटी' पर विश्वास है।

अपने संकल्पों की सिद्धि, समस्याओं के समाधान और चिरआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह देश मोदी को 'भगीरथ' के रूप में देखता है। सुदूर किसी खेत में काम कर रही महिला किसान हो या किसी साफ्टवेयर कंपनी में कुछ नया प्रयोग कर रहा युवा, सीमा पर मुस्तैद जवान हो या विदेश में प्रवासरत भारतीय, सभी को मोदी की नीति, नीयत और निर्णयों पर भरोसा है। यही जनविश्वास मोदी को 'बड़े और कड़े' निर्णय लेने का सामर्थ्य देता है। अनुच्छेद 370 और 35 ए का हटना असंभव माना जाता था। कश्मीर में राष्ट्रध्वज जलाए जाते थे, संविधान का मखौल उड़ाया जाता था, लेकिन आज यह सब अतीत की बात है। नरेन्द्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति ने कश्मीर से एक देश में 'दो निशान-दो विधान' का कलंक मिटा दिया। आज घाटी में स्थापित होते नए उद्योग, चिनाब पर बनते एफिल टावर से ऊंचे रेलवे ब्रिज के चित्र देखने को मिलते हैं। नए भारत के नए कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव के लिए तत्पर है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ है। भारत 'स्व से साक्षात्कार' कर रहा है। पांच सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्रीअयोध्याधाम में भगवान श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पुनरुद्धार जैसे चिरप्रतीक्षित कार्यों से भारत की आस्था गौरवान्वित हुई है। आजादी के बाद से जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को पोसने वाले दलों के दलदल में फंसे देश को 2014 के बाद मुक्ति मिली। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, स्वनिधि, सौभाग्य, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, मातृ वंदना जैसी योजनाओं के भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन ने सामान्य भारतीय परिवारों के जीवन को सरल बनाया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' इसी नवीन कार्यसंस्कृति का प्राण है। 'अंत्योदय से सर्वोदय' का मंत्र आत्मसात करने वाली इस व्यवस्था में समाज के

अवधेश राजपूत

अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। पहली बार कृषि और किसान राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। आज किसानों को फसल बीमा, एमएसपी, सब्सिडी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर ही कई बड़े निर्णय ले लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कवर प्रदान किया और लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' लागू करने का निर्णय लिया।

विगत 10 वर्षों में जनधन, आधार और मोबाइल के रूप जैम-त्रिशक्ति का उपयोग करते हुए तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करके आम आदमी को सरकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैम का आशय है, खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल, गरीबों का अधिकतम सशक्तीकरण और जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार। प्रधानमंत्री की यह पहल एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति की शुरुआत थी। यूपीआइ, रूपे कार्ड, डिजीलाकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग-अलग तरह के डिजिटल प्लेटफार्म्स, आम आदमी की दिनचर्या का अंग बन गए हैं।

पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक समुदाय भी समझ रहा है कि जो विकास स्थायी नहीं, वह वास्तविक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया है और हमारा देश इस आंदोलन के अग्रणी मार्गदर्शक के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री की 'पंचामृत और लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फार एनवायरनमेंट' की पहल ने भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल माडल के रूप में प्रस्तुत किया है। दस वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2300 प्रतिशत बढ़ी है। 2014 के बाद से सौर ऊर्जा दरों में लगभग 70-80 प्रतिशत की कमी आई है। अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली जैसी योजना के माध्यम से पूरा भारत अक्षय ऊर्जा से लाभान्वित हो रहा है।

कोविड महामारी के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध से उबरने का प्रयास कर रहे अनेक बड़े देश आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मोदी की कूटनीति और वित्तीय कुशलता के चलते इसी दौरान भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। आज वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की मेजबानी में संपन्न 'सेमिकान इंडिया' सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग के ग्लोबल हब बनने के अभियान का औपचारिक शुभारंभ था। प्रधानमंत्री ने कहा भी था, 'मेरा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो।' सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वह सब करने वाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत एक लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान कोष की जो स्थापना की, वह हमारे नवाचारी युवाओं के लिए बड़ा संबल बनेगी।

यह सुखद दैवीय योग है कि देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और प्रधानमंत्री की जन्मतिथि एक ही दिन है। आज भारत विश्वनेता की भूमिका में भविष्य की आकांक्षाओं की आधारशिला पर गौरवशाली निर्माण कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस 'अमृत नव निर्माण' के शिल्पकार बन रहे हैं।

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

response@jagran.com

# विदेशी धरती पर बेलगाम राहुल गांधी

उमेश चतुर्वेदी

विदेश यात्रा पर राहुल गांधी की बयानबाजी को प्रचार जरूर मिलता है, पर इससे भारत की छवि भी बिगड़ती है

वाशिंगटन में एक सभा को संबोधित करते राहुल ● पेट्र

महाभारत का एक प्रसंग है। वनवास के आखिरी दिनों में एक बार भीम ने देखा कि दुर्योधन को यक्ष बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। दुश्मन दुर्योधन को बंदी बनाया जाते देख भीम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। कुटिया पर लौटते ही इसकी जानकारी उन्होंने धर्मराज को दी, लेकिन युधिष्ठिर ने भीम की खुशी पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि आपस में भले ही हमारा बैर हो, लेकिन किसी बाहरी के लिए हम एक सौ पांच हैं। विदेशी धरती पर भारतीय राजनीति भी अपने घरेलू मुद्दों को लेकर इसी परंपरा को ही निभाती रही है, जिसे दुनिया ने 27 फरवरी, 1994 को जेनेवा में देखा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कोआपरेशन के जरिये कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा था। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो भारत को सुरक्षा परिषद के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इसकी अनूठी काट खोजी। भारत का पक्ष रखने के लिए उस समय विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल जेनेवा भेजा, जिसमें तब के विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद सदस्य की भूमिका में थे। भारतीय राजनीति ने उस संकट का मिलकर सामना किया और पाकिस्तान का प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया।

राहुल गांधी अब नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस परंपरा में उनका कोई विश्वास नहीं है। वह जब भी विदेश जाते हैं तो ऐसे बयान देते हैं, जिनसे देशविरोधी मुद्दों को हवा मिलती दिखती है। गत दिनों अमेरिका दौरे पर गए राहुल ने कहा, 'आज भारत में लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें पगड़ी या कड़ा धारण करने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जाने में सक्षम होंगे। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।' इस बयान के जरिये राहुल गांधी विदेशी धरती पर यह जताने की कोशिश करते नजर आए कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने या गुरुद्वारा जाने से रोका जा रहा है? निश्चित तौर पर इसका जवाब न में है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान को अगर उनके विरोधी खालिस्तानी आंदोलन से जोड़कर देखें तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा द्वारा राहुल को 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाना भी स्वाभाविक है।

विदेशी धरती पर राहुल गांधी की बयानबाजी को वैश्विक प्रचार जरूर मिलता है, लेकिन इससे भारत की छवि लोकतंत्रहीन और तानाशाही वाले देश की बनती है। इस तरह राहुल दुनिया को यह बताने की कोशिश करते नजर आते हैं कि भारत में हर कोई खतरे में है और वहां नागरिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। पिछले साल अमेरिका में ही राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसके पहले 2022 में लंदन में कहा था कि भारत के आत्मा पर हमले हो रहे हैं और बिना आत्मा के देश कुछ भी नहीं होता। 2018 में जर्मनी दौरे पर गए राहुल ने कहा था कि मोदी के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। तब उन्होंने मोदी की तुलना ट्रंप से की थी। 2017 में अमेरिका में राहुल ने कहा था कि मोदी को देश की संघीय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है और वह देश को बांटना चाहते हैं। दिलचस्प यह है कि बीते आम चुनाव में राहुल लगातार लोगों को डराते रहे कि भाजपा और मोदी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना के मूल में उनके आरक्षण संबंधी विचार ही हैं, लेकिन अमेरिका के हालिया दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर उन्होंने कह दिया कि जब भारत में बेहतर हालात होंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में आरक्षण बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। आरक्षण और जातिगत जनगणना वहां के बड़े मुद्दे हैं। विवाद बढ़ता देखकर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वह आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक करना चाहते हैं। राहुल ने अमेरिका में यह भी कह दिया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषियों से कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, संस्कृति और खानपान कमतर हैं।

बेलगाम बयानबाजी के जरिये राहुल गांधी का एक मकसद देश में जारी चुनावों में अपने पक्ष में माहौल बनाना भी रहता है, क्योंकि विदेशी धरती पर घट रही भारत से संबंधित घटनाएं पूरे देश का ध्यान खींचती हैं। इसके जरिये राहुल अपने वोटरों को लुभाने और अपना समर्थक आधार वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त भूल जाते हैं कि वह मामूली नेता नहीं हैं। पहले उनके बयानों को तवज्जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के बयानों के नाते मिलती थी, अब वह नेता विपक्ष की भूमिका में हैं। इसलिए उनके बयानों को और महत्व मिलना स्वाभाविक है। अब वह भी संविधान और राष्ट्र के प्रति उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना सत्ता पक्ष है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह जो भी बोलेंगे, नपा-तुला और जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे, लेकिन राहुल यहीं चूक रहे हैं। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों से भारत और भारत के बाहर स्थित देशविरोधी ताकतों का उत्साह बढ़ता है। राहुल के बयानों को लेकर कांग्रेस जिस तरह उनका बचाव करती दिख रही है, उससे लगता नहीं कि भविष्य में वह अपनी बयानबाजी को लेकर सचेत होंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

## आध्यात्मिक प्रगति

बौद्धिक स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, जो समाज में नवाचार की कमी का कारण बनता है। यह स्वतंत्रता न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो उसका मन हमेशा भोजन के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार बौद्धिक स्वतंत्रता की कमी प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से शारीरिक और मानसिक प्रगति की योजना बनाने में रुकावट डालती है।

योग शास्त्र में उल्लेखित है कि योगी उन देशों में जाते थे जहां शक्तिशाली राजा शासन करते थे, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक साधना को बिना किसी विघ्न के संपन्न कर सकें। आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति के जीवन में गहरी मानसिक और आत्मिक उन्नति को संदर्भित करती है। यह प्रगति उस स्थिति की ओर इशारा करती है, जहां व्यक्ति आत्म-ज्ञान, जागरूकता और परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साधना, ध्यान और स्वयं की गहन खोज से होकर गुजरता है। यह प्रक्रिया आत्मा के भीतर की सच्चाई को पहचानने की यात्रा है।

आध्यात्मिक प्रगति के लिए नियमित साधना, मानसिक शांति और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करता है, तो उसकी आध्यात्मिक समझ और अनुभव में वृद्धि होती है। ध्यान, योग और आत्मा की खोज के माध्यम से व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को खोजता है और जीवन के उच्चतर उद्देश्यों को समझने में सक्षम होता है। आध्यात्मिक प्रगति और बौद्धिक स्वतंत्रता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बौद्धिक स्वतंत्रता आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा को सुगम और प्रभावी बनाती है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

## पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

### मतांतरण का खतरा

आरके सिन्हा ने अपने आलेख 'मत प्रचार की स्वतंत्रता पर हो पुनर्विचार' में उचित प्रश्न उठाया है कि संविधान निर्माताओं ने मत प्रचार की जो छूट दी थी क्या उसकी कोई आवश्यकता थी? वह भी भारत जैसे देश में जहां बिना 'सेक्युलरिज्म' रूपी किसी सिद्धांत के सदियों से सभी धर्म के लोग भयरहित होकर साथ-साथ रहते आए हैं। शायद यही कारण था कि संविधान निर्माताओं द्वारा मूल संविधान में सेक्युलर जैसा कोई शब्द भी नहीं रखा गया था। हालांकि कालांतर में कुछ स्वार्थी नेताओं ने इस शब्द को जोड़ दिया। ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक युग में प्रचार के द्वारा हर बढ़िया और हर खराब चीज बेच दी जाती है, लेकिन धर्म कोई चीज नहीं है, खासकर सनातन धर्म। यह अन्य मजहबों की तरह संगठित गिरोह जैसा नहीं है जिसे अपने जीवन के लिए निरंतर नए सदस्यों की आवश्यकता हो। यही कारण है कन्वर्जन जैसा कोई सिद्धांत किसी भारतीय धर्म में नहीं है। जैसा अरबी या वेटिकन मजहबों में दिखता है। इसलिए मत प्रचार के अधिकार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। नीति नियंताओं को इस पर विचार करना चाहिए।

युवराज पल्लव, धामपुर, बिजनौर

### कार्यशैली में बदलाव

सहमति की राह पर सरकार संपादकीय आलेख पढ़ा। कड़े फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्यशैली इस कार्यकाल में कुछ बदली लग रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर भी सरकार को सहयोगियों के साथ ही यदाकदा समर्थन करने वाले मित्र दलों की आपत्तियों के चलते कदम पीछे खींचने पड़े। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड के ढांचे को और व्यापक बनाते हुए उनमें महिलाओं, बोहरा और आगाखानी के अलावा मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की पहल की गई है। साथ ही, बोहरा और आगाखानियों जैसे इस्लामिक वर्गों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड स्थापित करने की भी बात है। हालांकि, सहयोगी दलों ने इस विधेयक का पूरी तरह विरोध नहीं किया, लेकिन उसे संसदीय समिति को भेजने का सुझाव जरूर दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। चूंकि संसद में विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक की राह में अवरोध खड़े करना तय था तो सरकार ने विधेयक के परीक्षण के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इन मामलों को देखते हुए मोदी सरकार पर पलटी मारने का आरोप लगा रहे लोग भूल जाते हैं कि संसद में दमदार बहुमत के बावजूद उन्होंने कई मुद्दों पर अपने कदम पीछे खींचे हैं। कदम वापसी की इस सूची में एक नाम अगस्त 2022 में डाटा प्रोटेक्शन बिल से जुड़ा है, जो कई साल पहले प्रस्तावित किया गया था। सरकार ने उच्चस्तरीय समिति के सुझावों को समायोजित करते हुए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसने उसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए। इसके बाद मोदी सरकार ने विधेयक को वापिस लेने का फैसला किया। साल भर बाद सरकार ने संसद में नया विधेयक रखा। डाटा प्रोटेक्शन बिल पर उतार-चढ़ाव की यह स्थिति दर्शाती है कि पूर्ण बहुमत के बावजूद विधि निर्माण को ले मोदी सरकार का रवैया कितना उदार एवं लचीला रहा।

-रवि कुमार, पटना

### जमानत क्लीन चिट का पर्याय नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर फिर चौंकाया कि वह दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने जिस तरह यह स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उससे यह स्पष्ट है कि अटकलबाजी का दौर चलता रहेगा और इससे देश भर में उनकी चर्चा होती रहेगी। उन्होंने यह कहते हुए त्यागपत्र दिया कि वह आम जनता के समक्ष अग्निपरीक्षा देना चाहते हैं। केजरीवाल ने यह पाया हो कि उनके पास त्यागपत्र देने के अलावा उनके पास और कुछ उपाय नहीं बचा था। वह और उनके साथी भले ही यह कहते रहे हों कि नई आबकारी नीति लाकर कहीं कोई अनियमितता नहीं की गई, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं कि अगर इस नीति में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। यह ठीक है कि इस घोटाले में अन्य अनेक लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत क्लीन चिट का पर्याय नहीं हो सकती। भले ही केजरीवाल कह रहे हों कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और वह जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेने के बाद मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन आबकारी घोटाले का सच-झूठ जनता को नहीं, देश की अदालतों को तय करना है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, ऐसे में केजरीवाल इसको लेकर भी कुछ रणनीति बना रहे होंगे। यह अच्छी बात है कि शर्तों के साथ ही सही, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है।

सुभाष, आरा

## पोस्ट

जनता की अदालत अलग ही तरह से चलती है। वहां न सुबूत देखे जाते हैं और न दलील। भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईमानदारी का प्रमाणपत्र देने में देश की जनता बेहद उदार रही है। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

नितिन गडकरी के हालिया बयान से स्पष्ट है कि जून में लोकसभा के चुनाव नतीजे आने के बाद किसी ने भाजपा और राजग में तोड़फोड़ का प्रयास किया था। वे लोग किसी भी कीमत पर मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते थे। स्मिता प्रकाश@smitaprakash

मोदी सरकार के सौ दिन विपक्षी नेताओं को सदमा देने वाले हैं। उन्होंने सोचा था कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार सौ दिन भी पूरे नहीं कर पाएगी। अब सरकार 2029 तक का कार्यकाल सहजता से पूरा करती दिख रही है। विपक्षी नेताओं में खीझ एवं आक्रोश स्पष्ट है। मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार जिहादी एवं इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। उसने कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों पर प्रतिबंध हटाने के साथ ही आतंकियों को जेल से रिहा करके स्थिति और विकट बना दी है।

प्रकाश सिंह@singh_prakash

## जनपथ

अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार,
उतर गया है चित्त से घाटी में इस बार।
घाटी में इस बार युवक चाहें वह सत्ता,
आतंकी खुद आय जहां पर टेकें मत्था।
'खानदान के राज' मचा बस हल्ला-गुल्ला,
इसीलिए बेकार लगें मुफ्ती-अब्दुल्ला।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 157

********

पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

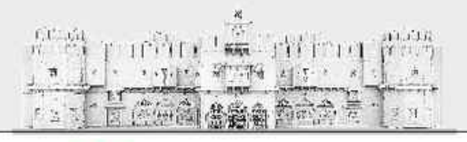

# डॉक्टरों के डेटाबेस से होगी सही-गलत की पहचान

देश में सभी एलोपैथिक (एमबीबीएस) पंजीकृत डॉक्टरों के लिए एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इससे एक ओर सरकारों को चिकित्सा से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, वहीं देश में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या और योग्यता के बारे में सटीक जानकारी भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि ऑनलाइन एकीकृत पंजीकरण अनिवार्य होने से झोलाछाप 'चिकित्सकों' पर लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी। यह आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों तक में भी अस्पताल का बोर्ड लगाकर फर्जी लोग इलाज करते दिख जाते हैं। मरीज की मौत या हालत बिगड़ने पर कई बार ऐसे फर्जी डॉक्टर पकड़े भी जाते हैं।

हाल ही बिहार के छपरा में यूट्यूब चैनल देखकर पथरी का ऑपरेशन करने के चक्कर में फर्जी डॉक्टर ने एक किशोर की जान ले ली। राजस्थान में डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में तो बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया। वहां एक फर्जी डॉक्टर पिछले तीन साल से आठ बेड का अस्पताल चला रहा था। असल में वह पहले गुजरात के किसी अस्पताल में सफाई का काम करता था। ऐसे एक नहीं, अनेक झोलाछाप इलाज के नाम पर न केवल चांदी कूट रहे हैं बल्कि लोगों की जान के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। असल में गुणवत्तापूर्ण सरकारी चिकित्सा तंत्र के अभाव में इस तरह के ठग जगह-जगह पनप गए हैं। जिन पर इनकी रोकथाम की जिम्मेदारी है, वे निष्क्रिय हैं। ऐसी हालत में मरीजों को इस बात का भी पता नहीं चल पाता कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, वह असली है या नकली। अब, जब चिकित्सकों का डेटाबेस ऑनलाइन हो जाएगा, तो मरीज या उनके परिजन एक ही क्लिक में संबंधित डॉक्टर की योग्यता के बारे में पता लगा लेंगे और फर्जी डॉक्टरों से बच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की ओर से जारी पोर्टल के जरिए देश के सभी एमबीबीएस डॉक्टरों को यूनीक आइडी मिलेगी। इससे अलग-अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन से लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी और भ्रम की संभावना खत्म हो सकेगी। पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए भी इसी तरह का रजिस्टर शुरू करने पर काम हो रहा है।

चिकित्सा ही नहीं, हर क्षेत्र के पेशेवरों के बारे में सटीक आंकड़े और जानकारी होने से सरकार को योजनाएं बनाने में तो आसानी होती ही है, इनकी सेवाएं लेने वालों को भी सही पेशेवर का चयन करने में मदद मिलती है। डिजिटल युग में जब पूरी दुनिया की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है, तो चिकित्सकों समेत सभी पेशेवरों के बारे में अधिकृत जानकारी उपलब्ध कराने के किसी भी विश्वसनीय नेटवर्क की पहल स्वागतयोग्य है।

**राजनीति:** आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऐलान से दिल्ली ही नहीं, देश में भी बढ़ेगी हलचल

# इस्तीफे की पतवार से पार लगेगी उम्मीदों की नौका!

राज कुमार सिंह
लेखक
वरिष्ठ पत्रकार हैं
@patrika.com

**विपक्ष के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकने वाले केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप के लिए कुछ सीटों का दबाव बना सकते हैं। उससे परे देखें तो भाजपा की हार विपक्ष की ही जीत होगी, पर उस संभावित परिदृश्य से पहले भी कई किंतु-परंतु हैं।**

चित कौन होगा–यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, पर शराब घोटाले में जमानत पर रिहा अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के दांव से चौंका सभी को दिया है। गिरफ्तारी के बाद से ही केजरीवाल का इस्तीफा मांगती रही भाजपा ने जमानत की शर्तों के आधार पर भी मांग दोहराई थी, पर आप ने साफ इनकार कर दिया था। केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत मिली और 15 सितंबर को उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और मतदाताओं द्वारा जनादेश के जरिए उन्हें 'ईमानदार' मान लेने के बाद ही पद लेंगे। यह भी कि चुनाव तक आप का कोई अन्य नेता मुख्यमंत्री पद संभालेगा।

केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नवंबर में कराए जाएं। उनकी इच्छा कितनी पूरी होगी–यह तो उनके इस्तीफे पर उप राज्यपाल और फिर चुनाव आयोग के फैसले से तय होगा, पर शराब घोटाले से बनीं परिस्थितियों का दबाव उन पर भी है। बेशक जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने सीबीआइ पर तल्ख टिप्पणियां भी कीं, जिसने ईडी केस में जमानत मिलते ही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तत्परता दिखाई थी, पर जमानत की शर्तों के मद्देनजर केजरीवाल मुख्यमंत्री की वैसी भूमिका निभा ही नहीं सकते, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। वह न तो नीतिगत फैसले ले सकते हैं और न ही लोकलुभावन घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। फिर वह चौथी बार जनादेश के लिए मतदाताओं के बीच किस आधार पर जाते? दूसरी ओर 'जमानत पर रिहा अभियुक्त' करार देते हुए भाजपा उनके विरुद्ध चुनाव अभियान चलाती, जिसकी सफाई देते हुए खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताने में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार निकल जाता। लोकपाल के मुद्दे पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना आंदोलन का समय हो या उसके बाद बनी आम आदमी पार्टी की राजनीति का दौर– केजरीवाल की छवि आक्रामक नेता और वक्ता की रही है। ऐसे में अपने और पार्टी के भविष्य की लड़ाई वह रक्षात्मक मुद्रा में लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। पहले भी केजरीवाल सरकार चलाने की जिम्मेदारी अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप कर आप के राजनीतिक विस्तार के जरिए अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के पंख फैलाने में ही जुटे थे। इसलिए इस अभूतपूर्व संकटकाल में उन्होंने 'पद-मुक्त' हो कर अपनी उसी पुरानी आक्रामक छवि में लौटने का विकल्प चुना है, जिसने नई नवेली आप को साल भर में ही दिल्ली में सत्तारूढ़ और एक दशक में ही राष्ट्रीय दल बनवा दिया। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आप ने प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की।

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल, राजनीतिक प्रतिशोध की शिकार आप के संयोजक के रूप में खासकर भाजपा के विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाएंगे। अभियान हरियाणा विधानसभा चुनाव से शुरू हो कर दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड तक जारी रहेगा। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत न मिलने से तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी पर बढ़ गई नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता के मद्देनजर इन राज्यों के विधानसभा चुनावों का महत्त्व जगजाहिर है। अगर जनादेश भाजपा के अनुकूल नहीं आया तो विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के तेवर और भी आक्रामक हो जाएंगे। नई लोकसभा के अभी तक के दो सत्रों में और संसद के बाहर भी विपक्ष के तेवर सत्तापक्ष को लगातार घेरने वाले नजर आ रहे हैं। पूछा जा सकता है कि इन राज्यों में दिल्ली के अलावा तो कहीं भी आप का जनाधार नहीं है। बेशक, लेकिन हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाली कांग्रेस ने कई दौर की बातचीत के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस की तरह आप भी 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के आक्रामक प्रचार का खतरा कांग्रेस आलाकमान समझता है। ऐसे में अब भी हरियाणा में तालमेल का रास्ता खोजा जा सकता है।

विपक्ष के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सकने वाले केजरीवाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप के लिए कुछ सीटों का दबाव बना सकते हैं। उससे परे देखें तो भाजपा की हार विपक्ष की ही जीत होगी, पर उस संभावित परिदृश्य से पहले भी कई किंतु-परंतु हैं। मसलन, केजरीवाल के इस्तीफे के बाद चुनाव तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सिसोदिया भी कह चुके हैं कि नए जनादेश के बाद ही कोई पद संभालेंगे। क्या अरविंद पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये अटकलें अरविंद की गिरफ्तारी के बाद से ही लगती रही हैं। गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में हुई 'इंडिया' की रैली में भागीदारी के बाद भी सुनीता राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आई हैं, पर क्या पत्नी की ताजपोशी केजरीवाल को 'परिवारवाद' के आरोप के कटघरे में खड़ा नहीं कर देगी और वह चुनाव प्रचार में सफाई देते नजर नहीं आएंगे? इसलिए ज्यादा संभावना है कि चुनाव तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक-सामाजिक समीकरण को साधते हुए किसी विश्वस्त चेहरे पर दांव लगाया जाए, पर चुनाव के बाद क्या होगा?

एक दशक से भी ज्यादा समय से आप दिल्लीवासियों की पसंदीदा पार्टी बनी हुई है। ऐसे में जीत में संदेह की ज्यादा गुंजाइश नहीं, पर उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल और सिसोदिया नए जनादेश के बाद पद लेने की बात कह तो रहे हैं, पर नए जनादेश से जमानत की शर्तें तो नहीं बदल जाएंगी। तब भी दोनों के सरकारी कामकाज करने पर रोक रहेगी। तब क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में ही ऐसे किसी विश्वस्त को चुना जाएगा, जिसे चुनाव बाद भी सत्ता सौंपी जा सके? संभव है कि फिलहाल पार्टी के किसी बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री बना कर नए जनादेश के बाद सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की रणनीति बनाई जाए। उस सूरत में सत्ता के सूत्र तो अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल के हाथों में रहेंगे ही, पार्टी संयोजक के रूप में वह अपना ज्यादा समय और ऊर्जा आप के राष्ट्रीय विस्तार और उसके जरिए राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बड़ी करने में लगा पाएंगे। यह केजरीवाल की रणनीति हो सकती है, पर 'इंडिया' गठबंधन के अन्य महत्त्वाकांक्षी नेताओं और भाजपा की भी अपनी-अपनी रणनीतियां होंगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि केजरीवाल के इस्तीफा-दांव से सिर्फ दिल्ली नहीं, देश की राजनीति में भी हलचल बढ़ेगी।

**फैक्ट फ्रंट**

## एशियाई ग्रीन बी-ईटर

एशियाई ग्रीन बी-ईटर, जिसे श्रीलंका में छोटा ग्रीन बी-ईटर भी कहा जाता है, बी-ईटर परिवार में एक निकटवर्ती पक्षी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के माध्यम से पूर्वी ईरान के तटीय दक्षिणी भाग से लेकर वियतनाम तक पूरे एशिया में व्यापक रूप से वितरित पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कीट खाने वाले होते हैं और घास के मैदान, पतली झाड़ियों और जंगल में अक्सर पानी से काफी दूर पाए जाते हैं। एशियाई ग्रीन बी-ईटर ज्यादातर मैदानी इलाकों में देखे जाते हैं पर कभी-कभी हिमालय में 5,000 या 6,000 फीट तक पाए जा सकते हैं।

**प्रसंगवश**

## सजा ऐसी हो जिससे रिश्वत लेते सरकारी लोगों के हाथ कांपें

**भ्रष्टाचार-घूसखोरी पर लगाम कसने एडीएम को तत्काल निलंबित कर मुख्यमंत्री जो संदेश देना चाहते हैं, उसे तो कानून बना देना चाहिए**

प्रदेश में भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर लगाम कसने की मंशा से मुख्यमंत्री ने रिश्वत लेते पकड़े गए मऊगंज जिले के अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी के निलंबन के आदेश दिए। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। यह अच्छी पहल है, लेकिन यह कार्रवाई अकेले एडीएम तक नहीं सिमटकर रह जाना चाहिए। अब हर प्रकरण में मुख्यमंत्री स्वयं तो एक्शन लेते नहीं रहेंगे, इसलिए अपने नियम-कानून में ही इसका प्रावधान कर देना चाहिए। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कम से कम निलंबन का भय तो बने, वरना कतिपय अधिकारी-कर्मचारी तंत्र में बैठ भ्रष्टाचार करने को अपना हक माने हुए हैं। निर्भीक इतने हैं कि न उन्हें लोकनिंदा की परवाह है और न कानून का डर है। समाज का रवैया भी इसमें कोई मदद नहीं करता। समाज भी अब रिश्वतखोर से कोई नाता नहीं तोड़ता। सब जानते हैं एक दिन फिर पद पर लौट आएगा। रसूख बना रहेगा और काली कमाई का रुतबा कायम रहेगा। अब रिश्वतखोरी का मामला उजागर होने पर चर्चा के विषय ही बदल चुके हैं। छोटी मछली फंस गई और मगरमच्छ बच गए, नाक के नीचे घूसखोरी, बड़े साहब इतना कम लेते पकड़े गए, वहां देखो छोटे से कर्मचारी ने मोटी रकम वसूली है, इस तरह के तमाम जुमले जुबान पर होते हैं। विचारणीय है कि आखिर यह गंभीर विषय मजाक में तब्दील क्यों हो चुका है? गहराई में जाएंगे, तो पाएंगे कि इसके स्पष्ट कारण भी हैं और वे ठोस भी हैं, क्योंकि इक्का-दुक्का मामले छोड़ भी दें तो प्रदेश में ऐसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई जो नजीर पेश करने योग्य हो। मध्यप्रदेश की तुलना में राजस्थान इस दृष्टि से बेहतर स्थिति में है। राजस्थान में देखिए, एजेंसियां बड़े से बड़े अफसर को भी भ्रष्टाचार में पकड़ने का माद्दा रखती हैं। मध्यप्रदेश में अभी तो अदालत में चालान प्रस्तुत होने तक निलंबित नहीं किया जाता और चालान के लिए सरकार की अनुमति में ही महीनों गुजर जाते हैं। अनुमति मिल भी जाए तो अदालतों में वर्षों बीत जाते हैं। अब निलंबन बना रहे तो बरी होने पर एकमुश्त राशि देनी पड़ती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कुछ कठोर निर्णय लिए जाएं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाली सरकारी एजेंसियों जैसे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और लोकायुक्त को ज्यादा कारगर बनाया जाए। उनको ताकत देने के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। अदालतों में भ्रष्टाचार संबंधी सभी प्रकरणों को फास्ट ट्रैक पर निबटाया जाए।

-नितिन त्रिपाठी
-nitin.tripathi@in.patrika.com

**इतिहास के झरोखे से:** गणेशोत्सव की झांकी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस

**महाराष्ट्र** में माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की आराधना, उत्सव मनाने की परंपरा पहले से थी, लेकिन हिंदू समाज और इसके सभी वर्गों को संगठित करने के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत 1893 में पुणे में की थी। कुछ ही दिनों में इस उत्सव ने राष्ट्रधर्म का स्वरूप ले लिया था और यह वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि शहरों में फैल गया था। स्वयं तिलक इन उत्सवों में स्वराज का व्याख्यान देते थे। धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज भी हस्तक्षेप करने से हिचकिचाते थे। गणेशोत्सव का विस्तार पहले पूरे महाराष्ट्र में और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी, कराची से बंगाल, कलकत्ता तक हुआ। तिलक की मृत्यु 1920 ई. में हो गई थी, लेकिन गणेशोत्सव की परिपाटी आज भी देश-विदेश में ज्यों की त्यों बनी हुई है। तिलक के समय पुणे में सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सवों की संख्या लगभग सौ थी। 1945 में पुणे की एक झांकी में नेताजी सुभाषचंद्र बोस को स्वाधीनता के सूर्योदय के रथ के सारथी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। रथ में श्रीगणेश विराजमान थे। यह झांकी इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसे देखने देश भर से लोग पहुंचे। जनता के आग्रह पर और दर्शानार्थियों का तांता देखकर इस झांकी को 10 दिन के स्थान पर 45 दिन बाद विसर्जित किया गया था।

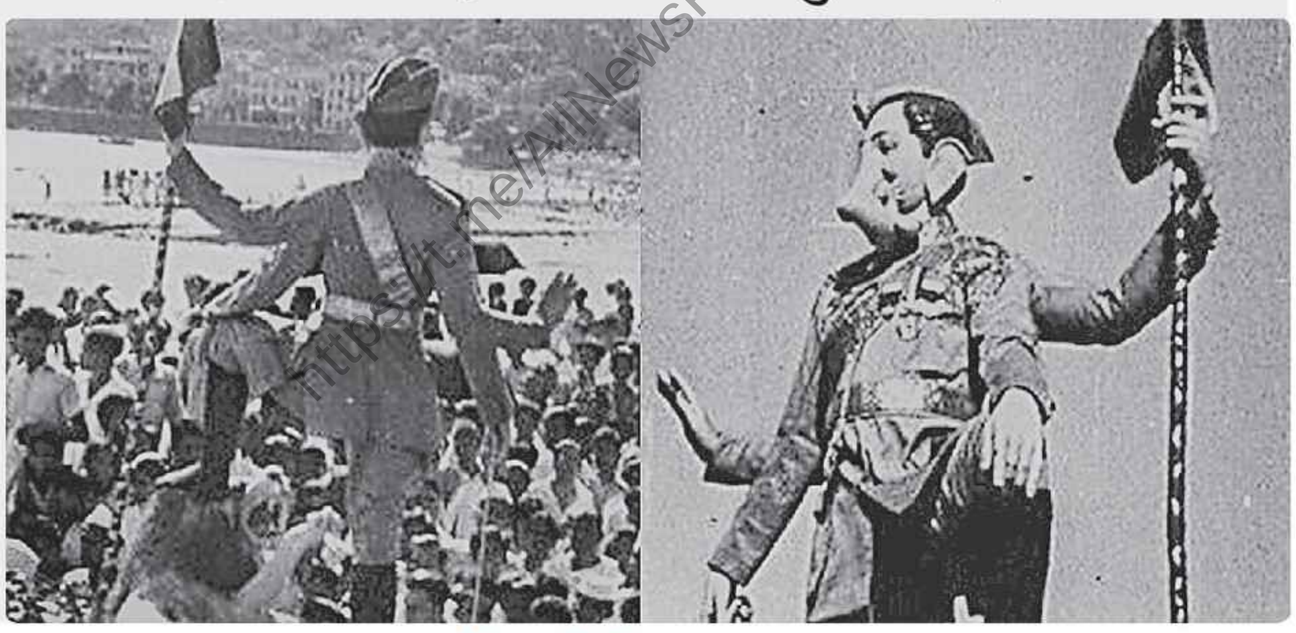

https://t.me/AIINewsPaper

**विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर विशेष :** एआइ का किया जाए इस्तेमाल

# मरीजों की सुरक्षा का रहे ध्यान, इलाज के नाम पर न मिले मर्ज

डॉ. पंकज जैन
एसोसिएट प्रोफेसर,
मेडिकल कॉलेज, कोटा
@patrika.com

कोई भी रोगी किसी चिकित्सक के पास या अस्पताल में एक विश्वास एवं भरोसे के साथ पहुंचता है। मुश्किल यह है कि तेजी से बदलते नए उपचार तंत्र एवं चिकित्सा में प्रौद्योगिकी के प्रवेश ने रोगी देखभाल से जुड़े नए खतरे भी पैदा किए हैं। रोगी सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा का एक ठोस आधार है और अब इसे एक बढ़ती वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। प्रतिकूल घटनाओं के चलते रोगी को होने वाली हानि दुनिया भर में बीमारी और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति दस में से एक मरीज स्वास्थ्य देखभाल त्रुटियों से प्रभावित होता है, वहीं असुरक्षित देखभाल के कारण प्रति वर्ष 3 मिलियन से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। दवाइयों की चूक, असुरक्षित शल्य प्रक्रियाएं, स्वास्थ्य देखभाल संबंधित संक्रमण, निदान संबंधी चूक, गिरकर चोटिल होना, लंबे समय से बेहोश मरीजों में शरीर के दबाव से नासूर हो जाना, मरीजों की गलत पहचान, असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कारण कई मरीजों की जान जाती है। रोगी सुरक्षा से संबंधित इन स्वास्थ्य देखभाल त्रुटियों में से 50 प्रतिशत से अधिक बचाव योग्य हैं। प्रति वर्ष 17 सितम्बर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है जिसके प्रमुख उद्देश्यों में रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता एवं सहभागिता बढ़ाना, रोगी को होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करना है। वर्ष 2024 विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम 'रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार', 'इसे सही करें, इसे सुरक्षित बनाएं', रखी गई है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए रोगी सुरक्षा आवश्यक है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में विश्वास का निर्माण जरूरी है। त्रुटियों के चलते मरीजों पर वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। प्रत्येक रोगी की सुरक्षित देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक है।

हाल ही के वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद रोगी सुरक्षा आज भी एक जटिल चुनौती बनी हुई है। आधुनिक जटिल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में रोगियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रौद्योगिकी एवं दवाओं के बीच कई स्तर पर सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इसमें गड़बड़ी कई प्रतिकूल घटनाओं और त्रुटियों की संभावना बढ़ाती है। स्टाफ, उपकरण, स्थान सहित अन्य संसाधनों की कमी भी रोगी सुरक्षा में व्यवधान पैदा करती है। मानवीय कारक जैसे थकान, तनाव व अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त प्रशिक्षण भी रोगी सुरक्षा त्रुटियों का कारण हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, मरीज एवं मरीज के परिजनों के बीच निरन्तर संवाद की कमी भी रोगी सुरक्षा को कमजोर करती है।

मरीजों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों एवं बहुआयामी दृष्टिकोण की महती आवश्यकता है। रोगी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवा संगठनों, नीति निर्माताओं के साथ ही मरीजों एवं उनके परिजनों को भी जोड़ना होगा। रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला वातावरण तैयार करना होगा। सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण नियंत्रण, दवा वितरण एवं सुरक्षित शल्य प्रक्रिया के लिए मापदंड विकसित करने होंगे। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के आधुनिक प्रशिक्षण और सतत शिक्षा के लिए निवेश बढ़ाना होगा ताकि वे रोगी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ-साथ नवीन तकनीकों पर भी अपडेट रह सकें। आधुनिक टेक्नोलॉजी रोगी सुरक्षा को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, चिकित्सकीय परामर्श की कम्प्यूटरीकृत प्रविष्टि, नैदानिक विभागों में एआइ का उपयोग करके त्रुटियों की आशंका को कम किया जा सकता है। रोगी देखभाल प्रक्रिया में मरीजों एवं उनके परिजनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। समय-समय पर उनको उपचार एवं निदान के बारे में बताया जाना चाहिए।

**जन्मदिन पर विशेष:** दो अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता ही सेवा अभियान

# राष्ट्र के लिए समर्पित, स्वच्छता अभियान के संवाहक मोदी

*नीति सही, रीति नई।*
*गति सही, राह नई।।*
*चुनो चुनौती सीना तान।*
*जग में बढ़ाओ, देश का मान।।*

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश
@patrika.com

लाल किले की प्रचीर से यह उद्घोष करने वाले विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 74वें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई...। प्रधानमंत्री के जीवन का एक-एक पल समाज, संस्कृति और राष्ट्र की समृद्धि के लिए समर्पित है। राष्ट्र निर्माण के लिए उनका अविराम कार्य, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे लिए प्रेरणास्रोत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में होने वाले रिफॉर्म्स और परफॉर्मेंस से पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ पर भारत को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने देश को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया।

स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से समृद्धि को धरातल पर लाने के लिए मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते ही स्वच्छता को प्राथमिकता में लिया। 2014 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता के आह्वान को आत्मसात कर देश को स्वच्छ भारत मिशन का स्वरूप दिया। इस आधारभूत आवश्यक स्वच्छता अभियान से समूचा देश जुड़ गया। यह अभियान स्वच्छता के स्थायी व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने, स्वच्छता को आचरण में शामिल करने और स्वस्थ वातावरण के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य में सफल हुआ है। स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े इस मिशन से विशेषकर बच्चों और महिलाओं में अस्वच्छता से होने वाली बीमारियां कम हुई हैं। स्वच्छता चर्चा का विषय बना और उसे अमल में लाया गया जिससे महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। सम्मान बढ़ा है।

स्वच्छ भारत मिशन की इस वर्ष 10वीं वर्षगांठ है। देश को स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न बनाने के दृष्टा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर हमने प्रदेश में 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' चलाने का निर्णय लिया है। अभियान 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' थीम पर आधारित है। इससे लगभग 18 हजार स्थानों को पूर्ण स्वच्छ, 70 हजार सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई, स्वच्छता मित्र शिविर और स्वच्छ भारत सांस्कृतिक महोत्सव से स्वच्छता का मानस निर्मित होगा। अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा।

स्वच्छ भारत मिशन मध्यप्रदेश के लिए विशेष रहा है। प्रदेश ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इंदौर को लगातार सातवीं बार देश में स्वच्छ शहर का पुरस्कार और स्वच्छ राज्य की श्रेणी में मध्यप्रदेश को दूसरा स्थान स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता सुविधाएं जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण सहित कचरा प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इंदौर वाटर प्लस प्रमाणन और सेवन स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना यहां गोबर-धन बायो सीएनजी प्लांट स्थापित होने से वेस्ट-टू-वेल्थ तथा सर्कुलर ईकोनॉमी की परिकल्पना साकार हुई है। रीवा और जबलपुर में कचरे से बिजली बनाई जा रही है।

पर्यावरण सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। मध्यप्रदेश में पांच करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। इंदौर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री ने जहां विश्व पटल पर व्यापक पहल की वहीं भारत निर्माण के लिए आधारभूत कार्य से निर्माण और विकास का मार्ग खोजा। स्वच्छता के लिए क्रांतिकारी कदम ने राष्ट्र में स्वच्छ संस्कृति स्थापित की है। उनका यह कदम महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और महिला सम्मान का आधार भी है और आयाम भी। भारत को यश, कीर्ति और गौरव दिलाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की पुनश्च आत्मिक बधाई।

**आपकी बात**

## जागरूकता आवश्यक

**अंधविश्वास** के कारण होने वाले अपराधों को रोकने का श्रेष्ठ माध्यम शिक्षा व जन-जागरूकता है। कानून और पुलिस का भय भी आवश्यक है।

-चूना राम बेनीवाल, बायतु, बालोतरा

**आज का सवाल**

**सरकारी विभागों में बढ़ती छुट्टियों का जनता पर क्या असर हो रहा है?**

ईमेल करें
edit@epatrika.com

**patrika.com** पर पढ़ें

## पाठकों की प्रतिक्रियाएं

**पत्रिकायन** का सवाल था, 'अंधविश्वास के कारण होने वाले अपराधों को कैसे रोका जा सकता है?' ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/WIqmQ
इसे स्कैन करें

## चिंतन

# संस्कारों और नैतिकता से दूर क्यों हो रही युवा पीढ़ी

हम आधुनिकता की चकाचौंध में लगातार भाग रहे हैं। इस अंधी दौड़ में न केवल अपनी संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों को दरकिनार कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इनसे दूर करते जा रहे हैं। अगर यही सब ऐसे ही चलता रहा तो शिष्टाचार, नैतिकता महज शब्दकोष में लिखित अक्षर बनकर रह जाएंगे। इन्ही हालात को देखते हुए ही नई दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवन ने कहा कि भारत में भी परिवार के संस्कारों को खतरा है। मीडिया के दुरुपयोग से नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही है, इसलिए हफ्ते में एक बार निश्चित समय पर अपने कुटुंब के सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार घर में भजन-पूजन, उसके बाद घर में बनाया हुआ भोजन साथ में करें। समाज के लिए भी कुछ न कुछ करें। इसके लिए छोटे-छोटे संकल्प लें। वैसी भी यही हमारी संस्कृति है। किसी भी विषय को ले लें, हम अपनी युवा पीढ़ी पर पूरा दोष डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल यह नहीं कि आज की युवा पीढ़ी में नैतिकता व शिष्टाचार की कमी हो रही है, बल्कि सवाल यह है कि क्या सिर्फ युवा पीढ़ी पर दोषारोपण से हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। क्या हम युवा पीढ़ी के लिए अपना कर्तव्य निष्ठा से निभा रहे हैं। क्या सारी गलती युवा पीढ़ी की ही है। आज उनमें अगर संस्कारों, शिष्टाचार की कमी हो रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम उनमें संस्कार नैतिकता शिष्टाचार नहीं भर पा रहे हैं। बच्चों का अनैतिक होने के लिए हम जिम्मेदार हैं। बच्चों में अनैतिकता के प्रवेश से न केवल उनके, बल्कि पूरे समाज के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगता है। इसके चलते अनेक तरह की बुराइयों को जगह मिलती है। नशा, अपराध इसी से ही पनपते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग खाली होता है। ये हम पर हैं कि हम उसके दिमाग में क्या भरते हैं। आप उसको जिस प्रकार के संस्कार व शिक्षा देंगे उसी राह पर वह आगे बढ़ता है। अगर बाल्यकाल में बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि चोरी करना बुरी बात है तो वह चोरी जैसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचेगा। बाल अवस्था में बच्चों को संस्कारित करने में माता-पिता, दादा-दादी व बुजुर्गों का बड़ा हाथ होता था। कहानियां भी प्रेरणादायी होती थीं। आज हम बच्चों को कहानी सुनाने की बजाय मोबाइल फोन थमा रहे हैं। उसमें न जाने क्या-क्या देखा जा रहा है। एक नैतिक शिक्षा की पुस्तक होती थी। आज वह पुस्तक गायब हो चुकी है। ढेरों कंप्यूटर गेम्स, वीडियो गेम्स, फिल्मी गानों की दुनियाभर की सीडी मिल जाएंगी, लेकिन भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद आदि के जीवन की कहानियों की किताब स्कूल बैग से गायब ही हो चुकी हैं। यहा तक कि हम कोशिश भी नहीं करते कि अपने बच्चों को ऐसी किताबे दें जिससे वह नैतिकता व शिष्टाचार को समझें। यह बात जरूर है कि आजकल की युवा पीढ़ी नैतिकता तथा शिष्टाचार को भूल सी गई है। संस्कारों का अभाव कहीं भी देखने को मिल सकता है। युवा पीढ़ी में संस्कार, नैतिकता व शिष्टाचार की कमी न हो, इसके लिए हमें स्वयं से ही शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले खुद को बच्चों के साथ जोड़ना होगा। यह सही है कि आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में समय का अभाव है, लेकिन बच्चों के लिए समय निकालना जरूरी है। जो टाइम आप और हम फोन पर खर्च करते हैं। वो बच्चों को देना शुरू करें। उनको अच्छी तरह से समझें और उनके दिल की बात जानें, तभी हम उन्हें संस्कारों से जोड़ पाएंगे।



यूएन महासभा
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

# फ़िलेमॉन के समक्ष चुनौतियां

संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यंग ने जलवायु परिवर्तन, हिंसक टकराव और टिकाऊ विकास की धीमी होती रफ्तार समेत अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विविधता में एकता की अपनी दृष्टि पेश की है और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की पुकार लगाई है। उन्होंने यह भी पुकार लगाई है कि समतापूर्ण आर्थिक प्रगति हासिल की जाए, नवाचार और हरित अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देना होगा और आर्थिक विकास से मिलने वाले लाभों को हर देश के लिए सुनिश्चित करना होगा। यह सत्र फिलेमॉन यंग की सूझबूझ, स्पष्टता और हाशिये के देशों को मिलने वाले महत्व पर ही मूल्यांकित होगा।

फिलेमॉन यंग के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का आगाज हो चुका है। यह महासभा न्यूयॉर्क में हो रही है और इसके साथ ही भविष्य के लिए सम्मलेन भी आयोजित होगा इस सत्र वाली महासभा अपने पूरे जोश के साथ भविष्य के सम्मलेन पर भी अपना मंतव्य प्रकट करने जा रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यंग ने जलवायु परिवर्तन, हिंसक टकराव और टिकाऊ विकास की धीमी होती रफ्तार समेत अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विविधता में एकता की अपनी दृष्टि पेश की है और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की पुकार लगाई है। उन्होंने यह भी पुकार लगाई है कि समतापूर्ण आर्थिक प्रगति हासिल की जाए, नवाचार और हरित अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देना होगा और आर्थिक विकास से मिलने वाले लाभों को हर देश के लिए सुनिश्चित करना होगा।

संयुक्त राष्ट्र का यह सत्र फिलेमॉन यंग की सूझबूझ, स्पष्टता, गरिमापूर्ण बहस के लिए उनकी उद्दात्तता और हाशिये के देशों को मिलने वाले महत्व पर ही मूल्यांकित होगा। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में विजय लक्ष्मी पंडित ने इस दायित्व को शुरूआती वर्षों में निभाया है। इस साल कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमॉन यंग के नेतृत्व में महासभा हो रही है। वैश्विक शांति व लोकतंत्र के पैरोकार इसमें जुटकर अपना-अपना पक्ष रखते हैं और विश्व की चिंताओं को प्रकट करते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस का मानना है कि मुश्किलों से घिरी दुनिया में समाधान की तलाश में सामूहिक कार्रवाई पर बल दिया जाए तो हम दो कदम आगे बढ़ सकते हैं। साझा लक्ष्यों के लिए सभी सदस्य देशों को एकजुट करने के लिए सभी देशों की संगठित शक्ति और फिलेमॉन यंग की दूरदर्शी, सम्यक साझी रणनीति से दुनिया बदली जा सकती है। पहले दिन से ही, संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय समाधानों का स्थल रहा है, जिसकी बुनियाद रचनात्मक सहयोग, सम्वाद, कूटनीति व यूएन चार्टर में है। इन सबके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के चिह्नित लक्ष्य जिसमें एसडीजी-2030, भविष्य के लिए सम्मलेन, वैश्विक शांति के हालात ये सब दिमाग में बुद्धिजीवियों के आ ही जाते हैं। पूरी दुनिया में समालोचकों द्वारा यह चिंता जताई जा रही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं। अफगान की औरतों के साथ ठीक नहीं हो रहा है। युद्धरत देश युद्धविराम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कभी गाज़ा, कभी म्यांमार, कभी बांग्लादेश तो कभी गल्फ देशों से अस्थिरता, संघर्ष और मतभेद की पराकाष्ठा देखने-सुनने को मिल रही है। समस्या यह है कि संकटग्रस्त देशों का यह समूह जब-जब न्यूयॉर्क में इकठ्ठा होता है तो कोई समाधान न निकालकर केवल अपना दिल हल्का करने के लिए कुछ-कुछ कहकर चला जाता है। एंटोनियो गुतारेस की यह चिंता कि निर्धनता में कमी लाने, असमानता को दूर करने और जलवायु संकट समेत अन्य चुनौतियों पर पार पाने के लिए ठोस समाधानों की आवश्यकता है। हमें समाधानों की जरूरत है। टिकाऊ विकास लक्ष्यों में फिर से ऊर्जा भरने और निर्धनता व



असमानता का अंत करने की जरूरत है। आर्थिक प्रगति व रोजगार सृजन को प्राथमिकता देकर महिलाओं व युवाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। उभरती हुई टेक्नॉलॉजी, जैसे कृत्रिम बुद्धिमता को प्रगति के औज़ार बनाने की जरूरत है। यह सब बातें अच्छी लगती हैं लेकिन समस्या इस बात की है कि इस पर अमल कितना हो रहा है। कूटनीतिक का ऊंट जिस खूंट से सन 1945 में बांधा गया, वह कभी इस करवट-कभी उस करवट अपनी पोजीशन बदलता है। यदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं होंगे तो संयुक्त राष्ट्र व संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकत्रित होने वाले देशों व उनके नेतृत्वकर्ताओं पर भी तो प्रश्न चिह्न लगेंगे। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया बदलेगी, ऐसी आशाएं कम नहीं ही गईं, लेकिन यह आशाएं क्या केवल भ्रमजाल ही बनी रहेंगी या अबूझ पहेली? तो क्या दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा, आज सवाल यह है।

फ़िलेमॉन यंग अपनी फिलहाल दृढ़ संकल्प व प्रतिबद्धता व्यक्त किया है कि इस महासभा के जनादेश को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि सुरक्षा परिषद का सुधार करूंगा, महासभा का पुनरुद्धार करूंगा। सामाजिक शिखर सम्मेलन 2025 की सफलता के लिए काम करूंगा। विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथा अअंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है उसे गंभीरता से लूंगा और एसडीजी 14 के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी हमारी गंभीर इनिशिएटिव में सम्मिलित है संचारी रोगों पर चौथा उच्च स्तरीय सम्मेलन और भविष्य के समझौते का कार्यान्वयन जल्द अपनाया जाएगा। सही बात यही है कि सदस्य देशों को, अपनी विविधता के साथ ही अपने हितों के बारे में अपने विचारों और प्रस्तावों को मुक्त रूप में रखने का अवसर है जहां देश, लड़ाई किए बिना, चर्चा में शिरकत कर सकते हैं। उसमें फिलेमॉन यंग का यही दायित्व देशों के प्रतिनिधियों को जोड़ने और समाधान ढूंढने के लिए अवसर प्रदान करेगा, यह सच्चाई है, लेकिन देश यदि किसी समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे तभी कुछ संभव है। यदि सदस्य देश फिलेमॉन यंग स्वयं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव इन प्राथमिकताओं, सहयोगात्मक भावना के साथ आगे बढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समुदाय के लिए कुछ अभिनव आशा की किरण और समाधान का सूत्र बन जाए तो दुनिया इस सत्र की तारीफ़ करेगी। मैत्रीपूर्ण विश्व का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है इस पर वैश्विक राय बनानी फिलेमॉन यंग की प्राथमिकता होगी। वैसे भी सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक जो रखा गया है, उस पर संयुक्त राष्ट्र यदि सच स्वीकार करे तो वह उससे बहुत दूर है। सत्ता और संप्रभुता में चल रही विश्व के देशों की सरकारें इन गंभीर मसलों पर यदि बेचैन नहीं हैं तो इस दुनिया का भला भगवान भरोसे है। यदि फिलेमॉन यंग सरकारों की सोच को बदलने में सफल हुए तो निःसंदेह परिणाम भी अच्छे आएंगे। फिलेमॉन यंग की प्राथमिकता है कि उन्होंने देशों से ग़ाज़ा पट्टी, हेती, यूक्रेन, और अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में मौजूदा हिंसक टकरावों के निपटारे का आग्रह किया और अंतरराष्ट्रीय क़ानून व न्याय के फ्रेमवर्क को मज़बूती देने और मानवीय सहायता प्रयासों के लिए आपसी समन्वय को बढ़ाने की पुकार लगाई। वह चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, ड्रग, मानव तस्करी और आधुनिक दासता की चुनौतियों से निपटने के लिए मानव गरिमा का ध्यान रखा जाए।

सुनहरे भविष्य की चिंता तो पूरे विश्व को करनी होगी। इसमें फिलेमॉन यंग केवल जिम्मेदार नहीं हैं। एक वैश्विक साझी रणनीति ही हमारे लिए सुरक्षित भविष्य तैयार कर सकती है, इसलिए फिलेमॉन यंग की बतौर अध्यक्ष जो जिम्मेदारी है उसे वह निभाएंगे लेकिन उनकी उपस्थिति में यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह सत्र आमूलचूल परिवर्तन लाने में सफल हुआ तो निःसंदेह उनके नेतृत्व को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी व उन्हें श्रेय भी मिलेगा।

(लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

## मुद्दा
रोहित कौशिक



# ओजोन परत बचेगी तो बचेंगे हम

सोलह सितम्बर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही गईं। सवाल यह है कि आजोन परत की स्थिति को सुधारने के लिए जब तक हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे तब तक स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा। हालांकि अब कई स्थानों पर ओजोन परत की स्थिति सुधर रही है, लेकिन सिर्फ इतने से ही संतुष्ट होकर नहीं बैठा जा सकता। दरअसल ओजोन परत की स्थिति में उतार-चढ़ाव होता रहता है। समय-समय पर ओजोन परत को लेकर विभिन्न अध्ययन सामने आते रहते हैं। कभी-कभी इन अध्ययनों में विरोधाभासी बातें भी सामने आती हैं। यानी कभी ओजोन परत की स्थिति में सुधार का शोध प्रकाशित होता है तो कभी ओजोन परत की स्थिति बदतर होने का शोध प्रकाशित होता है। ऐसी विरोधाभासी शोध हमें भ्रमित करते हैं। दरअसल यह एक जटिल मामला है, इसलिए ओजोन परत से सम्बन्धित शोधों में अलग-अलग बातें सामने आती हैं। भिन्न-भिन्न जगहों पर ओजोन परत की स्थिति भिन्न-भिन्न हो सकती है। मूल बात यह है कि आज जिस तरह से पर्यावरण को हानि पहुंचायी जा रही है, वह ओजोन परत के लिए शुभ नहीं है। पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाकर ही हम ओजोन परत को बचा सकते हैं। कुछ समय पूर्व ओजोन परत पर काम करने वाले कोलोरेडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उपग्रहों के जरिए किए गए अध्ययन में पाया था कि कुछ जगहों पर पिछले दस साल के दौरान ओजोन के स्तर में स्थिरता बनी रही है या फिर इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है। सम्पूर्ण विश्व में ओजोन परत पर हुए अन्य शोधों के द्वारा भी यह बात सामने आई कि 1997 के आस-पास ओजोन क्षय की दर कम हो गई थी। वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में 25 साल के आंकड़ों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि लगातार खराब होती जा रही ओजोन परत की स्थिति कुछ जगहों पर अब बेहतर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगहों पर ओजोन परत की स्थिति में सुधार 1987 की अंतरराष्ट्रीय मांट्रियल संधि के कारण ही संभव हुआ है। मांट्रियल संधि का उददेश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों एवं तत्वों के उत्सर्जन पर रोक लगाना था। लेकिन इसके बाद कुछ जगहों से ओजोन परत की खराब हालत की खबरें भी आईं। वैज्ञानिकों ने सत्तर के दशक में यह खोजा था कि ओजोन परत पतली हो रही है। 1980 के आस-पास यह बहुत स्पष्ट हो गया था कि ओजोन परत का तेजी से क्षरण हो रहा है। इसके लिए विभिन्न मानवनिर्मित कारक जिम्मेदार थे। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा यह बात सामने आई कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन नामक गैस ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रही है। यह गैस मुख्यतः वातानुकूलन एवं प्रशीतन (रेफ्रिजिरेशन) में काम आती है। इसके अतिरिक्त वातावरण में ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट विमान भी क्लोरो फ्लोरो कार्बन छोड़ते हैं। इस गैस के द्वारा ओजोन परत को हानि पहुंचते देख वैज्ञानिक जगत चिन्तित था, इसलिए इस तरह की गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 1987 में अंतरराष्ट्रीय मांट्रियल संधि को लागू किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगहों पर ओजोन परत की सुधरती स्थिति इसी मांट्रियल संधि का नतीजा है। दरअसल कुछ समय पूर्व जारी ओजोन परत की सुधरती स्थिति से सम्बन्धित रिपोर्ट के कारण कोई भ्रम पाल लेना तर्कसंगत नहीं होगा। अनेक जगहों पर ओजोन परत की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मात्र क्लोरो फ्लोरो कार्बन ही ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि कुछ अन्य कारक भी ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नासा तथा कुछ विश्वविद्यालयों का मानना है कि आज कुछ जगहों पर ओजोन परत की बेहतर स्थिति के लिए क्लोरो फ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन में कमी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वातावरण में सभी जगह ओजोन की सान्द्रता बराबर नहीं रहती है। उष्णकटिबन्धी क्षेत्रों में ओजोन की सान्द्रता अधिक होती है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी सान्द्रता कम होती है। वातावरण में ओजोन फोटो केमिकल प्रक्रिया के द्वारा लगातार बनती तथा नष्ट होती रहती है और इस तरह से इसका संतुलन बना रहता है, लेकिन मानवनिर्मित प्रदूषण के द्वारा वातावरण में ओजोन का सन्तुलन गड़बड़ा जाता है। यह माना जाता है कि वातावरण में ओजोन की हर एक प्रतिशत कमी पर विभिन्न रोग बढ़ने की संभावना दो प्रतिशत अधिक हो जाती है। यह विडम्बना ही है कि एक ओर तो विकसित देश स्वयं ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों को प्रदूषण न फैलाने का भाषण दे रहे हैं। इससे वातावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश खोखले आदर्शवाद की परिधि से बाहर निकलकर वातावरण को बचाने का सामूहिक प्रयास करें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

# ईश्वर की प्राप्ति ही तो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य

संकलित
**दर्शन**

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने ईश्वर प्राप्ति के तीन -ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मार्ग बताए हैं। ज्ञान मार्ग में सांख्य की सहायता से मनुष्य तर्क-वितर्क द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु अक्सर तर्क-वितर्क में वह अपने मार्ग से भटक जाता है। कर्म मार्ग में भी मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना होता है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। इसलिए इसमें भी भटकने की पूरी संभावना होती है। वहीं भक्ति मार्ग में वह अपने आप को पूर्णतया ईश्वर भक्ति में समर्पित कर देता है। वह स्वयं को विचलित नहीं करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ईश्वर प्राप्ति की पूरी संभावना होती है। इन तीनों मार्गों पर चलकर सफल होने के लिए मनुष्य को अष्टांग योग के पहले दो चरणों को जीवन में अपनाना जरूरी है। यह हैं यम और नियम। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्माचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह आते हैं। सत्य शब्द से तात्पर्य है सत्यता का जीवन में हर समय पालन करना। अहिंसा केवल जीव हिंसा से ही संबंधित नहीं है, इसमें दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना भी आता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह से तात्पर्य है कि आवश्यकता से ज्यादा किसी वस्तु या धन का संग्रह न करना। वहीं नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान आते हैं। शौच से मतलब मन की सफाई होता है। इसके लिए मनुष्य को स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। यम और नियम को जीवन में अपनाने के लिए सर्वप्रथम ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी है।

# जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें

संकलित
**प्रेरणा**

द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज बीस तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्रीकृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्रीकृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्रीकृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्रीकृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्रीकृष्ण आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्रीकृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे।श्रीकृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्रीकृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्रीकृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीकृष्ण जीत गए। इसके बाद जामवंत ने मणि श्रीकृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्रीकृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी।

## अंतर्मन




### आज की पाती

#### जनता का दायित्व सिर्फ वोट डालने तक

लोकतंत्र यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार। लेकिन क्या यह तंत्र असलियत में अपना राजधर्म निभा रहा है, इसका निर्णय भी जनता को ही करना चाहिए। हमारा दायित्व सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, जबकि यह आकड़ा भी 50 से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाता। बाकि बची 40 से 45 प्रतिशत जनता इसलिए वोट नहीं डालती कि उन्हें उम्मीदवार पसंद नहीं या उन्हें वोट डालना पसंद नहीं या वो वर्तमान के राजनीतिक हालात से खुश नहीं हैं। ऐसी कई संभावनाएं हैं जो वोट के प्रतिशत को चुनाव आयोग के कई आयोजनों के बावजूद नहीं बढ़ा पा रही हैं। उन नाखुश वोटरों को बेशक वर्तमान में नोटा जैसा प्रावधान दिया है, लेकिन इसके अलावा राइट टू रीकॉल रूपी हथियार को मजबूती दी जाए तो जरूर लोकतंत्र जमीनी स्तर तक वोटरों की भारी भागीदारी के साथ ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा।

*- मुकेश झा, भाटापारा*

## करंट अफेयर

# तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण रोका

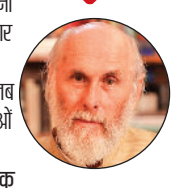

तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही केवल दो ऐसे देश हैं, जहां पोलियो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सितंबर में टीकाकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले इसे रोकने की खबर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को दी गई है और इसके पीछे किसी कारण भी उल्लेख नहीं किया गया है। तालिबान सरकार की तरफ से इस बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उन्हें घर-घर जाकर टीकाकरण करने के बजाय मस्जिदों जैसे स्थानों पर टीकाकरण करने की चर्चाओं की जानकारी मिली है। डब्ल्यूएचओ ने इस वर्ष अफगानिस्तान में पोलियो के 18 मामलों की पुष्टि की है। पाकिस्तान में भी पोलियो के छह मामले सामने आने की बात कही जा रही है। जिसके बाद वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया गया पर स्थानीय लोगों के काफी विरोध के बाद उस अभियान को संयुक्त राष्ट्र को रोकना पड़ा। आज विश्व के अधिकांश देशों से पोलियो का सफाया हो चुका है।

## ऑफ बीट

# पृथ्वी के पास शनि की तरह कभी कोई छल्ला रहा होगा

लगभग 46.6 करोड़ वर्ष पहले बना एक ऐसा छल्ला हमारे ग्रह के अतीत की कई पहेलियों को सुलझा सकता है। लगभग 46.6 करोड़ वर्ष पहले बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने लगे थे। हम यह जानते हैं क्योंकि भूवैज्ञानिक रूप से संक्षिप्त अवधि में इसके असर के कारण पृथ्वी पर कई गड्ढे बने। इसी अवधि में हमें यूरोप, रूस और चीन में चूना पत्थर के भंडार भी मिले जिनमें एक प्रकार के उल्कापिंड का बहुत ज्यादा मलबा था। इन तलछटी चट्टानों में उल्कापिंड के मलबे का संकेत मिलता है कि वे आज गिरने वाले उल्कापिंडों की तुलना में बहुत कम समय के लिए अंतरिक्ष विकिरणों के संपर्क में थे। इस दौरान कई सुनामी भी आईं, जैसा कि अन्य असामान्य अव्यवस्थित तलछटी चट्टानों में देखा जा सकता है। हमारा मानना है कि ये सभी विशेषताएं एक-दूसरे से संबंधित हैं लेकिन उन्हें आपस में क्या जोड़ता है? हम उल्कापिंड के असर के कारण बने 21 गड्ढों के बारे में जानते हैं। हम देखना चाहते थे कि क्या उनके स्थान में कोई गौर करने वाली बात है। अतीत में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के मॉडल का उपयोग करके हमने यह पता लगाया कि जब ये सभी गड्ढे पहली बार बने थे तो वे कहां थे। हमने पाया कि सभी गड्ढे उन महाद्वीपों पर हैं जो इस अवधि में भूमध्य रेखा के करीब थे।

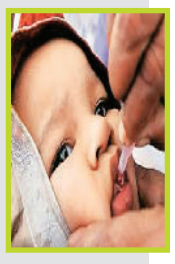



## ट्रेंड

### प्रभावशाली विकास लाए

हमारे तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन सभी के लिए प्रभावशाली विकास लेकर आए हैं। आज, विकसित भारत के दृष्टिकोण को आकार देने वाली कई परियोजनाएं अहमदाबाद से शुरू की जा रही हैं।

**-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**



### समान मानवाधिकार नहीं

हिंदू मंदिर सरकार के अधीन हैं और कानूनी नियंत्रण चर्च या मस्जिद के समान अधिकार नहीं हैं। वक्फ बोर्ड सरकार से जो चाहे जमीन व कानूनी मंजूरी ले सकता है। जब तक इसमें बदलाव नहीं होता तब तक हिंदुओं के पास समान मानवाधिकार नहीं हैं।

**-डॉ डेविड फ्रॉली, अमेरिकी हिंदू लेखक**



### सिर शर्म से झुक गया

एक शर्मनाक वीडियो सामने आया, जिसमें देश के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने को लेकर सफाई दे रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। इससे देश के 144 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया।

**-संजय सिंह, आप नेता**



### धैर्य शांत शक्ति

परिवार के साथ धैर्य ही प्रेम है। दूसरों के प्रति धैर्य ही सम्मान है. स्वयं के प्रति धैर्य रखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धैर्य ही विश्वास है। धैर्य वह शांत शक्ति है जो एक समय में एक पल में हमारी यात्रा को आकार देती है।

**-हर्ष गोयनका, उद्योगपति**



### अपने विचार

**हरिभूमि कार्यालय**

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अमर उजाला

# प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 17 सितंबर 2024

निर्दोष व्यक्ति को सजा देना न्याय तंत्र की खामी है, तो अपराधी को सजा न देना उससे भी बदतर है। -इमैनुएल कांट

**मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन निश्चित ही एक सशक्त शुरुआत और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों की झलक देते हैं। लेकिन विकास की गति को बनाए रखने के लिए घोषणाओं का जमीनी स्तर पर समुचित अमल भी जरूरी है।**

## सौ कदम और चुनौतियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन ऐतिहासिक सुधारों और महत्वपूर्ण पहलों के रहे हैं, जिनसे यह स्पष्ट संकेत मिला कि सरकार का ध्यान बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर तो है ही, इस पर भी है कि इनके लाभ समाज के निचले स्तर तक पहुंच सकें। इसकी पहली झलक तब मिली थी, जब नौ जून, 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के अगले ही दिन यानी दस जून को प्रधानमंत्री किसान निधि की सत्रहवीं किस्त जारी करने के लिए मंजूरी दी थी। इसके तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए थे, जिससे करीब 9.3 करोड़ किसानों को फायदा मिला। उल्लेखनीय है कि किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन सहित सात बड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में वृद्धि किए जाने से करीब 12 करोड़ किसानों को लगभग दो लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में, रोजगार विहीन विकास के विपक्ष के आरोपों और नौकरियों को सिर्फ सरकारी नौकरी का पर्याय समझने के विचार को खारिज करते हुए मोदी सरकार के पहले सौ दिनों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि इस दौरान सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाली 11 लाख से ज्यादा लखपति दीदी का भी उदय हुआ। कौशल विकास मिशन के मद्देनजर 4.1 करोड़ युवाओं के लिए दो लाख करोड़ के पैकेज और एक करोड़ युवाओं के लिए 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की घोषणाएं भी बेरोजगारी दूर करने के लिहाज से अहम हैं। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी देना हो या सत्तर वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को हर साल पांच लाख रुपये तक के मेडिकल कवर का एलान, मोदी सरकार ने इन ऐतिहासिक घोषणाओं के जरिये देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनी फिक्रमंदी ही जाहिर की है। साथ ही वैश्विक युद्धों के संदर्भ में अपने शांति-समर्थक रुख पर अडिग रहकर कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने दुनिया को दिखाया है कि शांति उसकी विदेश नीति की रीढ़ है। पेपर लीक, लैटरल एंट्री या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरना अपनी जगह है, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन निश्चित ही एक सशक्त शुरुआत और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने की झलक देते हैं। सरकार ने आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनका उसी भावना से समुचित अमल भी उतना ही जरूरी है।

## मृत्युदंड का भी इंतजार

**वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, जेलों में बंद 561 कैदी ऐसे हैं, जिनकों मृत्यदंड की सजा मिली है। ये आंकड़े ऐसी स्थिति बयान कर रहे हैं, जो न्याय तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित समय सीमा में कैदियों को फांसी न देना भी मानवाधिकार व संविधान प्रदत्त अधिकारों के अनुसार असंगत ही है।**

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में मृत्युदंड पाने वाले कैदियों की संख्या बढ़कर 561 हो गई है, जो पिछले 19 वर्षों में सर्वाधिक है। इससे पहले, जेलों पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2004 में मृत्युदंड पाने वाले कैदियों की सबसे ज्यादा संख्या 563 थी। हाल के वर्षों में यह वृद्धि कई कारणों से हो सकती है, जैसे, अपीलीय न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटारे की कम दर और सुनवाई अदालतों द्वारा मृत्युदंड देने की बढ़ती प्रवृत्ति आदि। गौरतलब है कि दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रोजेक्ट 39-ए के तहत मृत्युदंड पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें उल्लेख है कि 2023 में मृत्युदंड के 120 आदेश दिए गए थे, हालांकि इसमें कमी आई है, क्योंकि 2016 में 156 ऐसे आदेश दिए गए थे।

**सीबीपी श्रीवास्तव**
*अध्यक्ष, सेंटर फॉर अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली*

वर्ष 2019 के बाद यौन अपराधों से जुड़े मामलों में ट्रायल कोर्ट ने सबसे ज्यादा मौत की सजा के आदेश दिए हैं। वर्ष 2023 में दुष्कर्म और हत्या सहित यौन अपराधों के लिए 64 लोगों (लगभग 53 फीसदी) को मौत की सजा सुनाई गई। यह 2016 में मौत की सजा पाए 27 कैदियों से ज्यादा है। 75 फीसदी मामलों में, अदालतों ने मौत की सजा तब सुनाई, जब मामला 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा था। पिछले साल भी 2020 के बाद से उच्च न्यायालयों में मौत की सजा की पुष्टि की सबसे कम निपटान दर देखी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 के बाद से अपीलीय अदालतों द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की 2023 में सबसे कम दर दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने जांच प्रक्रिया के प्रभावी नहीं होने और लोगों को दोषी ठहरा कर मौत की सजा सुनाने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसेमंद साक्ष्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर चिंता जताई है।

रिपोर्ट में दिए गए ये आंकड़े मृत्युदंड के मामलों की ऐसी स्थिति बयान कर रहे हैं, जिसमें न्याय तंत्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग रहे हैं। यहां भारत में मृत्युदंड की सांविधानिक स्थिति पर विचार करना समीचीन होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति दी गई है। ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रपति जनता का सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि है, अतः संप्रभु जनता में निहित ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरी ओर, हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार, 2021 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता था, लेकिन इस मामले में न्यायालय ने कहा कि चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने के साथ-साथ राज्य का सांविधानिक प्रधान भी है, अतः दोनों की शक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जा सकता।

भारतीय दंड संहिता में धारा 302 के तहत मृत्युदंड का प्रावधान था। वर्तमान में प्रचलित भारतीय न्याय संहिता में भी कई अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान है। जैसे हत्या, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या आदि। उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर मृत्युदंड की सांविधानिक वैधता के संबंध में निर्णय दिए हैं। भारत में मृत्युदंड को पहली चुनौती जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1972 मामले में दी गई थी। न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड की सजा परिस्थितियों की विस्तृत जांच और गंभीर मूल्यांकन के बाद दी जाती है, इसलिए ऐसी प्रक्रिया मृत्युदंड के प्रावधान को उचित ठहराती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह दंड कई न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित है। राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1979 मामले में न्यायालय ने प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से अलग हटकर सामाजिक लक्ष्यों के रूप में निवारण और सुधारात्मक सिद्धांत पर जोर दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड के आदेश के लिए आवश्यक 'विशेष कारण' अपराध से संबंधित नहीं होने चाहिए, बल्कि अपराधी पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

वर्ष 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में मृत्युदंड की सांविधानिक वैधता को फिर से चुनौती दी गई। इस मामले में सबसे पहले, आजीवन कारावास और मृत्युदंड के बीच विकल्प वाले अपराधों के लिए आजीवन कारावास देने के नियम के संबंध में मृत्युदंड को अपवाद बना दिया गया था। दूसरे, राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1979 के सिद्धांत ने उस आधार की व्याख्या की थी, जिसके आधार पर 'मृत्युदंड' अपराधी की परिस्थिति से संबंधित होना चाहिए, न कि अपराध से। तीसरे, इसने मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 के आलोक में मृत्युदंड की समीक्षा की, क्योंकि प्रत्येक दंडात्मक कार्रवाई को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के स्वर्णिम त्रिभुज परीक्षण को संतुष्ट करने के बाद तर्कसंगतता के परीक्षण को पूरा करना चाहिए। मृत्युदंड के संबंध में बच्चन सिंह मामले के अलावा मारू राम बनाम भारत संघ, 1980 मामले में भी न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड 'दुर्लभ में दुर्लभतम' मामलों में ही दिया जाएगा, अर्थात यह अपवाद स्वरूप ही दिया जाएगा।

सवाल यह है कि आज के समय में, जब अधिकारों के प्रति दिन-प्रतिदिन जागरूकता बढ़ रही है और विशेषकर मानवाधिकारों के संबंध में कई राष्ट्रों ने मृत्युदंड को समाप्त करने पर जोर दिया है, भारत में भी मृत्युदंड की सांविधानिक वैधता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा दंड मानव अधिकारों के विरुद्ध लगता है, लेकिन कानून को हटाना या उसे इस आधार पर अवैध कहना तर्कसंगत नहीं होगा। देखना यह होगा कि ऐसा दंड किन परिस्थितियों में दिया गया है और यदि परिस्थितियां 'दुर्लभ में दुर्लभतम' हैं, तो मृत्युदंड को तार्किक मानना होगा। लेकिन यदि मामले एक निश्चित समय-सीमा से अधिक समय तक लंबित रहते हैं या ऐसी सजा पाने वाले कैदियों को फांसी नहीं दी जाती, तो ऐसी स्थिति मानव अधिकारों या संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज से असंगत मानी जाएगी।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

लियो टॉलस्टॉय

सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उस व्यक्ति को खुश करना है, जो आपके करीब खड़ा है। आपको अपने जीवन का अर्थ समझना होगा, उसके बाद ही जी पाएंगे। जीवन की अंतिम सच्चाई तो मौत ही है।

### सिर्फ वर्तमान क्षण पर ही हमारा प्रभुत्व है

*एक यात्री को खूंखार जानवर ने घेर लिया। जानवर से बचकर वह एक सूखे कुएं के पास जाता है और छलांग लगाने के बारे में सोचता है, लेकिन कुएं के अंदर एक अजगर को देखता है, जो उसे निगलने के लिए अपना जबड़ा खोलता है। वह यात्री सोच में पड़ जाता है कि अगर बाहर रहा, तो खूंखार जानवर खा जाएगा और कुएं में कूदा, तो अजगर खा जाएगा। वह कुएं की दरार में उगी एक टहनी को देखता है और उसी को पकड़कर चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि दो चूहे, एक काला और एक सफेद है, टहनी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे कुतर रहे हैं, जिससे वह चिपका हुआ है। अब उसके मन में एक दृश्य बन रहा है कि कुछ समय के बाद टहनी खुद ही टूट जाएगी और अजगर उसे खा जाएगा। यह सोचते हुए उसका ध्यान टहनी की पत्तियों पर जाता है, और वह पत्तियों पर शहद की कुछ बूंदें देखता है। वह अपनी जीभ की मदद से शहद चाटने का प्रयास करता है। उसे शहद अच्छा लगता है, लेकिन वापस से सोचने लग जाता है कि मृत्यु मेरे करीब है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस पीड़ा में क्यों पड़ा है। उसने उस शहद को वापस चखा, लेकिन वह अब बेस्वाद लगने लगा। उसका पूरा ध्यान अजगर और दो चूहों पर चला गया। उसे मौत के डर ने वर्तमान से दूर कर दिया। जीवन के जो पल थे, उन्हें भी उसने बर्बाद कर दिया। इसलिए हमारा वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है, जिस पर हमारा प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमेशा वह होता है, जिसके साथ आप हैं, जो आपके ठीक सामने है, क्योंकि कौन जानता है कि भविष्य में आपका किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार होगा या नहीं? सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उस व्यक्ति को खुश करना है, जो आपके करीब खड़ा है, यही जीवन का लक्ष्य है। आपको जीवन का अर्थ समझना होगा, उसके बाद ही आप जीवन जी पाएंगे, क्योंकि ज्ञान का हर कदम आपको सच्चाई की ओर ले जाता है। अंतिम सच्चाई तो मौत ही है।*

*हम और आप आमतौर पर किसी व्यक्ति से मिलते ही उसे विशेष तरीके से परिभाषित करते हैं-दयालु, दुष्ट, मूर्ख, ऊर्जावान, उदासीन इत्यादि। लेकिन असल में लोग ऐसे नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अक्सर क्रूर से ज्यादा दयालु होता है, और अक्सर मूर्ख से ज्यादा बुद्धिमान होता है, अक्सर उदासीन से ज्यादा ऊर्जावान होता है या बिल्कुल इसके विपरीत। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति दयालु या बुद्धिमान है। मनुष्य नदियों की तरह हैं, उन सभी में पानी एक जैसा है, लेकिन हर नदी कहीं संकरी है, तो कहीं तेज बहती है, कहीं चौड़ी है, तो कहीं शांत, साफ, ठंडी, मैली या गर्म है। ऐसा ही मनुष्यों के साथ होता है। समाज में हम अक्सर एक-दूसरे पर आरोप थोपते रहते हैं। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। पहले खुद बदलें, फिर दूसरों को बदलने के बारे में सोचें।*

### निश्चित उद्देश्य रखें

सूत्र

*जीवन सेवा का स्थान है। सेवा करने में व्यक्ति को बहुत कष्ट भी सहने पड़ते हैं, लेकिन उससे आनंद भी बहुत मिलता है। वह आनंद तभी वास्तविक हो सकता है, जब लोग अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखें और जीवन में खुद और अपने व्यक्तिगत सुख के अलावा एक निश्चित उद्देश्य रखें।*

## दूसरा पहलू

दुर्लभ फूलों के पौधों को खोजने और बचाने में जुटे कार्लोस मैग्डालेना अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते।

### मगरमच्छों से नहीं डरते लोग कहते हैं 'मसीहा'

वह ऑस्ट्रेलिया में वाटर लिली को देखने के लिए हेलिकॉप्टर से मगरमच्छों से भरे हुए पानी में उतरे। मॉरीशस में उन्होंने चट्टान किनारे से एक पौधे का नमूना उठाया था। पिछले महीने वह ओरिनोको नदी की कोलंबियाई सहायक नदी में लिली की तलाश में सुबह चार बजे तैरते हुए पीपे के पुल तक पहुंचने के लिए अंधेरे में एक तख्त से दूसरे तख्त पर कूद गए। लंदन में रॉयल बॉटेनिक गार्डन, क्यू के बागवानी विशेषज्ञ कार्लोस मैग्डालेना ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि मैं इतना साहसी हूं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं।'

**सिलवाना पैटरनोस्ट्रो**

रॉयल बॉटेनिक गार्डन के बागवानी विशेषज्ञ ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि मैं इतना साहसी हूं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं।'

दुनिया की सबसे छोटी वाटर लिली निम्फिया थर्मारम, जिसका फूल नाखून के आकार का होता है, क्यू गार्डन की बहुमूल्य संपत्ति थी। वर्ष 2014 में उसे चुरा लिया गया, तब से पौधों की आवाज बन गए हैं मैग्डालेना।

क्यू गार्डन में उष्णकटिबंधीय पौधों की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी मैग्डालेना के पास ही है। लेकिन वह 'पौधों के मसीहा' के नाम से जाने जाते हैं। यह नाम 2010 में एक स्पेन समाचार पत्र ने उन्हें पौधों की विलुप्त होती विभिन्न प्रजातियों को बचाने के लिए दिया था। उनके इस काम ने उन्हें वनस्पति जगत में काफी सम्मान दिलाया और वह बागवानी की दुनिया की मशहूर हस्ती बन गए। उनकी प्रसिद्धि वर्ष 2012 में तब भी बढ़ी, जब प्रकृति वृत्तचित्रों के ब्रिटिश विशेषज्ञ डेविड एटनबरो ने एक फिल्म के प्रीमियर में 'पादप मसीहा' टैगलाइन दोहराई, जिसमें मिस्टर मैग्डालेना को पिगी लिली का प्रचार करते हुए दिखाया गया था। इससे मैग्डालेना शुरू में निराश हुए, लेकिन पिगी लिली ने उन्हें चर्चा में ला दिया।

दुनिया की सबसे छोटी वाटर लिली निम्फिया थर्मारम, जिसका फूल नाखून के आकार का होता है, क्यू गार्डन की बहुमूल्य संपत्ति थी। वर्ष 2014 में उसे चुरा लिया गया, लेकिन चोर कभी पकड़ा नहीं गया। उस छोटे से पौधे की देखभाल करने वाले मैग्डालेना ने मीडिया को रवांडा मूल के उस दुर्लभ फूल के बारे में बताया था। इसके बाद से वह वनस्पतियों के एक बड़े पैरोकार बन गए। उन्होंने कहा कि पौधे कभी बोलते या रोते नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए बोलने का संकल्प लिया है।

अपने माता-पिता की पांच संतानों में सबसे छोटे मैग्डालेना उदासीन छात्र थे, लेकिन आठ वर्ष की उम्र में ही उन्होंने माता-पिता के बागवानी विश्वकोश को 12 बार पढ़ लिया था। उनकी मां फूल उगाती थीं और खेती करना उनके पिता का शौक था। प्रकृति की निकटता उन्हें विरासत में मिली है। मैग्डालेना के अनुसार, करीब एक लाख से अधिक पौधों की प्रजातियां खतरे में हैं।

©The New York Times 2024

## आंकड़े

### कृषि में मशीन

भारत में कृषि कार्यों में धीरे-धीरे मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है। लेकिन हम अब भी प्रमुख देशों से मशीनीकरण में पीछे हैं।

| | |
|---|---|
| अमेरिका व यूरोप | 95% |
| रूस | 80% |
| ब्राजील | 75% |
| चीन | 48% |
| भारत | 40% |

आंकड़े मशीनीकरण के उपयोग के, प्रतिशत में | स्रोत : RBI

भगवान राम के कहने पर भोलेनाथ जब पार्वती जी से विवाह करने को तैयार हुए, तो उन्होंने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा।

### सप्तऋषियों ने ली पार्वती की परीक्षा

**माता** पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। इधर भोलेनाथ राम नाम में मग्न होकर घूम रहे थे। भगवान राम ने शंकर जी को दर्शन देकर कहा कि पार्वती जी आपके लिए कठोर तप कर रही हैं। आपको अब उनसे शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए।

शंकर जी ने कहा कि माता-पिता और गुरु की आज्ञा तो बिना किसी विचार के ही मान लेनी चाहिए। आप तो मेरे आराध्य हैं। इसके बाद भगवान राम अंतर्धान हो गए और शंकर जी आगे बढ़ गए। उन्हें रास्ते में सप्तऋषि मिले। शंकर जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप जाकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्तऋषि माता पार्वती के पास पहुंचे और कहा कि आप जिन नारद जी की बात मानकर तपस्या कर रही हैं, उनकी बात मानकर, तो आज तक किसी का भी घर नहीं बसा है। इसके साथ ही सप्तऋषियों ने कहा कि आप जिन शंकर के लिए घोर तप कर रही हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। वह तो कंगाल हैं। वह खुद भीख मांगकर अपना निर्वाह करते हैं। तुम्हारा भरण-पोषण कैसे होगा? नारद जी और भगवान भोलेनाथ की निंदा, सुनने के बाद पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा कि मेरे गुरु (नारद) ने जो उपदेश दिया है, अब उससे पीछे नहीं हटूंगी।

अंतर्यात्रा
संकलित

*नारद बचन न मैं परिहरऊं। बसउ भवनु उजरउ नहिं डरउं॥ गुर कें बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेही॥*

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 06 फरवरी, 1959

### मैकमिलन रूसी नेताओं से मिलने मास्को जाएंगे

श्री मैकमिलन रूसी नेताओं से मिलने मास्को जायंगे

अमेरिकी विदेशमन्त्री श्री डलेस से परामर्श

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेरॉल्ड मैकमिलन विदेश मंत्री लॉयड के साथ इसी माह मास्को जा रहे हैं, जहां वह रूसी नेताओं से शिखर सम्मेलन के बारे में वार्ता करेंगे, ताकि युद्धप्रिय देशों में समझौता हो जाए।

## सुलझाने के बजाय उलझा रही तकनीक

**तकनीक जब हमारे संचार के हर पहलू को नियंत्रित करती है, तब मानवीय संवेदनाएं, आवाज की गर्माहट और भाव सब गायब हो जाते हैं।**

मुकुल श्रीवास्तव | मुद्दा

आज के डिजिटल युग में तकनीक ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट, एप और एआई जैसी तकनीकों ने न केवल हमारे कामकाज को अधिक सुविधाजनक और तेज बना दिया है, बल्कि संवाद के तरीकों को भी बदल दिया है। एक ओर तकनीक संचार को त्वरित और सुलभ बना रही है, तो दूसरी ओर इसका प्रभाव मानवीयता पर भी पड़ा है। संचार में मानवीय भावनाएं, आवाज की गर्माहट और चेहरों के भाव धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं, जो समस्याओं को सुलझाने के बजाय और बिगाड़ रहे हैं।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स हों या ऑनलाइन कंपनियां, ये हमारे जीवन का आज अहम हिस्सा बन गई हैं। चाहे अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगाना हो या ऊबर, ओला जैसी कैब सर्विस से कहीं जाना। इन एप आधारित कंपनियों ने हमारे रोजाना के कामों को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। मगर इसका एक और पहलू भी है, इन तकनीकों और ऑनलाइन सेवाओं के फायदे के साथ कुछ चुनौतियां और समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हमारे पास सीधे और व्यक्तिगत संपर्क की कमी होती है, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान मुश्किल हो जाता है।

फेसबुक ने भारत में 32 करोड़ उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए केवल हेल्प, सपोर्ट और रिपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, जो कि एक पूर्वनिर्धारित एकतरफा तंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। यह स्थिति दर्शाती है कि कैसे तकनीकी सुविधाएं हमारे समस्या समाधान की प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं और मानवीय संबंधों को एक तंत्र में बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई उत्पाद खरीदते हैं और वह खराब निकलता है, तो आपको अक्सर चैटबॉट से ही मदद मिलती है। वास्तविक उपभोक्ता सेवा प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर फूड डिलीवरी एप पर आपके ऑर्डर में खराब या गलत भोजन आता है, तो आपको स्वचालित सपोर्ट और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता है। सीसीडब्ल्यू डिजिटल और कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस के अध्ययन में बताया गया है कि 55 फीसदी उपभोक्ताओं का अनुभव चैट-बेस्ड सपोर्ट में बदतर रहा है यानी स्वचालित सहायता तंत्र अक्सर मानवीय समाधान की कमी को पूरा नहीं करता।

तकनीक ने ग्राहक सेवा के क्षेत्र में एक बुनियादी परिवर्तन ला दिया है। ग्लोबल स्ट्रैटजिक बिज रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 तक विश्व भर का कॉल सेंटर बाजार 332 अरब डॉलर का था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी करीब दस प्रतिशत है। नैसकॉम के मुताबिक, भारत में पांच करोड़ लोग इन बीपीओ और कॉल सेंटरों से रोजगार प्राप्त करते हैं। बड़ी कंपनियों ने ग्राहक सेवा में वेटिंग टाइम को कम करने के लिए लाइव चैट का विकल्प दिया, जिसमें ग्राहकों को अपनी समस्याएं लिख कर देने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। और धीरे-धीरे मौखिक संचार को कम कर कंपनियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट्स को तरजीह देनी शुरू कर दी, इससे कंपनियों का ग्राहक सेवा पर खर्च कम हुआ है। इस वजह से कंपनियों ने कॉल सेंटर प्रतिनिधियों की संख्या घटाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव से कॉल सेंटरों का अस्तित्व खतरे में है। कैंपेन एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2023 में इंडियन एयरलाइंस के चैटबॉट 'महाराजा' ने 93 प्रतिशत ग्राहकों के सवालों का समाधान बिना कॉल सेंटर प्रतिनिधि के पास भेजे किया है।

कंपनियों की लागत कम करने के लिए यह आसान तरीका है, ताकि लोगों की कॉल सेंटरों पर निर्भरता कम की जा सके। मगर कई एप कॉल हेल्पलाइन की लिंक तक पहुंचने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना देते हैं कि ग्राहकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। न्यू वॉइस मीडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, खराब ग्राहक सेवा के कारण हर साल करीब 75 अरब डॉलर के व्यापार की हानि होती है। जिनमें कॉल सेंटरों और खराब सहायता तंत्र भी एक अहम कारण होते हैं।

तकनीक के अंधाधुंध प्रयोग से मानवीय संवाद का स्थान एक निर्जीव तंत्र ने ले लिया है, जहां अब समस्याओं का समाधान मशीनों और बिना मौखिक संवाद के द्वारा किया जाता है। वहीं यह सिर्फ व्यापार और ग्राहक सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। तकनीक जब हमारे संचार के हर पहलू को नियंत्रित करती है, तो हम अपनी मानवीय संवेदनाओं से दूर होते जाते हैं। अंत में हमें इस बात पर विचार करना होगा कि तकनीक हमारे जीवन को जितना आसान बना रही है, उतना ही हमें मानवीय मूल्यों से दूर कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण समय है, जब हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीक हमें उलझाने के बजाय हमारे जीवन को सुगम बनाए।